

वर्ष के दौरान देशी समष्टि आर्थिक स्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों में तीव्र गिरावट को दर्शाता है। पहली छमाही में, उच्च मुद्रास्फीति तथा चक्रीय मंदी के उभरते संकेतों से निपटने के लिए नीतिगत परिवर्तन किए गए; तथापि दूसरी छमाही में, वैश्विक आर्थिक संकट के संसर्ग के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए समन्वित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत कार्रवाइयां आवश्यक हो गईं ताकि वृद्धि में आयी मंदी कम की जा सके, देशी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता का परिरक्षण किया जा सके, और व्यवस्थित एवं भलिभांति कार्य करने वाले बाजारों को बनाए रखा जा सके। वृद्धि को समर्थन देने वाले राजकोषीय रुख के कारण राजकोषीय समेकन के मार्ग से विचलित होना पड़ा और राजकोषीय घाटा तदनुसार बढ़ गया। मौद्रिक नीति के रुख में निभाव की प्रवृत्ति बनी रही; रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में उपयुक्त कटौती कर अपनी चलनिधि की लागत ने उल्लेखनीय कमी करते हुए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित किया। साल की दूसरी छमाही में डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में आयी तीव्र गिरावट ने निभाव वाली मौद्रिक नीति का अनुसरण करने की गुंजाइश पैदा की। भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं वैश्विक संक्रमण से काफी सीमा तक मुक्त रहीं क्योंकि ये मूल रूप से सुदृढ़ थीं तथा उन्नत देशों में मौजूद संकटग्रस्त आस्तियों तथा तनावपूर्ण संस्थाओं के प्रति इनका कोई प्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं था। रिजर्व बैंक के त्वरित एवं आवश्यक प्रतिसाद से बाजार की व्यवस्थित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा सकी। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली में मौजूद हालात ने विकसित देशों की भांति भारत में संवृद्धि के लिए बाधा का काम नहीं किया। तथापि, मांग में आयी कमी साल की दूसरी छमाही में एक बड़ी चिंता बनकर उभरी क्योंकि वृद्धि पर इसका मंदकारी प्रभाव पड़ा।

I. समष्टि आर्थिक नीतिगत परिवेश

II.1.1 नीति निर्माण के लिए 2008-09 के दौरान वातावरण अपवादात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण बना रहा, क्योंकि वैश्विक मंदी तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों की उत्तेजक स्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनके प्रतिकूल प्रशासन को नियंत्रित करने हेतु त्वरित एवं उपयुक्त नीतिगत उपायों की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान देशी समष्टि आर्थिक स्थिति में भी नाटकीय परिवर्तन आया; जहां पहली छमाही में मुद्रास्फीतिकारी दबाव बनने तथा चक्रीय मंदी के कुछ साक्ष्य से संबंधित चिंताएं थीं वहीं दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक संकट और गहराने तथा फलस्वरूप वृद्धि में कमी आने के कारण पूंजीगत आवक बदलने तथा वित्तीय बाजारों पर दबाव से उत्पन्न आशंकाएं पैदा हुईं। उच्च वृद्धि तथा कम मुद्रास्फीति संबंधी चार वर्षों के चरण के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा अनुभूत वैश्वीकरण के लाभों के बावजूद, 2008-09 में उत्पन्न संकट ने न सिर्फ संसर्ग की गति और मात्रा के रूप में, अपितु बने हुए प्रतिकूल बाह्य वातावरण को देखते हुए चुनौतियों

से निपटने संबंधी राष्ट्रीय नीतियों की सीमाओं के रूप में भी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्वीकरण से जुड़ी जोखिमें सामने ला दीं। विश्वभर के अधिकांश देशों के लिए, जहां अनाज और पण्य की उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने वर्ष की पहली छमाही में प्रति-मुद्रास्फीतिकारी नीतियों के संचालन के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दीं, वहीं ऋण की वैश्विक तंगी, तनावग्रस्त वित्तीय संस्थाओं, दुष्क्रियाशील बाजारों तथा इन सबसे ऊपर गिरते हुए वैश्विक उत्पाद, निवेश, रोजगार एवं व्यापार ने वृद्धि में कमी को रोकने तथा वित्तीय स्थिरता के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीतियों के उपयोग हेतु परीक्षात्मक स्थितियां उत्पन्न कर दीं।

II.1.2 अत्यधिक वैश्विक मंदी के बीच भी, भारत वृद्धि में कमी को रोक सका, वित्तीय स्थिरता का परिरक्षण कर सका तथा बाजारों में सामान्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित कर सका। भारत के समष्टि आर्थिक नीतिगत ढांचे तथा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजारों के विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रति दृष्टिकोण ने देशी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने में स्पष्ट तौर

पर अंशदान किया। तथापि वैश्वीकृत दुनिया में, व्यापार, पूंजी प्रभार तथा विश्वास सरणियों के जरिए इस संक्रमण ने नैसर्गिक रूप से फैलते हुए देशी आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों को प्रभावित किया है। जीडीपी में वास्तविक वृद्धि, जिसका औसत 2003-08 के दौरान 8.8 प्रतिशत था, कम हो कर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत रह गई। व्यापार एवं पूंजी प्रवाह संबंधी सरणियों का दबाव भुगतान संतुलन पर पड़ा। संसर्ग की विश्वास सरणी के साथ इन गतिविधियों ने वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया। बैंकिंग प्रणाली में आघात-सहनीयता के बावजूद, चलनिधि की मांग, देशी और विदेशी मुद्रा दोनों में, बढ़ गई। भारत सरकार के परामर्श और समन्वय से रिज़र्व बैंक को अर्थव्यवस्था, बाजारों और वित्तीय संस्थाओं को समाविष्ट करते हुए व्यापक नीतिगत उपाय करने पड़े। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में गतिविधियों का ब्यौरेवार विश्लेषण भाग I के विभिन्न खंडों में अलग से प्रस्तुत किया गया है, जबकि विशिष्ट नीतिगत उपाय शुरू करने के पीछे मौजूद संदर्भ/ मूलाधार की रूपरेखा भाग II के संबंधित अध्यायों में प्रस्तुत की गई है। इस खंड में 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था के वास्तविक, राजकोषीय, मौद्रिक, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रों में भारत में लिए गए सभी प्रमुख नीतिगत उपायों के रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

वास्तविक क्षेत्र की नीतियां

कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

II.1.3 जीडीपी, रोजगार, खाद्य सुरक्षा में अंशदान के रूप में तथा समावेशक वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, संघ सरकार कृषि आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों की संपूर्ति एवं अनुपूर्ति करती रही है। कृषि वृद्धि का संवर्धन करने तथा कृषकों की जीविका एवं आय को सुदृढ़ करने धारणीय समाधान खोजने के लिए हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2007-08 में सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय योजनाएं शुरू की गई हैं। उल्लेखनीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को 2008-09 में और सुदृढ़ किया गया।

II.1.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 तथा 2 मिलियन टन की वृद्धि करने के उद्देश्य से 2007 में शुरू किया गया था, का कार्यान्वयन देश के 17 राज्यों के 312 अभिजात जिलों में किया जा रहा है। अधिक संभावना वाले परंतु वर्तमान में उत्पादकता के अपेक्षाकृत निम्न स्तर वाले लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उपज में सुधार के जरिए उक्त फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना उक्त मिशन का उद्देश्य है। 2008-09 के दौरान, उक्त कार्यक्रम के तहत 883 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। समावेशक वृद्धि के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, केंद्रीय बजट 2009-10 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर अभिमत के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा रखने का प्रस्ताव है।

II.1.5 अगस्त 2007 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन से आरंभ की गई राष्ट्रीय विकास योजना कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। राष्ट्रीय विकास योजना के तहत संसाधनों तक पहुंच अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा जिला कृषि योजनाएं (डीएपी)/राज्य कृषि योजनाएं (एसएपी) बनाए जाने पर निर्भर थी। 2008-09 के दौरान, 2,887 करोड़ रुपए की राशि पात्र राज्यों को जारी की गई। केंद्रीय बजट 2009-10 में आरकेवीवाइ के तहत आबंटन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

II.1.6 2007 में एनएफएसएम तथा आरकेवीवाइ शुरू किए जाने की पृष्ठभूमि में, 27 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समन्वयन करके 2000-01 में शुरू की गई कृषि का समष्टि प्रबंधन (एमएमए) योजना को जुलाई 2008 में संशोधित किया गया। तदनुसार, उक्त योजना की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है ताकि प्रयासों की ओवरलैपिंग या डुप्लिकेशन को टाला जा सके तथा इसे खाद्य सुरक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और ग्रामीण आबादी की जीविका में सुधार लाने के लिए राज्यों में कृषि के वर्तमान परिदृश्य से अधिक सुसंगत किया जा सके। राज्यों को निधियां आबंटित करने के लिए बनाए गए आबंटन मानदंडों को भी संशोधित किया गया है ताकि अधिक फसल क्षेत्र वाले एवं लघु और सीमांत किसानों के अधिक संकेंद्रण वाले राज्यों को अधिक संसाधनों का आबंटन सुकर बनाया जा सके।

II.1.7 *भारत निर्माण* ग्रामीण बुनियादी सुविधा के निर्माण के लिए 2005-06 में शुरू किया गया। इसके छः घटक हैं यथा ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण टेलीफोन, सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति, ग्रामीण आवास तथा बिजली। उक्त प्रत्येक लक्ष्य के तहत विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। 2008-09 के लिए 7,300 करोड़ रुपए के लगभग समग्र बजट प्रावधान का उपयोग वर्ष के दौरान किया गया। केंद्रीय बजट 2009-10 में इस कार्यक्रम के लिए 12,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

II.1.8 चल रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत 2008-09 के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। अनुपूरक अनुदान मांग के लिए बाद में किए गए आबंटन से 2008-09 के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कुल आबंटन बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2007-08 के 33.9 मिलियन परिवारों की तुलना में 2008-09 के दौरान 44.7 मिलियन परिवारों को रोजगार दिया गया। इस कार्यक्रम के आरंभ से अबतक लगभग 3,718 मिलियन मानव दिन का रोजगार पैदा किया गया है, जिसमें से लगभग 2,156 मिलियन मानव दिन 2008-09 के दौरान थे। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मजदूरी रोजगार में वृद्धि हुई है, मजदूरी से होनेवाली आय बढ़ी है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को काफी लाभ मिलने के साथ समता में सुधार हुआ है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और खपत में भी वृद्धि हुई है। 2009-10 के केंद्रीय बजट में इस योजना हेतु 39,100 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया।

II.1.9 2008-09 के केंद्रीय बजट में कुल कृषि ऋण के लिए 2,80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण का वास्तविक संवितरण 2,87,000 करोड़ रुपए पर उक्त लक्ष्य से अधिक था। 2009-10 के केंद्रीय बजट में वर्ष के दौरान कुल कृषि ऋण के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है तथा किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता प्रदान करना जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने निर्धारित अनुसूची के अनुसार अल्पावधि फसल ऋण की चुकौती करने वाले किसानों को एक प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता प्रोत्साहन के तौर पर देने का भी प्रस्ताव किया है।

II.1.10 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार 25 राज्यों में 13,596 करोड़ रुपए से पुनर्जीवन पैकेज लागू कर रही है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए उक्त पैकेज की विषयवस्तु के बारे में एक करार भी कर चुकी हैं। उक्त पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 2,642 करोड़ रुपए अथवा कुल भार का 86 प्रतिशत है।

II.1.11 ऋणग्रस्त किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच बहाल करने के लिए, सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी तथा राहत योजना शुरू की। रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से परामर्श करके सरकार ने उक्त ऋण माफी योजना की पद्धति को अंतिम रूप दिया। इस योजना में 'सीमांत और लघु किसानों' तथा 'अन्य किसानों' को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, आरआरबी, सरकारी ऋण संस्थाओं तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋण शामिल हैं। इस योजना के तहत, दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रखने वाले किसानों को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत के बराबर छूट दी जाएगी, बशर्ते वे 30 जून 2009 तक अपनी अतिदेय राशियों की 75 प्रतिशत राशि तीन किस्तों में चुका दें। दक्षिण-पश्चिम मानसून में आयी देरी के कारण, केंद्रीय बजट 2009-10 में इस अवधि को छः महीना बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 करने का प्रस्ताव है। उक्त बजट में विशेषकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता करने के लिए उन किसानों की समस्याएं देखने के लिए कार्यबल गठित करने का भी प्रस्ताव है जिन्हें ऋण माफी योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है तथा जिन्होंने साहूकारों से ऋण लिया है।

II.1.12 उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में मिट्टी की सीमांत उत्पादकता में कमी में अंशदान करने वाला एक प्रमुख कारक विषम एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम) प्रयोग अनुपात अर्थात् जटिल उर्वरकों (एनपीके), जिन्हें कृषिशास्त्र की दृष्टि से बेहतर और अधिक संतुलित उर्वरक उत्पाद माना जाता है, की तुलना में यूरिया, डीएपी (डाइ-अमोनियम फास्फेट) तथा एमओपी (म्यूरेंट ऑफ पोटाश) जैसे सीधे उर्वरकों का तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उपयोग है। केंद्रीय बजट 2009-10 में वर्तमान उत्पाद मूल्यन युग के बजाय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी युग की ओर अग्रसर होने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, उत्पादकता

बढ़ाने से उचित मूल्य पर बाजार में अभिनव उर्वरक उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, उर्वरक विनिर्माण क्षेत्र को बंधनमुक्त करने से इस क्षेत्र में नया निवेश आकृष्ट करने की आशा है। उचित समय में सरकार किसानों को सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण की प्रणाली की ओर अग्रसर होने पर विचार कर रही है।

II.1.13 राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) 2006 से सूखे, असिंचित वर्षा पोषित क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने और प्रणालीगत अपग्रेडेशन के लिए जानकारी प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत है। एनआरएए ने जलविभाजक विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किया है जो देश में सभी जलविभाजक विकास परियोजनाओं के आयोजन, अभिकल्प, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए समर्थक ढांचा प्रदान करेगा। इन सामान्य दिशानिर्देशों के तहत, बजट 2009-10 में चालू वित्त वर्ष में समन्वित जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम (आइडब्ल्यूएमपी) लागू करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

II.1.14 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार ने सतत आधार पर सेक्टर विशेष के लिए उपायों और अन्य कार्यक्रमों को चलाना जारी रखा। देशी उद्योग पर वैश्विक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने तथा देशी मांग को सक्रिय बनाने के लिए, भारत सरकार ने विशेषकर लघु उद्योगों सहित उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के अलावा, चलनिधि और ब्याज दर में नरमी लाने के रूप में रिजर्व बैंक से प्राप्त आनुपातिक समर्थन के साथ, अप्रत्यक्ष करों में कटौती तथा मूलभूत संरचना पर तर्क के रूप में अनेक उपाय किए हैं।

II.1.15 व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आरक्षित मदों की सूची से कुछ मदों को चरणबद्ध रूप में अनारक्षित करने की प्रक्रिया 2008 में जारी रही तथा सरकार ने वर्ष के दौरान इस सूची से 14 मदों को निकाल दिया। ऋण गारंटी योजना को आशोधित किया गया है। इन संशोधनों में शामिल हैं - 5 लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में एकबारगी गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क कम करके क्रमशः 1.0 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत करना; 50 प्रतिशत गारंटी कवर के साथ ऋण सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करना; 5 लाख रुपए के ऋणों के लिए गारंटी कवर 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना

तथा दावा करने के लिए लॉक-इन अवधि 24 माह से घटाकर 18 माह करना। वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रहे एमएसएमई को कुछ राहत प्रदान करने के लिए, केंद्रीय बजट 2009-10 में 40 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों को अग्रिम कर से छूट प्रदान की गयी। एमएसई को उचित दरों पर ऋण प्रदान करना सुकर बनाने के लिए, केंद्रीय बजट में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) में से विशेष निधि प्रदान करने का प्रस्ताव है। 4,000 करोड़ रुपए की यह निधि चालू वित्त वर्ष के दौरान एमएसई को वृद्धिशील उधार के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करके बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को एमएसई को उधार देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उद्योग विशिष्ट लाभ श्रम प्रधान तथा अधिकांश छोटे विनिर्माताओं यथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग को प्रदान किए गए हैं।

II.1.16 फार्मास्युटिकल सेक्टर में भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के साथ मिलकर जन औषधि अभियान चलाया है, जिसका लक्ष्य आम जनता को उचित कीमतों पर उत्कृष्ट औषधियां उपलब्ध कराना है। सरकार ने प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक जिले में जन औषधि भंडार स्थापित किए जाएं ताकि ब्रांडेड दवाओं के बराबर गुणवत्ता वाली जेनरिक अनब्रांडेड दवाओं की बिक्री की जा सके। इस प्रकार का पहला भंडार अमृतसर में नवम्बर 2008 में खोला गया।

II.1.17 वर्ष 2008-09 में सकल मांग को बढ़ाने और औद्योगिक संवृद्धि को पुन बढ़ाने के लिए दी गई प्रमुख कर-रियायतों में सेनवेट दरों में और सेवाकर दरों में कटौतियां शामिल हैं। आयातित सीमेन्ट पर 4 प्रतिशत की दर से प्रतिकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाया गया। भारत सरकार ने पिग आइरन, लोहा और इस्पात की सिल्ली, दण्ड और छड़ पर निर्यात शुल्क हटा दिया, इस्पात पर 5 प्रतिशत का आयात शुल्क दुबारा लगा दिया, आंशिक रूप से डीईपीबी के लाभ को बहाल किया, उत्पाद शुल्क घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया, हॉट रॉड (एचआर) आयातों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया तथा टीएमटी छड़ एवं स्ट्रक्चरल के आयात पर प्रतिकारी शुल्क से दी गयी छूट को हटा लिया।

II.1.18 निर्यात में काफी अंशदान करने वाले वस्त्र तथा परिधान उद्योग को सूती वस्त्र तथा वस्त्र संबंधी सामग्रियों पर शुल्क में

कटौती, पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के प्रति ब्याज सहायता और 10 अन्य देशों को शामिल कर फोकस बाजार योजना के विस्तार के जरिए गति मिली। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रौद्योगिकीय समुन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)के समस्त बैकलॉग का निपटान करने के लिए 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। एकीकृत टेक्स्टाइल पार्क की स्कीम (एसआइटीपी) के तहत 40 एकीकृत टेक्स्टाइल पार्कों की स्वीकृति दी गई है, बुनाई, निटिंग, प्रोसेसिंग और परिधान सेक्टरों को समाहित करने वाली इस समस्त परियोजना प्रस्तावों की लागत 4199 करोड़ रुपये है (जिसमें से सरकार की ओर से 1438 करोड़ रुपये की सहायता रहेगी)। वर्ष 2008-09 के दौरान चार टेक्स्टाइल पार्कों उद्घाटन किया गया। सरकार ने वाणिज्य वाहनों के लिए 50 प्रतिशत की दर से त्वरित मूल्यद्वारा लगाने की घोषणा भी की।

11.1.19 केंद्रीय बजट 2009-10 में अलग-अलग उद्योगों के सामने मौजूद समस्याओं को स्वीकार किया गया तथा विभिन्न उद्योग विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव किया गया। निर्माण उद्योग को मदद देने के लिए, बजट में निर्माण स्थल पर निर्मित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने की घोषणा की गयी। वाणिज्यिक वाहन उद्योग की संवृद्धि में आयी गिरावट को रोकने के लिए, बजट में पेट्रोल चालित ट्रकों पर उत्पाद शुल्क वर्तमान 20 प्रतिशत से कम कर 8 प्रतिशत किया गया है ताकि इस शुल्क को डीजल चालित इसी श्रेणी के वाहनों पर लगाये जाने वाले शुल्क के समतुल्य किया जा सके। बड़ी कारों तथा 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले यूटिलिटी वाहनों पर यथामूल्य शुल्क वर्तमान 20,000 रुपए से कम करके 15,000 रुपए कर दिया गया है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 2009-10 के केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में से प्रत्येक में एक हथकरघा बृहद खंड तथा राजस्थान में एक पावरलूम बृहद खंड बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कालीन के लिए श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश) में नए बृहद खंड जोड़े गए हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आयी मंदी से अत्यधिक प्रभावित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को समर्थन देने की दृष्टि से, केंद्रीय बजट 2009-10 में 10 वर्षीय कर छूट अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी है तथा कर लगाने के प्रयोजन के लिए एक उत्पाद अथवा सेवा के रूप में साफ्टवेयर के बीच अंतर करके

पैकेज्ड साफ्टवेयर पर कर के भार को कम कर दिया गया है। उद्योग के लिए दीर्घावधि सुधार उपायों में, उक्त बजट में अंतरण मूल्यन संबंधी विवादों के निपटान के लिए आय कर विभाग के भीतर वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रिया बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने की भी परिकल्पना की है, जिसके द्वारा देश भर में सभी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कृषि संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। उक्त नेटवर्क के आरंभिक चरण का उद्घाटन अप्रैल 2009 में किया गया।

11.1.20 वैश्विक आर्थिक संकट के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन की अनिश्चित संभावना तथा भारत में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति संबंधी परिणाम को स्वरूप देने में औद्योगिक वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2009 में बाह्य एजेंसियों तथा बैंक के संबंधित विभागों से सदस्यों को लेकर एक उद्योग निगरानी दल का गठन किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के संबंध में भारतीय उद्योग की गतिविधियों का आवधिक मूल्यांकन किया जा सके। निगरानी दल को संदर्भित विषयवस्तु में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के उभरते परिदृश्य के विश्लेषण, अलग-अलग स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि की प्रवृत्तियों पर निगरानी एवं नीतिगत उपाय सुझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उक्त दल की पहली बैठक 15 अप्रैल 2009 को की गयी जिसमें उद्योग के सामने मौजूद दबाव बिन्दुओं तथा मौद्रिक नीति निर्धारण की अपेक्षाओं की दृष्टि से पुनर्जीवन की संभावित प्रक्रिया पर चर्चा की गयी। उक्त दल ने 16 जुलाई 2009 को हुई अपनी दूसरी बैठक में उद्योगों की चालू स्थितियों एवं संभावनाओं का आश्वासन दिया।

मूलभूत संरचना

11.1.21 सरकार के नीतिगत पैकज में मूलभूत संरचना क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं, यथा करमुक्त बांड जारी करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आइआइएफसीएल) को अनुमति देना, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर ब्याज सीमा को हटाना, कंपनी ऋण बाजार में एफआइआइ निवेश पर अधिकतम सीमा बढ़ाना, रिजर्व बैंक से आसान पुनर्वित्तपोषण तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का सृजन।

II.1.22 वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना रखने वाले चुनिंदा कार्यपरक क्लस्टरों / स्थानों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के जरिए गुणात्मक मूलभूत सुविधा प्रदान कर देशी उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने औद्योगिक मूलभूत संरचना उन्नयन योजना (आइआइयूएस) को नया रूप दिया है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में उच्च वृद्धि की संभावना वाले क्लस्टरों / स्थानों में; जिनके लिए परिवहन, सड़क, बिजली आपूर्ति, निःस्त्रावी पदार्थ के उपचार तथा ठोस कचरे के निपटान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ऐसी अन्य भौतिक मूलभूत संरचनाओं के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने में रणनीतिक हस्तक्षेप अपेक्षित है; गुणवत्तापूर्ण मूलभूत संरचना का सृजन शामिल है। योजना को नया रूप देते समय, 10-15 क्लस्टरों/स्थानों का विकास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किया जाएगा। योजना को एसपीवी के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा ताकि पीपीपी विधि के तहत औद्योगिक मूलभूत संरचना के विकास के लिए केंद्रित, समयबद्ध और धारणीय पैटर्न सुनिश्चित किया जा सके।

II.1.23 पीपीपी विधि के तहत बड़ी संख्या में मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण की व्यवस्था करने में आनेवाली कठिनाइयों को देखते हुए, आइआइएफसीएल को 2008-09 के अंत तक सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त कर मुक्त बांड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए तथा 2009-10 में आवश्यकतानुसार उसी आधार पर अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इस प्रकार जुटायी गई पूंजी का उपयोग मूलभूत संरचना संबंधी पात्र परियोजना को दिए गए दीर्घावधि बैंक उधार के पुनर्वित्तपोषण के लिए आइआइएफसीएल द्वारा किया जाएगा। इस पहलकदमी के फलस्वरूप 15-18 माह की अवधि में लगभग 100 हजार करोड़ रुपए के पीपीपी कार्यक्रमों के लिए लिवरेजिंग बैंक वित्तपोषण प्राप्त होने की आशा है।

II.1.24 ऊर्जा क्षेत्र में, केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग ने फरवरी 2009 में नयी अंतर-राज्य व्यापार विनियमावली जारी की है। उक्त विनियमावली में व्यापार लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए सख्त शर्तें निर्धारित की गयी हैं ताकि गंभीर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। इसके अनुसरण में अंतर-राज्य व्यापार की परिभाषा को संशोधित कर बिक्री के लिए आयातित बिजली को

शामिल कर लिया गया है, लाइसेंसों की श्रेणी की संख्या 6 से घटाकर 3 कर दी गयी है तथा निवल मालियत संबंधी अपेक्षा को बढ़ाकर 5-50 करोड़ के दायरे में कर दिया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन संबंधी पहल में, नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय तथा यूएस जिओलोजिकल सर्वे के बीच भारत में गैस हाइड्रेट की संभाव्यता के दोहन के लिए वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी कार्मिकों की अदला बदली के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 2009-10 के केन्द्रीय बजट में ऊर्जा सुरक्षा को सुकर बनाने के लिए प्राकृतिक गैस पर करावकाश को लागू किया गया।

II.1.25 1 जनवरी 2009 से एअरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिनियम, 2008 (एईआरए) अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम में एअरपोर्ट सेवाओं के लिए शुल्क संरचना के निर्धारण, समीक्षा और अनुमोदन का तथा एअरपोर्ट के विकास एवं निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों पर निगरानी के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क का प्रावधान किया गया है।

राजकोषीय नीति

II.1.26 पांच वर्ष तक लगातार प्रभावी वृद्धि, जिससे राजस्व में काफी उछाल आया जिससे राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के तहत राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को सुकर बनाया गया, की पृष्ठभूमि में 2008-09 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। उक्त बजट में परिणामों तथा सार्वजनिक व्यय की आबंटनात्मक दक्षता सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राजकोषीय समेकन की राजस्व की अगुवाईवाली प्रक्रिया जारी रखने की परिकल्पना की गई। 2008-09 के दौरान कर नीति में उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के साथ राजस्व जुटाने हेतु कर प्रशासन की गुणवत्ता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। नीति संबंधी रणनीति यह थी कि कम तथा संख्या में थोड़ी कर दरों का आश्रय लिया जाए, छूटों को समाप्त किया जाए तथा कर-आधार को व्यापक बनाया जाए। कर-प्रशासन के मामले में कर-राजस्व की बकाया राशि की वसूली, करदाताओं को दी जानेवाली सेवाओं में सुधार तथा निवारक स्तरों में वृद्धि करने पर बल दिया गया। इस रणनीति के अनुरूप, कंपनी कर दरों को अपरिवर्तित रखा गया, जबकि व्यक्तिगत आय कर

(सीआईटी) के लिए छूट की आरंभिक सीमा बढ़ा दी गई और कर के चार स्लैब में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का प्रश्न है, बजट में सभी सामानों पर सामान्य सेनवैट को 16 प्रतिशत से कम कर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की गई ताकि विनिर्माण क्षेत्र को उत्प्रेरणा प्रदान की जा सके।

II.1.27 तथापि, अत्यधिक अप्रत्याशी बजटोत्तर गतिविधियों, विशेष तौर पर अप्रत्याशित वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अर्थव्यवस्था में आई उल्लेखनीय मंदी, के कारण केंद्र सरकार के वित्त पर काफी दबाव आ गया। सरकार ने पण्यों एवं पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए 2008-09 की पहली छमाही के दौरान अप्रत्यक्ष करों में कटौती करके तथा सब्सिडी बढ़ा कर राजकोषीय उपाय किए। तथापि, मुद्रास्फीति रोकने के लिए इन उपायों को लागू करते समय राजकोषीय समेकन के मार्ग से विचलित होने के लिए उस समय कोई सजग प्रयास नहीं किया गया। फिर भी 2008-09 की दूसरी छमाही में आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने के लिए विवेकाधीन राजकोषीय नीतिगत उपाय सक्रिय करने के साथ राजकोषीय रुख पूरी तरह बदल गया। राजकोषीय नीतिगत रुख में आया हुआ यह बदलाव वैश्विक संकट के वास्तविक प्रभावों के सामान्य प्रतिसाद के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक अंग था तथा यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त किए गए उस मुख्य दृष्टिकोण से भी संगत था कि मौजूदा संदर्भ की तरह गंभीर एवं लंबी आर्थिक मंदी की स्थितियों में राजकोषीय नीति स्थिरीकरण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। आर्थिक मंदी को रोकने के लिए, अधिकांश देशों में, विकसित और विकासशील दोनों में, समय पर उद्घाटन की ज्ञात चुनौतियों के बावजूद विवेकाधीन राजकोषीय नीति को सक्रिय किया गया है तथा इस प्रकार एक उपयुक्त निकासी रणनीति की जरूरत है। तथापि, राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेज तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह समय पर, सुलक्षित तथा स्थायी हो ताकि इसका असर सही समय पर महसूस हो, इसका अधिकतम असर पड़े और मध्यावधि में ऋण की धारणीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न न हों (बॉक्स II.1)।

II.1.28 भारतीय संदर्भ में, मंदी के वर्तमान दौरा में समस्त मांग को उत्प्रेरित करने में राजकोषीय नीति की भूमिका को आर्थिक मंदी की पिछली घटनाओं से अलग करना होगा। 2008-09 में वृद्धि में आई कमी मोटे तौर पर अनुकूलित थी तथा वह वैश्विक

मंदी एवं फलस्वरूप विश्वास की कमी द्वारा प्रभावित बनी हुई है, जिसके कारण निजी क्षेत्र की मांग में काफी गिरावट आई है। अतः वर्तमान संदर्भ में राजकोषीय नीति कि भूमिका सामान्य व्यवसायिक मंदी की पिछली घटनाओं से अलग हो सकती है। भारत के मामले में अब तक प्रदान की गई राजकोषीय उत्प्रेरणा अप्रत्यक्ष करों में कटौती तथा निवेश एवं उपभोग व्यय दोनों में वृद्धि का मिश्रण है तथा उसमें बाद वाले का बड़ा हिस्सा है। सामान्य सेनवैट दर को दिसंबर 2008 तथा फरवरी 2009 में क्रमशः 4.0 प्रतिशत अंक तथा 2.0 प्रतिशत अंक और कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे जीडीपी के 0.2 प्रतिशत की अनुमानित राजस्व हानि हुई। अक्टूबर-दिसंबर 2008 तथा फरवरी 2009 के दौरान तीन अनुपूरक अनुदान मांगों के जरिए जीडीपी के 3.0 प्रतिशत के अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया गया। व्यय संबंधी उपायों में, राजस्व व्यय लगभग 84 प्रतिशत था तथा शेष पूंजी व्यय घटक था। कुल मिलाकर राजकोषीय उत्प्रेरणा संबंधी उपायों से निवेश की मांग की तुलना में उपभोग की मांग को समर्थन देने पर अधिक बल दिया गया प्रतीत होता है। राजकोषीय घाटा 2007-08 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में जीडीपी का 6.2 प्रतिशत (अंतिम खाते) हो गया।

केंद्रीय बजट 2009-10

II.1.29 2009-10 का केंद्रीय बजट अर्थव्यवस्था में वृद्धि में आयी मंदी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेतों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में अल्पावधि एवं मध्यावधि में तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रस्ताव है, अर्थात् यथाशीघ्र 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, समावेशक विकास के लिए कार्यसूची को गहरा और व्यापक बनाना तथा सरकार को पुनः जागरूक करना एवं सुपुर्दगी की प्रक्रिया में सुधार लाना। बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि मूलभूत संरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार तथा आबादी के लाभ से वंचित वर्गों के सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आबंटन बढ़ाया जाए। सरकार ने यथाशीघ्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के ऋणात्मक असर दूर होते ही राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस जाने के महत्व को दुहराया है। मध्यावधि धारणीयता प्राप्त करने के लिए, सरकार ने सब्सिडी, कर संबंधी खर्च और विनिवेश जैसे

बॉक्स II.1

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति

बड़ी मंदी के समय से कई दशकों तक समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के लिए या तो कर दरों में अंतरण या कटौती सहित सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके या दोनों को सम्मिलित करके विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता रहा है। तथापि 1980 के दशक तक, विवेकाधीन राजकोषीय नीति पर संदेह प्रकट किया जाने लगा क्योंकि इसका अनुसरण करने में अनेक राजनैतिक एवं प्रशासनिक चुनौतियां थीं तथा नीति-निर्माण एवं समष्टि आर्थिक नीति संबंधी अनुसंधान की पद्धति में काफी परिवर्तन हुए थे। इसे अधिकाधिक रूप में स्वीकार कर लिया गया कि राजकोषीय नीति अप्रभावी है अथवा राजकोषीय गुणक निम्न है, क्योंकि अस्थायी कर कटौती के कारण बचत (उपभोग) की सीमांत प्रवृत्ति ऊंची (निम्न) होती है, जबकि सरकारी खर्च बढ़ा कर सकल मांग में वृद्धि करना दीर्घावधि ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि के कारण निष्प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा, राजकोषीय नीति में कई पश्चताएं हैं यथा मान्यता संबंधी पश्चताओं, कार्यान्वयन संबंधी पश्चताएं तथा सकल मांग पर प्रभाव में पश्चताएं, जिनके कारण इसके प्रभाव की मात्रा में अनिश्चितता पैदा हो जाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की जोखिम बढ़ जाती है। सहवर्ती तौर पर, मौद्रिक नीति को आर्थिक स्थिरीकरण के लिए प्रमुख नीतिगत विकल्प के रूप में वरीयता मिली जिसके कारण थे। त्वरित समायोजनों के प्रति इसकी प्रभावग्राहकता; आवश्यक उत्प्रेरणा के समय तथा परिमाण के बारे में निर्णय लेने की बेहतर योग्यता; तथा विवेक की गुंजाइश कम करने वाली नियम आधारित नीति का बढ़ता हुआ उपयोग (टेलर, 2000)। इस प्रकार राजकोषीय नीति की स्थिरीकरण संबंधी भूमिका स्वचालित स्थिरताकारकों के परिचालन मात्र तक सीमित थी (देखें इस अध्याय के खंड IV का बॉक्स II.24)।

तथापि कम सकल मांग तथा ब्याज दरों एवं गिरती कीमतों वाली बनी हुई आर्थिक मंदी की स्थितियों में विवेकाधीन राजकोषीय नीति की वकालत की गई है (फेल्डस्टीन, 2002)। तेजी से गिरती आर्थिक स्थितियों में, भलीभांति तैयार की गई विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरणा में मौद्रिक उत्प्रेरणा की तुलना में अधिक तेजी से आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने का संभाव्य लाभ होता है। इसके अलावा, गंभीर मंदी के दौरान, न सिर्फ नीतिगत दर कुछ अवस्था में शून्य के नजदीक पहुंचने के कारण अपितु मौद्रिक नीति संबंधी संप्रेषण प्रक्रिया में उच्चस्तरीय असंबद्धता के कारण भी मौद्रिक नीति अप्रभावी हो सकती है (एलमेंडोर्फ तथा फर्मन, 2008)। वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान यह महसूस किया गया कि जोखिम प्रीमियम में हुई अचानक वृद्धि गिरती हुई नीति दरों के प्रभाव को प्रतिबलित करने से कहीं अधिक है, तथा इससे संप्रेषण प्रक्रिया में उल्लेखनीय कमजोरी आ सकती है। आर्थिक मंदी गंभीर तथा लंबी होने पर विवेकाधीन राजकोषीय नीति लागू करने में शामिल निर्णय संबंधी पश्चताओं की समस्या भी कम बाध्यकारी हो सकती है। तथापि नीति की अभिकल्पना महत्वपूर्ण है। कम से कम तीन मानदंडों का सुझाव दिया गया है। पहला, कार्रवाई की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए यह समय पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इसका लक्ष्य भलीभांति तैयार किया जाना चाहिए ताकि मध्यम से दीर्घ अवधि में ऋण की धारणीयता का उल्लंघन न हो। वर्तमान वैश्विक मंदी के संदर्भ में विवेकाधीन नीति के तहत निम्नलिखित विशेषताएं भी होनी चाहिए: i) काफी अधिक क्योंकि मांग में काफी कमी आई है; ii) स्थायी क्योंकि मंदी लंबे समय तक रहने की आशा है; iii) विशाखीकृत क्योंकि विशिष्ट राजकोषीय उपायों कि प्रभावशालिता के बारे में अनिश्चितता है; iv) वास्तविक प्रगति पर निर्भर ताकि यह सूचित किया जा सके कि आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई कि जाएगी; तथा v) मंदी की गंभीरता तथा वैश्विक स्वरूप को देखते हुए देशों के बीच सामूहिक (फ्रीडमैन आदि, 2009)।

तथापि, विवेकाधीन राजकोषीय नीति कई माध्यमों से चलाई जा सकती है। नीति का प्रभाव अथवा राजकोषीय गुणक का परिमाण उन माध्यमों पर, जिनके जरिए उत्प्रेरणा प्रदान की जाती है, मौद्रिक नीति के निभाव की मात्रा तथा अर्थव्यवस्था की संरचना पर निर्भर होगा। गुणक सामान्यतः छोटी और खुली अर्थव्यवस्थाओं में,

तथा उन देशों में जो वित्तीय बाजार के दबावों के प्रति अतिसंवेदनशील हैं, अल्पतर होता है तथा वह मौद्रिक नीति को प्रतिबलित किए जाने के अधीन होता है। दूसरी ओर, यह दीर्घतर होगा यदि पैकेज कि संरचना में संकट की विनिर्दिष्ट विशेषताओं को हिसाब में लिया जाए। विश्वास समाप्त होने के साथ, राजकोषीय गुणक, विशेष तौर पर कर कटौतियों के लिए, बचत की बढ़ी हुई प्रवृत्ति के कारण कमजोर हो सकते हैं। अतः सरकारी खर्च के उपायों से कर कटौतियों अथवा एकमुश्त अंतरणों की तुलना में समस्त मांग पर अधिकतम अल्पावधि प्रभाव पड़ सकता है। यदि कर कटौतियों को लागू किया जाना हो, तो इसे चलनिधि कि कठिनाईयों का सामना करने वालों को लक्ष्य बनाकर लागू किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि गरीब परिवारों को लक्ष्य बनाकर किए गए अंतरणों के गुणक होते हैं, जो एकमुश्त अंतरणों की तुलना में दुगुने होते हैं। इसके अलावा, गरीब परिवारों के उच्चतर हिस्से के कारण एशिया के उभरते देशों तथा अन्य देशों में ये गुणक बड़े होते हैं (फ्रीडमैन आदि, 2009)।

अल्पावधि स्थिरीकरण में राजकोषीय नीति संबंधी उपायों की सफलता में ऋण की दीर्घावधि धारणीयता एक महत्वपूर्ण बात है (देखें इस अध्याय के खंड II.IV में बॉक्स II.25)। जब बाजार प्रतिभागियों की ऋण सम्बद्ध चिंताएं - विशेष रूप से भविष्य के लिए चुकौती संबंधी चुनौतियों के रूप में - अधिक होती है, तो विवेकाधीन राजकोषीय उत्प्रेरणा से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं तथा फलस्वरूप सकल मांग में कमी आ सकती है, जिससे राजकोषीय गुणक संभाव्य रूप से ऋणात्मक तथा इस प्रकार प्रति-उत्पादक हो सकता है। राजकोषीय उत्प्रेरणा की मात्रा तथा ऋण की धारणीयता संबंधी चिंताएं अधिकांशतः आरंभिक राजकोषीय स्थितियों अथवा उपलब्ध राजकोषीय अन्तराल पर निर्भर होती हैं। यह देखा गया है कि चूँकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संबंधी चिंताएं अधिक होती हैं, अतः अतीत में संकट आने पर इन देशों में वृद्धि पर राजकोषीय उत्प्रेरणा का सीमित असर हुआ था (आइएमएफ, 2008)। सीमित राजकोषीय अंतराल के कारण, साक्ष्य यह भी सुझाता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं कम आक्रामक प्रतिचक्र्रीय राजकोषीय नीति का अनुसरण करती हैं। यह भी देखा गया है कि जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि से राजकोषीय अनुशासन की कमी का अवबोध होता है, उस समय राजकोषीय उत्प्रेरणा का प्रभाव अत्यधिक सीमित होता है अथवा वह ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार, राजकोषीय उत्प्रेरणा के साथ इस बात की विश्वसनीय वचनबद्धता होनी चाहिए कि सुधार होने पर एक मध्यावधि राजकोषीय रूपरेखा तैयार कर उसे वापस लिया जाए अथवा उलट दिया जाए। इस संभावना को देखते हुए कि राजकोषीय उत्प्रेरणा का उद्घाटन अपने आप में वसूली की गति मंद कर सकता है, उपयुक्त निकासी की रणनीति बनाने में चुनौतियां हो सकती हैं।

संदर्भ:

1. एलमेंडोर्फ डगलस डब्ल्यू. तथा जैसन फर्मन (2008), 'इफ, व्हेन, हाउ: ए प्राइमर ऑन फिस्कल स्टिमुलस', दि हैमिल्टन प्रोजेक्ट, स्ट्रेटिजी पेपर, जनवरी.
2. फेल्डस्टीन मार्टिन (2002), 'दि रोल फॉर डिस्क्रीशनरी फिस्कल पॉलिसी इन ए लो इन्टरेस्ट रेट एनवायरनमेंट', एनबीईआर वर्किंग पेपर 9203.
3. फ्रीडमैन सी., एम. कुमहोफ, डी. लैक्सटन तथा जे.ली, 'दि केस फॉर ग्लोबल फिस्कल स्टिमुलस', आइएमएफ स्टाफ पोजिशन नोट, मार्च 6, 2009.
4. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) (2008), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सितंबर.
5. टेलर जोन बी. (2000), 'रिअसेसिंग डिस्क्रीशनरी फिस्कल पॉलिसी', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव्स, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, खंड 14(3), 21-36.

बजट के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए संस्थागत सुधार के महत्व को स्वीकार किया है।

II.1.30 पिछले कुछ वर्षों में सुधार के क्षेत्र में कर संरचना की विकृतियों को दूर कर, कम कर दरें लागू करके तथा कराधार बढ़ाकर कर प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता को सुधारने के लिए जोर दिया गया है। सरकार ने 12 अगस्त 2009 को नयी प्रत्यक्ष कर संहिता जारी कर प्रत्यक्ष करों में संरचनागत बदलाव का अनुसरण करने तथा 1 अप्रैल 2010 से माल और सेवा कर (जीएसटी) कारगर तरीके से लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव किया है। कर प्रशासन की क्षमता को सुधारने के लिए इस बात का प्रस्ताव है कि सुसंगत अधिनियमों को संशोधित कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर अग्रिम व्यवस्थाओं के लिए दोनों प्राधिकरणों का विलय किया जाए। केंद्रीय बजट 2009-10 में प्रत्यक्ष कर संबंधी उपायों से राजस्व पर कोई असर न पड़ने तथा अप्रत्यक्ष करों से 2,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है।

II.1.31 प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, कंपनी कर दरों तथा उन पर लगाये जाने वाले अधिभार को अपरिवर्तित रखा गया। प्रत्यक्ष आय कर के क्षेत्र में, छूट की आरंभिक सीमा 15,000 रुपए बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,40,000 रुपए कर दी गयी जबकि महिलाओं तथा अन्य सभी वर्गों के निजी करदाताओं के लिए इसे 10,000 रुपए बढ़ाकर क्रमशः 1,90,000 तथा 1,60,000 रुपए कर दिया गया। अत्यधिक विकलंता वाले आश्रित व्यक्ति के उपचार सहित उसके भरण-पोषण के लिए भुगतान करने वाले व्यक्तियों की मौजूदा 75,000 रुपए की सीमा से धारा 80डी के तहत 25,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी गयी। वैयक्तिक आय कर पर अधिभार हटा लिया गया। निर्यात में आयी मंदी से निपटने के लिए सरकार ने एक और वर्ष अर्थात् 2010-11 के लिए प्रभावहीनता खंडों को बढ़ा दिया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास की आय को आयकर से मुक्त करने तथा इस न्यास को दिए गए लाभांश को लाभांश वितरण कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है। एनपीएस न्यास द्वारा ईक्विटी शेयरों और डेरिवेटिवों की सभी खरीद और बिक्री को भी प्रतिभूति लेनदेन कर से मुक्त किया गया।

II.1.32 अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) लागू करने का अनुपालन कठिन कार्य मान जा रहा था, अतः इसे समाप्त कर दिया गया।

अनुसंधान एवं विकास के लिए कंपनी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु आंतरिक अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय पर 150 प्रतिशत की भारांकित कटौती के वर्तमान प्रावधान की व्याप्ति को एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर विनिर्माण संबंधी सभी व्यवसायों पर लागू करने का प्रस्ताव किया गया। व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि निवेश-संबद्ध कर प्रोत्साहनों को 'कोल्ड चैन' की स्थापना एवं परिचालन, कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदाम की सुविधा तथा सामान्य वाहक सिद्धांत पर वितरण के लिए देश भर में प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने तथा परिचालित करने के व्यवसायों तक बढ़ा दिया जाए। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर बही लाभ के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी। एमएटी के तहत कर जमा सात साल के बजाय दस साल तक आगे ले जाने की अनुमति देने के लिए अवधि विस्तार का भी प्रस्ताव किया गया।

II.1.33 कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के बारे में अप्रत्यक्ष कर को युक्तियुक्त बनाने संबंधी उपाय लागू किए गए। देशी मूल्य योजन को प्रोत्साहित करने के लिए, सेट-टॉप बॉक्सों पर 5 प्रतिशत का सांकेतिक मूल सीमा शुल्क लगाया गया। इसी तरह, एलसीडी पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया ताकि देशी उत्पादन को समर्थन मिल सके। मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए आयातित सहायक पुर्जों, पुर्जों तथा संघटकों को 4 प्रतिशत के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से एक और वर्ष के लिए छूट प्रदान किया गया। मूल्य योजन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, अनगढ़ मूंगों को मूल सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया गया। इन्फ्लुएंजा के टीके तथा स्तन-कैंसर, हेपटाइटिस-बी, सन्धिवातीय गठियां के उपचार के लिए उपयोग में लायी जाने वाली नौ विनिर्दिष्ट जीवनरक्षक दवाओं तथा ऐसी दवाओं के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले अशोधित औषध पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। सोने की छड़ के लिए सीमा शुल्क प्रति 10 ग्राम 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए तथा सोने के अन्य प्ररूपों (आभूषण को छोड़कर) के लिए प्रति 10 ग्राम 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया, तथा चांदी (आभूषण को छोड़कर) पर शुल्क को प्रति किलोग्राम 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन धातुओं की कीमतों में कई गुनी वृद्धि हुई थी।

II.1.34 उत्पाद शुल्क दरों से संबंधित प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: सूती वस्त्र क्षेत्र तथा मानव निर्मित रेशों के क्षेत्र के बीच विभेदक दरें; रेशे की अवस्था के आगे सूती वस्त्र के लिए 4 प्रतिशत की पहले की वैकल्पिक दर को बहाल करना; मानव-निर्मित रेशे पर अधिदेशात्मक आधार पर 8 प्रतिशत की दर तथा रेशे एवं धागे के आगे की अवस्थाओं के लिए उस दर पर वैकल्पिक आधार पर शुल्क बहाल करना; बायो-डीजल मिश्रित पेट्रो-डीजल को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करना; और वातावरण के लिए उपयोगी इस ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए बायो-डीजल पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत अर्थात् पेट्रो-डीजल के समतुल्य करना। निर्माण उद्योग के मामले में, पूर्व-निर्मित कंक्रीट स्लैब अथवा ब्लॉक सहित स्थल पर निर्मित वस्तुओं को पूर्ण छूट प्रदान की गई। पेट्रोल-चालित ट्रकों पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।

II.1.35 माल परिवहन एजेंटों और कमीशन एजेंटों से प्राप्त सेवाओं को, जहां सेवा कर अदा करने का दायित्व मूल रूप से निर्यातक का है, सेवा कर से मुक्त कर दिया गया। निर्यातों द्वारा प्राप्त अन्य सेवाओं के लिए, उक्त छूट का परिचालन मौजूदा वापसी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा जो दस्तावेजों के स्वतः प्रमाणन पर आधारित है, जिसके तहत इस प्रकार की वापसी एफओबी मूल्य के 0.25 प्रतिशत से कम होती है, तथा उक्त सीमा से अधिक वापसी के मूल्य के लिए एक सनदी लेखाकार द्वारा दस्तावेजों का प्रमाणन किया जाना चाहिए। माल परिवहन क्षेत्र में कार्य के लिए सम आधार (लेवल प्लेइंग फील्ड) प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा अथवा तटीय कार्गो द्वारा अथवा आंतरिक जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले सामान पर सेवा कर लागू किया गया। विधि के क्षेत्र में प्रदान की गयी सलाह, परामर्श अथवा तकनीकी सहायता को सेवा कर की परिधि में लाया गया। तथापि, यह कर उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब सेवा प्रदान करने वाला अथवा सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो।

II.1.36 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को 8 प्रतिशत की माध्य दर पर अभिसरित करके राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के उद्देश्य को सुकर बनाने के लिए उत्पाद शुल्क की दर को खाद्य सामग्रियों, ओषधियों, भेषज तथा अन्य वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुओं पर 8 प्रतिशत कर दिया गया। जीएसटी लागू करने के संबंध में, सरकार ने यह संकेत

दिया है कि संविधान में निहित राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप मूल संरचना के संबंध में सहमति है। जीएसटी मॉडल एक द्वैध मॉडल होगा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी शामिल होंगे। केंद्र तथा राज्य में से प्रत्येक क्रमशः केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी के बारे में कानून बनाएगा, कर लगाएगा तथा उसे प्रशासित करेगा।

II.1.37 अभिप्रेत परिणामों पर फोकस करते हुए वृद्धि की गति जारी रखने के लिए सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के बारे में जानबूझकर निर्णय लिया है। सार्वजनिक सेवाओं की कारगर सुपुर्दगी के लिए शासन में सुधार लाने हेतु व्यय प्रबंधन पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। उक्त उद्देश्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं : नियमित आधार पर सरकार के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने तथा कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया तैयार करना, सरकार से काफी दूर रखते हुए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का सृजन कर प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाना जो साथ-साथ इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन कर उसे पब्लिक डोमेन में दर्शाएगा; तथा गैर-रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हुए सभी जानकारी पब्लिक डोमेन पर दर्शाने संबंधी सार्वजनिक आंकड़ा नीति स्थापित करना जिससे नागरिक उन आंकड़ों को चुनौती दे सकें तथा प्रबंधन-सुधार में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकें।

II.1.38 सरकार द्वारा मूलभूत संरचना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, ग्रामीण रोजगार तथा अन्य प्रमुख कार्यक्रमों पर खर्च का आबंटन बढ़ा दिया गया है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मूलभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा शहरी मूलभूत संरचना पर आबंटन में काफी वृद्धि की गयी है। विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशक बनाने के लिए, वर्तमान कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाते हुए सरकार ने कई क्षेत्रों में पहल की है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे सार्वभौमिक तौर पर लागू किया जा सके, केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए समयबद्ध किया जा सके, जिससे 2014-15 तक गरीबी निवारण हो सके। बजट में अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य बनाने का उल्लेख किया गया है तथा इन एसएचजी को बैंकों के साथ संबद्ध करना एक महत्वपूर्ण

उद्देश्य होगा। ग्रामीण महिलाओं को ऋण समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। कमजोर वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्र ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें स्थगन अवधि के दौरान पूरी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी तथा इस योजना से 5 लाख छात्रों को लाभ मिलने का अनुमान है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आबंटन बढ़ा दिया गया है। सरकारी-निजी सहभागिता से रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु नयी परियोजना की परिकल्पना की गयी है ताकि नौकरी चाहने वाले कहीं से भी ऑन-लाइन पंजीकरण कर सकें तथा किसी भी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकें। 2009-10 के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आबंटन काफी बढ़ा दिया गया है। जनसांख्यिकी संबंधी लाभ उठाने की दृष्टि से, 'आइसीटी के माध्यम से शिक्षा का मिशनट योजना के लिए प्रावधान में काफी वृद्धि की गयी है। सरकार ने शामिल न किए गए प्रत्येक राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी आबंटन किया है। सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए, सरकार ने भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

राज्य सरकारें¹

II.1.39 बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) द्वारा निर्धारित राजकोषीय पुनर्विन्यास तथा उसके संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) के रूप में राजकोषीय सुधार और समेकन संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों को 2008-09 के दौरान कुछ झटका लगा। इसका कारण राजकोषीय प्राथमिकता में हुआ वह परिवर्तन था, जो समग्र आर्थिक मंदी के कारण राजस्व में आई गिरावट को देखते हुए राजकोषीय उत्प्रेरणा को समर्थन देने हेतु अतिरिक्त व्यय के निभाव के लिए जरूरी हो गया। घाटे के लक्ष्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले अतिरिक्त व्ययों का निभाव करने के लिए तीन राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और राजस्थान ने अपने एफआरएल में संशोधन करने का प्रस्ताव किया।

II.1.40 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्यों ने आर्थिक पुनर्जीवन के लिए व्यय निदेशित करने के उद्देश्य से कई नीतिगत पहलों की घोषणा की। केरल ने 10,000 करोड़ रुपए के उत्प्रेरणा

पैकज की घोषणा की, जिसका कार्यान्वयन मूलभूत संरचना के विकास के लिए दो साल के भीतर किया जाना था। सुधार के उपाय के रूप में, इसने करेतर राजस्व संग्रहण संबंधी उपायों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष कक्ष तथा जीएसटी के बारे में तैयारी करने के लिए एक और कक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। हरियाणा ने अगले दो वर्षों के भीतर विभिन्न मूलभूत संरचना संबंधी विनिर्दिष्ट परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक आर्थिक उत्प्रेरणा पैकेज शुरू किया जिसमें अस्पतालों के उन्नयन, मलनिकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली, तथा औद्योगिक कामगारों के लिए भवन निर्माण पर बल दिया गया। पीपीपी आधार पर बस स्टैंडों के उन्नयन जैसे अन्य नीतिगत पहल किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत राज्यों (कर्नाटक तथा हरियाणा) द्वारा राशि का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव था। कर्नाटक ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए विलासिता कर, व्यावसायिक कर, मनोरंजन कर सहित विभिन्न करों में तथा कृषि भूमि सहित सभी अचल संपत्तियों पर स्टॉप शुल्क में कटौती करने की घोषणा की। सरकारी कार्यक्रमों पर होनेवाली व्यय की समीक्षा करने तथा कम उत्पादक कार्यक्रमों पर होनेवाले व्यय में कटौती करने के लिए व्यय समीक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।

II.1.41 आंध्र प्रदेश द्वारा कमजोर वर्गों के लिए मकान आबंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव था। बुनकरों की सहकारी समिति तथा अलग-अलग बुनकरों को स्वीकृत ऋण को एक बार बट्टे खाते डालने के अलावा सामाजिक सुरक्षा संबंधी पेंशन की व्याप्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। कर्नाटक, हरियाणा तथा गुजरात द्वारा शिक्षा तथा तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन के लिए आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्यों ने भी परिवहन, पावर और प्रमुख शहरों के विकास सहित विभिन्न मूलभूत संरचना संबंधी क्षेत्रों के लिए उच्चतर आबंटन का प्रस्ताव किया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए कृषि तथा सिंचाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होंगे। कर्नाटक ने 3 प्रतिशत की रियायती दर पर 50 हजार रुपए तक का फसल ऋण किसानों को देने का प्रस्ताव किया है।

II.1.42 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा गठित छठे वित्त आयोग में 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

¹ 27 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित, इनमें से दो लेखा अनुदान पर हैं।

कर दी। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा उड़ीसा सहित कई राज्यों ने छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा हेतु अलग वेतन आयोगों का गठन करने का निर्णय लिया। कर्नाटक तथा केरल उनके द्वारा गठित वेतन आयोगों के आधार पर अपने कर्मचारियों का वेतनमान पहले ही संशोधित कर चुके हैं, जबकि पंजाब सरकार ने पांचवें राज्य वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

II.1.43 रिजर्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन संबंधी समिति ने मार्च 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकारों के स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता का मूल्यांकन किया (बॉक्स II.2)।

बाह्य क्षेत्र की नीतियां

II.1.44 अक्टूबर 2008 से देखी गयी ऋणात्मक वृद्धि के साथ भारत का निर्यात क्षेत्र वैश्विक उत्पादन और व्यापार में आए संक्रमण से सीधे प्रभावित हुआ। इसके जवाब में, निर्यात क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए गए यथा पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदानोत्तर ऋण के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता; ईसीसीसी के लिए सरकार समर्थन गारंटी; निर्यात-आयात बैंक से 5,000 करोड़ रुपए की निर्यात व्यवस्था; तथा बुने गए कपड़ों, साइकल, कृषि हस्त औजार एवं विनिर्दिष्ट श्रेणी के धागे जैसी कतिपय मर्दों पर शुल्क वापसी संबंधी लाभ। निर्यातकों के सामने मौजूद प्रक्रियागत समस्याओं के समाधान तथा विभिन्न अनुमोदनों में तेजी लाने के लिए सचिवों की समिति का भी गठन किया गया है।

II.1.45 चल रहे वैश्विक आर्थिक संकट तथा भारत के व्यापार संबंधी कार्यनिष्पादन पर उसके प्रभाव की पृष्ठभूमि में 26 फरवरी 2009 को भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक अनुपुरक में कई उपाय निहित हैं। अग्रिम प्राधिकारों के प्रति निर्यात दायित्व की अवधि 36 महीनों तक बढ़ा दी गई। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत, यदि किसी उत्पाद (उत्पादों) के निर्यात में हुई गिरावट 5 प्रतिशत से अधिक हो, तो उस उत्पाद (उत्पादों) के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात संबंधित दायित्व अनुपातिक रूप से

कम हो जाता है। 2008-09 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए यह प्रावधान 2009-10 तक बढ़ा दिया गया है। प्रमुख व्यापार गृह के रूप में मान्यता प्राप्त करने की प्रवेश सीमा वर्तमान 10,000 करोड़ रुपए से कम करके 7,500 करोड़ रुपए कर दी गयी। शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना के तहत निर्यात आगमों की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना शुल्क जमा पर्चियां जारी करने की अनुमति दी गयी। 1 अप्रैल 2002 से पहले जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के लिए, मोडवैट/सेनवैट प्रमाणपत्र संबंधी अपेक्षा कुछ मामलों में समाप्त कर दी गयी। डीईपीबी/शुल्क जमा पर्ची का उपयोग प्रतिबंधित मर्दों के आयात हेतु शुल्क की अदायगी के लिए भी किया जाने लगा। डीईपीबी के तहत लागू मूल्य अधिकतम सीमा को दो उत्पादों के लिए ऊपर की ओर संशोधित किया गया। निर्यात बढ़ाने संबंधी क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं में चमड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज: फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) की व्याप्ति में वृद्धि; कारीगरी युक्त मूंगा (कोरल) पर से आयात प्रतिबंधों को हटाना; तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए निर्यात अभिमुख इकाई (ईओयू) में स्थित रत्न एवं आभूषण संबंधी इकाइयों को एक वित्त वर्ष में 10 किलोग्राम तक सोने की व्यक्तिगत टुलाई शामिल हैं।

II.1.46 भीलवाड़ा तथा सूरत को क्रमशः वस्त्र एवं हीरों के निर्यात के लिए उत्कृष्ट शहरों के रूप में मान्यता दी गयी। कई अन्य सुसाध्यकारी उपाय भी किए गए यथा अग्रिम प्राधिकरण एवं ईपीसीजी योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेश अंतरण सुविधा की स्थापना; 4 प्रतिशत राशि पुनः जमा करने की अनुमति देना; विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाइ) के लिए एकल प्रशासनिक प्रलेख (एसएडी); ईओयू के बारे में शुल्क आहरण वापसी तथा सीमांत उत्पादन शुल्क की वापसी एवं ईंधन पर लागू अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।

II.1.47 निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्रीय बजट 2009-10 में चुनिंदा उद्योगों के लिए ब्याज सहायता योजना मार्च 2010 तक बढ़ाने, बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्यात ऋण और गारंटी निगम का कवर बढ़ाने हेतु समायोजन सहायता योजना के लाभ मार्च 2010 तक बढ़ाने, नए बाजारों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए निर्यातकों को समर्थ बनाने हेतु 'बाजार विकास योजना' के लिए आबंटन बढ़ाने तथा सरलीकृत सेवा कर वापसी प्रस्तावों की घोषणा की गयी है।

बॉक्स II.2

राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता

सारणी क : राजकोषीय पारदर्शिता : राज्यों का मूल्यांकन

	ओ	बीओ	पीओ	एनओ
I. भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्पष्टता	6	1	3	-
II. खुली बजट प्रक्रियाएं	4	4	1	-
III. जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता	4	-	7	2
IV. ईमानदारी का आश्वासन	8	1	4	-

ओ-अनुपालित; बीओ - मोटे तौर पर अनुपालित;
पीओ- आंशिक रूप से अनुपालित; एनओ- अनुपालन नहीं किया गया।

स्रोत : वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, मार्च 2009.

तथा लेखा महा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में मेल नहीं खाता। बकाया गारंटियों, बजट-बाह्य उधार, सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप, राजस्व संबंधी बकाया, सब्सिडी, ब्याज दर तथा बेचान किए गए ऋणों के परिपक्वता प्रोफाइल के संबंध में आंकड़ों का प्रसार विशेष तौर पर खराब स्थिति में है। कुछ राज्य सरकार अपने बजट में 'आंतरिक ऋण के उन्मोचन' के बारे में ब्यौरेवार जानकारी प्रदान नहीं करतीं। इसी तरह, लेखा वर्ष के लिए अलग-अलग राजकोषीय आंकड़े कुछ राज्यों के बारे में उपलब्ध नहीं हैं। इस संदर्भ में, सीएफएसए ने यह पाया कि जहां इस प्रकार के अंतरों को पूरी तरह से सुलझाना कठिन होगा, वहीं लेखांकन संबंधी वास्तविक आंकड़े सिद्धांत रूप में अलग-अलग नहीं हो सकते। सीएएसए ने सलाहकार पैनल की इस सिफारिश का समर्थन किया कि सूचित किए गए राजकोषीय आंकड़ों में पायी गयी ऐसी विसंगतियों को सुलझाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किए जाने की जरूरत है। इसने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) गठित करें, रिपोर्ट समय पर सुनिश्चित करें तथा किसी सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए तर्क के साथ अनुपालन प्रस्तुत करें। उक्त रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि सार्वजनिक स्वामित्व वाले निगमों के साथ राज्य सरकारों का संबंध हमेशा समझौता ज्ञापनों द्वारा नियंत्रित नहीं होता। अधिकांश मामलों में, राज्य पीएसयू की हानियों के लिए राजस्व खाते से सब्सिडी देने के बजाय पूंजी खाते से इक्विटी अभिदान के माध्यम से रक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के अपारदर्शी लेनदेनों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर न्यायगत कार्यों के कार्यनिष्पादन के लिए निधियों के अंतरण की सूचना पारदर्शी तरीके से, ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग, दी जानी चाहिए। सीएएसए ने आंकड़ा देनेवाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचित राजकोषीय आंकड़ों में मौजूद विसंगतियों के समाधान की जरूरत पर तथा साथ ही व्यय सूचित करने के लिए बनायी गयी संरचना के पुनर्विन्यास एवं युक्तियुक्तकरण की जरूरत पर बल दिया। संक्षेप में, राज्यों को उनके वित्त के संबंध में पारदर्शिता के स्तरों को सुधारना चाहिए ताकि सार्वजनिक डोमेन में दी गयी जानकारी की विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा बढ़ सके।

संदर्भ

1. चंद, प्रेम (2008), ठराजकोषीय पारदर्शिताड, एन्साइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन एण्ड पब्लिक पॉलिसी, दूसरा संस्करण।
2. कोपिट्स, जी. तथा जे. क्रैग (1998), 'सरकारी परिचालनों में पारदर्शिता', आइएमएफ ऑकेजनल पेपर संख्या 158.
3. भारतीय रिजर्व बैंक (2009), वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, मार्च 2009.

राजकोषीय पारदर्शिता में सरकारी कामकाज के बारे में विश्वसनीय, व्यापक, समय पर, समझने योग्य, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना शामिल है, ताकि मतदाता और वित्तीय बाजार सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उसके कामकाज की सही लागत एवं लाभ का सही एवं आसानी से मूल्यांकन कर सकें (कोपिट्स तथा क्रैग 1998)। राजकोषीय पारदर्शिता से भलीभांति सूचित सार्वजनिक बहस तथा गुरुतर सरकारी जबावदेही एवं विश्वसनीयता को प्रोत्साहन मिलता है। आइएमएफ ने गुरुतर राजकोषीय पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए 'अच्छी प्रथाओं की संहिता' तथा 'राजकोषीय पारदर्शिता संबंधी मैनुअल' प्रकाशित किए, जिन्हें 2007 में अद्यतन किया गया। राजकोषीय पारदर्शिता संबंधी इस व्यापक ढांचे में स्पष्ट भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों, पारदर्शी बजट प्रक्रियाओं, जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता तथा ईमानदारी के आश्वासन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राजकोषीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद, विश्व की लगभग एक तिहाई जनसंख्या को सार्वजनिक निकायों के राजकोषीय परिचालनों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है (चंद, 2008)।

भारत के मामले में, पहली बार 2001 में सलाहकार दल की रिपोर्ट तथा मानकों और कोडों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट (आरओएससी) में तथा 2004 में समीक्षा रिपोर्ट में राजकोषीय पारदर्शिता का मूल्यांकन किया गया। इन मूल्यांकनों में मुख्य रूप में केंद्र सरकार वित्त को शामिल किया गया। सभी राज्यों के स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता का स्पष्ट मूल्यांकन पहली बार मार्च 2009 में जारी की गयी वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन) की रिपोर्ट में किया गया। उक्त रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता सामान्यतः केंद्र सरकार के स्तर पर प्राप्त: मानकों के काफी पीछे है। यद्यपि, किस प्रकार की पारदर्शिता संबंधी मानकों का अनुपालन करने के लिए राज्यों के लिए कोई अधिदेशात्मक अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार की प्रथाएं अपनाते से जनता को विभिन्न नीतिगत निर्णयों के पीछे के तर्क स्पष्ट करने में राज्य सरकारों को मदद मिल सकती है। इसके अलावा, चूँकि कई राज्य अपने उधार संबंधी कार्यक्रम पूरे करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में बाजार में जा रहे हैं, अतः इस प्रकार की पारदर्शिता संबंधी प्रथाओं में वृद्धि करना उनके लिए लाभकारी होगा। सभी राज्यों (पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के अलावा) द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) बनाए जाने से राज्य स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता में कुछ सुधार हुआ है।

राज्य सरकारों द्वारा आइएमएफ कोड का अनुपालन केंद्र सरकार की तुलना में अपेक्षाकृत न्यूनतर पाया गया है, परंतु 45 प्रथाओं में से बड़ी संख्या में 28 प्रथाओं का या तो 'पूरा' अथवा 'मोटे तौर पर' अनुपालन किया गया। 'आंशिक रूप से अनुपालित' प्रथाओं की संख्या 15 थी तथा स्तंभ III (जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता) के बारे में दो प्रथाओं का अनुपालन नहीं किया गया। कुल मिलाकर, अनुपालन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गुरु तर पारदर्शिता के लिए काफी सुधार की जरूरत है (सारणी क)।

राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय पारदर्शिता की स्थिति जानकारी की उपलब्धता के अभाव, उपलब्ध जानकारी में सुसंगति तथा आंकड़ों की रिपोर्टिंग में एकरूपता में दिखाई देती है। इनके अलावा, राज्य बजटों में कतिपय परिवर्तियों को परिभाषित करने की पद्धति में स्पष्टता एवं एकरूपता की कमी है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक,

II.1.48 रिजर्व बैंक ने निर्यात क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अनेक उपाय भी शुरू किए, जिनमें पोतलदान-पूर्व एवं पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के पहले स्लैब की हकदारी की अवधि बढ़ाना; अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) की सुविधा की कुल सीमा बढ़ाना; अतिदेय बिलों पर पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर लागू निर्धारित ब्याज दर का 180 दिनों तक विस्तार करना; विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर बढ़ाना तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्त के रूप में बैंकों को स्थायी चलनिधि सुविधा संबंधी सीमा में वृद्धि करना शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन²

II.1.49 2008-09 के दौरान, वैश्विक आर्थिक संकट के साथ जुड़े बाह्य आघातों की तीव्रता के बावजूद, रिजर्व बैंक बाह्य अदायगी युग को सरल और उदार बनाने के लिए उपाय करता रहा। तथापि, पूंजी खाता उदारीकरण की गति भारत द्वारा अपनाए गए सतर्क, क्रमिक एवं आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप बनी रही। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति द्वारा सुझाए गए चरणबद्ध उदारीकरण उपायों को भी आगे बढ़ा दिया। समष्टि आर्थिक स्थितियों, वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों की स्थिति, वित्तीय संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन क्षमताओं तथा वित्तीय बाजारों की गहराई को हिसाब में लेते हुए पिछले तीन वर्षों में पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने संबंधी विनियमनों को काफी उदार बनाया गया है।

II.1.50 ऋण प्रवाहों के बजाय इक्विटी प्रवाहों के पक्ष में अंतर्वाहों के उदारीकरण के प्रति अधिमान्यताप्राप्त श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, 2008-09 के दौरान इक्विटी मार्ग के तहत अंतर्वाहों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की व्याप्ति को साख सूचना कंपनियों एवं पण्य एक्सचेंजों तक बढ़ाना; तथा विदेशी फर्मों की पहुंच स्थानीय इक्विटी बाजारों तक बढ़ाना शामिल हैं। एफआईआई को उनके निवेशों के आबंटन में लचीलापन प्रदान करने के लिए, एफआईआई के निवेश संविभाग में ऋण के प्रति इक्विटी के अनुपात पर लगाए

गए प्रतिबंध को हटा लिया गया। बाहरी निवेश को उदार बनाने के लिए 2008-09 के दौरान किए गए विशिष्ट उपायों में सेबी के पास पंजीकृत भारतीय कम्पनियों एवं म्यूच्युअल फंडों की निवेश सीमाओं को बढ़ाना; तथा विनिर्माण/शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्र में संलग्न पंजीकृत न्यासों और समितियों को भारत के बाहर संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में उसी क्षेत्र (उन्हीं क्षेत्रों) में निवेश के लिए अनुमति देना शामिल हैं।

II.1.51 ईसीबी नीति को, जिसे मौजूदा समष्टि आर्थिक स्थितियों को देखते हुए 2007 में सख्त किया गया था, पूंजीगत अंतर्वाहों में आयी मंदी, देशी पूंजी बाजार में संसाधन कम होने तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऋण स्प्रेडों पर दबाव बने रहने के कारण 2008-09 में शिथिल किया गया। इस दिशा में किए गए उपायों में सेवा क्षेत्रों अर्थात् होटल, अस्पताल एवं सॉफ्टवेयर कंपनियों को ईसीबी की व्याप्ति बढ़ाना; अनन्य रूप से मूलभूत संरचना संबंधी वित्तपोषण में शामिल एनबीएफसी को ईसीबी तक पहुंच की अनुमति देना; ईसीबी तक पहुंच के प्रयोजन के लिए मूलभूत संरचना संबंधी परिभाषा को व्यापक बनाकर उसमें देश के खनन, अनुसंधान एवं तेल-शोधन क्षेत्र को शामिल करना; मूलभूत संरचना क्षेत्र के लिए ईसीबी की सीमाएं बढ़ाना, अनुमति-योग्य अंतिम उपयोग के लिए रुपया संबंधी खर्च पर से प्रतिबंध हटाना; तथा ईसीबी के लिए समस्त लागत वाली ब्याज दर की अधिकतम सीमाओं को हटाना शामिल हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय तौर पर आस्ति मूल्यों में आयी कमी को हिसाब में लेते हुए कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं स्वचालित दोनों मार्गों के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा एफसीसीबी की पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान की गयी।

II.1.52 पूंजीगत प्रवाहों को प्रभावित करने वाले वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता के प्रतिसाद में देशी बाजार में विदेशी मुद्रा संबंधी चलनिधि में सुधार लाने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए। इन उपायों में ये शामिल हैं - एफसीएनआर(बी) तथा एनआर(ई)आरए जमाराशियों एवं विदेशी बैंकों के साथ की गयी ऋण व्यवस्थाओं पर ब्याज दर की अधिकतम सीमाओं में वृद्धि करना; भारतीय बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं तथा सम्पर्की

² वित्तीय क्षेत्र संबंधी नीतियों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा रिपोर्ट के अध्याय V (वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन) तथा अध्याय VI (वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण) में प्रस्तुत की गयी है।

बैंकों से निधियां उधार लेने की अनुमति देना; तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) और आवास वित्त कं पनियों (एचएफसी) को अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार राशियां जुटाने की अनुमति प्रदान करना।

II.1.53 समकालिक वैश्विक मंदी के कारण निर्यातों में आयी मंदी को देखते हुए, माल या साफ्टवेयर निर्यातों से प्राप्त राशियों की वसूली तथा भारत को उनका प्रत्यावर्तन की अवधि एक साल के बाद की जाने वाली समीक्षा के अधीन निर्यात की तारीख से छः माह से बढ़ाकर बारह माह कर दी गयी। इसी तरह, आयातकों को राहत देने के उपाय के तौर पर उनके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात बिलों/दस्तावेजों की प्रत्यक्ष प्राप्ति की सीमा गैर-स्थितिधारक निर्यातकों द्वारा अनगढ़ हीरों, अनगढ़ मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थरों के आयात के मामले में 100,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 300,000 अमरीकी डालर कर दी गयी ताकि उनकी लेनदेन की लागत कम की जा सके। तदनुसार, श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को उन मामलों में आयातों के लिए अर्थप्रेषण की अनुमति दी गयी, जहां आयात बिल/दस्तावेज विदेशी आपूर्तिकर्ता से आयातक को सीधे प्राप्त हुए हों तथा आयात बिल का मूल्य कतिपय शतों के अधीन 300,000 अमरीकी डालर से अधिक न हो।

मौद्रिक नीति संबंधी उपाय³

II.1.54 मुद्रास्फीति, वृद्धि और वित्तीय बाजारों संबंधी तेजी से बदलती स्थितियों के कारण 2008-09 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन में उल्लेखनीय चुनौतियां सामने आयीं। 2008-09 के दौरान मौद्रिक नीति में दो स्पष्ट दौर दिखायी दिए। अप्रैल-सितम्बर 2008 के पहले दौर में मुद्रास्फीति की बढ़ रही प्रत्याशाओं के प्रतिसाद में मौद्रिक सख्ती की अवधि देखी गयी। सितम्बर 2008 के मध्य से आरम्भ दूसरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के प्रतिसाद में मौद्रिक नीति में नरमी तथा मुद्रास्फीतिकारी दबावों में उल्लेखनीय कमी की अवधि देखी गयी।

II.1.55 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह नोट किया गया कि 2007-08 के लिए आरंभिक मूल्यांकन संबंधी वैश्विक एवं देशी दोनों गतिविधियों में उल्लेखनीय बदलाव आया था तथा वैश्विक मंदी के खतरे वक्तव्य की घोषणा के समय बढ़ गए थे। इस पृष्ठभूमि में, 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति बनाए रखते हुए मुद्रास्फीतिकारी दबाव एवं वैश्विक अनिश्चितताओं को कम करने संबंधी व्यापक नीतिगत चुनौतियों पर बल दिया गया।

II.1.56 तथापि, सितम्बर 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट की तीव्रता ने वित्तीय स्थिरता को परिरक्षित करने तथा वृद्धि को उत्प्रेरित करने पर दिए जाने वाले विशेष बल के महत्व को बढ़ा दिया। मध्यावधि समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया कि जहां विवेकपूर्ण विनियमात्मक निगरानी एवं कारगर पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि भारत का वित्तीय क्षेत्र स्थिर बना रहे तथा उसमें सुदृढ़ता जारी रहे, वहीं वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के कारण वित्तीय स्थिरता के परिरक्षण पर विशेष बल देना जरूरी हो जाता है। तदनुसार, मौद्रिक नीति के सामने इस बात की चुनौती थी कि परम्परागत और अपरम्परागत दोनों साधनों का उपयोग करते हुए वित्तीय स्थिरता के परिरक्षण, मूल्य स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं पर लगाम लगाने, तथा वृद्धि की गति बनाए रखने के बीच इष्टतम संतुलन रखा जाए।

II.1.57 वैश्विक आर्थिक संभावना में आयी और गिरावट तथा वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के बारे में और अधिक अनिश्चितता के संदर्भ में मौद्रिक नीति 2008-09 की तीसरी तिमाही की समीक्षा की गयी। भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें 2008-09 की पहली छमाही में उच्च मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि में चक्रीय मंदी का अनुभव किया गया था, वैश्विक गिरावट के फलस्वरूप और अधिक मंदी के स्पष्ट साक्ष्य देखे गए। वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरीके से प्रभावित किया; पूंजी प्रवाहों में गिरावट आयी; पूंजी बाजार का मूल्यन कम बना रहा; औद्योगिक उत्पादन संबंधी वृद्धि में कमी आयी; निर्यात वृद्धि ऋणात्मक हो गयी; तथा समग्र कारोबारी रुख में गिरावट आयी। सकारात्मक पक्ष यह था कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आयी,

³ मौद्रिक प्रबंधन के बारे में ब्यौरेवार चर्चा रिपोर्ट के अध्याय III (मौद्रिक नीति संबंधी परिचालन) में प्रस्तुत की गयी है।

हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई कमी नहीं देखी गयी। देशी वित्तीय बाजार भी अधिक अस्थिरता की छोटे दौर को छोड़कर सामान्य तौर पर कार्य करते रहे। यद्यपि, बैंक ऋण वृद्धि पिछले साल की तुलना में उच्चतर थी, अप्रैल 2008 तथा जनवरी 2009 के बीच वाणिज्य क्षेत्र को समग्र वित्तीय संसाधन प्रवाह में पिछले साल की तुलना में थोड़ी गिरावट आयी। ऐसा निधीयन के अन्य स्रोतों यथा पूंजी बाजार एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में आयी गिरावट के कारण हुआ। वैश्विक परिदृश्य तथा देशी अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन, विशेष रूप से वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना, के आधार पर रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि के समग्र लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए अच्छी चलनिधि के प्रावधान संबंधी मौद्रिक नीति के अपने रुख को बनाए रखा। रिजर्व बैंक ने वृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली वैश्विक एवं देशी स्थिति द्वारा अपेक्षित सभी संभव उपायों के साथ त्वरित एवं कारगर रूप से रेस्पांड करने के अपने संकल्प को व्यक्त किया। साथ ही इसने मूल्यस्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजारों की व्यवस्थित स्थितियों के अनुरूप मौद्रिक एवं ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की।

II.1.58 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह देखा गया कि रिजर्व बैंक द्वारा पहले से नीति दरों में की गयी कमी के भीतर समग्र ब्याज दर संरचना में गिरावट आने की गुंजाइश है। समष्टि आर्थिक स्थिति के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, मौद्रिक नीति के रुख में ऐसा नीतिगत युग सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया गया जिससे ऋण की गुणवत्ता परिरक्षित करने के साथ अर्थक्षम दरों पर ऋण विस्तार में मदद मिलेगी ताकि अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के मार्ग पर वापस ले जाने को समर्थन मिले।

II.1.59 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद उन कई तात्कालिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, जिनका समाधान जरूरी है। ये चुनौतियां इस प्रकार हैं : अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के मार्ग पर वापस ले जाने के लिए सकल मांग के वाहकों को समर्थन देना; सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बहाल करना; व्यवस्थित रूप में एक समय के भीतर राजकोषीय उत्प्रेरणा का उद्घाटन तथा विश्वसनीय राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापसी; व्यवस्थित रूप में बड़ी मात्रा में किए गए चलनिधि के अंतर्वेश को वापस लेना ताकि

ऊर्ध्वमुखी मुद्रास्फीतिकारी दबावों एवं आस्ति मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को टाला जा सके; तथा अंततः निवेश संबंधी मांग के पुनर्जीवन को समर्थन देने वाले ब्याज दर माहौल को सुनिश्चित करने संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना। 2009-10 की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही की समीक्षा में इस बात को दुहराया गया कि सुधार के निश्चित एवं सुदृढ़ संकेत मिलने तक रिजर्व बैंक निभाव संबंधी मौद्रिक रुख को बनाए रखेगा। यह स्वीकार करते हुए कि रिजर्व बैंक को कुछ समय में विस्तारकारी उपायों को बदलना होगा ताकि वृद्धि की गति को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर लगाम लगाया जा सके एवं मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम किया जा सके, उक्त समीक्षा में इस बात का उल्लेख किया गया कि 'निर्गम की नीति को विकसित हो रही समष्टि आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा'।

II.1.60 तिमाही नीतिगत वक्तव्य में घोषित समग्र नीतिगत रुख को दर्शाते हुए, रिजर्व बैंक ने 2008-09 की पहली छमाही में मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि के प्रतिसाद में मौद्रिक शक्ति से अपने नीतिगत रुख में बदलाव लाते हुए, मुद्रास्फीतिकारी दबावों में आयी नरमी तथा संकट द्वारा वृद्धि में आयी कमी के प्रतिसाद में मौद्रिक नरमी का रुख अपनाया। नीति में बदलते रुख को सितम्बर 2004 से अगस्त 2008 तक निभाव क्रमिक रूप से वापस लिए जाने की पिछली अवधि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसके दौरान रिपो/रिवर्स रिपो दरों में 300/150 आधार अंकों की वृद्धि की गयी थी, वाणिज्य बैंकों के लिए नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 450 आधार अंकों की वृद्धि की गयी थी, मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाओं तथा जोखिम भार को विशिष्ट क्षेत्रों के मामले में बढ़ाया गया था। 2008-09 की दूसरी छमाही में, अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों को प्रतिबिंबित करते हुए, रिजर्व बैंक ने सितम्बर-मार्च 2008-09 के दौरान सीआरआर में 400 आधार अंकों की कमी की। उसी अवधि के दौरान, रिपो दर में 400 आधार अंकों की तथा रिवर्स रिपो दर में 250 आधार अंकों की कमी की गयी। 21 अप्रैल 2009 को रिपो तथा रिवर्स रिपो दरों में 25 आधार अंकों की और कमी करके उन्हें क्रमशः 4.75 प्रतिशत तथा 3.25 प्रतिशत किया गया। 2008-09 के दौरान वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के उद्देश्यों को संतुलित करते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति

संबंधी उपायों के साथ समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों का उपयोग रिजर्व बैंक के नीतिगत दृष्टिकोण की एक अद्वितीय विशेषता बनी रही।

ऋण की सुपुर्दगी⁴

II.1.61 ऐसी अवधि में, जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को ऋण में अत्यधिक अवरोध का सामना करना पड़ा, भारत में आर्थिक मंदी के कारण ऋण की मांग में आयी गिरावट के बावजूद ऋण बाजार सामान्य तरीके से कार्य करता रहा। रिजर्व बैंक ऋण सुपुर्दगी संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार पर बल देता रहा तथा अर्थव्यवस्थाओं के उन क्षेत्रों को ऋण का प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने विभिन्न उपाय किए, जो समकालिक वैश्विक मंदी के कारण अपेक्षाकृत रूप से अत्यधिक प्रभावित थे तथा जो रोजगार-उन्मुख क्षेत्र थे। वित्तीय समावेशन, ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श के क्षेत्रों में भी व्यापक पहल किए गए। इनमें ऐसी ग्रामीण सहकारिताओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करना जो प्रमुख तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करते हैं; आरआरबी की शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाना; स्वयं सहायता दलों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) जैसे उधार के बहुल माध्यमों को प्रोत्साहित करना तथा बैंकिंग सुसाध्यकर्ता/ बैंकिंग सम्पर्की (बीसी) मॉडल को अपनाना; कृषि तथा व्यष्टि, लघु और मझौले (एमएसएमई) क्षेत्रों को उधार देने के लिए क्रियाविधियों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा व्याप्ति बढ़ाने एवं लेनदेन की लागत घटाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संबंधी समाधानों को अपनाना शामिल हैं।

वित्तीय क्षेत्र संबंधी नीतियां⁵

II.1.62 अभूतपूर्व वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए भारतीय वित्तीय क्षेत्र की आघात सहनीयता ने काफी सीमा तक रिजर्व बैंक की विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक नीतियों की सुदृढ़ता तथा आर्थिक वृद्धि एवं विकास को समर्थन देने के लिए वित्तीय सुधार के प्रति देश के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। 2008-09 के दौरान रिजर्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक पहलों में

ग्राहक सेवा सुधारने के लिए विवेकपूर्ण विनियमनों एवं उपायों में बदलाव, वित्तीय समावेशन में संवर्धन तथा बैंकिंग क्षेत्र में धनशोधन निवारण को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं। विवेकपूर्ण विनियमन, जिन्हें जोखिम भारों के प्रतिचक्रीय उपयोग एवं गतिशील प्रावधानीकरण के जरिए आर्थिक उछाल के दौर में पहले बढ़ा दिया गया था, को शिथिल किया गया ताकि आर्थिक मंदी के दौरान ऋण वृद्धि में तेज गिरावट को रोकने के लिए समर्थक स्थितियां बनायी जा सकें। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप देश-विशिष्ट जरूरतें पूरी करने; सीमा पार पर्यवेक्षण के रूप में पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने; वित्तीय संगुटों, बैंक की अगुवाई वाले संगुटों का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण; तथा बैंक के ऋण संविभागों पर निगरानी रखने के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए भी पहल किए गए।

II.1.63 रिजर्व बैंक ने विज्ञान दस्तावेज के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों को (यूसीबी) सुदृढ़ करने के लिए 2008-09 में उपाय करना जारी रखा। वर्ष के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसिंग मानदंडों का उदारीकरण; अधिमान शेयर तथा दीर्घावधि जमाराशियां जारी करने की अनुमति; वित्तीय पुनर्विन्यास; तथा आर्थिक मंदी द्वारा उत्पन्न तनाव का समाधान करने के लिए गतिशील प्रावधानीकरण और आस्तियों का पुनर्विन्यास शामिल हैं। सुदृढ़ यूसीबी के साथ विलय के माध्यम से इस क्षेत्र के समेकन की प्रक्रिया को जमाकर्ताओं को अदायगी, अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय अंशदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा बलिदान सहित ऐसे विलय के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित कर और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

II.1.64 रिजर्व बैंक ने, अप्रैल 2007 से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे से प्राप्त अनुभव की समीक्षा के आधार पर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा बढ़ा दी तथा अक्टूबर 2008 में जारी प्रकटीकरण के विनिर्दिष्ट मानदंडों सहित चलनिधि प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। तथापि, विश्व स्तर पर आस्ति

⁴ ऋण सुपुर्दगी से संबंधित नीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श रिपोर्ट के अध्याय IV (ऋण सुपुर्दगी) में दिया गया है।

⁵ वित्तीय क्षेत्र नीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श रिपोर्ट के अध्याय V (वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन) तथा अध्याय VI (वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण) में दिया गया है।

मूल्यों में तेज अधोमुखी करेक्शन के अनुरूप साल की दूसरी छमाही में बाज़ार में आयी मंदी के कारण इक्विटी पूंजी जुटाने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, इन एनबीएफसी के लिए 31 मार्च 2009 तक 12 प्रतिशत और 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत सीआरएआर के कार्यान्वयन को क्रमशः एक साल के लिए स्थगित कर दिया। कारोबारी और विनियामक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए निधियों तक पर्याप्त पहुंच की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को शाश्वत ऋण लिखतें जारी करने की अनुमति दी गई। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में चलनिधि और एएलएम के बीच बेमेल पन की समस्याएं दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन एक अस्थायी उपाय के रूप में अनुमोदन मार्ग के तहत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार जुटाने की अनुमति एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को दी तथा विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जरिए पात्र एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को चलनिधि समर्थन भी प्रदान किया।

वित्तीय बाज़ारों के लिए नीतियां

II.1.65 व्यापार, पूंजी प्रवाह और विश्वास सरणियों के जरिए परिचालित वैश्विक संकट के संक्रमण से भारत के वित्तीय बाज़ारों, विशेषतः विदेशी मुद्रा बाज़ारों, पूंजी बाज़ार एवं मुद्रा बाज़ार, में दबाव आया और अस्थिरता बढ़ गई। रिज़र्व बैंक द्वारा समय पर किए गए उपायों से अल्पावधि में मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाज़ारों व्यवस्थित स्थितियां बहाल हो गईं। इससे महत्वपूर्ण यह है कि सभी बाज़ारों में साल भर सामान्य कामकाज हुआ। बाज़ारों में हुए तनाव के स्तरों के समाधान हेतु विशिष्ट उपाय करने के अलावा, गंभीर और प्रतिस्पर्धी बाज़ार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए।

II.1.66 2008-09 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की गतिविधि सुधारने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं: (i) अस्थिर दर वाले बांड (एफआरबी) जारी करने के लिए नई निर्गम संरचना; (ii) स्ट्रिप्स शुरू करने की परिचालनात्मक तैयारी; (iii) रिपो लेखांकन दिशा-निर्देशों का संशोधन; (iv) ओटीसी डेरिवेटिवों का समाशोधन और निपटान; तथा (v) गैर-चालू खातेदारों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में नई निपटान प्रक्रिया।

II.1.67 2008-09 के दौरान, पूंजी बाज़ार के विनियामक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) बाज़ार का और विकास करने के लिए उपाय करती रही। वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में भी विशिष्ट उपाय किए गए ताकि भारतीय पूंजी बाज़ार को सुदृढ़ किया जा सके, बाज़ार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और निवेशकों के हित की रक्षा की जा सके।

II.1.68 सेबी ने 21 अप्रैल 2008 से प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने (एसएलबी) की शुरुआत की। बाज़ार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के अनुसरण में, राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (एनएसई) तथा बम्बई शेयर बाज़ार (बीएसई), सेबी ने एसएलबी संबंधी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए हैं, यथा एसएलबी की अवधि वर्तमान 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना, एसएलबी के सत्र का समय वर्तमान एक घंटे (10 बजे प्रातः से 11 बजे प्रातः तक) से बढ़ाकर सामान्य ट्रेडिंग समय अर्थात् 9.55 बजे से 3.30 बजे तक करना तथा शेयर बाज़ारों को सामान्य जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का अनुसरण करने की सलाह देना।

II.1.69 बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा मार्जिन पूंजी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए, सेबी ने दिसम्बर 2008 में क्रॉस-मार्जिनिंग की वर्तमान सुविधा को संशोधित कर इसे सभी श्रेणियों के बाज़ार प्रतिभागियों पर नकदी एवं डेरिवेटिव खण्डों में लागू कर दिया। जिस सीमा तक नकदी और डेरिवेटिव दोनों खण्डों में ग्राहकों की स्थिति एक-दूसरे को प्रतिबलित करती है, उस पर क्रॉस-मार्जिनिंग के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

II.1.70 6 अगस्त 2008 से बैंकों सहित भारतीय संस्थाओं के लिए मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की अनुमति दी गयी। डेरिवेटिव शुरू करने के प्राप्तता मानदण्डों को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से, सेबी ने अक्टूबर 2008 में शेयर बाज़ारों को सूचित किया कि वे निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले शेयरों पर डेरिवेटिव शुरू करें, चाहे उनको सूचीबद्ध करने की तारीख और/अथवा निर्गम का आकार कुछ भी हो।

II.1.71 सेबी ने आरबीआइ-सेबी की स्थायी तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार एक्सचेंज में ट्रेडिंग वाले करेंसी डेरिवेटिवों के लिए ग्राहक तथा ट्रेडिंग सदस्य के लिए लागू स्थिति सीमा को संशोधित किया। ये स्थिति सीमाएं विशिष्ट रूप से एक एक्सचेंज के लिए होंगी, न की पूरे एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव बाज़ार

के लिए। 17 जून 2009 को रिजर्व बैंक और सेबी ने संयुक्त रूप से मानदंड निर्धारित किए जिनके माध्यम से एक्सचेंज - ट्रेडेट ब्याज दर फ्यूचर्स की अनुमति दी गई।

II.1.72 कंपनी ऋण में एफआइआइ निवेश के लिए संचयी ऋण निवेश सीमा 6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 15 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गयी। इसे देखते हुए बाजार प्रतिभागियों को खुले बिडिंग प्लेटफॉर्म में 8 बिलियन अमरीकी डालर का आबंटन किया गया है। इन सीमाओं के लिए सारी बोलियां शेयर बाजारों के माध्यम से लगायी जाएंगी तथा बोली लगाने के लिए दो घंटों तक खिड़की खुली रहेगी। वर्तमान ट्रेडिंग सदस्यों की पहुंच बोली लगाने के प्लेटफॉर्म तक होगी। एफआइआइ अथवा उप-खातों को वर्तमान ट्रेडिंग सदस्यों के माध्यम से आना होगा, जो बदले में सीमाओं के लिए बोली लगाएंगे।

II.1.73 एफआइआइ-उप-खातों द्वारा सहभागिता पत्र/अपतटीय डेरिवेटिव लिखत (ओडीआइ) जारी करने पर 2007 में अक्टूबर 2008 में लगाए गए कतिपय प्रतिबंधों की समीक्षा करने पर, सेबी ने अंतर्निहित प्रलेख के रूप में डेरिवेटिव सहित प्रतिभूतियों की जमानत पर एफआइआइ द्वारा सहभागिता पत्र जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) ने यह निर्णय लिया कि विदेशी निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत निजी इक्विटी निधियों में आ सकता है, इस प्रकार न्यास के रूप में पंजीकृत जोखिम पूंजी निधियों तथा निजी इक्विटी खिलाड़ियों के लिए निधियों का एक और मार्ग खुल जाएगा। विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों के रूप में सेबी में पंजीकरण चाहने वाले आवेदकों को पहले तो आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने निवेशकों से पक्की प्रतिपुष्टि के तौर पर 1 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान लेना होगा। जुलाई 2009 में एफआइआइ और एनआरआइ को कतिपय शर्तों के तहत भारतीय डिपाजिटरी रिसीट में निवेश की अनुमति दी गई।

II.1.74 सेबी ने अधिकार निर्गम के लिए समय में कटौती; अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) की परिभाषा तथा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) की पात्रता एवं मूल्य-निर्धारण मानदंडों के संबंध में सेबी (डीआइपी) दिशानिर्देश, 2000 को संशोधित किया। पूंजी बाजार में संस्थागत खरीदारों की

सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, क्यूआइबी को वारंट सहित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के संयुक्त प्रस्ताव में तथा सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी अलग-अलग लिखतों में अभिदान करने की अनुमति दी गयी। सेबी (डीआइपी) दिशानिर्देश तथा सूचीबद्धता करार में संशोधन के साथ, अधिकार निर्गम की कालावधि कम कर दी गयी, जिसका अभिप्राय यह था कि निवेशकों के लिए धन के तीव्रतर टर्नअराउंड के अलावा निर्गमकर्ता द्वारा सामना की जा रही बाजार जोखिम में कमी आई।

II.1.75 अत्यधिक प्रौद्योगिकी-चालित प्रतिभूति बाजार में सिस्टम लेखा-परीक्षा के महत्व पर विचार करते हुए, जुलाई 2008 में सभी बाजारों को सूचित किया गया कि वे वार्षिक आधार पर किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के द्वारा अपने सिस्टम और प्रोसेस की व्यापक लेखा-परीक्षा कराएं। कुछ कंपनियों में कारपोरेट अभिशासन संबंधी चिंताओं को देखते हुए निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, सेबी ने 2008-09 के लिए तथा 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध फर्मों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समकक्ष समीक्षा शुरू करने के लिए लेखा-परीक्षक फर्मों का एक पैनेल बनाया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंडों के साथ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना के लेखांकन मानकों को संरेखित करने के लिए सेबी के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

II.1.76 एक सूचीबद्ध कंपनी में शेयरधारिता के पैटर्न संबंधी प्रकटीकरण बढ़ाने तथा सूचीबद्ध कंपनी के अभिशासन में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, सेबी ने अप्रैल 2009 में इक्विटी सूचीबद्धता करार के कुछ खंडों को संशोधित किया। इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ दावा न किए गए शेयरों के निपटान के लिए एकरूप प्रक्रिया का प्रावधान करना; सूचना अवधि को कम करना; सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा 'प्रति शेयर' आधार पर लाभांश घोषित किए जाने में एकरूपता; तथा प्रत्येक वर्ग के शेयरों एवं मताधिकार पैटर्न के लिए शेयरधारिता पैटर्न का प्रकटीकरण।

II.1.77 म्युचुअल फंडों द्वारा प्रकटीकरण में एकरूपता लाने के लिए, भारतीय म्युचुअल फंड संघ (एएमएफआइ) के परामर्श से सेबी ने जुलाई 2008 में संक्षिप्त स्कीम-वार वार्षिक रिपोर्ट का नया फार्मेट निर्धारित किया। बंद छोर वाली स्कीमों के लिए ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए, 12 दिसंबर 2008 को अथवा उसके

बाद शुरू की गई बंद छोर वाली सभी स्कीमों (इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों को छोड़कर) को अधिदेशात्मक तौर पर सूचीबद्ध कराया जाना था तथा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना कर उसे दैनिक आधार पर प्रकाशित किया जाना था।

II.1.78 बाजार में गुरुतर पारदर्शिता लाने के लिए, सेबी ने निर्णय लिया कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा उधार दी गई प्रतिभूतियों और विदेश स्थित उनके उप-खातों को सप्ताह में दो बार अर्थात् हर सप्ताह मंगलवार एवं शुक्रवार को समेकित आधार पर प्रचारित किया जाएगा।

विधायी उपाय

II.1.79 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, जिसे 20 दिसंबर 2007 को अधिसूचित किया गया और यह 12 अगस्त 2008 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने दो विनियमावलियाँ तैयार की अर्थात् भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन के पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008 तथा भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण विनियमावली, 2008। इस अधिनियम में बैंकों से इतर संस्थाओं यथा सीसीआईएल, कार्ड कंपनी, अन्य भुगतान प्रणाली प्रदाता तथा भुगतान के लिए सभी भावी संस्थाओं सहित देश में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक को प्राधिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। निवल राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा निपटान अंतिमता, जो पहले संविदात्मक करार(करारों) द्वारा नियंत्रित थी, को अधिनियम के तहत विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। जो संस्थाएं भुगतान प्रणाली परिचालित करते रहना चाहती हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे प्राधिकार के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन प्रस्तुत करें। इस

अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक को प्राप्त अन्य अधिकारों में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए परिचालनात्मक और तकनीकी मानक निर्धारित करना; सेवा प्रदान करने वालों से जानकारी और विवरणी तथा प्रलेख मंगाना तथा ऐसा करने में चूक होने पर यह गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर दंड लगाना शामिल हैं। रिजर्व बैंक को सिस्टम प्रदाताओं को निदेश एवं दिशानिर्देश जारी करने, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य निर्धारित करने तथा उनकी प्रणालियों-परिसरों का लेखा-परीक्षा और निरीक्षण करने का भी अधिकार है। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना, जिसमें भुगतान प्रणाली शुरू करने/जारी रखने के प्राधिकार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप और तरीका तथा प्राधिकार प्रमाणपत्र की स्वीकृति शामिल है; (ख) भुगतान अनुदेश तथा मानकों का निर्धारण; (ग) विवरणी, प्रलेख तथा अन्य जानकारी प्रस्तुत करना; तथा (घ) लेखा एवं तुलनपत्र प्रस्तुत करना।

II.1.80 2008-09 के दौरान सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समष्टि आर्थिक नीतियां गतिशील रूप से बदलते वैश्विक वातावरण तथा देशी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के अनुरूप बदलती रहीं। विकसित हो रही गतिविधियों के प्रतिसाद में तैयार की गयी नीतियों का उद्देश्य यह था की साल की पहली छमाही के दौरान वैश्विक पण्य एवं ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के देशी मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव से और दूसरी छमाही में वैश्विक वित्तीय संकट के आर्थिक वृद्धि पर अप्रत्यक्ष प्रभाव से अर्थव्यवस्था को कुशन प्रदान किया जाए। तथापि, नीति में गैर मुद्रास्फीतिकारी उच्च वृद्धि पर फोकस करना जारी रहा जो समावेशक हो तथा उदारीकृत नीतिगत वातावरण में संसाधनों के दक्ष उपयोग पर आधारित हो।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था के समकालिक मंदी के चरण में प्रवेश करते ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में स्पष्ट रूप से मंदी का अनुभव किया, जो वैश्विक संकट के बढ़ते संक्रमण के साथ-साथ चक्रीय वृद्धि के आवेगों में मंदी को प्रकट करता है। 2003-08 के दौरान प्राप्त औसतन 8.8 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि की तुलना में 2008-09 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाती है, तथापि यदि विश्व के प्रमुख देशों के वृद्धि निष्पादन को देखें तो भारत उच्चतम वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी, चिंता की बात यह है कि 2008-09 की चार क्रमिक तिमाहियों में उद्योग और सेवाओं में वृद्धि में गिरावट आई है।

II.2.2 मुख्य रूप से उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्रों में वृद्धि में आयी मंदी के कारण 2008-09 के दौरान सकल देशी उत्पाद की

वृद्धि में कमी आई। औद्योगिक वृद्धि में कमी का एक बड़ा कारण कुछ चक्रीय मंदी और देशी तथा बाह्य मांग में गिरावट था। सेवा क्षेत्र ने हाल ही में भारत के सुदृढ़ वृद्धि निष्पादन को गति प्रदान की थी, लेकिन इसमें भी कुछ मंदी देखी गई जो देशी और विदेशी दोनों ही स्तरों पर मांग में कमजोरी को प्रकट करता है। सेवा के व्यापक उप-क्षेत्रों जैसे, व्यापार, परिवहन, होटल, पर्यटन, वित्त और निर्माण, में वैश्विक मंदी के कारण वृद्धि कम रही। हालांकि, 'सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं' नामक उप-क्षेत्र ने कुछ समर्थन दिया क्योंकि मुख्यतः छोटे वेतन आयोग के अधिनिर्णय के प्रभाव से इसकी वृद्धि में तेजी आई। 2008-09 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि में भी मंदी आई। जहां तक सकल देशी उत्पाद के क्षेत्र-वार संयोजन की बात है, 2008-09 में जहां भारत के कुल जीडीपी में कृषि और उद्योग के हिस्से में मामूली गिरावट दर्ज की गई, वहीं सेवाओं के हिस्से में तदनु रूप बढ़ोतरी हुई (सारणी 2.1)।

सारणी 2.1: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें
(1999-2000 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2000-01 से	2005-06 से	2006-07	2007-08*	2008-09#	2008-09			
	2008-09 (औसत)	2007-08 (औसत)				ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2.8	4.9	4.0	4.9	1.6	3.0	2.7	-0.8	2.7
1.1 कृषि	3.0	5.0	4.1	5.0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2. उद्योग	6.5	8.7	10.7	7.4	2.6	5.1	4.8	1.6	-0.5
2.1 खनन और उत्खनन	5.0	5.7	8.8	3.3	3.6	4.6	3.7	4.9	1.6
2.2 विनिर्माण	7.1	9.7	11.8	8.2	2.4	5.5	5.1	0.9	-1.4
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	4.5	5.2	5.3	5.3	3.4	2.7	3.8	3.5	3.6
3. सेवाएं	9.0	11.1	11.3	10.8	9.4	10.0	9.8	9.5	8.4
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार	10.6	12.4	13.4	12.4	9.0	13.0	12.1	5.9	6.3
3.2 वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं	8.7	12.3	13.8	11.7	7.8	6.9	6.4	8.3	9.5
3.3 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.4	6.5	5.7	6.8	13.1	8.2	9.0	22.5	12.5
3.4 निर्माण	10.2	12.7	11.8	10.1	7.2	8.4	9.6	4.2	6.8
4 उपादान लागत पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद	7.2	9.4	9.7	9.0	6.7	7.8	7.7	5.8	5.8
			(100)	(100)	(100)				

* : त्वरित अनुमान. # : संशोधित अनुमान. उ.न.: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े वास्तविक सकल देशी उत्पाद प्रतिशत अंश के द्योतक हैं।

2. ति1 : पहली तिमाही (अप्रैल-जून), ति2 : दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर), ति3 : तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर), और ति4 : चौथी तिमाही।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

11.2.3 वृद्धि में नरमी के बावजूद, भारत विश्व की तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा, जो इसके अंतर्निहित वृद्धि संवेगों और सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों की शक्ति को प्रकट करता है। वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान, और वैश्विक स्तर पर उदीयमान बाजारों के संकट की पिछली घटनाओं के दौरान, भारत की वृद्धि के अनुभवों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उत्पाद में किसी प्रकार की स्थायी हानि का अभाव है (बॉक्स 11.3)।

11.2.4 भारत में वृद्धि की प्रक्रिया की एक और स्पष्ट विशिष्टता यह है कि वृद्धि के पथ में समग्र परिवर्तन के बावजूद उत्पाद में उतार-चढ़ाव को आकार देने में चक्रीय कारकों की स्पष्ट भूमिका रही है, जो संरचनागत सुधारों और वैश्वीकरण के प्रभावों को दिखाती है। चक्रीय कारकों की भूमिका के बारे में सामने आ रहे प्रमाणों से संकेत मिलता है कि विश्वव्यापी संकट नहीं होता तो भी भारत की वृद्धि में कुछ कमी हुई होती, यद्यपि वैश्विक संकट के

कारण वास्तव में दिखाई दे रही कमी की तुलना में इसकी प्रवणता काफी कम रहती (बॉक्स 11.4)।

सकल आपूर्ति

कृषि

11.2.5 भारतीय कृषि का निष्पादन काफी बड़ी सीमा तक मानसून और इसके स्थानिक तथा कालिक वितरण पर निर्भर है। इसके अलावा इस पर सरकार की कीमत समर्थन नीति, कृषि में निवेश, सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसी अन्य निविष्टियों और जोखिमों से बचाव के लिए बाजार की गतिविधियों जैसे अन्य कारकों का भी असर पड़ता है। भारत में खाद्य-भंडारों का प्रबंधन और उत्पादन, व्यापार तथा कीमतों की दृष्टि से विश्व कृषि बाजार की गतिविधियां भी देशी बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतों के निर्धारण में उनके प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण हैं।

बॉक्स 11.3

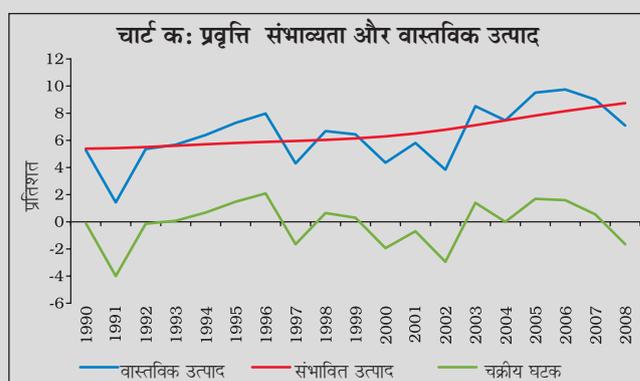
स्थायी और अल्पकालिक उत्पाद हानि

संकटकाल में, एक अर्थव्यवस्था संकट के स्वरूप और उसकी गंभीरता के आधार पर स्थायी या अल्पकालिक उत्पादन हानि का सामना कर सकती है। आर्थिक-साहित्य के अनुसार, उत्पादन में स्थायी हानि उस समय स्पष्ट होती है जब अर्थव्यवस्था के संभावित उत्पादन में गिरावट हुई हो। वैश्विक संकट के संदर्भ में, यह दीर्घावधि में कमजोर कारोबारी विश्वास द्वारा चालित गिरती हुई सकल मांग के कारण या फिर निवेश में गंभीर संकुचन के कारण हो सकता है। अर्थमितीय दृष्टि से यह दिखाया जा सकता है कि प्रवृत्ति में स्थिरता का गुण दिखाने वाली किसी भी उत्पाद वृद्धि श्रृंखला में स्थायी उत्पाद हानि दिखाने की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्पाद वृद्धि में आए हुए विचलन माध्य को बदल सकते हैं।

आर्थिक संकट और अन्य प्रतिकूल झटके, चाहे बाह्य हों या देशी, उत्पाद पर केवल एक अस्थायी या अल्पकालिक प्रभाव डालते हैं और भविष्यगत सुदृढ़ वृद्धि इस प्रारंभिक गिरावट को प्रतितुलित करने से भी ज्यादा कर सकती है। सुधारात्मक नीतियां बहुधा आर्थिक बहाली को गति प्रदान करती हैं जो वृद्धि के पथ को मूल प्रवृत्ति की रेखा से ऊपर ले जा सकती हैं, खासकर तब जब कि संकट से प्रेरित नीतिगत उपायों से अदक्षता में कमी और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके।

विभेदक स्थायी (डीएस) प्रक्रिया के साथ-साथ प्रवृत्तिपरक स्थायी (टीएस) प्रक्रिया की अप्रभावी मूलकल्पना के तहत इकाई मूल परीक्षण सांख्यिकी [विर्धित डिकी फुलर (एडीएफ)] के वितरण प्राप्त करने के लिए रि-सैपलिंग तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्राप्त भारतीय आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत की जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्ति स्थिरतापूर्ण है, जिसका आशय यह हुआ कि इस प्रवृत्ति के आस-पास उत्पाद में होने वाले विचलन अस्थायी ही रहेंगे और इनमें मूल प्रवृत्ति की ओर लौटने

का रुझान रहेगा। इसके अलावा हॉडरिक-प्रेसकॉट फिल्टरों का प्रयोग करते हुए संभाव्य उत्पाद की जो प्रवृत्तियां तैयार की गई हैं, उनसे प्रकट होता है कि 1990 के दशक से ही किसी भी आर्थिक संकट की घटना के दौरान भारत के संभाव्य उत्पाद में स्थायी गिरावट, देशी स्तर पर अथवा बाह्य स्तर पर, कभी नहीं हुई (चार्ट-क)। हालांकि, संभाव्य उत्पाद निवेश की दरों में उछाल तथा सुधार से संबद्ध उत्पादकता संबंधी लाभों के कारण हाल के वर्षों में बढ़ गयी है, जो कि 2003-08 के दौरान औसतन 8.8 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है।



संदर्भ :

1. कैम्पबेल, जे और मेन्किव, एन.जी.1987. "आर आउटपुट फ्लक्चुएशन्स ट्रांजिटरी?" *क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स*, 102:857

बॉक्स II.4

भारत में वृद्धि चक्र : चक्रीय मंदी के नवीनतम प्रमाण

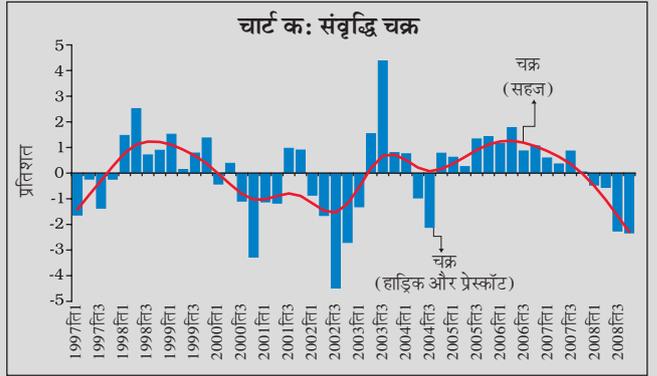
21 अप्रैल 2009 को वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया था कि 2003-08 के दौरान उच्च औसत वृद्धि दर्ज करने के बाद, 2008-09 में भारत चक्रीय गिरावट की ओर उन्मुख हुआ। भारत की वृद्धि में गिरावट की तीव्रता को बढ़ाने में चक्रीय गिरावट के साथ वैश्विक संकट भी आ मिला।

सुधार से बाद की अवधि में व्यवसाय चक्र के प्रतिरूप में आए बदलावों का विश्लेषण करने के लिए वृद्धि के अनुभव को तीन व्यापक अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, अर्थात् 1992-93 से 1996-97; 1997-98 से 2002-03; और 2003-04 से 2008-09 तक। सुधार-पश्चात की तत्काल अवस्था में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की औसत वृद्धि दर बढ़कर 1992-93 से 1996-97 के दौरान 6.2 प्रतिशत हो गई (1996-97 में यह 7.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी)। 1997-98 में एशियाई संकट, अमरीका में 11 सितंबर 2001 की गतिविधियों के साथ-साथ 2000-01 से 2001-02 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी विभिन्न प्रतिकूल बाह्य गतिविधियों; 1999-2000 में कारगिल युद्ध और 2002-03 में मानसून की विफलता जैसी देशी गतिविधियों के कारण दूसरी अवस्था में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में औसत 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विगत पांच वर्ष और 1980 के दशक की औसत वृद्धि दोनों ही से कम होने पर भी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता की दृष्टि से उल्लेखनीय माना गया। अर्थव्यवस्था ऋणात्मक वृद्धि के वर्ग में नहीं गई, जैसा कि 1965-66 और 1979-80 के दौरान भयंकर सूखे और 1970 के दशक के आरंभ में तेल के कारण हुए आघातों जैसी प्रतिकूल गतिविधियों के कारण अतीत में हुआ था। तथापि, सुधार-पश्चात की इन दोनों अवस्थाओं में अर्थव्यवस्था के वृद्धि संबंधी निष्पादन से अर्थव्यवस्था की क्षमता या संभाव्यता में थोड़ा सुधार दिखाई दिया, हालांकि सुधार उपायों का पिटाया खोल दिया गया था। औसत आधार पर 1990 के दशक में (1990-91 को छोड़कर) वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि 1980 के दशक में दर्ज 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर से थोड़ी अधिक रही।

तीसरी प्रमुख चक्रीय अवस्था (2003-04 से 2007-08) के दौरान वृद्धि रेखापथ 8.8 प्रतिशत के वार्षिक औसत के साथ उच्चतर स्तर पर रहा। यह वृद्धि योजना युग के प्रथम तीन दशकों के दौरान तथाकथित 'हिंदू वृद्धि दर' से लगभग 5 प्रतिशत अंक अधिक थी, यह दर 1980 के दशक की मांग-प्रेरित वृद्धि दर से 3 प्रतिशत अंक अधिक थी, और सुधार-पश्चात 1990 के दशक से 2.5 प्रतिशत अंक अधिक थी। यह ऐसी अवस्था थी जब भारत की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन

बचत, निवेश दरों, सकल देशी उत्पाद की संरचना, संरचनात्मक सुधारों तथा वैश्वीकरण के साथ मजबूत समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के रूप में किए गए। समूचे चक्र के स्तर में स्पष्ट ऊर्ध्वमागी परिवर्तन रहा और सर्वोच्च स्तर (जो ओवरहीटिंग को प्रकट करता है) 10 प्रतिशत के अंक पर पहुंच गया।

तिमाही वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि की दृष्टि से, एशियाई संकट के बाद 1990 के दशक के अंतिम वर्षों के बाद से अर्थव्यवस्था ने तीन या चार वृद्धि चक्र देखे; एशियाई संकट में सुधार के अनुरूप 1997(ति.1) से 2000 (ति.4) के बीच लगभग 15 तिमाहियों का मध्यावधि चक्र; 2000(ति.4) से 2002 (ति.3) के बीच दो छोटे चक्र, जो कि विश्वव्यापी मंदी और खराब मानसून के रहे; और फिर 2002 (ति.4) से 2004 (ति.3) तक; और इसके बाद 2004(ति.4) से लेकर 2008(ति.3) के बीच चार से पांच वर्ष का अपेक्षाकृत बड़ा चक्र, जो अर्थव्यवस्था में उछाल का दौर रहा। इस चक्र के दौरान 2004(ति.4) से शुरू होकर अगली 8 से 9 तिमाहियों में वृद्धि दर ने बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई और 2006 की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में यह 10 प्रतिशत के आसपास शिखर पर रही। इसके बाद अंतर्निहित वृद्धि की गति में 2008-09 (ति.4) तक कुछ नरमी दिखाई दी। इस प्रकार 2008-09 की शुरुआत तक चक्रीय नरमी पहले ही शुरू हो चुकी थी (चार्ट क)। 2008 की चौथी तिमाही में वृद्धि फिसल कर 5.8 प्रतिशत पर आ गई, जो कि वैश्विक संकट और देशी चक्रीय आवेग के मिश्रित असर को दिखाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्विक मंदी की गैर मौजूदगी में भी भारत की उच्च वृद्धि अवस्था को चक्रीय गिरावट का सामना करना पड़ता, अलबत्ता इसका पैमाना और परिमाण थोड़ा कम रहता।



II.2.6 2003-08 की प्रवृत्ति के ऊपर तीव्र वृद्धि दर्ज करने के बाद कृषि क्षेत्र में 2008-09 के दौरान मुख्यतः उच्च आधार प्रभाव के कारण स्पष्ट मंदी दिखाई दी। तथापि, 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों का समस्त उत्पादन 233.9 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 मिलियन टन अधिक है (सारणी 2.2)।

II.2.7 2008-09 के लिए अनुमानित उच्चतर समग्र खाद्यान्न पैदावार के बावजूद, खरीफ मौसम में अनाज की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम रही, जिसका कारण 2008 के खरीफ मौसम के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे कुछ राज्यों में बाढ़ से फसल का खराब होना था। 2008-09 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2007-08 की तुलना में थोड़ा-

सारणी 2.2: कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09#
1	2	3	4	5
क. खाद्यान्न	208.6	217.3	230.8	233.9
i. चावल	91.8	93.4	96.7	99.2
ii. गेहूँ	69.4	75.8	78.6	80.6
iii. मोटे अनाज	34.1	33.9	40.8	39.5
iv. दालें	13.4	14.2	14.8	14.7
ख. खाद्यान्नेतर				
i. तिलहन++	28.0	24.3	29.8	28.2
ii. गन्ना	281.2	355.5	348.2	271.3
iii. कपास@	18.5	22.6	25.9	23.2
iv. जूट और मेस्ता+	10.8	11.3	11.2	10.4
v. चाय*	946.0	981.8	944.7	980.8
vi. कॉफी*	274.0	280.0	262.0	277.0

: 21 जुलाई 2009 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान

++ : कुल ग्यारह में से 9 तिलहनों के लिए।

+ : मिलियन गांठें प्रत्येक 180 किलोग्राम की।

@ : मिलियन गांठें प्रत्येक 170 किलोग्राम की।

* : मिलियन किलोग्राम और चाय के लिए कैलेंडर वर्ष के आधार पर आंकड़े।

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

सा कम रहने का अनुमान है, लेकिन 2006-07 की तुलना में यह काफी अधिक रहेगा (सारणी 2.3)। तथापि, रबी की पैदावार विगत वर्ष में दर्ज पैदावार से अधिक रही और इसने खरीफ पैदावार में हुई हानि की भरपाई कर दी। कुल मिलाकर, चावल और गेहूँ की

कुल पैदावार बढ़ी, जबकि मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों की पैदावार में कुछ गिरावट रही तथा गन्ने और कपास की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में काफी गिरावट रही। कृषि के सम्बद्ध क्षेत्रों में 2008-09 के दौरान मजबूत वृद्धि बने रहने की आशा है।

मानसून का मिजाज

II.2.8 2008 (1 जून से 30 सितंबर) के दौरान दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का निष्पादन संतोषजनक रहा तथा संचयी वर्षा सामान्य से 2 प्रतिशत अंक कम रही। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून केरल में सामान्य तारीख से एक दिन पहले अर्थात् 31 मई को ही पहुंच गया। सारे देश में 10 जुलाई तक, सामान्य अनुसूची से लगभग 5 दिन पहले, मानसून छा गया। हालांकि, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की प्रगति असमान रही, तथा जुलाई और अगस्त 2008 के बुवाई के महीनों में ज्यादातर सप्ताह में वर्षा कम हुई। वर्षा का कालिक वितरण यह दर्शाता है कि जून में जलवृष्टि सामान्य से अधिक रही, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान सामान्य से कम रही (चार्ट II.1)। इसके बावजूद, वर्षा का स्थानिक वितरण संतोषजनक रहा, तथा अधिकांश मौसम विज्ञान उपखंडों में अत्यधिक/सामान्य⁶ वर्षा दर्ज की गई और केवल कुछ उपखंडों में कम/छिटपुट/अनावृष्टि दर्ज की गयी (चार्ट II.2)।

सारणी 2.3: मौसम के अनुसार कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	खरीफ			रबी		
	2006-07	2007-08	2008-09 AE	2006-07	2007-08	2008-09 अ.अ.
1	2	3	4	5	6	7
चावल	80.2	82.7	84.6	13.2	14.0	14.6
गेहूँ	-	-	-	75.8	78.6	80.6
मोटे अनाज	25.6	31.9	28.3	8.3	8.9	11.1
दालें	4.8	6.4	4.8	9.4	8.4	9.9
कुल खाद्यान्न	110.6	121.0	117.7	106.7	109.8	116.2
तिलहन	14.0	20.7	17.9	10.3	9.0	10.3
गन्ना	355.5	348.2	271.3	-	-	-
कपास*	22.6	25.9	23.2	-	-	-
जूट और मेस्ता**	11.3	11.2	10.4	-	-	-

- : लागू नहीं।

अ.अ.: 21 जुलाई 2009 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान।

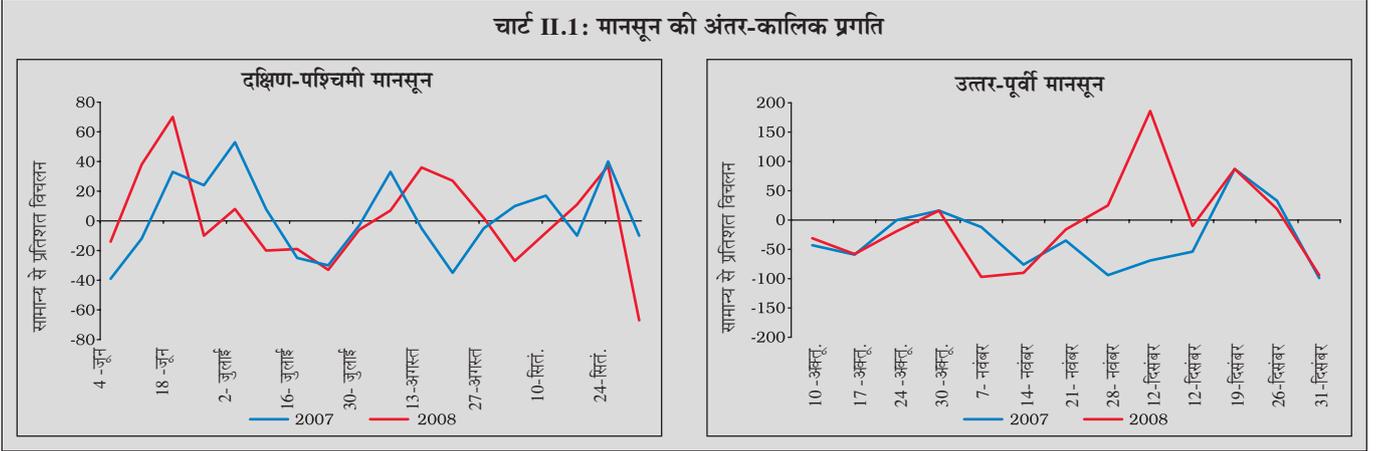
* : 170 कि.ग्रा. वजन वाली मिलियन गांठें।

** : 180 कि.ग्रा. वजन वाली मिलियन गांठें।

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

⁶ अधिक: + 20 प्रतिशत या अधिक; सामान्य: +19 प्रतिशत से -19 प्रतिशत; कम: -20 प्रतिशत से - 59 प्रतिशत; छिटपुट: -60 प्रतिशत से -99 प्रतिशत वर्षा नहीं; -100 प्रतिशत (सभी तुलनाएँ दीर्घ अवधि औसत के संबंध में)

चार्ट II.1: मानसून की अंतर-कालिक प्रगति



II.2.9 चार व्यापक समस्तरीय क्षेत्रों के बीच देखें तो दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की मौसमी वर्षा पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य से अधिक रही, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा हुई। वर्षा के असमान कालिक वितरण से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की अवधि के अंत (अक्टूबर 2008) में देश के प्रमुख जलाशयों में जल-भंडारण पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) का 74 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष (79 प्रतिशत) की तुलना में कम है लेकिन विगत 10 वर्षों के औसत (66 प्रतिशत) से अधिक है।

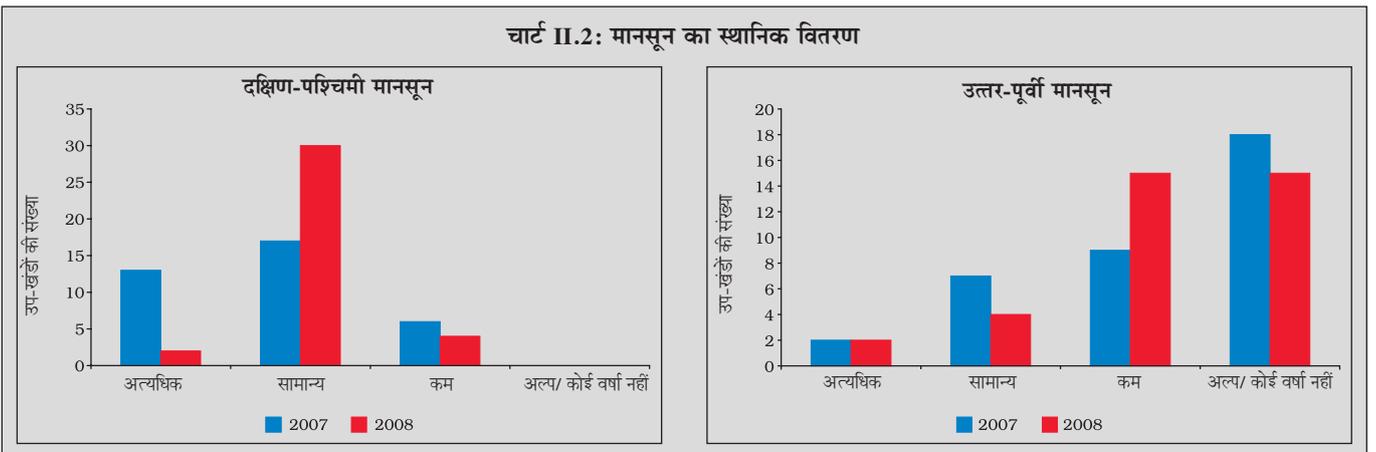
II.2.10 15 अक्टूबर 2008 को प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वोत्तरीय मानसून (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2008 तक) की बरसात शुरू हो गई। सामान्य से 31 प्रतिशत कम वर्षा, जो कि लगभग पिछले वर्ष में दर्ज वर्षा जितनी ही है, के साथ पूर्वोत्तर मानसून की संचयी

स्थिति कम रही। केवल कुछ उपखंडों में संचयी वर्षा अत्यधिक/सामान्य रही जबकि अधिकांश में कम/छिट-पुट/ अनावृष्टि दर्ज की गई।

2008-09 में (अब तक) दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति

II.2.11 भारतीय मौसम विभाग द्वारा अगस्त 2009 में जारी किए गए नवीनतम मानसून संबंधी पूर्वानुमानों में इस बात की संभावना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम 2009 के दौरान समस्त देश में वर्षा सामान्य से कम रहेगी, अर्थात् एलपीए का 87 प्रतिशत, जिसमें +/- 4 प्रतिशत की मॉडल चूक हो सकती है। 2009-10 में अब तक (12 अगस्त तक) दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के दौरान संचयी वर्षा संतोषजनक से कम रही है तथा पूरे देश में वर्षा सामान्य से 29 प्रतिशत कम रही, जबकि पिछले साल की तदनु रूप अवधि में यह सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक थी।

चार्ट II.2: मानसून का स्थानिक वितरण



खाद्यान्न उत्पादन संबंधी भारित वर्षा सूचकांक⁷ 12 अगस्त 2009 को 64 था जबकि पिछले साल की तदनु रूप अवधि में यह 114 था। 18 अगस्त 2009 की स्थिति के अनुसार 10 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने आंशिक या पूर्ण सूखे की घोषणा की है।

कृषि-मूल्य नीति

11.2.12 भारत में कृषि मूल्य नीति का मूल उद्देश्य यह रहा है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की खास तौर पर रक्षा करते हुए अर्थव्यवस्था की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संतुलित और समन्वित मूल्य संरचना तैयार की जाए। किसानों के हितों के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार 24 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में पद्धतिपरक मुद्दों का परीक्षण करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: प्रो. वाइ.के.अलग) की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा की गई गणनाओं के लिए तीन और परिवर्तियों को शामिल किये जाने को अनुमोदित किया है। फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने और किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार ने 2008-09 मौसम की रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को और बढ़ा दिया है (बॉक्स 11.5)।

कृषि में निवेश

11.2.13 समस्त सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में कृषि में किया गया निवेश हाल के वर्षों में स्थिर रहा। हालांकि, कृषि में सकल देशी उत्पाद के संबंध में इस क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में लगातार सुधार आ रहा है तथा वह 2003-04 के 11.1 प्रतिशत से सुधरते हुए 2007-08 में 14.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.4)। ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की जरूरत है ताकि कृषि के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

11.2.14 भारत में निजी क्षेत्र ने कृषीय अनुसंधान में निवेश करने की अगुआई की है और बीटी कपास और चावल, मक्का तथा सूरजमुखी की अन्य संकर किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय कृषि को धारणीय वृद्धि के उच्चतर स्तर तक उठाने के लिए अत्यावश्यक संरचनागत परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए निवेशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जरूरत है। इसके बावजूद, निवेशों की संरचना और इनके द्वारा सृजित सुविधाओं की गुणवत्ता और इन सुविधाओं के प्रबंधन की दक्षता का भी कृषीय निष्पादन और ग्रामीण आय की वृद्धि में महत्वपूर्ण अंशदान होगा।

सम्बद्ध क्षेत्र

11.2.15 हाल के वर्षों में बढ़ती आय, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने कृषि के विशाखीकरण के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। किसानों को कृषि उपज की सामान्यतया अस्थिर कीमतों से बचाने के लिए कृषि क्षेत्र में फसल विशाखीकरण को अधिकतर जोखिम प्रबंधन की रणनीति के रूप में देखा जाता है। कृषि को अधिकाधिक लाभजनक बागवानी फसलों की ओर अधिक विशाखीकृत करने के साथ-साथ पशुधन, बायो-टेक, खाद्य-प्रसंस्करण और अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों ने विगत कुछ वर्षों में उच्चतर कृषीय वृद्धि में योगदान किया है। बागवानी, पशुधन और मछलीपालन जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि 2008-09 के दौरान 5 से 6 प्रतिशत के दायरे में मजबूत बनी रहने की आशा है।

11.2.16 बागवानी बड़ी संख्या में कृषि-आधारित उद्योगों को चलाते रहने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, जिनसे रोजगार के काफी अवसर पैदा हो सकते हैं। यद्यपि खेतों के एकड़ की दृष्टि से बागवानी क्षेत्र का रकबा केवल 10 प्रतिशत है, तो भी यह कृषि से होने वाले सकल देशी उत्पाद में लगभग 28 प्रतिशत का योगदान देता है। 2002-08 के दौरान बागवानी उत्पादन में औसतन 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई। 2007-08 के दौरान भारत में 207 मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ। चीन के बाद भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

⁷ खाद्यान्न उत्पादन भारित सूचकांक (पीआरएन) राज्यों द्वारा प्राप्त वास्तविक वर्षा के भारित औसत के आधार पर निकाला जाता है, जहां भारांकों को समग्र खाद्यान्न में विशिष्ट राज्य के खाद्यान्न उत्पादन के औसत हिस्से के रूप में लिया जाता है। 100 का पीआरएन सामान्य वर्षा का सूचक है, जहां सामान्य पिछले 10 वर्षों की भारित वर्षा के औसत का सूचक है।

बॉक्स II.5

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना को औचित्यपूर्ण बनाना

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की वाजिब कीमतें मिल सकें। सभी प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य फसल बुवाई से पहले ही घोषित कर दिए जाते हैं, जो कि फसल का रकबा निर्धारित करने में किसानों के निर्णय को प्रभावित करता है। सामान्यतया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं वे उत्पादन की लागत से ज्यादा होते हैं, जो खानानों के बाजार-भाव के लिए एक आधार प्रदान करता है। मूल्य समर्थन नीति नई तकनीक अपनाने, खासकर सिंचित क्षेत्रों में, और उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने में सफल रही है। वर्ष 1965 के बाद 15 साल से भी कम समय में गेहूं की पैदावार तीन गुनी हुई जबकि चावल की पैदावार 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी, जिससे देश ने कमी की स्थिति पर काबू पा लिया। आपूर्ति स्थिति के सहज होने के साथ ही पैदावार बढ़ाने की जगह पैदावार पैटर्न को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाने लगा, जो कि अर्थव्यवस्था की समग्र जरूरतों के अनुरूप संसाधनों के संतुलित आबंटन पर आधारित हो। इसके बाद, 1985 से विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पाद की संपूर्ण लागत को गणना में शामिल कर लेने पर जोर दिया जाने लगा। भारत की खाद्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के प्रतिसाद में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों को आवधिक रूप से बढ़ाया है ताकि बढ़ती हुई निविष्टि लागतों के कारण खेती की बढ़ती लागत को पूरा किया जा सके (सारणी -क)।

कृषि मंत्रालय द्वारा 7 मई 2003 को एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: प्रो. वाइ.के. अलग) का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में नीति के बदलते परिवेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने से सम्बद्ध पद्धतिपरक मुद्दों का परीक्षण करना। समिति ने 31 मई 2005 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में कृषि पण्यों की लागत और कीमतों, व्यापार और टैरिफ नीति, बाजार सुधार, अधिभ्रयकर्ता एजेंसियों के पुनर्गठन और ग्रामीण ऋण उपायों को सुदृढ़ करने जैसे लागत से इतर और मूल्य से इतर उपायों के विभिन्न पहलुओं पर कुछ टिप्पणियां शामिल हैं। इसकी कुछ सिफारिशों का अनुसरण करते हुए आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट समिति (15 जनवरी 2009) ने सीएसीपी को यह अनुमोदन प्रदान किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालने के लिए गणना करते समय तीन और परिवर्ती शामिल किए

सारणी क: गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रु. प्रति क्विंटल)

फसल वर्ष	गेहूं		धान-सामान्य@	
	न्यूनतम समर्थन मूल्य	% परिवर्तन	न्यूनतम समर्थन मूल्य	% परिवर्तन
1	2	37	4	5
1990-91	225	4.7	205	10.8
1995-96	380	5.6	360	5.9
2000-01	610	5.2	510	4.1
2004-05	640	1.6	560	1.8
2005-06	650 *	1.6	570	1.8
2006-07	750 #	15.4	580 **	1.8
2007-08	1,000	33.3	645 #	11.2
2008-09	1,080	8.0	850 ##	31.8

@ : 1977-98 से धान की दो किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत घोषित की जाती है - सामान्य और ग्रेड 'ए',

इससे पहले धान के तीन वर्ग हुआ करते थे - सामान्य, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम।

* : न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 50 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस शामिल है।

: न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 100 रु. का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।

** : पहली अक्टूबर 2006 से 31 मार्च 2007 के बीच अधिक्रय पर 40/- रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस।

: एमएसपी के उपर क्विंटल 50 रुपये का बोनस देय है।

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 के दौरान रबी की अन्य फसलों के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है - जौ - रु. 680 प्रति क्विंटल (रु. 35 की बढ़ोतरी); चना - रु. 1730 प्रति क्विंटल (रु. 130 की बढ़ोतरी); मसूर - रु. 1870/- प्रति क्विंटल (रु. 170 की बढ़ोतरी); और रेपसीड/सरसों रु. 1830 प्रति क्विंटल (रु. 30 की बढ़ोतरी)।

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

जाएं। ये तीन मर्दे इस प्रकार हैं : लागत की मद के रूप में किसानों द्वारा फसल बीमा के लिए वस्तुतः दिया गया प्रीमियम, विपणन, और परिवहन पर किसान द्वारा किया गया खर्च। आशा है कि इस कदम से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना औचित्यपूर्ण बनेगी।

II.2.17 भारत के कृषि निर्यातों में बागवानी का हिस्सा 35 प्रतिशत है तथा इसने 2004-08 के दौरान 22 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की और इसमें कृषीय वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। उपज बढ़ाने और आधारभूत संरचना में सुधार, बागवानी फसलों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना के बाद इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। आगे चलकर, इस क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों का निवारण करने की जरूरत है, जिनमें फसल-कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करने

के लिए पर्याप्त भौतिक मूलभूत संरचना का प्रावधान भी शामिल है।

II.2.18 पशुधन क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए अनुपूरक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, साथ ही, यह देश के लाखों लोगों को पोषक आहार भी देता है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाले देशों में भारत भी एक है। पशुधन क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में 5 प्रतिशत से अधिक है और कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से प्राप्त जीडीपी में एक चौथाई से अधिक

**सारणी 2.4: कृषि में सकल पूंजी निर्माण
(1999-2000 की कीमतों पर)**

वर्ष	कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में निवेश (करोड़ रुपये)			सकल निवेश में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा (प्रतिशत)		सकल पूंजी सृजन/ कृषि संबंधी सकल देशी उत्पाद (स्थिर कीमतों पर प्रतिशत)	कृषि में निवेश (स्थिर कीमतों पर सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)
	कुल	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-00	50,151	8,670	41,481	17.3	82.7	11.2	2.8
2003-04	53,542	10,805	42,737	20.2	79.8	11.1	2.4
2004-05	57,849	13,019	44,830	22.5	77.5	12.0	2.4
2005-06	66,065	15,947	50,118	24.1	75.9	12.9	2.5
2006-07	73,285	18,755	54,530	25.6	74.4	13.8	2.6
2007-08	79,328	22,107	57,221	27.9	72.1	14.2	2.5

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए कुल 6-7 प्रतिशत वार्षिक की सकल वृद्धि की परिकल्पना की गई है। दूध के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, 1950-51 में यहां दूध का उत्पादन 17 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2007-08 तक लगभग 105 मिलियन टन हो गया।

11.2.19 मत्स्य-पालन और जल-जीव पालन का समग्र जीडीपी में लगभग 1.1 प्रतिशत योगदान है, और कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों से होने वाले जीडीपी में इसका योगदान लगभग 5.3 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 14 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2007-08 में इस क्षेत्र से होने वाले वार्षिक निर्यात का मूल्य 7,620 करोड़ रुपये था, और ग्यारहवीं योजना के अंत तक यह बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। 2008-09 के दौरान, इस क्षेत्र में 6.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जो समग्र वृद्धि में कुछ मददगार होगा।

11.2.20 विश्व में खाद्य वस्तुओं के उत्पादकों में भारत दूसरे स्थान पर है। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आकार पांचवें स्थान पर है और जीडीपी में इसका योगदान 9.0 प्रतिशत से ज्यादा है तथा यह देश के निर्यात में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले क्षेत्र के रूप में भी उभरा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपने कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, और यह प्रति वर्ष 13.5 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रहा है तथा भविष्य में कृषिय वृद्धि के लिए यह संभाव्य चालक बना रहेगा।

11.2.21 बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती के सरकारी अनुमोदन के साथ 2002 में भारत ने बायोटेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश किया।

इसके बाद से देश के सभी बायोटेक्नॉलॉजी उद्योगों में कृषि-बायोटेक्नॉलॉजी सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड बना हुआ है। इसके अलावा, कृषि नवोन्मेषों की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें जलीय कृषि (हाइड्रोफोनिक्स) - अर्थात् मिट्टी का उपयोग किए बिना पौधे उगाने - की आयातित तकनीक शामिल है, जिसका प्रयोग गुजरात में विभिन्न किस्म की विदेशी संकर चाय, गुलाब और स्ट्रॉबेरी की खेती में हो रहा है। ट्रांसजेनिक चालव और जेनेटिक रूप से तैयार की गई कई सब्जियों के उत्पादन पर शोध कार्य चल रहा है। भारत काजू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में से है, और इसीलिए एथनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त खाद्य फसलों के विकल्प के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के सहयोग से काजू-फल का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

वैश्विक संकट के बीच भारतीय कृषि

11.2.22 वैश्विक वित्तीय संकट के गहराते जाने के साथ ही यह प्रतीत हुआ कि इसने मांग का रास्ता पकड़कर विश्व की कृषि को प्रभावित किया है, जिससे उपभोग और व्यापार दोनों पर खासी मार पड़ी है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें 2007 से 2008 के मध्य तक उच्च स्तरों पर रहने के बाद, आर्थिक मंदी और इसके परिणामस्वरूप कृषि पण्यों, खाद्यान्न चारे और ईंधन की मांग में कमी के कारण कमजोर पड़ गईं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि की अवनत संभावनाओं से भी कृषि उत्पादों में निवेश और उत्पादकता पर दूसरे दौर का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह वित्तीय संकट

पूँजी की उपलब्धता में ऐसे समय में गिरावट ला सकता है, जब कृषि में तीव्र निवेश की तत्काल जरूरत है। यद्यपि वित्तीय संकट की स्थिति में नीति निर्धारण में सामान्यतः अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तथापि कई देशों में तैयार किए गए प्रोत्साहन पैकेजों में कृषि और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिनका उद्देश्य बहुत-सी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, मलेशिया, और इंडोनेशिया में ग्रामीण मूलभूत संरचना पर व्यय को बढ़ाना है, तो थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में किसानों को रियायती ऋण प्रदान करना।

11.2.23 भारतीय संदर्भ में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस संकट ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। 2008 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान कुल मिलाकर संतोषजनक बारिश और पर्याप्त खाद्य भंडार की उपलब्धता ने कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहारा दिया है। इसके अलावा, भारत में कृषि सम्बद्ध क्षेत्र काफी प्रखर गति से विकास कर रहा है, और आशा है कि यह समग्र वृद्धि को कुछ आघात-सहनीयता एवं स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अलावा, भारत में प्राथमिकता क्षेत्र को अधिदेशात्मक रूप से उधार देने की नीति के कारण कृषि को मिलने वाला संस्थागत ऋण इस वैश्विक ऋण संकुचन से अप्रभावित बना रहा। सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी पैकेज ने भी दूरदर्शी उत्प्रेरणा का काम किया है, इसे संयोग ही कहें कि, इसने कृषि क्षेत्र को वित्तीय संकट से बचाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों से उम्मीद की जा सकती है कि यह ग्रामीण में गरीबों और वैश्विक संकट के प्रभाव से रोजगार गंवाकर लौट रहे कामगारों की जीविका का समर्थन करेगा।

11.2.24 व्यापार के रास्ते से वैश्विक आर्थिक मंदी का कृषि क्षेत्र पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि और सम्बद्ध उत्पादों सहित श्रम-प्रधान क्षेत्रों से होने वाले भारतीय निर्यातों में वैश्विक मांग में कमी, खासकर विकसित इलाकों जैसे अमरीका और यूरोपीय देशों से मांग में कमी, के कारण गिरावट दर्ज हुई है। तथापि, कृषि क्षेत्र के मामले में समग्र प्रभाव नहीं के बराबर प्रतीत होता है, क्योंकि भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात सकल देशी उत्पाद का केवल 1.5 प्रतिशत ही है।

11.2.25 कृषि ऋण माफी योजना के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के समन्वित जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि जैसी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत बढ़ाए हुए परिव्ययों तथा उर्वरक एवं खाद्य वस्तुओं की सब्सिडी में भारी बढ़ोत्तरी जैसे सरकारी नीतिगत पहलों से किसानों और ग्रामीण इलाकों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने एवं कम मानसून के कारण ग्रामीण आय में आई किसी भी गिरावट की क्षतिपूर्ति करने में मदद मिलेगी। शीघ्र खपत वाले उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी), दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और जीवन बीमा जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण खर्च आगामी वर्षों में सामान्यतया मजबूत रहने की आशा है तथा भारतीय कंपनी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में मांग-वृद्धि की संभावना को धीरे-धीरे स्वीकार कर रहा है।⁸ कृषि और कृषि से इतर क्षेत्रों में अग्र और पश्च सम्पर्कों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए यह आशा है कि वर्तमान संकट के दौरान कृषि क्षेत्र शेष अर्थव्यवस्था को सहारा देगा।

खाद्य प्रबंधन

11.2.26 2008-09 के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की सरकारी खरीद विगत वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई खरीद से अधिक रही, इसका मुख्य कारण था गेहूं की सरकारी खरीद में दुगुने से ज्यादा बढ़ोत्तरी (सारणी 2.5)। 2008-09 में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठाव विगत वर्ष में इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा। 2008-09 के दौरान सरकारी खरीद उठाव की तुलना में उच्चतर बनी रहने के कारण मार्च 2009 के अंत में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के कुल भंडार में पिछले साल की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। 1 अगस्त 2009 को खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 51.0 मिलियन टन था। इस समय चावल और गेहूं दोनों के स्टॉक अपने बफर स्टॉक मानदंड से काफी अधिक हैं।

11.2.27 प्रभावी खाद्य प्रबंधन के बावजूद, 2008-09 के दौरान प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुसार

⁸ रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टिट्यूट

सारणी 2.5: खाद्यान्न भंडार का प्रबंधन

(मिलियन टन)

वर्ष/ माह	खाद्यान्नों का शुरुआती भंडार			खाद्यान्नों की सरकारी खरीद			खाद्यान्नों का उठाव				अंतिम स्टॉक	मानदंड
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	पीडीएस	ओएमएस - ओडब्ल्यूएस	देशी	निर्यात		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008												
जनवरी	11.5	7.7	19.2	4.5	0.0	4.5	2.9	0.3	0.0	0.0	21.4	20.0
फरवरी	14.0	7.2	21.4	3.0	0.0	3.0	2.9	0.4	0.0	0.0	21.4	
मार्च	14.7	6.5	21.4	1.6	0.0	1.6	3.0	0.5	0.0	0.0	19.8	
अप्रैल	13.8	5.8	19.8	1.1	12.6	13.7	2.7	0.0	0.0	0.0	30.7	16.2
मई	12.9	17.7	30.7	2.1	8.8	10.9	3.0	0.1	0.0	0.0	36.4	
जून	12.1	24.1	36.4	1.2	0.9	2.2	2.8	0.4	0.0	0.0	36.3	
जुलाई	11.2	24.9	36.3	0.1	0.2	0.3	3.0	0.3	0.0	0.0	34.3	26.9
अगस्त	9.8	24.4	34.3	0.8	0.0	0.8	2.8	0.3	0.0	0.0	31.8	
सितंबर	8.5	23.3	31.8	1.4	0.0	1.4	3.0	0.4	0.0	0.0	30.0	
अक्टूबर	7.9	22.0	30.0	8.1	0.0	8.1	2.8	0.1	0.0	0.0	35.3	16.2
नवंबर	14.1	21.0	35.3	3.1	0.0	3.1	2.9	0.3	0.0	0.0	35.5	
दिसंबर	15.6	19.6	35.5	4.2	0.0	4.2	3.0	0.5	0.1	0.0	36.2	
2009												
जनवरी	17.6	18.2	36.2	4.8	0.0	4.8	3.0	0.2	0.2	0.0	37.4	20.0
फरवरी	20.2	16.8	37.4	3.7	0.1	3.8	3.0	0.3	0.2	0.0	37.1	
मार्च	21.3	15.3	37.1	2.3	0.0	2.3	2.9	0.4	0.5	0.0	35.6	
अप्रैल	21.6	13.4	35.6	1.4	19.4	20.8	3.3	0.1	0.0	0.0	51.8	16.2
मई	21.4	29.8	51.8	1.9	4.4	6.4	3.6	0.2	0.0	0.0	54.8	
जून	20.4	33.1	54.8	1.3	1.1	2.4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	53.2	
जुलाई	19.6	32.9	53.2	1.4	0.4	1.8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	51.0	26.9
अगस्त*	18.8	31.6	51.0	0.5	0.0	0.5	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	

उ.न.: उपलब्ध नहीं

*: 17 अगस्त तक सरकारी खरीद.

टिप्पणी : अंतिम स्टॉक के आंकड़े प्रारंभिक भंडार और सरकारी खरीद को जोड़ने तथा उसमें से उठाव को घटाने से प्राप्त आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मोटे अनाज भी शामिल हैं।

स्रोत : उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

अत्यधिक अस्थिर बनी रहीं। तथापि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि खाद्य वस्तुओं की देशी कीमतों में अस्थिरता उनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता से काफी कम रही, जिसका कुछ श्रेय कुछ पण्यों पर कीमत के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न देशी हस्तक्षेप की नीतियों को जाता है। यद्यपि जुलाई 2008 से विश्व में खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट आयी है, तथापि विश्व में अनाज की उपज कम होने की प्रत्याशा के कारण 2009 के लिए मिश्रित संभावना बनी हुई है (बॉक्स II.6)।

पण्य फ्यूचर्स

II.2.28 पण्य फ्यूचर्स बाजारों का लक्ष्य है सर्वोत्तम कीमतें खोजने को सुकर बनाना और जोखिम प्रबंधन के विकल्प प्रदान

करना। 2003 में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि पण्यों में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की अनुमति दी। पण्य फ्यूचर्स बाजार में लेनदेन की कुल मात्रा 2004-05 के 5.72 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 52.5 लाख करोड़ रुपये हो गई।

II.2.29 कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, इस बात को लेकर चिंता थी कि कई कृषि पण्यों के मूल्यों में वृद्धि के पीछे पण्य फ्यूचर्स बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी का हाथ हो सकता है। इसके प्रतिसाद में, 2007 में गेहूं, चावल, उड़द और तूर जैसे चार पण्यों में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर अस्थायी पाबंदी लगा दी गयी। यही नहीं, मई 2009 में मांग-आपूर्ति स्थिति और चीनी के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए, 31 दिसंबर 2009 तक चीनी में फ्यूचर्स ट्रेडिंग

बॉक्स II.6 कृषि की वैश्विक संभावना

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार 2008 में विश्व में अनाज का रिकार्ड उत्पादन 2,286 मिलियन टन था, जिसमें 2009 के दौरान 3.4 प्रतिशत की गिरावट रहेगी। एफएओ का अनुमान है कि 2009 के दौरान विश्व में गेहूँ की उपज में 4.2 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। अधिकांश गिरावट विश्व के बड़े उत्पादक देशों, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और अमरीका में आने की उम्मीद है। तथापि, एशिया के देशों में सर्दियों के दौरान गेहूँ की बुवाई चीन, भारत और पाकिस्तान में ज्यादा रकबे में होगी, क्योंकि इनकी सरकारों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्थक उपाय शुरू कर दिए हैं। चीन के बहुत से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा होने के बाद सर्दियों में गेहूँ की फसल के लिए आशा बढ़ी है। प्राथमिक अनुमानों से प्रकट होता है कि 2008 के स्तरों की तुलना में 2009 के दौरान विश्व में धान की पैदावार में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 2009 के दौरान विश्व में अनाज की पैदावार में गिरावट से खाद्यान्नों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव पड़ेगा। तथापि, विश्व के अनाज भंडार, विशेष रूप से चावल और गेहूँ के संतोषजनक स्तर पर होने कुछ हद तक आपूर्ति और कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाएगा।

एफएओ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सारे संसार के 30 देशों में खाद्यान्न संकट व्याप्त है। हाल के संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में हालात विशेष चिंताजनक हैं। संघर्ष, अशांति, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी एक के कारण या इनके मिश्रित प्रभाव से पूर्वी अफ्रीका के 180 लाख लोगों के सामने भोजन का संकट है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में कुल 8.7 मिलियन लोगों के सामने भोजन का संकट होने का अनुमान है। सूखे, नागरिक असुरक्षा और आर्थिक संकटों के कारण केन्या, सोमालिया और जिम्बावे में खाद्य असुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है।

रेबोबैंक की रिपोर्ट के अनुसार - फूड (रोटी), फाइबर (कपड़ा), फीड (चारा) और फ्यूएल (ईंधन) - इन चारों की मांग में विश्वव्यापी बढ़ोतरी होगी। इससे कृषि में होने वाले निवेश में बढ़ोतरी होगी और इनपुट के मूल्य में वृद्धि होगी, खासकर दक्षिण अमरीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2009-10 के दौरान गेहूँ की वैश्विक पैदावार 2008-09 के 683 मिलियन टन से घटकर 640 मिलियन टन रह जाएगी। कपास के बारे में अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आइसीएसी) ने अनुमान लगाया है कि 2009-10 के दौरान लगातार तीसरे मौसम में विश्व में कपास की उपज में गिरावट होगी और कीमतों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभावित है।

जी-8 राष्ट्रों के मंत्रियों हेतु तैयार रिपोर्ट में विश्व खाद्यान्नों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक अनाज की उपज दुगुनी करने की जरूरत है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन दिया जा सके; और 'सुस्पष्ट जलवायु परिवर्तनों' और इनपुट की बढ़ती हुई लागतों से जूझते हुए यह कार्य करना होगा। कृषि और कृषि-विपणन प्रणाली में तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया तो 2007-08 में जिस खाद्य संकट का सामना किया गया था वह कुछ ही दशकों में स्थायी रूप ले लेगा। विश्व बैंक (2008) ने भी यह उल्लेख किया है कि 2000 से 2030 तक अनाज के उत्पादन को लगभग 50 प्रतिशत और मांस के उत्पादन को 85 प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि भोजन और जैव-ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

बढ़ती हुई मांग की प्रतिक्रियास्वरूप कृषि के प्रबंधन हेतु समुचित नीतिगत उपायों और सुस्थिर निवेशों की जरूरत पड़ेगी।

2009-2018 के ओईसीडी-एफएओ एग्रिकल्चरल आउटलुक के अनुसार, यद्यपि 2007 और 2008 के दौरान जो ऊंची कीमतें थीं वे धीरे-धीरे नीचे आएंगी, लेकिन 2007-08 के पहले के दशक के ऐतिहासिक औसत की तुलना में मध्यम अवधि (2009-2018) के दौरान उच्च स्तर पर ही रहेंगी। आपूर्ति-पक्ष को देखें तो उक्त रिपोर्ट में यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि फसलों की आपूर्ति के लिए नई जमीन पर खेती करना शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि फसलों की उपज में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे। मांग-पक्ष को देखें तो बदलता हुआ आहार, शहरीकरण, आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई जनसंख्या और अभी हाल ही में जैव-ईंधन की बढ़ती मांग के विकासशील देशों में खाद्यान्नों और चारे की मांग प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक कृषि का केंद्र बिंदु ओईसीडी से हटकर विकासशील देशों में हो जाएगा। विकासशील देशों में गेहूँ के अलावा सभी उत्पादों का उपभोग और उत्पादन दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। भविष्य में इन देशों में अधिकांश जिनसों का उत्पादन और उपभोग बढ़ेगा, लेकिन मोटे अनाज, पनीर और स्किम-दुग्ध पाउडर अपवाद रहेंगे।

मांग/आपूर्ति और व्यापार/कीमतों की दृष्टि से देखें तो विश्व कृषि बाजारों में प्रत्याशित गतिविधियों में देशी कृषि के भविष्य हेतु बहुत से निहितार्थ हैं। हाल ही के गत समय में विश्व कृषि बाजारों में कृषि जिनसों की कीमतों में नाटकीय तेजी रही, और घरेलू कीमतों ने भी इसी अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण किया, अलबत्ता गति धीमी थी। इस तथ्य को देखते हुए कि भविष्य में कृषीय उत्पादों की कीमतें ऐतिहासिक औसत दरों से ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि विश्व में अनाज की पैदावार की संभावना अनिश्चित है, अतः देशी आपूर्ति प्रतिक्रिया को गति देने की जरूरत है ताकि मांग के तीव्र दबाव के कारण कीमत की स्थितियों को काबू में रखा जा सके। इसी संदर्भ में यह राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है कि गेहूँ, चावल, दालों जैसे खाद्यान्नों और खाद्य तेलों जैसी खाद्येतर फसलों की घरेलू उपज को बढ़ाकर अच्छे स्तरों पर लाना होगा और सरकारी खरीद एवं न्यूनतम समर्थन कीमतों के माध्यम से पर्याप्त बफर स्टॉक बनाने होंगे ताकि मौसम में किसी तेज उथल-पुथल और फसल मारी जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। वैश्विक संभावना का स्पष्ट संकेत यही है कि भारत की खाद्य सुरक्षा को बचाने के साथ-साथ ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि के उपाय के रूप में कृषीय उत्पादन बढ़ाने होंगे।

संदर्भ

1. खाद्य और कृषि संगठन, (2009): 'क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स एन्ड फूड सिक्योरिटी', अप्रैल तथा जुलाई।
2. ओईसीडी-एफएओ, (2009): 'एग्रिकल्चरल आउटलुक 2009-2018'.
3. विश्व बैंक (2008): एग्रिकल्चरल फॉर डेवलपमेंट, *वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट*.
4. रेबोबैंक (2008): दि बूम बियॉन्ड कमोडिटीज: ए न्यू एरा शेपिंग ग्लोबल फूड एन्ड एग्रीबिजनेस.

को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले, सरकार ने कृषि पण्य मूल्यों पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के प्रभाव, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए एक समिति (अध्यक्ष: प्रो. अभिजित सेन) भी गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाजिर मूल्यों को अत्यधिक रूप से बढ़ाने या कम करने में फ्यूचर्स ट्रेडिंग के उत्तरदायी होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। यही नहीं, समिति ने व्यापक सिफारिशें भी कीं, जैसे कि फ्यूचर्स बाजार में कृषकों की व्यापक सहभागिता; कृषि विपणन में शीघ्र सुधार लाना; और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से उपयुक्त संविदाएं तैयार करना। समिति ने यह भी कहा कि कई पण्यों के मामले में, पण्य फ्यूचर्स प्रारंभ करने के पश्चात देशी मूल्यों में वृद्धि एक संकुचित आधार से हुई है, और इसलिए, इस वृद्धि के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग को प्रत्यक्ष रूप से या अकेले उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

11.2.30 फ्यूचर्स प्रारंभ होने के बाद भारत में कृषि पण्य मूल्यों को देशी उत्पादन, बफर स्टॉक के स्तरों, सरकारी खरीद की नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से खाद्य बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप, कृषि पण्य निर्यात, अंतरराष्ट्रीय खाद्य मूल्य परिदृश्य तथा देशी आपूर्ति और मांग गतिकी जैसे ऐसे मूल्यों को प्रभावित करने वाले कई कारकों के संबंध में देखा जाना चाहिए। बाजार का विनियामक अर्थात् वायदा बाजार आयोग भी संवेदनशील पण्यों के फ्यूचर्स मूल्यों पर निगरानी रखता है। फ्यूचर्स बाजार में अस्थिरता और सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से, जैसे संवेदनशील पण्यों पर मार्जिन अपेक्षाएं लागू कर दी गईं, जैसाकि 2009 में चीनी, आलू और सोयाबीन के मामले में किया गया था।

मौसम बीमा

11.2.31 वैश्विक जलवायु में परिवर्तन के कारण, भारतीय कृषि को दीर्घावधि में गर्मी, अनिश्चित मौसम और सिंचाई सुविधाओं की कम उपलब्धता के कारण हानि होने की जोखिम रहती है। जलवायु में परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र को आघात-सहनीयता प्रदान करना एक चुनौती है जिसके लिए जलवायु-सह फसलों तथा पशु नस्लों को अपनाना तथा फसलों, पशुओं और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विवेकपूर्ण प्रबंधन करना अपेक्षित है। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है - नवोन्मेषी मौसम बीमा योजना जो कि जलवायु के आंकड़ों तथा मौसम का

पूर्वानुमान लगाने के बेहतर मॉडलों से जुड़ी हो। इस दिशा में हाल ही में की गई पहल को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है (बॉक्स II.7)।

औद्योगिक कार्यनिष्पादन

11.2.32 2003-08 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन में 8.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ सुदृढ़ वृद्धि देखी गई थी, लेकिन उसके बाद अत्यधिक अनिश्चितता तथा कमजोर देशी तथा बाह्य मांग के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी हुई और 2008-09 में यह 2.7 प्रतिशत रह गई (सारणी 2.6)। 2007-08 की पहली तिमाही में शुरू हुई वृद्धि में कमी (वर्ष-दर-वर्ष) हाल की अवधि में मंदी के दीर्घतम दौर में से एक साबित हुई। 1990 के दशक के मध्य से भारतीय उद्योग का वृद्धि का अनुभव यह दिखलाता है कि इसे मंदी के तीन स्पष्ट चरणों का सामना करना पड़ा। ये तीनों ही चरण किसी-न-किसी रूप में प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के समय आये, हालांकि मंदी पूर्णतया वैश्विक कारकों के कारण नहीं आई होगी (सारणी 2.7)।

11.2.33 1996-97 और 2000-01 के दौरान औद्योगिक मंदी वैश्विक आर्थिक मंदी के समय आयी लेकिन देशी कारणों जैसे कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता, बिजली, परिवहन तथा संचार में मूलभूत सुविधा संबंधी रुकावटों, बड़े पैमाने का लाभ न उठा सकने के कारण उद्योग में उत्पादकता के निम्न स्तर, पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी, प्रतिबंधात्मक श्रम कानून और सीमेंट, स्टील तथा ऑटोमोबाइल जैसे कुछ चक्रीय उद्योगों में मांग में उतार-चढ़ाव का औद्योगिक वृद्धि में गिरावट में काफी हाथ था। भारत के सकल देशी उत्पाद में निर्यात के बढ़ते योगदान (सीएसओ द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के आधार पर 2000-01 के 13.0 प्रतिशत से 2008-09 में 23.4 प्रतिशत) और पूंजी खाते के उदारीकरण के कारण, भारतीय उद्योग पर वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव कुछ समय से बहुत मुखर हो गया है। वर्तमान संकट में अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता के कारण, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में वर्तमान मंदी की तीव्रता कुछ अधिक है। 2008-09 की दूसरी छमाही में बाह्य मांग में तीव्र गिरावट के साथ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति में कमी आ गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी), जो कि 2008-09 की पहली छमाही में 5.0 प्रतिशत की मासिक औसत दर से बढ़ा, दूसरी छमाही में तेजी से गिरकर 0.6 प्रतिशत रह गया,

बॉक्स II.7

वैश्विक जलवायु परिवर्तन : भारतीय कृषि के लिए नई चुनौतियां

वैश्विक जलवायु के परिवर्तनों के कारण मानव जाति, पेड़-पौधों और पशुओं के लिए अभूतपूर्व और बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन्स इंटर-गवर्नमेंट पैनेल आन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की सतह का तापमान पिछले 100 वर्ष में औसतन 0.74 डिग्री सैल्सियस बढ़ा है लेकिन अगली शताब्दी में इसके औसतन 3 डिग्री बढ़ जाने की संभावना है। तापमान में संभावित 1.4 डिग्री की न्यूनतम वृद्धि होने पर भी ऐसा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है जो कि पिछले 10,000 वर्ष में देखने में नहीं आया। जलवायु में परिवर्तन का एक खतरा यह है कि समुद्र का परिमाण बढ़ जाने और ग्लेशियरों और आइस कैप के पिघल जाने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर में, प्रमुख शहरी क्षेत्रों सहित, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। इसी से जुड़ी एक और चिंता यह है कि विषम मौसम के प्रति कृषि की असुरक्षितता के कारण इसका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणाम विश्व के निर्धन और भूखे लोगों को झेलने पड़ेंगे। परीक्षण माडलों के आधार पर, वैज्ञानिकों का कहना है कि इन संकटों की बारंबारता और भी बढ़ जाएगी, विशेषकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यही नहीं, वर्षा के पैटर्न में बुनियादी परिवर्तनों तथा बढ़ते तापमान से फसल की बुआई की अवधि कम हो जाएगी, फसल की उपज में कमी आएगी जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु में परिवर्तन से हाइड्रोपावर सहित जल से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, बाढ़ से संरचनात्मक सुरक्षा, ड्रेनेज और सिंचाई प्रणालियों तथा जल प्रबंधन प्रथाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे जनसंख्या में वृद्धि, बदलती आर्थिक गतिविधियों, भूमि के प्रयोग के पैटर्न में परिवर्तन तथा शहरीकरण जैसे अन्य तनाव कारकों के प्रभाव और भी अधिक विकट हो जाएंगे। एशिया और शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की मांग तापमान में 1 डिग्री सैल्सियस की वृद्धि होने पर कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ जाएगी (फिशर और अन्य 2002; लियु; 2002)

सूखे (कृषि योग्य जमीन का 2/3 हिस्सा वर्षा पर निर्भर रहता है), बार-बार बाढ़ आने, विशेषकर पूर्वी भारत में, पाला गिरने जोकि उत्तर पश्चिमी भाग में सामान्य घटना है, अकसर लू चलने और पूर्वी तट पर चक्रवातों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में जलवायु संबंधी समस्याओं का प्रबंध करना बहुत आवश्यक हो गया है। जलवायु में इन परिवर्तनों के कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने में आएगा। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के संभावित अनुमानों के अनुसार, अल्पकाल में यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा लेकिन दीर्घावधि में 2100 तक फसल की उपज में 10-40 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। भारत के लिए यह बात विशेष सुसंगत है कि वैश्विक गर्मी से ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा में अत्यधिक परिवर्तन आएगा। चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए वर्षा पर आधारित कृषि पर निर्भर रहता है, इसलिए, अनिश्चित मानसून आबादी के बहुत बड़े हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 2 डिग्री सैल्सियस से 3.5 डिग्री सैल्सियस वृद्धि के लिए भारत में कृषि स्तर पर निवल राजस्व की हानि 9 से 25 प्रतिशत हो सकती है (कुमार तथा पारिख, 1998)। ऐसी संभावना है कि 2025

से पहले भारत जल दबाव की स्थिति में आ जाएगा, जब उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1000 एम³ से कम हो जाएगी (सीडब्ल्यूसी, 2001)। भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकालिक जलवृष्टि में अनुमानित कमी का अर्थ होगा मानसून के कम रहने की अवधि में कम भंडारण तथा जल पर और अधिक दबाव।

पारंपरिक तौर पर, किसान मिश्रित फसल, फसलों की किस्म/बुआई समय में परिवर्तन, मौसम/जल उपलब्धता के साथ फसल चक्र को समन्वित करके, पशुपालन, आदि सहित आय स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं और कुछ अन्य नीतियां अपनाने की जरूरत है जैसे कि (i) जलवायु संबंधी जोखिमों/संकटों के लिए चेतावनी प्रणालियां बनाना, (ii) कीड़े-मकौड़ों पर निगरानी और पूर्वानुमान क्रियाविधियों को सुदृढ़ करना, (iii) अच्छे बीजों की अनुकूलनीय किस्में समय पर उपलब्ध कराना, कृषकों के प्रशिक्षण सहित नई प्रौद्योगिकी अपनाना और उसे प्रदर्शित करना, संसाधनों के संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना सुनिश्चित कर फसलों और क्षेत्रों के बीच उपज के अंतरों को पाटना, (iv) पद्धतियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना, (v) फसलों, पशुधन, मत्स्य, कीड़ों-मकौड़ों, तथा माइक्रोब पर क्षेत्रीय प्रभाव का आकलन करना, (vi) 'प्रतिकूल जलवायु रोधी' जीनोटाइप तथा भूमि उपयोग प्रणालियां विकसित करना, तथा (vii) अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए जल तथा उर्वरक प्रबंधन परिपाटियों की फिर से जांच करना। हालांकि वर्तमान मंदी के समय में भारतीय कृषि ने आघात-सहनीयता दिखाई है और वृद्धि चक्र को समर्थन दिया है, लेकिन यदि इन समस्याओं को दूर करने के लिए समय पर कदम न उठाए गए तो वैश्विक जलवायु में हो रहे परिवर्तनों से जुड़ी जोखिमें भावी आघात-सहनीयता को समाप्त कर सकती हैं।

संदर्भ:

1. केंद्रीय जल आयोग (2001), जल और संबंधित आंकड़े, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट.
2. फिशर जी.एम.शहा तथा एच. वैन वेल्थूजन (2002), 'क्लाइमेट चेंज एण्ड अग्रिकल्चरल वल्वरेबिलिटी', प्रीप्रिंट, धारणीय विकास पर विश्व शिखर बैठक, जोहन्सबर्ग, 160 पीपी.
3. कुमार के. तथा पारिख जे. (1998), 'क्लाइमेट चेन्ज इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन अग्रिकल्चर : दि रिकार्डियन अप्रोच' भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की माप, वर्ल्ड बैंक टेक्निकल पेपर सं. 402.
4. लियू सी. जेड. (2002), 'सजेशन ऑन वॉटर रिसोर्सेस इन चाइना करेस्पॉन्डिंग विथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज'. चाइना वाटर रिसोर्सेज, सं.2, 36-37.
5. यूनाइटेड नेशन्स गवर्नमेंटल पैनेल ऑन क्लाइमेट चेंज (2008): 'क्लाइमेट चेंज एंड वॉटर' टेक्निकल पेपर ऑफ वर्किंग ग्रुप II, जून

सारणी 2.6: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र का वृद्धि कार्य-निष्पादन

(प्रतिशत)

माह/वर्ष	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		विद्युत		सामान्य	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	2.6	6.1	12.4	6.7	8.7	1.4	11.3	6.2
मई	3.8	5.5	11.3	4.5	9.4	2.0	10.6	4.4
जून	1.5	0.1	9.7	6.1	6.8	2.6	8.9	5.4
जुलाई	3.2	2.8	8.8	6.9	7.5	4.5	8.3	6.4
अगस्त	14.7	2.8	10.7	1.7	9.2	0.8	10.9	1.7
सितंबर	4.9	5.8	7.4	6.2	4.5	4.4	7.0	6.0
अक्टूबर	5.1	3.2	13.8	-0.6	4.2	4.4	12.2	0.1
नवंबर	6.3	0.7	4.7	2.7	5.8	2.6	4.9	2.5
दिसंबर	5.0	2.2	8.6	-0.6	3.8	1.6	8.0	-0.2
जनवरी	2.9	0.7	6.7	1.0	3.7	1.8	6.2	1.0
फरवरी	7.9	-0.2	9.6	0.2	9.8	0.7	9.5	0.2
मार्च	4.9	1.9	5.7	-0.3	3.7	6.3	5.5	0.3
अप्रैल-मार्च	5.1	2.6	9.0	2.7	6.3	2.8	8.5	2.7

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार.

तथा दिसंबर 2008 में वृद्धि दरें ऋणात्मक हो गईं। सामान्यतया यह देखा गया है कि भारत में औद्योगिक मंदी देशी मांग में, विशेषकर निवेश मांग में, कमी आने के साथ शुरू हुई, हालांकि कमजोर निर्यात और निम्न कारोबार विश्वास के कारण बाह्य मांग में कमी के कारण वर्तमान वैश्विक संकट में औद्योगिक वृद्धि की कमी बढ़ गई। अनुभवसिद्ध संबंधों से यह साक्ष्य मिलता है कि आइआइपी का देशी उपभोग मांग, निर्यात और देशी पूंजी निर्माण के साथ उल्लेखनीय सकारात्मक संबंध होता है, तथा आयात के साथ से विपरीत संबंध होता है (जो कि इस तथ्य को दिखलाता है कि आयात आंशिक रूप से देशी प्रतिस्थापनों से प्रतिस्पर्धा करते हैं)।

II.2.34 2008-09 में आइआइपी वृद्धि में कमी का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसका आधार व्यापक था और इसने तीनों क्षेत्रों अर्थात् खनन, विनिर्माण और विद्युत को प्रभावित किया।

सारणी 2.7: भारतीय उद्योग में मंदी के चरण

	आरंभ	अंत	विस्तार
1	2	3	4
1996-97	1996-97: ति 2	1997-98: ति 1	4 तिमाहियां
2000-01	2000-01: ति 2	2001-02: ति 3	7 तिमाहियां
2007-08	2007-08: ति 1	2008-09: ति 4	8 तिमाहियां

यह कमी विनिर्माण क्षेत्र में काफी प्रखर थी (परिशिष्ट सारणी-6)। खनन क्षेत्र में भी वृद्धि में कमी आयी, जो कि कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कच्चे तेल और उत्पादों में कमी दिखलाती है। थर्मल तथा हाइड्रो पावर संयंत्रों, दोनों ही में, बिजली उत्पादन में कमी के कारण समूचे वर्ष में बिजली का उत्पादन कम रहा, तथा वर्ष के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने सबसे अधिक कमी दिखाई।

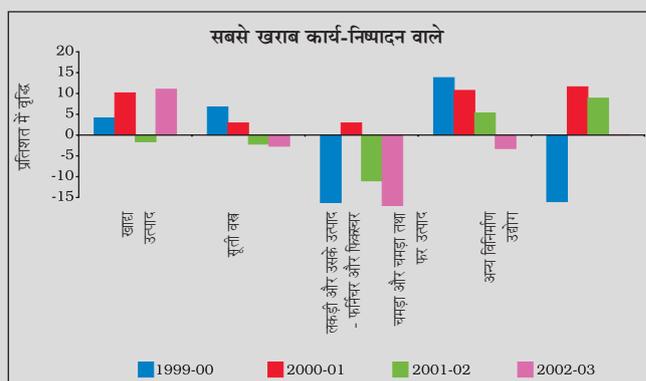
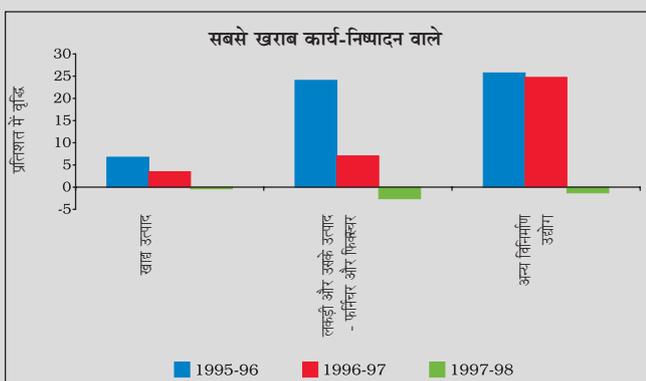
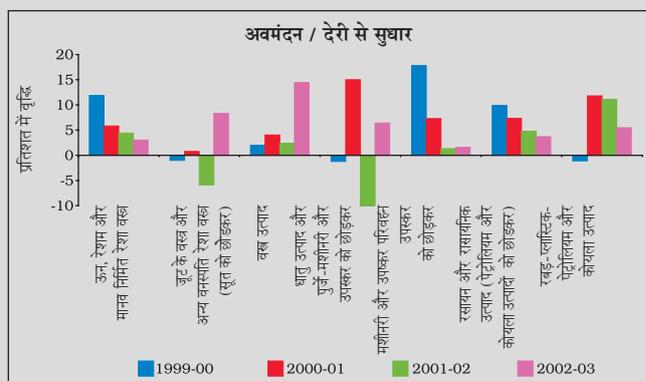
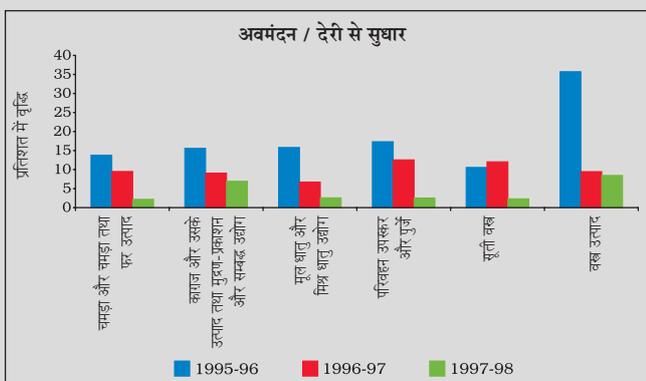
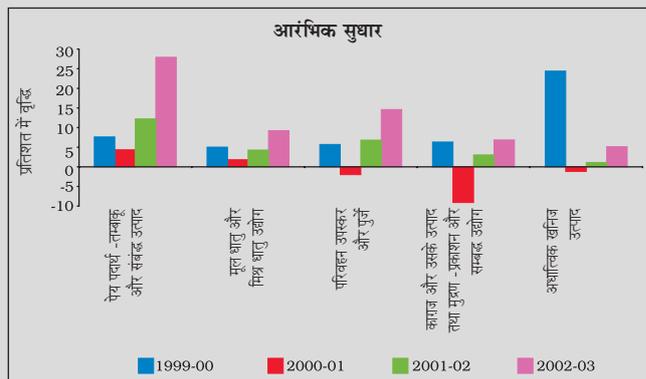
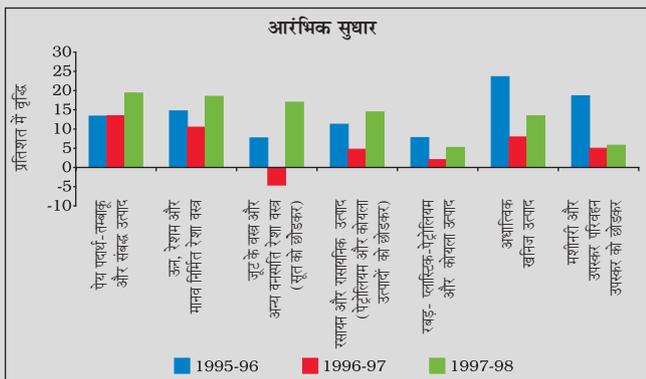
II.2.35 विनिर्माण क्षेत्र, जिसने 2002-03 से औद्योगिक वृद्धि को गति प्रदान की थी, 2007-08 में मंद पड़ गया। आइआइपी पर आधारित हेडलाइन औद्योगिक वृद्धि की प्रवृत्ति के अलावा, अलग-अलग 17 दो-अंकीय विनिर्माण उद्योगों के व्यवहार का पैटर्न पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसे समूहों के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है जो मंदी के वर्तमान चरण के दौरान शीघ्र सुधार, विलंब से सुधार और काफी अंतराल के बाद सुधार दिखाएंगे (चार्ट II.3)।

II.2.36 वर्तमान मंदी भी काफी व्यापक आधारवाली है क्योंकि 17 द्विअंकीय विनिर्माण उद्योग समूहों में से पन्द्रह ने, जिनका आइआइपी में 74.4 प्रतिशत भारांक है, 2008-09 में ऋणात्मक/कम वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.4; परिशिष्ट सारणी 7 और 8)। मंदी

चार्ट II.3: विगत काल में मंदी के दौरान 17 द्विअंकीय उद्योगों का कार्यनिष्पादन

1996-97 से 1997-98

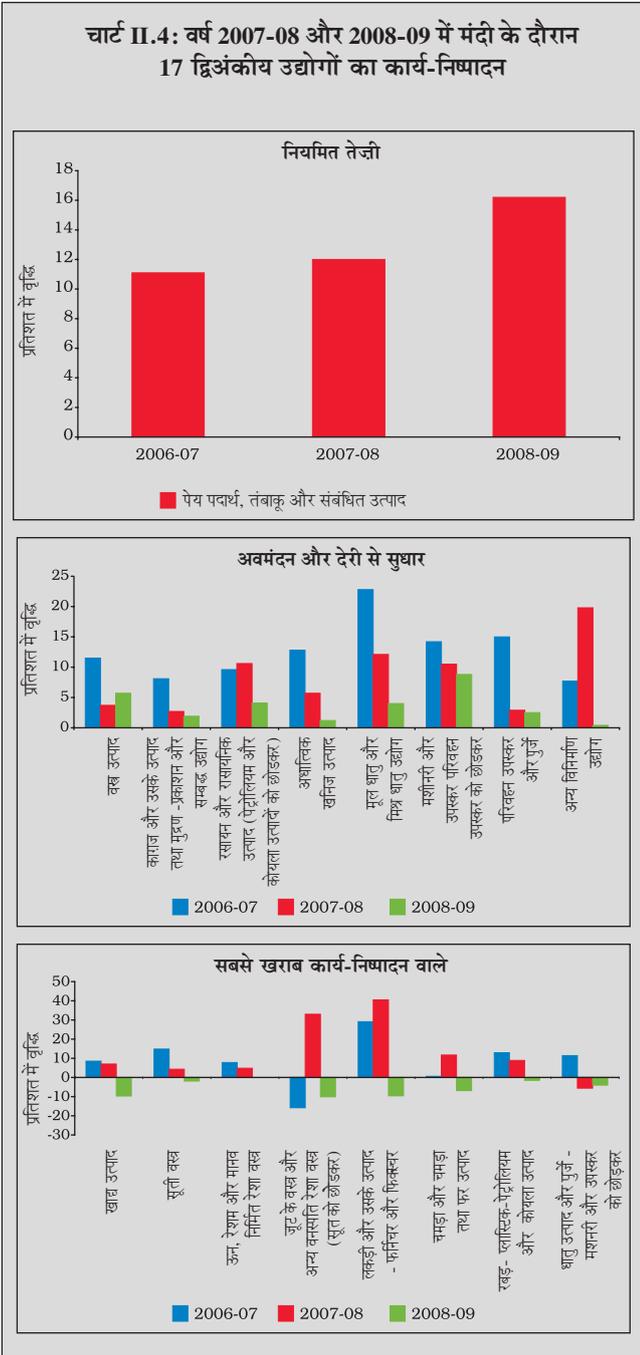
2000-01 से 2001-02



के पिछले दो चरणों के समान ही, वर्तमान चरण में भी 'सूती वस्त्रोद्योग', 'खाद्य पदार्थ', 'चमड़ा और चमड़े के उत्पाद', 'लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद', 'फर्नीचर और फिक्स्चर' ने ऋणात्मक वृद्धि दिखलाई। उच्चतर निर्यात सघनता वाले उद्योगों (वस्त्र उत्पादों को छोड़कर) के कार्य-निष्पादन में मंदी वर्तमान मंदी की एक प्रमुख विशिष्टता है, जो कि वैश्विक मंदी का समग्र प्रभाव दर्शाता है।

II.2.37 उपयोग आधारित वर्गीकरण के रूप में सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि में नरमी आयी थी, परंतु इस नरमी की तीव्रता भिन्न-भिन्न रही (सारणी 2.8, परिशिष्ट सारणी 9)। मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में कमी, जो अगस्त 2008 से ही प्रारंभ हो गयी थी, 2008-09 की तीसरी तिमाही में और अधिक गहरी और व्यापक हो गयी। समग्र रूप से, बारह महीनों में से सात महीनों में इस क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि ऋणात्मक रही। निर्यातोन्मुखी उद्योगों

चार्ट II.4: वर्ष 2007-08 और 2008-09 में मंदी के दौरान 17 द्विअंकीय उद्योगों का कार्य-निष्पादन



सारणी 2.8: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक: उद्योगों का क्षेत्रवार और उपयोग-आधारित वर्गीकरण (प्रतिशत)

औद्योगिक समूह	वृद्धि दर		भारत योगदान	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
क्षेत्रवार वर्गीकरण				
खनन	5.1	2.6	4.2	6.3
विनिर्माण	9.0	2.6	89.5	85.3
विद्युत	6.3	2.8	6.3	8.3
उपयोग-आधारित वर्गीकरण				
मूलभूत वस्तुएं	7.0	2.6	24.8	32.2
पूंजीगत वस्तुएं	18.0	7.3	25.1	38.2
मध्यवर्ती वस्तुएं	8.9	-1.9	27.5	-31.6
उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	6.1	4.7	23.0	59.1
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	-1.0	4.5	-1.0	14.3
ख) गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	8.5	4.8	24.1	44.7
सामान्य	8.5	2.7	100	100

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

पड़ा। निर्माण उद्योग में आयी मंदी ने अ-धात्विक खनिज निविष्टियों जैसे कि सिरामिक टाइल, पत्थर के टुकड़े/पॉलिशयुक्त ग्रेनाइट और सीमेंट की चादरों के उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित किया।

II.2.38 वर्ष की दूसरी छमाही में मूल वस्तु क्षेत्र की गति में कमी आने लगी। बिजली की कमी, मूलभूत रसायनों और रासायनिक उत्पादों, नाइट्रोजिनस और फास्फेटिक उर्वरकों, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला और अल्यूमिनियम उत्पादों में ऋणात्मक वृद्धि के कारण मूल वस्तु क्षेत्र में न्यूनतर वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में आयी मंदी 'मशीन एवं उपकरण टेक्स्टाइल-मशीनरी,' रेफ्रिजरेटर और एअर-कंडीशनिंग, मशीनी औजार और 'हवा एवं गैस कंप्रेसर, तथा परिवहन उपकरण और पुर्जे' जैसे सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी जिसने निवेश मांग में भी मंदी ला दी। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में अपेक्षाकृत कुछ मंदी आई, जो अर्थव्यवस्था में समग्र निजी उपभोग मांग में कमी को दर्शाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में कमी होने का प्रमुख कारण गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में आयी कमी था। तथापि, 2008-09 के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग ने एक वर्ष पहले की तुलना में बेहतर कार्य-निष्पादन दर्शाया, फिर भी इसमें अंतर-माह उतार-चढ़ाव अधिक रहा (सारणी 2.9)। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में इन लाभों का आंशिक श्रेय पिछले तीन वर्षों से हुई अच्छी फसल और कृषि ऋण माफी के कारण होनेवाली निरंतर ग्रामीण मांग को जाता है।

के लिए मध्यवर्ती निविष्टियों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की वृद्धि में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गयी। इसी प्रकार, देशी आटो उद्योग में आयी मंदी का असर 'आटो अनुषंगी इकाइयों और उनके पुर्जे' तथा 'धातु उत्पाद और कल-पुर्जा उद्योग' के कार्य-निष्पादन पर

सारणी 2.9: उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि का रुझान

(प्रतिशत)

माह/वर्ष	उपभोक्ता वस्तुएं वस्तुएं			उपभोक्ता टिकाऊ			उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	8.9	14.7	8.5	7.4	2.4	3.2	9.4	18.7	10.0
मई	10.5	8.7	7.4	17.5	-0.7	2.8	8.2	12.1	9.0
जून	6.1	3.6	9.9	19.9	-3.6	4.6	1.8	6.3	11.6
जुलाई	16.8	7.1	5.9	16.1	-2.7	13.9	17.1	10.5	3.4
अगस्त	15.0	0.0	6.4	19.0	-6.2	3.9	13.6	2.4	7.3
सितंबर	12.1	-0.2	7.4	11.8	-7.3	14.7	12.2	2.6	4.8
अक्टूबर	-2.8	13.7	-0.9	0.2	9.0	-1.6	-4.1	15.8	-0.6
नवंबर	13.5	-2.9	9.4	10.1	-5.5	0.3	14.8	-2.0	12.4
दिसंबर	10.7	8.7	1.7	1.8	2.8	-4.2	13.5	10.3	3.2
जनवरी	8.2	8.4	3.6	5.3	-0.5	2.1	9.1	11.1	4.0
फरवरी	7.4	11.7	-1.3	1.8	3.1	6.0	9.3	14.3	-3.4
मार्च	15.8	0.9	1.3	3.8	-2.0	8.4	20.2	1.9	-1.0
अप्रैल- मार्च	10.1	6.1	4.7	9.2	-1.0	4.5	10.4	8.5	4.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार।

क्षमता उपयोग

II.2.39 2008-09 के दौरान पिछले साल की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए, मुख्यतः विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में, क्षमता उपयोग⁹ में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी, विनिर्माण क्षेत्र में मांग में मंदी का प्रभाव स्पष्ट दिखायी दे रहा था क्योंकि 17 द्वि-अंकीय विनिर्माण उद्योगों में से, 15 उद्योगों ने पिछले साल की तुलना में 2008-09 के दौरान न्यूनतर क्षमता उपयोग दर्ज किया (सारणी 2.10)। 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान, अधिकांश उद्योगों में क्षमता उपयोग में गिरावट आयी। निजी क्षेत्र में विनिर्माण कंपनियों के संबंध में रिजर्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण, जिसमें आगामी तिमाही के लिए प्रत्याशाओं के संबंध में अग्रणी जानकारी प्रदान की जाती है, में यह सूचित किया गया है कि क्षमता उपयोग के स्तर में (पिछली चार तिमाहियों के औसत की तुलना में) दूसरी तिमाही में मंदी आयी तथा 2008-09 की अंतिम दो तिमाहियों में इसमें कमी हुई। उच्च सर्वेक्षण यह भी सूचित करता है कि 2009-10 की दूसरी तिमाही के लिए मुख्य

उत्पादों के क्षमता उपयोग की संभावनाएं, पहली तिमाही में थोड़ी गिरावट देखने के बाद, सकारात्मक हो गयीं।

मूलभूत संरचना उद्योग

II.2.40 औद्योगिक क्षेत्र के साथ-ही-साथ मूलभूत संरचना उद्योग ने भी मंदी का सामना किया (परिशिष्ट सारणी 10)। कोयला, विद्युत, तैयार इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम रिफाइनरी और कच्चे तेल जैसे मुख्य क्षेत्र की वृद्धि कम होकर 2008-09 में 2.8 प्रतिशत रह गई (2007-08 के 5.9 प्रतिशत से), जो 1998-99 से अब तक हुई निम्नतम वृद्धि है (चार्ट II.5)। नयी इकाइयों के पिछड़े कार्य-निष्पादन के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र गिरावट दर्ज की गयी (बॉक्स II.8)।

II.2.41 कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में आयी तीव्र गिरावट, देशी मांग में आयी कमी, अपर्याप्त लाजिस्टिक समर्थन, प्रसंस्करण प्लेटफार्म के निर्माण में हुए विलंब, पावर शटडाउन, जलाशयों के दबाव में कमी और पर्यावरणीय कारकों ने कच्चे तेल के उत्पादन

⁹ सर्वोच्च उत्पाद दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए क्षमता उपभोग का आकलन किया गया है। इस दृष्टिकोण के तहत एक उद्योग-विशेष के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वोच्च मासिक उत्पाद को उस वर्ष के लिए उत्पादक क्षमता माना जाता है जबकि मासिक औसत उत्पाद के आधार पर उस वर्ष के लिए उपभोग स्तर का आकलन किया जाता है। तदनुसार एक उद्योग विशेष का मासिक क्षमता उपभोग मासिक उत्पादन और वर्ष के दौरान उत्पादन के सर्वोच्च स्तर का अनुपात होता है।

सारणी 2.10: क्षमता उपयोग

(प्रतिशत)

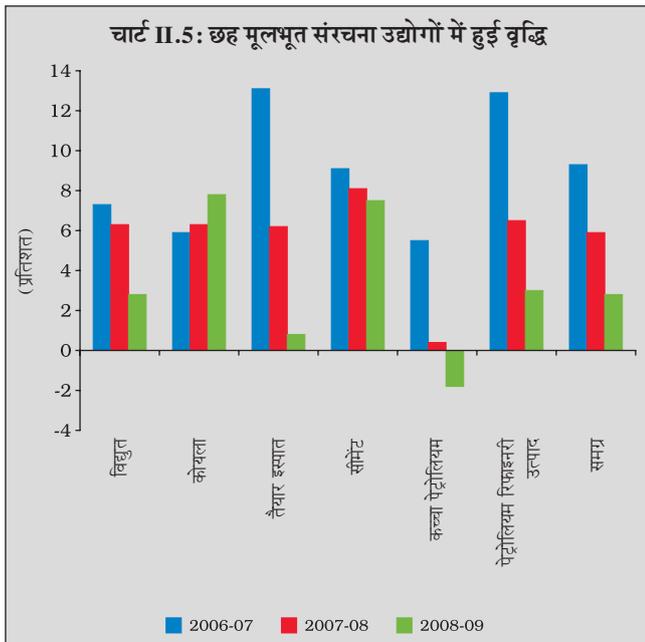
उद्योग	भार	क्षमता उपयोग		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	4	5	6
खाद्य उत्पाद	9.08	67.8	68.9	65.2
पेय पदार्थ, तंबाकू और संबंधित उत्पाद	2.38	84.2	83.4	81.8
सूती वस्त्र	5.52	94.6	96.5	93.0
ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्र	2.26	87.4	86.8	87.4
जूट और अन्य वनस्पति रेशों से बने वस्त्र (रूई को छोड़कर)	0.59	71.4	90.4	86.8
वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	92.3	95.6	94.5
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सर	2.70	69.6	88.9	74.8
कागज और कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन तथा संबंधित कार्यकलाप	2.65	93.8	93.3	88.5
चमड़ा, तथा चमड़ा और फर के उत्पाद	1.14	81.1	89.1	83.5
पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर रसायन एवं रासायनिक उत्पादन	14.0	79.2	81.1	77.2
रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयले के उत्पाद	5.73	86.8	86.5	80.0
अधात्विक खनिज उत्पाद	4.40	85.8	86.8	85.2
मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	7.45	83.4	85.3	90.2
धातु उत्पाद और पुर्जे (मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर)	2.81	65.3	74.2	69.6
परिवहन उपस्कर को छोड़कर मशीनरी और उपस्कर	9.57	74.9	77.0	73.4
परिवहन उपस्कर से इतर मशीनरी तथा उपस्कर	3.98	80.7	81.4	78.5
परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	2.56	73.4	73.4	70.0
विनिर्माण उद्योग	79.36	80.1	82.5	79.3
खनन और उत्खनन	10.47	83.2	83.3	84.9
बिजली	10.17	93.4	95.9	92.7
सभी उद्योग	100	81.8	83.9	81.3

टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं।

2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त 296 उद्योगों के उत्पादन आंकड़ों से क्षमता उपभोग का आकलन किया गया है।

3. सर्वोच्च उत्पादन दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुमानित क्षमता उपयोग केवल प्रवृत्तियों का संकेत देता है और उसे क्षमता के वास्तविक उपयोग के स्तर को दर्शानेवाले के रूप में न देखा जाए। क्षमता के उपयोग के बारे में अन्य किसी आंकड़े अथवा संकेतक के अभाव में सर्वोच्च-उत्पादन दृष्टिकोण का उपयोग क्षमता उपयोग के लिए परोक्षी के रूप में किया जाता है।

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित।



को प्रभावित किया। इस्पात का उत्पादन भी कम रहा, जिसने निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आयी मंदी का अनुकरण किया। सीमेंट उत्पादन में 2008-09 में साल-दर-साल वृद्धि पिछले वर्ष प्राप्त की गई उत्पादन वृद्धि से केवल कुछ ही कम रही।

II.2.42 लगभग सभी मूलभूत संरचना उद्योग 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहे (सारणी 2.11)। ऊर्जा, इस्पात, उर्वरक, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए लक्ष्य और प्राप्ति के बीच का अंतर बढ़ गया।

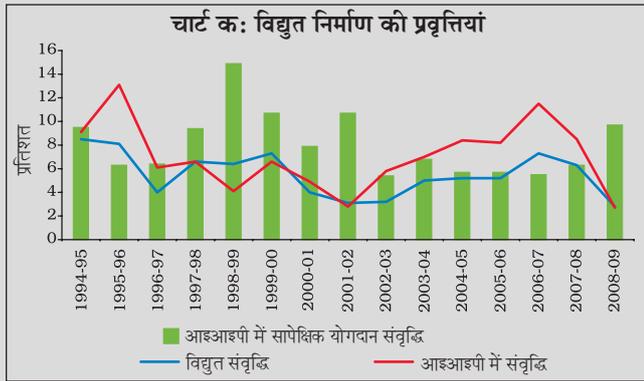
केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यानिष्पादन

II.2.43 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत आनेवाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की संख्या में पिछले साल की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्धारित समय

बॉक्स II.8 विद्युत क्षेत्र का निष्पादन

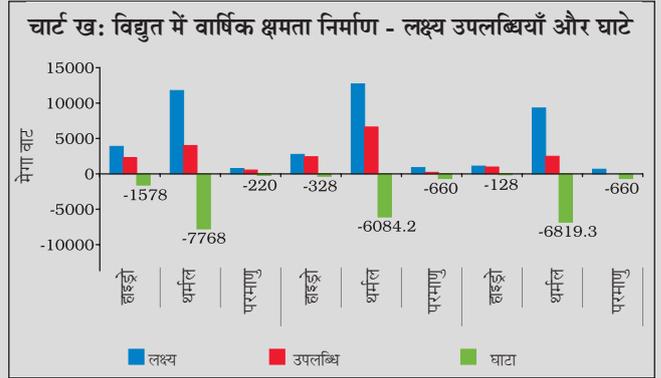
सुधारों के बाद की अवधि में भारतीय विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पादन और कुशलता लाभ हुए हैं। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता दुगुनी से अधिक होकर 1,47,965 एमडब्ल्यू हो गई है (मार्च 1990 के अंत की स्थिति के अनुसार 71,750 एमडब्ल्यू)। पावर यूटिलिटीज द्वारा विद्युत उत्पादन में 2007-08 में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई और वह 2007-08 में 662 बिलियन केडब्ल्यूएच हो गया (1990-91 में 264 बिलियन केडब्ल्यूएच से)। प्लांट लोड फैक्टर, जो कि अतिरिक्त मांग के दौरान थर्मल पावर प्लांट में परिचालनगत कुशलता का एक सशक्त संकेतक है, 1990 के 53.8 से बढ़कर 2006-07 में 77.2 हो गया है। सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने के प्रयासों के कारण विद्युत तक पहुंच कुछ और अधिक व्यापक और समावेशक हो गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2009 के अंत तक भारत में 4,87,338 या 82.1 प्रतिशत गांवों में विद्युत उपलब्ध थी। भारत में विद्युत का प्रतिव्यक्ति उपभोग भी 2002-03 में 566.7 केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2007-08 में 704.02 के डब्ल्यूएच हो गया है।

लेकिन उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विद्युत आपूर्ति अर्धव्यवस्था में तीव्र गति से बढ़ रही मांग को पूरा नहीं कर पाई। उपलब्धता के अनुसार, विद्युत की आपूर्ति में कमी 1992 के 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 12.0 प्रतिशत हो गई है। वस्तुतः विद्युत उत्पादन की औसत वृद्धि



दर 1990 के दशक के उत्तरार्ध के 6.8 प्रतिशत से कम होकर उसके बाद 4.7 प्रतिशत रह गई है (चार्ट क)।

आपूर्ति में लगातार कमी के कारण हैं - क्षमता में अपर्याप्त वृद्धि, उच्च समग्र और संचारण हानियां, अपर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय संचारण लिंक और ईंधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं। उत्पादन क्षमता की वृद्धि में कमी पिछले तीन वर्ष में सबसे अधिक ताप-विद्युत में हुई (चार्ट ख)। जहाँ दसवीं योजना के दौरान लक्ष्यित क्षमता में 66.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्ष (2007-08 और 2008-09) के दौरान



मात्र 16.2 प्रतिशत की वृद्धि (78,700 एमडब्ल्यू) हुई। 2008-09 में लक्ष्य की तुलना में केवल 4.4 प्रतिशत की प्राप्ति हुई।

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश करने में कई बाधाएं हैं जैसे कि उच्च क्रॉस सब्सिडाइजेशन तथा परिमाणतः विद्युत लागत की निम्न वसूली और उच्च समग्र संचारण तथा वाणिज्यिक हानियां (एटीएण्डसी)। 2007-08 के दौरान, कुल विद्युत सब्सिडी 42,607 करोड़ रुपए थी। 2006-07 में, प्रति यूनिट 2.76 रु. की आपूर्ति की लागत की तुलना में, कृषि सहित वसूली मात्र 2.27 रुपए प्रति यूनिट थी। केवल कृषि क्षेत्र से वसूली 0.71 रु. प्रति यूनिट के स्तर पर बहुत कम थी।

2000 में लागू किए गए ऐक्विस्ट्रेंटेंड पावर रिफार्म एण्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी केंद्रीय योजना के बावजूद अपर्याप्त मीटिंग, चोरी और निम्न वसूली के कारण एटीएण्डसी हानियां हुई हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि के लिए, विशाल विद्युत परियोजनाओं और वाणिज्यिक विद्युत संयंत्रों के विकास, जल विद्युत के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता, विद्युत व्यापार, संचारण तथा विद्युत के वितरण की कुशलता को बढ़ाने के लिए अंतर-राज्य संचारण में मुक्त पहुंच की व्यवस्था और तथा विद्युत लेखांकन के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के क्षेत्र में सुधार शीघ्रता से लाए जाने चाहिए।

संदर्भ :

1. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, (2009): 'हाइलाइट्स ऑफ दि सेक्टर'
2. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, (2008): 'हाइलाइट्स ऑफ दि सेक्टर'
3. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, (2008): 'इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिव्यू', अप्रैल-जनवरी.
4. भारत सरकार, (2009), आर्थिक सर्वेक्षण - 2008-09

सारणी 2.11: मूलभूत संरचना उद्योगों के लक्ष्य और प्राप्ति

क्षेत्र	यूनिट	2007-08			2008-09		
		लक्ष्य	प्राप्ति	अंतर(%)	लक्ष्य	प्राप्ति	अंतर(%)
विद्युत	बिलियन यूनिट	710	704	-0.8	774	724	-6.5
कोयला	मिलियन टन	455	450	-1.0	492	487	-0.9
तैयार इस्पात	000' टन	56984	55240	-3.1	60867	56413	-7.3
रेलवे	मिलियन टन	790	794	0.5	850	833	-2.0
शिपिंग (प्रमुख बंदरगाह)	मिलियन टन	515	519	0.7	576	530	-7.9
उर्वरक	000' टन	16823	14706	-12.6	16332	14334	-12.2
सीमेंट	मिलियन टन	-	174	-	-	187	-
कच्चा पेट्रोलियम	मिलियन टन	35	34	-2.5	36	34	-6.8
पेट्रोलियम	मिलियन टन	146	156	6.7	165	161	-2.4
रिफाइनरी उत्पाद							
प्राकृतिक गैस उत्पादन	मिलियन से.मी.	33241	32274	-2.9	36943	32846	-11.1

स्रोत : सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

अनुसूची के अनुसार चल रही परियोजनाओं की संख्या, जो कुल परियोजनाओं का 27.4 प्रतिशत है, में मार्च 2008 के अंत में दर्ज की गयी 24.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी दी। देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या, जो कुल परियोजनाओं का 52 प्रतिशत है, भी मार्च 2008 के अंत में हुई 35.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 24.1 प्रतिशत बढ़ी। क्षेत्रवार ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा, रेलवे तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विलंबित परियोजनाओं की संख्या बढ़ी है। रेलवे, भूतल परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई देरी का कारण भूमि अभिग्रहण; पर्यावरण संबंधी

अनुमोदन प्राप्त करने; ब्यौरेवार इंजिनियरिंग प्लान को अंतिम रूप देने; व्याप्ति में /उसको अंतिम रूप देने में परिवर्तन; तथा कुछ क्षेत्रों में अनुपूरक मूलभूत संरचना समर्थन के अभाव संबंधी समस्याएं हैं। वैश्विक वित्तीय संकट ने भी अपेक्षित निधियों की अनुपलब्धता तथा निविष्टियों की खरीद के रूप में देरी में अंशदान किया। 2008-09 के दौरान समग्र लागत में 54.2 प्रतिशत की और वृद्धि हो गई, जबकि विलंबित परियोजनाओं के मामले में लागत में हुई और वृद्धि लगभग 95.6 प्रतिशत थी (सारणी 2.12)। मूल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में विलंबित परियोजनाओं की लागत में हुई और वृद्धि, जो हाल के वर्षों में कम हो रही थी, 2008-09 के दौरान बढ़ गयी।

सारणी 2.12: केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

मद	2000-01	2005-06	2006-07	2007-08	2008-2009
1	2	3	4	5	6
1. परियोजनाओं की संख्या (क से घ)	187	396	491	514	552
(क) आगे	5	6	6	16	8
(ख) समय पर	58	113	179	135	151
(ग) विलंबित	65	149	171	232	288
(घ) शुरू किए जाने की तारीख के बिना	59	128	135	131	105
2. कुल परियोजनाओं की लागत वृद्धि (करोड़ रुपये)	40,303	47,337	39,741	40,906	63,065
3. कुल परियोजनाओं की लागत वृद्धि (मूल लागत का %)	36.4	18.2	12.4	11.9	13.7
4. विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि (करोड़ रुपये)	23,374	29,655	20,808	22,351	43,722
5. विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि (मूल लागत का %)	91.6	35.6	19.8	13.9	19.1

टिप्पणी : 100 करोड़ रुपये और अधिक की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को लिया गया है।

स्रोत : सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2.13: औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

वर्ष	आइ.ई.एम.		एलओआइ/डीआइएल	
	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
2003	3,875	1,18,612	102	1,057
2004	5,118	2,67,069	39	381
2005	6,203	3,53,956	24	333
2006	6,261	5,88,550	20	137
2007	3,725	8,27,500	8	74
2008	3,979	15,22,566	4	38
2009*	1,342	4,04,380	0	0

*: मई 2009 तक
 आइईएम : औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन
 एलओआइ : आशय-पत्र
स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,

निवेश माहौल

II.2.44 सितंबर 2008 के मध्य तक वैश्विक संकट के गहराने से पूर्व 2008 में निवेश वातावरण उत्साहवर्धक रहा, जो भारत सरकार को प्रस्तुत किए गये औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन (आइईएम) में दर्शायी गयी 84.0 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है (सारणी 2.13)। तथापि, आइईएमएस प्रस्तुत करने के बाद जारी आशय पत्रों (एलओआइ) के अनुसार, 2008 में प्रस्तावित निवेश नहीं किए जा सके।

व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम

II.2.45 भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्षों से उन्होंने अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और

आधारभूत उद्यमशीलता के निर्माण में अपने योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है। 2007-08 के दौरान, व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र ने उत्पादन के सांकेतिक मूल्य में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि 2006-07 में यह 17.5 प्रतिशत था (सारणी 2.14)। तथापि, इस क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के साथ ही रोजगार वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई तथा वह 2006-07 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 2.9 प्रतिशत रह गई। तदनुसार प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जो श्रम की उत्पादकता और लागत की बचत दोनों क्षेत्रों में वृद्धि दर्शाता है जिससे आर्थिक मंदी के दौरान मार्जिन पर पड़ने वाले दबावों का प्रबंधन किया जा सका।

II.2.46 2007-08 की पहली तिमाही में भारतीय उद्योग में मंदी शुरू हुई जो वैश्विक आर्थिक गिरावट का आधार पाकर प्रबल हो गई, तथा सितम्बर 2008 में वित्तीय संकट का सामना होते ही और भी गहरा गई। इस मंदी में वैश्विक पण्य व्यापार में आई तीव्र गिरावट भी कुछ अंशों तक दिखाई देती है, जिससे विनिर्मित उत्पादों के लिए भारत की बाह्य मांग पर प्रभाव पड़ा। हालांकि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वित्तीय संकट का प्रभाव नरम ही रहा (बॉक्स II.9)।

2009-10 की गतिविधियां

II.2.47 2009-10 की पहली तिमाही (अप्रैल-मई) के दौरान, आइआइपी में हुई वृद्धि में थोड़ा सुधार हुआ तथा वह 3.7 प्रतिशत हो गयी, हालांकि यह पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 5.3 प्रतिशत की तुलना में कम रही। मूल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में 2009-10 के दौरान क्रमशः 6.1 प्रतिशत तथा 7.1

सारणी 2.14: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कार्य-निष्पादन

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5	6	7
इकाइयों की संख्या (लाख में)	15.91	16.97	17.53	18.71	20.98	24.68
रोजगार (लाख व्यक्ति)	264	275	288	300	313	322
स्थायी निवेश (करोड़ रुपये)	1,69,913	1,79,306	1,85,821	1,96,186	2,13,219	2,38,975
उत्पाद का मूल्य (करोड़ रुपये)	3,14,850	3,64,547	4,29,796	4,97,842	5,85,112	6,95,126
एमएसएमई के निर्यात (करोड़ रुपये)	86,013	97,644	1,24,417	1,50,242	1,77,600 P	n.a.

अनु. : अनुपलब्ध अ: अनतिम
स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

बॉक्स II.9

औद्योगिक निष्पादन - चुनिंदा अर्थव्यवस्थाएं

अमरीका में वित्तीय बाजारों में जो उथल-पुथल शुरू हुई वह 2008-09 के दौरान वैश्विक आर्थिक संकट में बदल गयी और विकसित तथा विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों में फैल गयी। सभी देशों के औद्योगिक उत्पाद में गिरावट आई, यद्यपि इसकी प्रबलता अलग-अलग थी (सारणी क)।

अमरीका के औद्योगिक उत्पादन में 2007 के 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008 में 2.2 प्रतिशत की कमी आयी। 2009 की दूसरी तिमाही के दौरान अमरीका में समग्र औद्योगिक उत्पाद में 13.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से गिरावट आयी। उद्योगों की क्षमता का उपयोग करने की दर एक वर्ष पहले के 80.5 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2009 के अंत में 69.3 प्रतिशत की ऐतिहासिक निचाई पर आ गई।

जापान के औद्योगिक उत्पादन में 2007 में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008 में 3.0 प्रतिशत की कमी आयी, जो कि माल सूची पर समायोजन का बढ़ता हुआ दबाव प्रकट करता है। परिवहन उपकरण (जलयान और रोलिंग स्टॉक के अलावा), इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और उपकरणों और सामान्य मशीनरी जैसे उद्योगों के ऋणात्मक योगदान के कारण 2008 की चौथी तिमाही में उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट (-14.3 प्रतिशत) दर्ज हुई। 2008 की चौथी तिमाही में शिपमेंट में 11.8 प्रतिशत की खासी गिरावट दर्ज हुई, जिसमें पूंजीगत माल में सबसे ज्यादा गिरावट रही। 2009 की पहली तिमाही के दौरान उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 33.5 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी, जो 1983 की चौथी तिमाही के बाद न्यूनतम स्तर है। पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन में भी इसी प्रकार की गिरावट देखी गई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आई कमजोरी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन में भी परिलक्षित हुई,

जिसमें 2008 में चीन और कोरिया में औद्योगिक निष्पादन में हुई गिरावट सबसे ज्यादा रही। अन्य ईएमई जैसे मलेशिया और ब्राजील का प्रदर्शन भी धूमिल रहा। 2008 में मलेशिया, जो निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्था है, के औद्योगिक उत्पादन में 0.03 प्रतिशत की मंद वृद्धि हुई, इसकी तुलना में 2007 में वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत थी, इसका कारण निर्यात-उन्मुख उद्योगों में संकुचन होना था। ब्राजील में भी औद्योगिक उत्पादन 2007 के 5.9 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 3.0 प्रतिशत पर आ गया, जिसका कारण पूँजी, मध्यवर्ती और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन जैसे सभी क्षेत्रों में नरमी होना था। उल्लेखनीय बात यह है कि 2009 की दूसरी तिमाही में चीन और भारत की अगुआई में औद्योगिक उत्पादन में कुछ सुधार आया।

भारत में 2008 में औद्योगिक निष्पादन की गति में धीमापन दर्ज हुआ, जबकि इसकी तुलना में विकसित और बहुत सी अन्य उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों ही में उत्पादन में गिरावट रही, इसका कारण यह था कि देशी माँग ने भारत में वृद्धि प्रक्रिया को स्वरूप देने में बड़ी भूमिका निभायी। वर्ष के दौरान पहले ही से लागू कर दिए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2008 में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आइआइपी के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 2009 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में कम हुई परंतु 2009 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में पुनर्जीवित हो गयी। इस प्रकार, हालांकि अधिकांश देशों के औद्योगिक उत्पादन में वैश्विक मंदी के प्रभाव से 2008 में तथा 2009 की पहली तिमाही में तेज गति से गिरावट आयी, तथापि भारत के औद्योगिक उत्पादन में अपेक्षाकृत कम गति से गिरावट आयी। 2009 की दूसरी तिमाही में चीन तथा भारत की अगुवाई में औद्योगिक वृद्धि में कुछ सुधार आया।

सारणी अ: विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का औद्योगिक निष्पादन

(प्रतिशत)

	2006				2007				2008				2009	
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2#
<i>विकसित अर्थव्यवस्थाएं</i>														
जापान	2.6	4.1	4.9	5.7	2.9	2.3	2.6	3.3	2.5	0.8	-1.3	-14.3	-33.5	-27.9
अमरीका	2.1	2.1	3.2	1.7	1.3	1.5	1.4	1.8	1.2	-0.3	-3.2	-6.6	-11.5	-13.2
यूके	2.0	-0.5	0.2	1.5	-0.6	0.9	0.5	1.7	-0.3	-0.7	-1.7	-7.7	-12.7	-11.9
जर्मनी	4.7	6.3	7.1	6.6	8.9	6.7	6.3	5.8	5.3	3.3	0.4	-7.6	-21.8	-19.2
<i>विकासशील अर्थव्यवस्थाएं</i>														
चीन	-13.1	9.3	-0.2	-10.0	अनु.	1.7	12.2	18.7	अनु.	-13.1	-28.5	-63.3	5.1	9.0
दक्षिण कोरिया	10.5	9.0	9.9	4.8	4.1	6.3	6.1	10.9	10.9	8.9	5.6	-11.3	-16.3	-6.1
ब्राजील	3.5	1.6	3.0	3.3	3.8	5.6	6.3	7.9	6.7	5.2	6.3	-6.1	-14.0	-12.3
मलेशिया	5.2	5.5	4.3	3.2	0.6	1.8	2.1	4.5	5.9	3.1	0.2	-9.1	-16.3	-10.7
भारत	8.7	10.5	11.8	11.2	12.5	10.3	8.7	8.3	7.0	5.3	4.7	0.8	0.5	3.7

: 'दि इकोनॉमिस्ट' पर आधारित। अनु - अनुपलब्ध।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी और सीएसओ

संदर्भ:

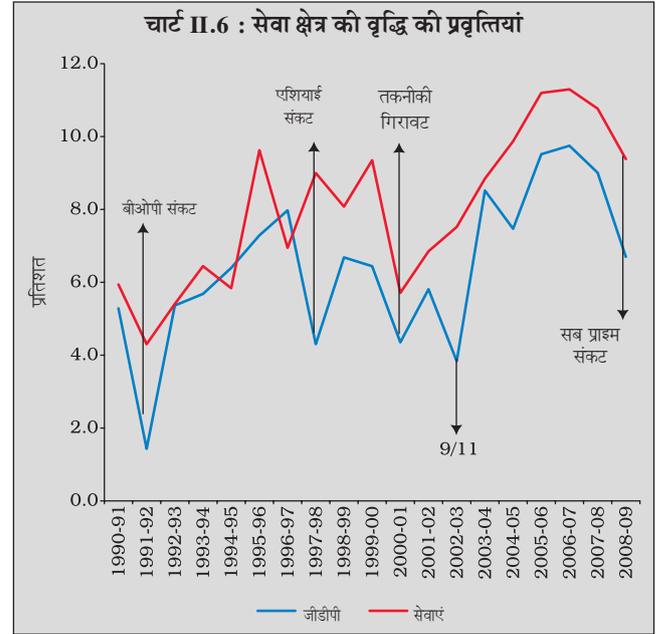
1. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2009), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल
2. बैंक ऑफ जापान (2009), मन्थली रिपोर्ट ऑफ रीसेन्ट इकोनॉमिक एंड फाइनान्शियल डेवलपमेन्ट्स, मार्च
3. बैंक नगारा मलेशिया (2009), इकोनॉमिक एंड फाइनान्शियल डेवलपमेन्ट्स इन मलेशिया इन दि फर्स्ट एन्ड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2009, ओवरव्यू, मई

प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2008-09 की उसी अवधि में उसने 3.1 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में आयी उल्लेखनीय गिरावट के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पिछले साल की तदनु रूप अवधि की 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में (-)0.1 प्रतिशत की कमी आयी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में एक साल पहले के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत माल के उत्पादन में अप्रैल-जून 2008 में हुई 7.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-जून 2009 में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-जून 2009 के दौरान प्रमुख मूलभूत संरचना क्षेत्र में पिछले साल की तदनु रूप अवधि के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गयी। औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न अग्रणी संकेतक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यह सुझाते हैं कि मंदी रुक गयी है तथा आगे उछाल आ सकती है।

सेवा क्षेत्र

II.2.48 विगत कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र ने तेज छलांग लगाते हुए वृद्धि दर्ज की थी, 2008-09 के दौरान इसकी वृद्धि में मामूली धीमापन रहा, जिसका कारण वैश्विक आर्थिक गिरावट का असर था। ऐतिहासिक रूप से भारत में सेवा क्षेत्र ने 1990-91 से ही वृद्धि की समग्र गिरावट की अवधि में भी आघात-सहनीयता दर्शायी है। विगत दो वर्ष को छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि की तुलना में सेवा क्षेत्र की वृद्धि निरंतर उच्चतर रही। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि शेष अर्थव्यवस्था की तुलना में सेवा क्षेत्र वैश्विक वित्तीय संकट से कम ही प्रभावित हुआ प्रतीत होता है (चार्ट II.6)।

II.2.49 2004-05 से ही सेवाओं के उत्पादन में जो तीव्र विस्तार हुआ वह सेवाओं के निर्यात से भी संचालित था। भारत में सेवा क्षेत्र के उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले वैश्विक कारकों का योगदान भारतीय सेवाओं के लिए विदेशी माँग में वृद्धि के रूप में रहा। इसका अप्रत्यक्ष योगदान बढ़ते हुए वैश्वीकरण और लागत में किफायत पर परिणामी दबाव के रूप में था, जिसने व्यवसाय प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों और ज्ञान की आउटसोर्सिंग के दायरे का विस्तार किया। आउटसोर्सिंग बाजार में भारत की तुलनात्मक लाभपरक स्थिति इससे प्रकट होती है कि सेवा क्षेत्र के सकल देशी उत्पाद में सेवाओं के निर्यात



का सकल और निवल अनुपात (सेवा निर्यात घटाव सेवा आयात) 2004-05 के बाद से अच्छा-खासा बढ़ता गया, जिसमें 2007-08 में मामूली गिरावट रही (बॉक्स II.10 और चार्ट II.7)।

II.2.50 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, 2008-09 में सेवा क्षेत्र से प्राप्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि 2007-08 के 10.8 प्रतिशत से घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 2007-08 में 63 प्रतिशत था, जो 2008-09 में मामूली सा बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गया, तथापि जीडीपी की वृद्धि में इसका सापेक्षिक योगदान 74.1 प्रतिशत से अच्छा खासा बढ़कर इसी अवधि में 88.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.15)।

II.2.51 वैश्विक मांग में मंदी विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र के उत्पाद को विभिन्न सरणियों के जरिए प्रभावित करती है (बॉक्स II.10)। 2008-09 के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि में कमी मुख्यतः निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपत्ति और कारोबारी सेवाओं तक सीमित रही। स्थावर संपदा बाजार में मंदी की स्थिति, खर्चने योग्य घरेलू आय में कमी और निजी क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन में धीमेपन से निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कारोबार, वाणिज्य और पर्यटन संबंधी यातायात में कमी के जरिए वैश्विक मंदी का व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वस्तुतः, वाणिज्यिक वाहन

बॉक्स II.10 वैश्विक मंदी और सेवा क्षेत्र

सब-प्राइम के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ होने से पहले, कई विकासशील बाजारों में सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि दिखलायी दी थी, विशेषकर 1990 के दशक के प्रारंभ से। संबंधित देशों के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंश भी उस समय तक काफी प्रमुख हो गया, जब वैश्विक मंदी के प्रभाव ने इस क्षेत्र के निष्पादन और संभावना पर अपना प्रभाव दिखलाना शुरू किया। 1990 के दशक के बाद की अवधि में सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, विशेषकर मध्यम और उच्च आय वाले देशों में, जो जनतांत्रिक थे, जिनके व्यापार में खुलापन था और जो प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्रों के आसपास स्थित थे (आइशनग्रीन तथा गुप्ता, 2009)। भारत में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते समन्वयन, कुशल श्रमशक्ति के साथ-साथ वैश्विक सेवा संबंधी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी में आनुपातिक विकास के कारण सेवाओं के बढ़ते व्यापार और विनियामक व्यवस्था और आर्थिक परिवेश में उदारीकरण जैसे कई कारणों से सेवा क्षेत्र में तेजी आयी। विशेषकर, विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आने से वित्तीय परामर्श, लेखा-परीक्षा, लेखाकरण, विधिक, आतिथ्य, दलाली, आदि की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसके कारण विभिन्न देशों में सेवाओं में परस्पर व्यापार करने के अवसर भी उपलब्ध हुए। 1990 के दशक के प्रारंभ से और विशेषकर 2003-04 से, विदेशों में मांग, विशेषकर आतिथ्य, वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, के कारण हुए निर्यात के कारण सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव आया। लेकिन वैश्विक मंदी के चलते बाह्य मांग कमजोर हो जाने से सेवा क्षेत्र के विकास की गति मंद हो गयी और 2008-09 की पहली तिमाही से और पूरे वर्ष तक इसके विकास की गति मंद रही। लेकिन, 2008-09 की चौथी तिमाही में सेवा क्षेत्र में मंदी और भी स्पष्ट हो गयी। यह मंदी प्रमुख रूप से 'वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपत्ति और कारोबारी सेवाओं' और 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं' के क्षेत्र में थी।

आउटसोर्सिंग बाजार में तुलनात्मक रूप से भारत की श्रेष्ठता को दिखलाते हुए, सेवा क्षेत्र जीडीपी में सेवा निर्यात का अंश, जो कि 1995-2000 के दौरान 5.4 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर 2006-07 में 15.0 प्रतिशत हो गया था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया परंतु 2008-09 में तेजी से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, 1995-2000 के 0.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर निवल सेवा निर्यात 2008-09 में 6.6 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वस्तुतः प्रमुख उभरते बाजार अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश था (सारणी क)।

वर्तमान वैश्विक मंदी से पहले, ऐसा लगता था कि सेवा क्षेत्र में वैश्विक फ्रै लाव जारी रहेगा और भारत एक वैश्विक सेवा 'हब' बन जाएगा। वर्तमान संकट के अभूतपूर्व स्वरूप और कृषि और विनिर्माण उत्पादों की तुलना में आय कम हो जाने से सेवाओं की मांग में कमी हो जाने की अधिक संवेदनशीलता को देखते हुए, सेवा क्षेत्र में पहले वाली

सारणी क : उभरते बाजारों में सेवा क्षेत्र का निष्पादन

(प्रतिशत)

देश	जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंश			सेवा क्षेत्र वृद्धि			जीडीपी वृद्धि		
	2001-05	2006	2007	2001-05	2006	2007	2001-05	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	52	52	52	8.4	11.0	11.0	6.8	10.0	9.0
ब्राजील	65	65	66	2.8	4.0	6.0	2.8	4.0	5.0
चिली	56	49	49	4.2	5.0	6.0	4.2	4.0	5.0
चीन	40	40	40	10.0	12.0	13.0	9.4	12.0	13.0
कोरिया	56	57	58	4.0	4.0	5.0	4.6	5.0	5.0
रूस	59	57	57	6.4	10.0	10.0	6.0	7.0	8.0

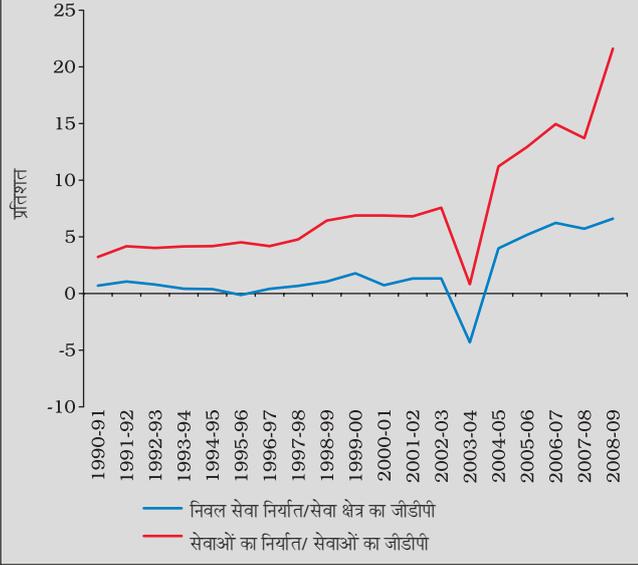
स्रोत : वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, विश्व बैंक।

स्थिति का फिर से आना इस बात पर निर्भर करेगा कि देशी उपभोग और निवेश मांग में वृद्धि होती है या नहीं। भारत जैसे विकासशील देशों में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण सेवाओं पर प्रभाव संबंधी जोखिम मांग में कमी के अलावा कई कारणों से उत्पन्न होती है जैसे कि निजी पूंजी प्रवाहों में कमी और वित्तीय प्रणालियों में विश्वास कम हो जाना, कारोबार विश्वास का कम हो जाना, व्यापारी और वाणिज्य गतिविधियों में कमी हो जाना, नॉलेज आउटसोर्सिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आय के प्रति संवेदनशील मांग का कम हो जाना। अक्सर यह समझा जाता है कि वैश्विक संक्रमण का प्रभाव सबसे पहले शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र सेवा क्षेत्र के साथ बहुत निकटता से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन एक जोखिम यह है कि बहुत ज्यादा शहरी मंदी से श्रमिकों का रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में नौकरी की हानियों और करदाताओं के दबाव के कारण संभावित संरक्षणवाद संबंधी जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा। कुछ देशों में इस तरह के वाक्ये पहले ही हो चुके हैं जिनमें उन्होंने अपने स्थानीय कारोबार और नौकरियों को बचाने के लिए आउटसोर्सिंग सेवाओं के संबंध में संरक्षणवादी नीतियां अपना ली हैं। लेकिन यह भी समझा जाता है कि मंदी का सामना करने के लिए लागत कम करने से ग्राहक अपना काम भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से ऑफशोर करने के लिए भी प्रोत्साहित हो सकते हैं।

संदर्भ :

1. आइशनग्रीन, बी. तथा पी. गुप्ता, (2009): 'द टू वेज ऑफ सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ' एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.14968.
2. सुब्बाराव, डी.(2009): 'इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनान्सिएल क्राइसिस ऑन इंडिया: कोलेटरल डैमेज एंड रेस्पांस', आरबीआई बुलेटिन, मार्च।

चार्ट II.7 : सेवा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली सेवाओं का निर्यात और जीडीपी



सारणी 2.16 : सेवा क्षेत्र की गतिविधि के संकेतक

(वृद्धि दर प्रतिशत)

उप-क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
पर्यटक आगमन	13.0	12.2	-2.5
वाणिज्यिक वाहन उत्पादन#	33.0	4.8	-24.0
माल भाड़ा अर्जक रेलवे राजस्व	9.2	9.0	4.9
नए सेलफोन कनेक्शन	85.4	38.3	44.8
प्रमुख बंदरगाहों पर माल चढ़ाई/उतराई	9.5	11.9	2.1
नागरिक उड्डयन			
निर्यात माल की चढ़ाई/उतराई	3.6	7.5	3.4
आयात माल की चढ़ाई/उतराई	19.4	19.7	-5.7
अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों पर			
यात्री यातायात	12.1	11.9	3.8
देशी टर्मिनलों पर			
यात्री यातायात	34.0	20.6	-12.1
सीमेंट**	9.1	7.8	7.5
इस्पात**	13.1	6.8	0.6

: परिवहन के लिए अग्रणी संकेतक।

** : निर्माण के लिए अग्रणी संकेतक।

स्रोत : पर्यटन मंत्रालय; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; भारतीय रिजर्व बैंक; तथा भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र।

उत्पादन, माल ढुलाई से अर्जित रेलवे के राजस्व, प्रमुख बंदरगाहों पर लादे-उतारे गए माल में न्यूनतर वृद्धि तथा और नागर विमानन क्षेत्र के अधिकांश संकेतक पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मंदी को दर्शाते हैं।

II.2.52 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकटग्रस्त आस्तियों में प्रत्यक्ष एक्सपोजर न होने के बावजूद, वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं में कमी मुख्यतः वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण आई। अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों, आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि और कंपनियों के निष्पादन में कमी संबंधी बाजार की प्रत्याशाओं के कारण मुख्यतः पूंजी बाजार में आए

बड़े करेक्शन की वजह से वित्तीय सेवाओं में भारी कमी दर्ज की गयी। दूसरी ओर, प्रति-चक्रीय राजकोषीय उपायों और छोटे वेतन आयोग की अदायगी के कारण सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गयी। नये सेलफोन कनेक्शनों को छोड़ दें, तो सेवाओं के सभी प्रमुख अंगों में 2008-09 में या तो वृद्धि की गति में कमी हुई या गिरावट देखने में आयी (सारणी 2.16)।

II.2.53 वर्तमान वैश्विक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मंदी के रूप में देखा जा सकता है जिसके कारण श्रम बाजारों में बढ़ती हुई अनिश्चितता के बीच रोजगार में

सारणी 2.15: सेवा क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

(प्रतिशत)

उप-क्षेत्र	वृद्धि दर						2008-09 (संअ)
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	9.4	12.0	10.7	12.1	12.8	12.4	9.0
वित्तपोषण, बीमा, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवाएं	8.0	5.6	8.7	11.4	13.8	11.7	7.8
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	3.9	5.4	6.9	7.0	5.7	6.8	13.1
निर्माण	7.9	12.0	16.1	16.2	11.8	10.1	7.2
सेवा क्षेत्र	7.5	8.8	9.9	11.2	11.3	10.8	9.4
जापन:							
जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा	58.7	58.9	60.2	61.1	62.0	63.0	64.5
जीडीपी की वृद्धि में सापेक्ष अंशदान	111.1	60.9	77.7	70.8	70.8	74.1	88.2
संअ: संशोधित अनुमान							
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन							

उल्लेखनीय कमी आयी है। यदि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाए गये अनुमान के अनुसार स्थिति में जल्द ही सुधार नहीं होता, तो श्रम बाजारों को और भी अधिक विकट परिस्थितियों का सामना

करना पड़ेगा। वैश्विक मंदी के कारण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से मंदी की जोखिम और नीति को लेकर चिंता बनी रहेगी (बॉक्स II.11)।

बॉक्स II.11

भारत में बेरोजगारी पर वैश्विक मंदी का प्रभाव

वैश्विक मंदी का एक चिंताजनक प्रभाव यह रहा है कि श्रम बाजारों में बेरोजगारी और अनिश्चयता बढ़ी है, विशेषकर उन्नत देशों में। इससे एक दुष्चक्र प्रारंभ हो गया है, जहां समग्र मांग में कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है और नौकरियों के बारे में अनिश्चयता हो जाती है, जिसके कारण समग्र मांग में कमी की दर बढ़ जाती है। भारत में, रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर श्रमिकों के एक बहुत बड़े तबके द्वारा निर्भर रहने के कारण, 2008-09 के दौरान कृषि क्षेत्र के आघात-सह बने रहने के कारण रोजगार का ऋणात्मक प्रभाव कुछ कम ही रहा है, लेकिन वृद्धि में धीमेपन के प्रतिकूल रोजगार प्रभाव नीति के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं, जो कि भारत में उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश के बारे में चिंता के बावजूद सरकार द्वारा पहले से किए गए उत्प्रेरक उपायों के आकार और उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है।

इधर-उधर से उपलब्ध रिपोर्टें यह बतलाती हैं कि रोजगार प्रधान लघु और मध्यम उद्यमों को संकट से बहुत हानि पहुंची है, और शहर से गाँवों की ओर रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण जनता की असुरक्षितता बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गये विप्रेषण कम हो रहे हैं जिसके कारण विप्रेषण पाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में आय/रोजगार में और कमी हुई है। चूंकि आउटपुट में वृद्धि होने के बाद भी श्रम बाजारों की स्थिति में सुधार कुछ समय बाद ही होता है इसलिये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित 2010 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ कमजोर-सा सुधार रोजगार की स्थिति के लिए बहुत बुरा हो सकता है जिसके गंभीर सामाजिक और राजनैतिक परिणाम होंगे (आइएलओ, अप्रैल 2009)।

मई 2009 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 'ग्लोबल एम्प्लायमेंट ट्रेन्ड रिपोर्ट' के अनुसार, संभवतया 2009 में वैश्विक बेरोजगारी में बहुत अधिक वृद्धि होगी, विशेषकर श्रम प्रधान निर्यात वाले विकासशील देशों में। बेरोजगारी की दर में 2007 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2009 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सबसे खराब परिदृश्य में, यह बढ़कर 7.1 प्रतिशत (अथवा 50 मिलियन जनता) तक जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि सुभेद्य रोजगार में लगे हुए लोगों का अनुपात काफी बढ़ सकता है तथा सबसे खराब परिदृश्य में यह नियोजित आबादी के 53 प्रतिशत के स्तर तक जा सकता है। दक्षिण एशिया में बेरोजगारी का स्तर 32.2 मिलियन होने का अनुमान है तथा मंदी की मात्रा के आधार पर 2009 में यह 32.6 - 32.1 मिलियन के बीच बदल सकता है। रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया कि 2009-10 में भारत की बढ़ती श्रमशक्ति के अवशोषण के लिए अनुमानित 20.3 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों की जरूरत होगी। महिलाओं तथा युवा श्रमशक्ति पर सर्वाधिक असर पड़ेगा। वस्तुतः, वैश्विक बाजार में अधिक एक्सपोजर रखने वाले क्षेत्रों में, जिनमें लाखों महिला कर्मचारी काम करते हैं, विशेष रूप से नागरिक उड्डयन, वस्त्र,

चमड़ा, तथा रत्न और आभूषण क्षेत्रों में भारतीय कामगारों को पहले ही नौकरियां गंवानी पड़ चुकी हैं। रिपोर्ट में ऐसे सार्वजनिक व्यय संबंधी कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया गया जिसका रोजगार पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ेगा।

आर्थिक मंदी के संदर्भ में बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए, श्रम मंत्रालय में अक्टूबर-दिसंबर 2008 तथा जनवरी-मार्च 2009 की अवधि के लिए दो त्वरित तिमाही सर्वेक्षण कराए, जिनमें 21 केंद्रों (10 राज्य/संघ शासित क्षेत्र) तथा खनन, वस्त्र, धातु, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल, परिवहन तथा आइटी/बीपीओ जैसे सेक्टर को कवर किया गया जिनमें जीडीपी का 60 प्रतिशत से अधिक भाग शामिल हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2008 में लगभग आधे मिलियन श्रमिक अपनी नौकरी खो बैठे, जबकि जनवरी-मार्च 2009 में रोजगार में चौथाई मिलियन से लगभग आधे की वृद्धि हुई। सितंबर 2008 में सभी क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार 16.2 मिलियन से कम होकर दिसंबर 2008 में 15.7 मिलियन रह गया। 2008-09 की तीसरी तिमाही में रोजगार की वृद्धि दर (-) 3.03 प्रतिशत थी। क्षेत्रवार, अक्टूबर-दिसंबर 2008 में आइटी/बीपीओ क्षेत्र को छोड़कर रोजगार में कमी सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ी, जबकि रत्न और आभूषण, वस्त्र, आइटी/बीपीओ, हथकरघा/पावरलूम और ऑटोमोबाइल में जनवरी-मार्च 2009 में रोजगार बढ़ गया।

मंदी का सामना कर रहे क्षेत्रों में वृद्धि का संवर्धन करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें प्रमुख उपाय हैं - हथकरघा और कारपेट के लिए दो नए मेगा क्लस्टर की स्थापना, श्रम प्रधान निर्यात-मुख्य क्षेत्रों के लिए पोतलदानपूर्व ऋण पर ब्याज सहायता, चुनिंदा निर्यातों के लिए ईसीजीसी कवर में वृद्धि तथा आधारभूत सीमाशुल्क में कटौती और सेवा कर में छूट। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) (144 प्रतिशत की वृद्धि), भारत निर्माण (45 प्रतिशत की वृद्धि), राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (23 प्रतिशत की वृद्धि), जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) (87 प्रतिशत की वृद्धि) के लिए संसाधनों का आबंटन बढ़ाने से 2009-10 में विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में, अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जाने की भी संभावना है।

संदर्भ:

1. भारत सरकार, 2008. रिपोर्ट ऑन इफेक्ट ऑफ इकॉनॉमिक स्लोडाउन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अक्टूबर-दिसंबर।
2. भारत सरकार (2008), रिपोर्ट ऑन इफेक्ट ऑफ इकॉनॉमिक स्लोडाउन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जनवरी-मार्च।
3. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, 2009. ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेन्ड्स. जनवरी।

11.2.54 1990 के दशक के दौरान, निर्यात के पक्ष में सेवा उत्पादों में आया संरचनात्मक बदलाव प्रौद्योगिकी द्वारा चालित वैश्विक समन्वयन के साथ 2003-04 से अधिक स्पष्ट रूप में दिखने लगा, जिससे देश में ही भारतीय सेवाओं की मांग बढ़ी। अलबत्ता, सब-प्राइम संकट के आने से इसकी गति में कुछ कमी देखने में आयी। हालांकि, आंतरिक मांग के कारण सेवा क्षेत्र के विकास में तेजी आयी है, लेकिन खुलेपन और वैश्विक अर्थ व्यवस्था के साथ समन्वयन के कारण इसे वैश्विक गतिविधियों से पूरी तरह अलग करना कठिन हो गया।

2009-10 की गतिविधियां

11.2.55 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र संबंधी कार्यकलाप के अग्रणी संकेतक यह सुझाते हैं कि कुछ खण्डों को छोड़कर शेष में वृद्धि की गति में गिरावट आएगी। व्यापार संबद्ध सेवाओं में यथा प्रमुख समुद्र और एयरपोर्ट पर चढ़ाए-उतारे गए माल, तथा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों में संभाले गए यात्रियों में अप्रैल-मई 2009 के दौरान कमी/ऋणात्मक वृद्धि बनी रही। देशी कार्यकलाप-संबद्ध सेवाओं यथा संचार, निर्माण तथा ऑटोमोबाइल खण्ड में उछाल के कुछ संकेत देखे गए।

समग्र मांग

11.2.56 अत्यंत समकालिक वैश्विक मंदी में भारतीय वृद्धि की सापेक्ष आघात-सहनीयता का कारण है - भारत में समग्र वृद्धि परिणामों को आकार देने में बाह्य मांग की तुलना में देशी मांग की

अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका। 2008-09 में उपभोग और निवेश दोनों ही के रूप में देशी मांग भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का मुख्य चालक बनी रही। राष्ट्रीय आय के मांग पक्ष में उपभोग व्यय का अंश काफी अधिक था और सकल देशी उत्पाद में इसका अंश 66.6 प्रतिशत था। 2008-09 में सकल देशी उत्पादन में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का अंश 55.5 प्रतिशत था, जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का अंश 11.1 प्रतिशत था। इसी अवधि में सकल देशी उत्पाद में सकल पूंजी निर्माण का अंश 36.6 प्रतिशत था (सारणी 2.17)।

11.2.57 सकल देशी उत्पाद के लिए पीएफसीई के काफी महत्त्व को देखते हुए उल्लेखनीय है कि पीएफसीई की वृद्धि दर में काफी कमी आयी और वह 2007-08 के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में केवल 2.9 प्रतिशत रह गयी (सारणी 2.18)। कमी के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह वृद्धि काफी अधिक थी, निजी उपभोग व्यय लगभग स्थिर रहा - 2008 में सिर्फ 0.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि।

11.2.58 2007-08 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में, भारत में जीएफसीई में तेज वृद्धि दर्ज की गई और वह दुगुनी से अधिक होकर 2008-09 में 20.2 प्रतिशत हो गयी, जिसका कारण छोटे वेतन आयोग के अधिनिर्णय के कारण हुए भुगतान और अन्य प्रति-चक्रीय राजकोषीय प्रेरक उपाय थे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए, 2007 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में 2008 में सार्वजनिक उपभोग 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

सारणी 2.17 : सकल देशी उत्पाद का मांग पक्ष-हिस्से @ (1999-2000 कीमतें)

(बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत में)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 त्वअ.	2008-09 संअ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल अंतिम उपभोग	76.7	75.6	73.6	71.5	69.8	67.6	67.0	66.6
निजी अंतिम उपभोग व्यय	64.5	63.9	62.5	60.9	59.5	57.7	57.2	55.5
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	12.2	11.7	11.1	10.6	10.3	9.9	9.8	11.1
सकल देशी पूंजी निर्माण #	22.2	25.0	27.1	30.5	33.3	34.4	35.9 ^	36.6^
निवल निर्यात	0	1.4	0.3	1.1	-2.5	-3.5	-4.4	-5.8

@ : सांख्यिकीय विसंगति के कारण हो सकता है कि हिस्सों का जोड़ जीडीपी के बराबर न हो।
त्वअ. : त्वरित अनुमान संअ : संशोधित अनुमान
: भूल चूक के लिए समायोजित। ^: सकल पूंजी निर्माण।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

सारणी 2.18 : जीडीपी का मांग पक्ष - वृद्धि दरें #
(1999-2000 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	त्वअ	2008-09 संअ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. कुल अंतिम उपभोग व्यय जिसमें से:	5.2	2.3	5.5	5.2	6.7	6.3	8.3		5.4
(i) निजी अंतिम उपभोग	5.7	2.8	6	5.5	6.8	6.4	8.5		2.9
(ii) सरकारी अंतिम उपभोग	2.3	-0.4	2.6	3.6	6.2	5.5	7.4		20.2
2. कुल निवेश+	-3.5	-2.9	17	19.9	19.5	19.4	10.9		8.3 [^]
(i) निजी निवेश++	4.1	18.4	14.4	24.6	19.6	13.6	12.9		n.a.
(ii) सार्वजनिक निवेश ++	3	-7	8.3	14.7	21.5	14.7	24.6		n.a.
(iii) मूल्यवान वस्तुएं ++	-5.4	-4.2	66.6	57.2	-2.2	14.9	2.7		27.5
3. कुल नियत निवेश जिसमें से:	0	7.4	6.6	13.7	18.9	17.4	12.9		8.2
(i) निजी नियत भाग	8.9	8.9	14.6	23.6	17.5	13.1	10.8		n.a.
(ii) सार्वजनिक नियत भाग	3.6	1.3	10.8	5.2	18.1	19.3	19.7		n.a.
4. निर्यात	5.7	21.8	7.4	27.2	17.6	21.1	2.1		12.8
5. घटाएं आयात	3.4	10.4	16.3	22.2	41.1	24.5	6.9		17.9

: बाजार कीमतों पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद की चयनित व्यवस्था पर आधारित. त्वअ : त्वरित अनुमान संअ : संशोधित अनुमान
+ : भूलचूक हेतु समायोजित. ^ : सकल पूंजी निर्माण ++ : भूलचूक हेतु असमायोजित. अनु : अनुपलब्ध.
टिप्पणी : 'मूल्यवान वस्तुओं' में कलाकृतियों और प्राचीन कृतियों को छोड़कर मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण पर किया गया व्यय शामिल है।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

II.2.59 2008 में अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सकल अचल पूंजी निर्माण में कमी देखने में आयी। भारत में सकल अचल पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय कमी हुई और वह 2007-08 में 12.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 8.2 प्रतिशत रह गयी। इसे सहज चलनिधि स्थितियों के बावजूद भारतीय उद्यमों के सामने वित्तीय संकटों और वित्त देने वाली संस्थाओं द्वारा जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति तथा निवेश मांग को कम करने वाले निवेशकों के विश्वास में काफी कमी के रूप में देखा जाना चाहिए। 2008-09 की क्रमिक तिमाहियों में निवल निर्यात अंतर में वृद्धि का भी समग्र सकल देशी उत्पाद वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा।

II.2.60 2008-09 के दौरान, उपभोग व्यय के भीतर संरचनागत बदलाव आया। समग्र वृद्धि में पीएफसीई का अंशदान 2007-08 के 53.8 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2008-09 में 27.0 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, समग्र वृद्धि में जीएफसीई का अंशदान 2007-08 के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 32.5 प्रतिशत हो गया तथा इसने पीएफसीई में आयी मंदी के वृद्धि प्रभाव को अंशतः प्रतितुलित कर दिया। फलस्वरूप, वृद्धि के प्रति उपभोग

मांग का समग्र अंशदान 2007-08 के 61.8 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2008-09 में 59.5 प्रतिशत रह गया।

II.2.61 देशी मांग के आधिक्य के कारण ही, भारत पहले संकट की घड़ियों में और अब वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद न केवल उच्च वृद्धि दर बनाये रखने में सफल रहा, बल्कि यही कारण है कि विगत में सभी संकटों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत अधिक शीघ्रता से संकट से उबर पाया है।

II.2.62 प्रमुख बाह्य आघातों की पिछली घटनाओं के दौरान समग्र मांग के उप-घटकों की प्रवृत्ति यह दिखलाती है कि देशी निवेश व्यय में कमी के कारण समग्र मांग और आय की वृद्धि में कमी होती है। वीएआर अनुमानों के माध्यम से प्राप्त 'वेरिएन्स डिकम्पोजिशन' परिणाम यह दिखलाते हैं कि हालांकि हाल ही में, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी समन्वित हो गई है, लेकिन फिर भी देशी मांग का वर्चस्व बना हुआ है। हालांकि, निवेश व्यय पर निर्यात का प्रभाव सकारात्मक और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सापेक्ष रूप में यह उपभोग व्यय के प्रभाव की तुलना में कम महत्वपूर्ण बना हुआ है (बॉक्स II.12)।

बॉक्स II.12

वित्तीय संकट और आर्थिक वृद्धि : अंतर-कालिक परिप्रेक्ष्य

विकास के आकलन में आघातों का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण अंश है और 1970 के दशक से, वैश्विक अर्थव्यवस्था को आपूर्ति संबंधी कई आघातों का सामना करना पड़ा है। साहित्य में मांग और आपूर्ति आघातों, देशी और बाह्य आघातों, देश विशिष्ट और वैश्विक आघातों, सांकेतिक (मौद्रिक) और वास्तविक आघातों आदि के बीच अंतर किया गया है। नव शास्त्रीय विचार धारा के अनुसार, आघात अल्पकालिक समग्र मांग और आपूर्ति में अप्रत्याशित परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और इसलिए, अल्पकालिक वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव बढ़ाते हैं।

यदि कुछ वैश्विक वित्तीय संकटों के कालक्रम और भारत में चुनिंदा समष्टि आर्थिक समुच्चयों पर उनके प्रभाव को देखा जाए, तो संकट के दौरान संभावित स्तर की तुलना में उत्पाद और निवेश में स्पष्ट गिरावट देखी जा सकती है। भारत में, एशियाई संकट के दौरान केवल तीन तिमाहियों में डॉटकॉम विस्फोट के दौरान पांच तिमाहियों में, ही वास्तविक उत्पाद (वाइ) संभावित उत्पाद (वाइ*) की तुलना में कम रहा, जिसका आंशिक कारण निवेश में तीव्र गिरावट तथा औसत से कम मानसून होना था (चार्ट क)।

वर्ष 2000 में डॉटकॉम विस्फोट के कारण हुए संकट के दौरान भारत में उत्पाद-अंतर (अर्थात् संभावित की तुलना में वास्तविक) बढ़कर - 30.8 प्रतिशत हो गया (सारणी क)। वर्तमान वैश्विक संकट के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह अभी चल रहा है और इसलिए उत्पाद हानि का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत के निर्यात, निवेश और उपभोग पर और इसलिए व्यापार, वास्तविक और कारोबार विश्वास चैनलों के बीच परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से परिचालित वृद्धि वैश्विक संकट के संभावित प्रभाव का आकलन निवेश, निर्यात और उपभोग अवधि 1996-97 (क्यू1) से 2008-09 (क्यू3) के लिए वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (वीएआर) द्वारा किया गया। इस प्रकार के आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है कि निर्यात (बाह्य मांग) और उपभोग (देशी मांग) किस हद तक निवेश मांग को प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत में निवेश व्यय पर निर्यात का प्रभाव सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उपभोग व्यय के प्रभाव की तुलना में कम है। चौलेस्की वेरिएन्स डिकम्पोजिशन से पता चलता है कि उपभोग की तुलना में निर्यात द्वारा स्पष्ट किए गए निवेश में उतार-चढ़ाव कम होता है।

सारणी क : चुनिंदा समष्टि आर्थिक घटबढ़ पर वित्तीयसंकट का प्रभाव

(संभाव्यता प्रतिशत)

संकट का स्वरूप	अवधि	पीएफसीई अंतर	निवेश अंतर	बचत जीडीपी अंतर	जीडीपी अंतर
1	2	3	4	5	6
पूर्वी एशियाई संकट	1997	-32.4	14.4	5.1	-27.7
	1998	28.8	-59.8	-52.5	10.7
डॉटकॉम विस्फोट	2000	-34.7	-92.7	-80.5	-30.8
वैश्विक वित्तीय संकट	2008				-18.9
	2008*				-22.9

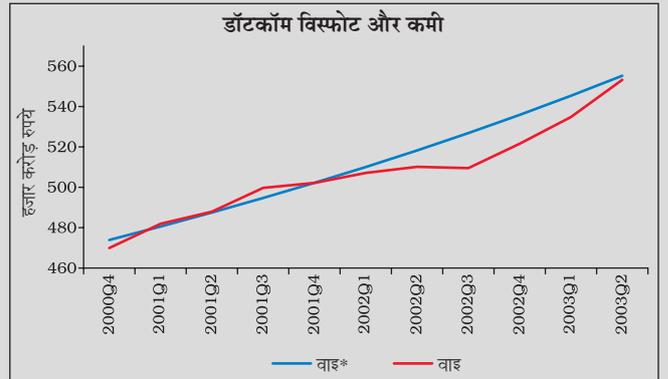
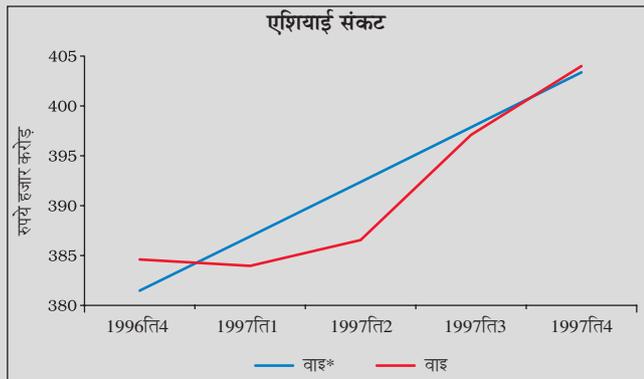
*: यदि जीडीपी में वास्तविक वृद्धि 6.6 प्रतिशत हो।

नोट : वृद्धि दर पर एचपी फिल्टर लगाया गया ताकि वृद्धि का वियोजन प्रवृत्ति और चक्रीय घटकों में किया जा सके।

संदर्भ

1. बी.बी.भट्टाचार्य और सब्यसाची कार (2005) 'शॉक्स, इकॉनॉमिक ग्रोथ एण्ड दि इंडियन इकॉनॉमी'। www.imf.org/external/np/res/seminars/2005.
2. लुकास, रोबर्ट ई., ज्यु.(1988) 'ऑन दि मैकैनिक्स ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट'। *जरनल ऑफ मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स* 22(1),3-42.
3. प्रीचेट्टु, लॉन्ट(2000) 'अन्डरस्टैंडिंग पॅटर्न्स ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ: सर्चिंग फॉर हिल्स अमंग प्लॅटूस, माउन्टेन्स, एण्ड प्लेन्स दि वर्ल्ड बैंक इकॉनॉमिक रिव्यू 14(2), 221-50.
4. रॉड्रीक, दानी (1999) 'व्हेअर डिड ऑल दि ग्रोथ गो?: एक्स्टर्नल शॉक्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एण्ड ग्रोथ कोलॅप्सेस' *जरनल ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ*, 4, 358-412.

चार्ट क: संभावित और वास्तविक उत्पाद में चलन



II.2.63 इस संकट के प्रारंभ होने के पहले ही, यह समझ लिया गया था कि निरंतर बढ़ते वैश्विक असंतुलन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं और संकट के बाद, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पलटते बिना संकट से सीख लेते हुए वृद्धि की रणनीतियों को पुनःसंतुलित करने पर गंभीर रूप से विचार करना आवश्यक हो जाएगा। कई देशों में भविष्य में ऐसे आघातों से देश की आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों के जरिए वृद्धि का पुनःसंतुलन जरूरी हो सकता है (बॉक्स II.13)।

बचत और पूंजी निर्माण

II.2.64 2002-03 से भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल देशी बचत में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही है। यह वृद्धि राजकोषीय समेकन में प्रगति के कारण निजी कंपनी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़े हुए अंशदान के कारण 2007-08 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। 2006-07 के 35.7 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत 2007-08

बॉक्स II.13

आर्थिक मंदी का प्रबंधन : विकास को पुनः संतुलित करना

निरंतर बने हुए वैश्विक असंतुलन वर्तमान संकट का प्रमुख कारण हैं। कुछ देशों में अनुपयुक्त नीतियों और विनियामक फ्रेमवर्क के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है लेकिन अपर्याप्त उपभोग क्षमता के चलते कुछ देशों में बचत के आधिक्य, तथा कुछ अन्य देशों में देशी बचत की तुलना में अत्यधिक उपभोग और निवेश के कारण भी ये असंतुलन उत्पन्न हुए हैं। अब इस बात पर मतैक्य है कि वैश्विक संकट का सामना करने, इसके प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने और भावी आघातों के संबंध में विभिन्न देशों की आघात-सहनीयता को मजबूत करने के लिए कई देशों में वृद्धि को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता है। संकट के बीच, विशेष रूप से आधिक्य वाले देश, देशी मांग में वृद्धि के संवर्धन के लिए उच्चतर व्यय के माध्यम से वृद्धि को फिर से संतुलित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। देश विशेष जैसी परिस्थितियां जैसे कि देशी बाजार का आकार, निर्यात पर निर्भरता और उसमें वृद्धि की संभावना, राजकोषीय गुंजाइश, आय असमानता, भुगतान संतुलन में चालू खाते की स्थिति के लिए उत्तरदायी अंतर्निहित कारण और अन्य कई आर्थिक घटक पुनःसंतुलन के मार्ग और उसकी गति को निर्धारित कर सकते हैं।

अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2009 में एशियाई विकास बैंक ने मांग में वृद्धि करने और संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए एशियाई देशों के लिए निम्नलिखित पुनर्संतुलन नीतिगत उपाय अपनाने का सुझाव दिया है:

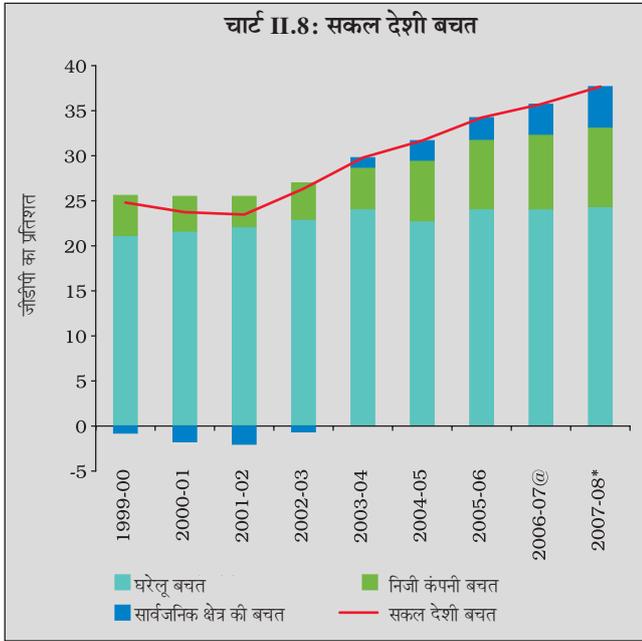
- सुदृढ़ देशी उपयोग के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो कि कंपनियों की बचत को घरेलू बचत की ओर ले जाएं तथा जो घरेलू बचत के लिए पूर्वसतर्कता संबंधी प्रेरणा में कमी करें।
- सरकारें निवेश परिवेश में सुधार लाने को प्राथमिकता दें न कि निवेश की मात्रा बढ़ाने को।
- कुछ और अधिक सक्रिय राजकोषीय नीति अपनाकर अल्पकाल में बाह्य मांग की कमजोरी दूर की जा सकती है, साथ ही, दीर्घावधि में कुछ और अधिक मजबूत देशी मांग का भी मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

- आपूर्ति संबंधी ऐसी नीतियां जो लघु और मध्यम आकार के उद्यमों और सेवा उद्योग को बढ़ावा देती हैं, वे ऐसे उत्पादन के सापेक्ष महत्व को बढ़ा सकती हैं जिनके कारण देशी मांग को पूरा किया जाता है।
- वित्तीय विकास और विनिमय दर के संबंध में नीतियां आपूर्ति और मांग दोनों ही के समायोजन को सहज कर सकती हैं जिससे कुछ और अधिक संतुलित विन्यास प्राप्त होगा।

प्रसाद (2009) के अनुसार संभावित विकास असंतुलनों के कुछ और पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था उपभोग द्वारा नियंत्रित होती है या निवेश द्वारा, वह इस बात का निर्धारण करेगी कि विकास को फिर से संतुलित करने के लिए किस तरह के उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके घरेलू श्रम आय, रोजगार तथा समग्र कल्याण के लिए निहितार्थ हैं। प्रसाद द्वारा विकास को संतुलित करने के लिए सुझाये गये उपाय हैं: (क) सामाजिक सुरक्षा उपायों और अन्य सरकारी बीमा क्रियाविधियों पर व्यय में वृद्धि ताकि ऐहतहाती बचतों को कम किया जा सके और उपभोग में वृद्धि की जा सके; (ख) और अधिक कुशल जोखिम साझेदारी के लिए, वित्तीय बाजार का विकास, उपभोग की अंतर-कालिक सहजता तथा आय और आस्तियों के संबंध में अवसरों का विविधीकरण; (ग) पूंजी के इष्टतम आबंटन और कुशल जोखिम साझेदारी के लिए वित्तीय प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना जिससे उद्यमों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा; (घ) बेहतर उपभोग और बचत के लिए वित्तीय समावेशन में वृद्धि करना; (ङ) एक अधिक नम्य विनिमय दर प्रणाली जिसमें विनिमय दर व्यापार संबंधी भागीदारों के संबंध में उत्पादकता वृद्धि के अंतरों के प्रति रेस्पांड करे, जिससे व्यापार शर्तों के परिवर्तनों के माध्यम से समृद्धि आए।

संदर्भ:

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक (2009) एशियन डेवलपमेंट आउटलुक
2. प्रसाद, ईश्वर (2009) रिबैलेन्सिंग ग्रोथ इन एशिया
3. ब्लांचार्ड, ओलिवियर जे तथा फ्रान्ससिस्को जीएवाजी (2006) रिबैलेन्सिंग ग्रोथ इन चाइना: ए थ्री-हैन्डेड एप्रोच, सीईपीआर डिस्कशन पेपर सं.5403.



में बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गयी। निजी कंपनी बचत दर में लगातार छठे वर्ष में सुधार हुआ जो कि कंपनियों का बेहतर निष्पादन और उच्चतर अर्जन धारिता दिखलाता है। घरेलू क्षेत्र की बचत में भी मामूली-सी वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत - जिसमें 2003-04 की अवधि से पहले अप-बचत की स्थिति से निकलकर सकारात्मक बचत देखने में आयी थी - मुख्य रूप से गैर-विभागीय तथा विभागीय उद्यमों में उच्चतर बचत के परिणामस्वरूप थी, जिसमें 2007-08 में क्रमिक लेकिन महत्वपूर्ण सुधार दिखायी दिया (चार्ट II.8)।

II.2.65 2007-08 के दौरान देशी बचत दर में सकल देशी उत्पाद के 2.0 प्रतिशत अंकों का सुधार आया, लेकिन देशी निवेश में

सकल देशी उत्पाद के 2.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। देशी बचत से निवेश के 95 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण हुआ, और शेष का वित्तपोषण पूंजी प्रवाहों द्वारा हुआ। 2006-07 में 36.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में देशी निवेश दर सकल देशी उत्पाद के 39.1 प्रतिशत पर पहुंच गयी(सारणी 2.19)।

II.2.66 सकल देशी बचत और निवेश के अनुमान हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं क्योंकि आय स्तरों और बचत प्रवृत्ति के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेज संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। भारत के पिछले अनुभव और वैश्विक असंतुलों के वृहद् प्रभाव से प्राप्त सबक को देखते हुए बाह्य खाते के प्रबंधन पर बहुत ज्यादा दबाव न बनाते हुए, उच्च विकास प्राप्त करने के लिए देशी बचत में किस हद तक विदेशी पूंजी की सहायता ली जा सकती है, यह मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। रिजर्व बैंक ने सरकार को सुझाव दिया था कि बचत और निवेश संबंधी आंकड़ों के संकलन की पद्धति में सुधार लाने सहित अनुमान लगाने की क्रियाविधियों की समीक्षा करने और मजबूत तरीके से घरेलू बचत का अनुमान लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। इस मुद्दे की महत्ता को समझते हुए, भारत सरकार ने *हाई लेवल कमिटी ऑन ऐस्टिमेशन ऑफ सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट* (अध्यक्ष: डॉ.सी.रंगराजन) नियुक्त की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 मार्च 2009 को प्रस्तुत कर दी (बॉक्स II.14)।

II.2.67 नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2008-09 में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतें (निवल) वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 10.9 प्रतिशत थीं, जो 2007-08 के 11.5 प्रतिशत के अनुमान से कम है

सारणी 2.19: सकल पूंजी निर्माण

(वर्तमान बाजार मूल्यों पर)

(जीडीपी का प्रतिशत)

क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र	12.6	12.7	12.7	12.4	12.4	12.6
2. निजी कंपनी क्षेत्र	5.9	6.8	10.8	13.7	14.8	15.9
3. सार्वजनिक क्षेत्र	6.1	6.3	6.9	7.6	8	9.1
4. मूल्यवान वस्तुएं	0.6	0.9	1.3	1.2	1.2	1.1
5. सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#	25.2	27.6	32.1	35.5	36.9	39.1
6. निवल पूंजी प्रवाह	-1.2	-2.2	0.4	1.2	1.1	1.4

*: त्वरित अनुमान #: भूल-चूक के लिए समायोजित।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

बॉक्स II.14

बचत और निवेश के संबंध में अनुमान पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

(अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन)

पृष्ठभूमि

बढ़ती देशी बचत और निवेश तथा पूंजी अंतर्वाहों में वृद्धि के आधार पर जब भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आर्थिक विकास के दौर में थी, तब डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में बचत और निवेश के अनुमान पर एक उच्च स्तरीय समिति 12 दिसंबर 2007 को गठित की गयी। समिति ने विचारणीय विषयों की एक लंबी सूची पर विचार किया जिनमें संकलन संबंधी क्रियाविधि और आंकड़े संबंधी मुद्दे शामिल थे। उक्त समिति ने समन्वित आय और व्यय सर्वेक्षणों के माध्यम से सीधे ही घरेलू बचत का अनुमान लगाने, कंपनी निवेश और बचत के अनुमान के लिए पद्धतियों और क्रियाविधियों में सुधार लाने; अनुमानों, आदि की विश्वनीयता या वैधता की जांच करने में सुधार के लिए तैयार किए जाने वाले नए आंकड़ा आधार, यदि कोई हो, का सुझाव देने की संभावना, की जांच की।

दृष्टिकोण

समिति ने क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाया और, जहां तक संभव हो, बचत और निवेश के नमूना-आधारित अनुमानों के स्थान पर जनगणना आधारित अनुमानों की ओर शिफ्ट करने की सिफारिश की। समिति ने शीर्ष संस्थाओं और राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के साथ भी विचार विमर्श किया और कुछ संस्तुत परिवर्तनों के नमूना अनुमानों पर भी कार्य किया। यह पिछली समितियों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से अलग था।

प्रमुख सिफारिशें

1. घरेलू बचत

- घरेलू बचत के संबंध में अनुमान लगाने की वर्तमान अप्रत्यक्ष पद्धति जारी रह सकती है क्योंकि एक स्वीकार्य, व्यावहारिक और वैकल्पिक पद्धति उपलब्ध नहीं है।
- चूंकि घरेलू क्षेत्र एक सम्मिलित इकाई है जिसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही शामिल हैं, जिनकी बचत प्रवृत्ति में उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हैं, इसलिए समिति द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण का उद्देश्य यह था कि घरेलू क्षेत्र के लिए आवधिक व्यापक आय-व्यय सर्वेक्षणों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया जाए।
- उद्यम सर्वेक्षणों के साथ, यह आशा है कि उपभोक्ता घरेलू इकाइयों के लिए घरेलू बचतों का प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्ध कराया जाए जैसा कि कई उन्नत देशों में होता है और वर्तमान अवशिष्ट आधारित अनुमानों के प्रति-वैधीकरण में भी सहायता दी जाए।

2. निजी कंपनी क्षेत्र बचत

- वर्तमान में अपनायी जा रही बचत और निवेश के अनुमान लिए नमूना आधारित पद्धति के स्थान पर जनसंख्या आधारित क्रियाविधि अपनायी जाये।
- इस संबंध में समिति कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ ई-गवर्नन्स अरेन्जमेंट (एमसीए 21) के अधीन उनका डेटाबेस नियमित आधार पर शेयर करने के लिए समझौता कर रही है ताकि निजी कंपनी क्षेत्र बचत और निवेश की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सके।
- उच्च स्तरीय समिति सिफारिश करती है कि 2010-2011 से बचत और निवेश के अनुमान, ब्लो-अप फैक्टर पद्धति के स्थान पर, सभी कंपनियों के लिए एमसीए 21 का उपयोग करते हुए लगाये जायें।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की बचत

- सार्वजनिक क्षेत्र की बचत के संबंध में समिति ने सकल देशी उत्पाद, स्थानीय निकायों के लिए उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण तथा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अर्ध/स्वायत्त सरकारी निकाय के अलग अनुमान लगाने का सुझाव दिया।
- समिति ने यह सिफारिश की कि पीपीपी के वार्षिक खातों के आकलन के लिए एक क्रियाविधि बनायी जाये। ताकि इन उद्यमों से बचत और निवेश अनुमानों का सही आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

अन्य संबंधित मुद्दे

- समिति यह सिफारिश करती है कि निधियों के प्रवाह से संबंधित आकड़ों का संकलन कुछ और अधिक सामयिक तरीके से किया जाये ताकि कुछ और वास्तविक आधार पर घरेलू नकदी धारण के अनुपात सहित विभिन्न अनुपातों का संकलन किया जा सके। वित्तीय प्रणाली में कृषकों और गैर-सरकारी संगठनों और स्वसहायता समूहों जैसी संस्थाओं की बढ़ती महत्ता को देखते हुए और नीतिगत मुद्दों के परिप्रेक्ष्य से भी, समिति यह सिफारिश करती है कि ऐसी अनिगमित गैर-लाभकारी संस्थाओं को घरेलू बचत के अधीन एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाए। तदनुसार, बैंकों द्वारा जमाराशियों के संबंध में रिजर्व बैंक को दी जानेवाली विवरणियों में इन इकाइयों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- सांख्यिकी कक्षों में तकनीकी स्टाफ की पर्याप्त संख्या और दक्षता के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के कारण, समिति ने यह सिफारिश की है कि कंपनी कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा साथ ही रिजर्व बैंक, सेबी तथा नाबार्ड के सांख्यिकीय स्कंधों में स्टाफ की स्थिति सुदृढ़ की जाये।

(सारणी 2.20)। शेयरों और डिबेंचरों में घटे निवेश में आई कमी 2008-09 में न्यूनतर घरेलू वित्तीय बचतों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार थी। इसके अलावा, पिछले सालों की तुलना में

2008-09 में अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर में आयी कमी का भी घरेलू वित्तीय बचत पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। तथापि, मुद्रा, जमाराशि, संविदात्मक लिखतों और सरकार पर

सारणी 2.20: वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचत

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2006-07	2007-08 अ	2008-09 #
1	2	3	4
क. वित्तीय आस्तियां (सकल)	650,412 (15.8) {100.0}	715,994 (15.2) {100.0}	746,865 (14.0) {100.0}
1. मुद्रा	66,274 (1.6) {10.2}	81,278 (1.7) {11.4}	93,056 (1.7) {12.5}
2. जमाशियां@	319,385 (7.7) {49.1}	374,088 (7.9) {52.2}	436,710 (8.2) {58.5}
3. सरकार पर दवे	19,198 (0.5) {3.0}	-28,315 (-0.6) {-4.0}	-23,479 (-0.4) {-3.1}
4. शेयरों और डिबेंचरों में निवेश+	58,598 (1.4) {9.0}	89,134 (1.9) {12.4}	19,349 (0.4) {2.6}
5. संविदागत बचतें**	186,957 (4.5) {28.7}	199,809 (4.2) {27.9}	221,228 (4.2) {29.6}
ख. वित्तीय देयताएं	176,787 (4.3)	173,135 (3.7)	165,656 (3.1)
ग. वित्तीय आस्तियों में बचत (निवल) (क-ख)	473,624 (11.5)	542,859 (11.5)	581,209 (10.9)

अ : अंतिम; # : प्राथमिक

@ : इसमें बैंक जमाशियां गैर बैंकिंग जमाशियां और व्यापार ऋण (निवल) शामिल हैं।

+ : भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों की विशिष्ट वचनबद्धतावाली यूनिटें शामिल हैं।

** : जीवन बीमा निधि और भविष्य तथा पेंशन निधियों सहित

टिप्पणी: 1. पूर्णांकन के कारण कुल योग में अंतर हो सकता है।

2. () में दिए गए आंकड़े वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं और { } में दिए गए आंकड़े वित्तीय आस्तियों (सकल) का प्रतिशत दर्शाते हैं।

दावों जैसी अन्य लिखतों में घरेलू बचतें साल के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहीं। मुख्यतः बैंकों से लिए गए ऋणों और अग्रिमों में आयी गिरावट के कारण घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताएं 2007-08 में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रह गईं। सकल वित्तीय आस्तियों में आई गिरावट वित्तीय देयताओं में आई गिरावट से काफी अधिक थी, जिसके फलस्वरूप 2008-09 में घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतें न्यूनतर रहीं।

II.2.68 लगातार 5 वर्षों तक सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2008-09 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय कमी देखी गई, जो शुरुआत के तौर पर कुछ क्षेत्रों में चक्रिय मंदी के प्रभाव को परंतु बाद में वैश्विक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। कमी के बावजूद, भारत की

जीडीपी वृद्धि विश्व में सर्वाधिक बनी रही। साल की क्रमिक तिमाहियों के दौरान औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों की वृद्धि में आयी मंदी का प्रभाव साल की चौथी तिमाही में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप में आए टर्नअराउंड द्वारा कुछ प्रतितुलित हो गया। तथापि, भारतीय कृषि के सामने जलवायु में वैश्विक परिवर्तन, विशेष रूप से मानसून पर निर्भरता के कारण, से जुड़ी जोखिमें हैं। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ भारत की खाद्य सुरक्षा को परिरक्षित किया जाए। 2008-09 के दौरान, आइआइपी द्वारा मापी गयी औद्योगिक उत्पादन की मंदी का आधार व्यापक था, जिसने खनन, विनिर्माण और बिजली नामक सभी तीनों क्षेत्रों को प्रभावित किया। तथापि, मंदी की गति अधिकांश देशों की तुलना में अपेक्षाकृत न्यूनतर थी। सेवा क्षेत्र, जो आर्थिक वृद्धि का मुख्य चालक है, में समकालिक वैश्विक आर्थिक मंदी के संक्रमण के कारण थोड़ी मंदी देखी गयी। वैश्विक आर्थिक मंदी में तेजी तथा फलस्वरूप आने वाली संरक्षणवादी प्रवृत्तियां कुछ सेवाओं की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जो मंदी से निपटने के लिए इन अर्थव्यवस्थाओं में लागत कम करने संबंधी दबावों के कारण उल्लेखनीय नहीं होगा।

II.2.69 जहां देशी मांग द्वारा अदा की गयी बड़ी भूमिका ने अत्यधिक वैश्विक मंदी को देखते हुए भारतीय आर्थिक वृद्धि को थोड़ी आघात-सहनीयता प्रदान की, वहीं निजी उपभोग व्यय में आयी उल्लेखनीय मंदी तथा निवेश मांग में आयी कमी के लिए प्रतिचक्रिय राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों की जरूरत महसूस की गयी। अतः सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 2008-09 में तेजी से बढ़कर 20.2 प्रतिशत हो गयी जिसने मंदी के प्रभाव को कम करने में मदद की। 2009-10 के लिए उपलब्ध जानकारी से औद्योगिक सुधार के आरंभिक संकेत दिखायी देते हैं परन्तु मानसून की प्रगति में होने वाली देरी कृषि के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है तथा वृद्धि की संभावनाओं को मंद कर सकती है। उपभोग संबंधी मांग बढ़ाने के लिए किए गए उत्प्रेरक उपायों में मध्यावधि वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करने की जोखिम है, यदि उन्हें लम्बे समय तक बनाये रखा जाए, अतः सुधार की अल्पावधि आवश्यकताओं तथा धारणीय उच्च वृद्धि की मध्यावधि जरूरतों को संतुलित करने के लिए राजकोषीय समेकन के प्रति वापसी का समय महत्वपूर्ण होगा।

III. मुद्रा, ऋण और मूल्य

11.3.1 वर्ष 2008-09 में भारत की मौद्रिक और ऋण संबंधी स्थितियों में काफी उतार-चढ़ाव दिखाई दिये जो वृद्धि, मुद्रास्फीति और वित्तीय बाजारों में हुई अस्थिर गतिविधियों और परिणाम नीतिगत प्रतिसादों को दिखलाते हैं। 2008-09 में, जबकि 2008-09 की दूसरी छमाही में वृद्धि में काफी अधिक कमी आई, डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति अगस्त 2008 तक बढ़कर 12 प्रतिशत से अधिक हो गयी जो बाद में वर्ष के अंत तक काफी कम होकर लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। लेकिन सीपीआइ मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रही। 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान, वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थाओं की चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को परखा। वृद्धि में कमी और संबद्ध घटती कुल मांग को दर्शाते हुए, ऋण वृद्धि भी वर्ष के अंत तक काफी अधिक कम हुई। इन गतिविधियों का स्वरूप और मान 2008-09 के दौरान मौद्रिक और ऋण संबंधी समुच्चयों की वृद्धि के पैटर्न में दिखलायी पड़ा।

11.3.2 वर्ष के पहले भाग में, रिजर्व मुद्रा के विस्तार में एक प्रमुख प्रेरक के रूप में रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि का पूर्व अनुभूत पैटर्न जारी रहा। चूंकि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में पूंजी बहिर्वाहों और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेपों के कारण रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में कमी आई, अतः चलनिधि पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतितुलित करने से अधिक कार्य रिजर्व बैंक की निवल देशी आस्तियों में विस्तार करके किया जाना था, क्योंकि ऐसा करना वैश्विक वित्तीय संकट के अल्प संक्रमण के कारण चलनिधि की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरी हो गया था।

11.3.3 2008-09 के दौरान, निवल देशी आस्तियों में वृद्धि करने के लिए सरकार को रिजर्व बैंक का निवल ऋण एक प्रमुख स्रोत बन गया, और यह विकल्प ऐसे समय अपनाया गया जबकि आर्थिक मंदी पर नियंत्रण लगाने के लिए बृहद् राजकोषीय प्रोत्साहन आवश्यक हो गये थे। इसके अतिरिक्त, नीति के कारण रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में संघटनात्मक परिवर्तन हुए, देयता पक्ष में भी आस्ति निधि की अपेक्षा में कमी और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास सरकार की जमा राशियों के मोचन के कारण भी प्रमुख नीतिगत परिवर्तन हुए। इन दोनों उपायों के कारण बैंकिंग प्रणाली और सरकार को उपलब्ध चलनिधि में वृद्धि हुई तथा इनके संयुक्त प्रभाव से रिजर्व

बैंक के तुलनपत्र में संकुचन हुआ। अतः बहुत से देशों में केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में वृद्धि करना मात्रात्मक नरमी का प्रतीक बन गया था, लेकिन रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में देयता पक्ष में आरक्षित निधि की निम्नस्तर अपेक्षाओं और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अनवाइडिंग के माध्यम से चलनिधि में नीति चलित विस्तार तथा तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में कम होती विदेशी आस्तियों के प्रभाव को प्रतितुलित करने के लिए देशी आस्तियों में वृद्धि परिलक्षित हुई।

11.3.4 अतः 2008-09 के दौरान भारत में मौद्रिक समुच्चयों (एग्रीगेट्स) का विकास रिजर्व बैंक के नीतिगत रुझान के अनुरूप रहा है और कई क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के परिचालन के प्रभाव को दिखलाता है, जिनका उद्देश्य प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराना, बाजारों में फिर से व्यवस्था कायम करना और निम्न मुद्रास्फीति के चलते वृद्धि में तेजी से सुधार को समर्थन देना सुनिश्चित करना है।

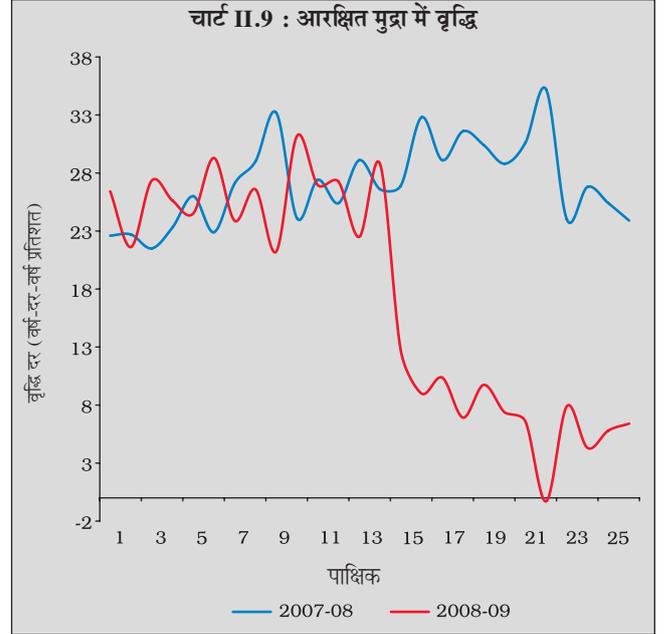
भारत में मौद्रिक स्थितियां

11.3.5 बृहद् और बहिर्जात पूंजी प्रवाहों में, जिनकी पिछले कुछ वर्षों में चलनिधि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका थी, वैश्विक वित्तीय संकट के गहरा जाने के कारण 2008-09 में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। भारत में बैंक ऋण के विस्तार में भी कमी आयी, जो 2008-09 की तीसरी तिमाही से वृद्धि की गति में आयी कमी को दिखलाती है। तदनुसार, 2008-09 में मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों की वृद्धि में कुछ कमी आयी। 2008-09 की अंतिम तिमाही में व्यापक मुद्रा की वृद्धि में कमी हुई जो वृद्धि और समग्र मांग में कमी दिखलाती है। उद्योग क्षेत्र को निधियों के अन्य स्रोत खत्म हो जाने के कारण अक्टूबर 2008 तक वाणिज्य क्षेत्र बैंक ऋण के विस्तार में मजबूती बनी रही लेकिन बाद में यह कम हो गई और वर्ष 2008-09 के लिए रिजर्व बैंक की तीसरी तिमाही समीक्षा (जनवरी 2009) में 24.0 प्रतिशत के अनुमान से कम रही। रिजर्व मुद्रा और देशी चलनिधि पर निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी के प्रभाव को खुला बाजार परिचालनों के तहत खरीद, एमएसएस के तहत शेषों के मोचन और रुपये की चलनिधि को बढ़ाने के लिए किये गये अन्य उपायों से प्रतितुलित किया गया जिनके कारण रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को दिये गये निवल ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पिछले वर्षों की तुलना में, 2008-09 में रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिये गये निवल ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

आरक्षित मुद्रा

11.3.6 वर्ष 2008-09 में रिज़र्व मुद्रा में हुई वृद्धि देशी और वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण चलनिधि की बदलती स्थिति के प्रति मौद्रिक नीति संबंधी प्रतिसाद का प्रभाव दिखलाती है। संघटकों के रूप में, 2008-09 में रिज़र्व मुद्रा में परिवर्तन संचलन में मुद्रा में वृद्धि और बैंकों के लिए नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तनों के कारण हुआ। 2008-09 के प्रारंभ में स्फीतिकारी दबावों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने आरंभ में सीआरआर में 150 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए अप्रैल-अगस्त 2008-09 में उसे 9.0 प्रतिशत कर दिया। बाद में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय उथल-पुथल के प्रभाव और देशी मौद्रिक तथा चलनिधि स्थितियों पर भी उसके प्रभाव, विशेषकर स्फीतिकारी दबावों के सहज हो जाने की स्थिति में, को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2008 से सीआरआर में कुल 400 आधार अंकों की कमी कर दी। सीआरआर में कटौती से बैंकिंग प्रणाली को 1,60,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध हुई, परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक के पास रखी गई बैंकों की जमाराशियों में वर्ष 2007-08 के दौरान हुई 66.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 11.3 प्रतिशत की कमी आई। आरक्षित मुद्रा वृद्धि 31 मार्च 2009 को एक वर्ष पहले के 31.0 प्रतिशत की तुलना में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) 6.4 प्रतिशत थी (चार्ट 11.9)। वर्ष 2008-09 के दौरान सीआरआर में हुए तेज परिवर्तनों के संदर्भ में विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए सीआरआर में हुए परिवर्तनों के प्रथम दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा वृद्धि के उपयोग को अधिक उचित समझा गया है (बॉक्स 11.5)। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार सीआरआर में परिवर्तनों के प्रथम दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) एक वर्ष पहले के 25.3 प्रतिशत की तुलना में 19.0 प्रतिशत पर रही।

11.3.7 सीआरआर में हुए परिवर्तन मुद्रा गुणक अर्थात् व्यापक मुद्रा और आरक्षित मुद्रा के बीच के अनुपात को प्रभावित करते हैं। मुद्रा गुणक, जो मार्च 2007 के अंत में 4.7 था, सीआरआर में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप घटकर मार्च 2008 के अंत में 4.3 पर आ गया किंतु मार्च 2009 के अंत में यह बढ़कर 4.8 पर आ गया, जो सीआरआर में की गई कमी को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान मुद्रा गुणक में काफी घट-बढ़ दिखाई दी। तथापि, जब अपेक्षानुसार मुद्रा गुणक को समायोजित आरक्षित मुद्रा के संबंध



में हिसाब में लिया जाता है तो काफी अधिक स्थिरता दिखाई देती है (बॉक्स 11.15 में चार्ट क)। मुद्रा-जमा (सी.डी.) अनुपात, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कमी की एक सामान्य प्रवृत्ति प्रदर्शित की है, में हाल की अवधि में कुछ वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय गतिविधि है क्योंकि उच्चतर सी-डी अनुपात घटती हुई आरक्षित निधि अपेक्षा के मुद्रा गुणक पर प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सी.डी. अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति सितंबर 2007 (अर्थात् सब-प्राइम संकट की शुरुआत से) से लगभग रुक गई और सी-डी अनुपात में प्रासंगिक वृद्धियां होती रहीं जो यह सुझाता है कि उच्चतर जमाराशि वृद्धि के बावजूद मुद्रा वृद्धि अधिक रही। सीडी अनुपात में पैटर्न को वर्ष 2008-09 में मुद्रास्फीति में हुई उल्लेखनीय प्रत्याशाओं, बढ़े हुए जोखिम के सामने चलनिधि हेतु वर्धित अधिमान, 2008-09 के पूर्ववर्ती आम चुनाव से विस्तार से स्पष्ट किया जा सकता है जिसे अक्सर मुद्रा मांग से संबद्ध किया जाता है। 2009-10 में, यद्यपि मुद्रा में वृद्धि स्पष्ट रूप से जमाओं में वृद्धि से पीछे है।

11.3.8 2008-09 के दौरान मौद्रिक प्रबंधन में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों के प्रति प्रतिसाद और विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान देशी मांग की स्थितियों में आयी मंदी से निपटने की जरूरत का प्रभुत्व रहा। चूंकि रिज़र्व बैंक को आयातकों की मांग को पूरा करने के लिए और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पूंजी बहिर्वाहों से उत्पन्न अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित

बॉक्स II.15 समायोजित आरक्षित मुद्रा और मुद्रा गुणक

रिज़र्व बैंक के पास रखी गई वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां न केवल आरक्षित मुद्रा का आकार निर्धारित करती हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के बहुविध विस्तार के लिए एक आधार के रूप में भी काम आती हैं। आरक्षित निधि की अपेक्षा, जो परंपरागत मौद्रिक नीति का साधन है, में परिवर्तन के साथ आरक्षित मुद्रा और मुद्रा गुणक दोनों में परिवर्तन हो सकता है, हालांकि व्यापक मुद्रा पर इसका विपरीत प्रभाव रहता है। आरक्षित मुद्रा में उच्च अथवा कम वृद्धि को अक्सर चिंता से देखा जाता है, यद्यपि आरक्षित मुद्रा में ऐसी वृद्धि आरक्षित निधि की अपेक्षा में हुए परिवर्तनों के माध्यम से जानबूझकर की जा सकती है। आरक्षित मुद्रा में नीति उत्प्रेरित परिवर्तनों का प्रभाव एक बार समायोजित हो जाते हैं तो हो सकता है कि समायोजित आरक्षित मुद्रा में हुई वृद्धि काफी अस्थिर प्रतीत न हो। ऐसा मामला भारत में 2008-09 में रहा, जब प्रथमतः रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2008 तक सीआरआर में 150 आधार अंकों की बढ़ोतरी की और उसके पश्चात 400 आधार अंकों की कमी की, जिसके कारण आरक्षित मुद्रा में बड़े उतार-चढ़ाव हुए। परिणामतः, जहां आरक्षित मुद्रा में 3 अक्टूबर 2008 की स्थिति के अनुसार 34.1 प्रतिशत की उच्च वृद्धि प्रदर्शित हुई, वहीं मार्च 2009 के अंत तक वृद्धि दर गिरकर 6.4 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन यदि आरक्षित निधि की अपेक्षा में नीति आधारित परिवर्तन नहीं हुए होते, तो जनता और वाणिज्य बैंकों पर निर्भर करने वाली क्रमशः मुद्रा वृद्धि और अतिरिक्त आरक्षित निधि जैसे गैर-नीतिगत घटकों द्वारा आरक्षित निधि वृद्धि का समायोजन होता। इस प्रकार एक अवधारणा के रूप में, समायोजित आरक्षित मुद्रा मुद्रा गुणक के लिए आरक्षित निधि अपेक्षा में परिवर्तनों के प्रति अपरिवर्तनीय बना देती है। जब समायोजित आरक्षित मुद्रा की ऐसी धारणा का प्रयोग किया जाता है तो गुणक का समायोजन भी तदनुसार किया जाना चाहिए जिसमें गुणक निर्धारित करने में आरक्षित निधि अपेक्षा के अलावा अन्य घटकों को ही लिया जाए।

समायोजित आरक्षित मुद्रा की परिभाषा निम्नानुसार है:
समायोजित आरएम: आरएम - $(r_t - r_0)$ एनडीटीएल

जहां r_t चालू सीआरआर है, r_0 प्रारंभिक बेंचमार्क सीआरआर और एनडीटीएल निवल मांग और मीयादी देयताएं हैं वहीं ये सीआरआर की गणना के प्रयोजन से संबंधित हैं। यदि किसी समयावधि में सीआरआर में दोतरफा परिवर्तन किया जाता

है, तो प्रारंभिक बेंचमार्क सीआरआर के बारे में निर्णय अपेक्षित होगा।

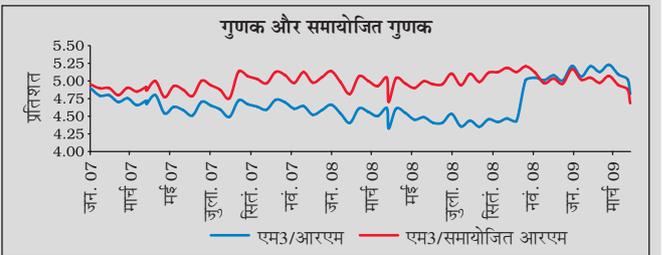
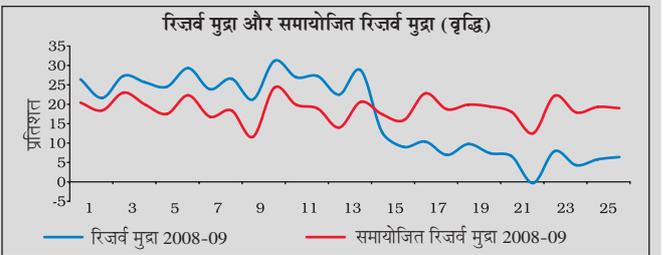
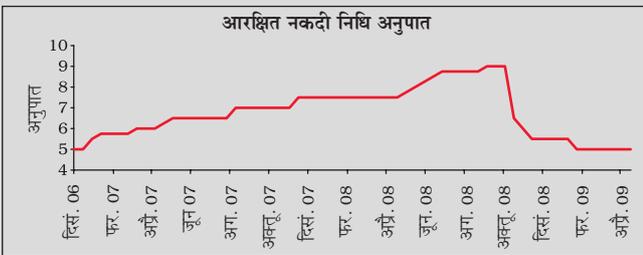
व्यापक मुद्रा गुणक (m) की व्यावहारिक परिभाषा के अनुसार, यह सीआरआर (r) और मुद्रा-जमा (c) के अनुपात $[(m=(1+c)/(c+r))]$ की संक्रिया है। यद्यपि सीआरआर नीतिगत मानक के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है, c एक व्यावहारिक अनुपात है और यह उम्मीद की जा सकती है कि इस पर कम समय में आय, ब्याज दर, निवेशकों की जोखिम धारणा का तथा दीर्घावधि में संस्थागत कारणों जैसे अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण और डेबिट/ क्रेडिट कार्डों के रूप में गैर-नकदी विकल्पों के साथ-साथ नकद वित्तीय आस्तियों के रूप में गैर-मुद्रा विकल्पों के विकास का प्रभाव पड़ सकता है। भारत के संदर्भ में 'c' अनुपात में 1970 के दशक से निरपेक्ष गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। फिर भी, हाल के वर्षों में मुद्रा वृद्धि उच्च जमा वृद्धि से कुछ अधिक रही है और इसलिए 'c' अनुपात ने अगस्त 2007 से वृद्धि दर्ज की है, हालांकि कुछ बदलाव के साथ। चूंकि यह गुणक 'r' और 'c' दोनों से विपरीत सम्बद्ध रखता है, जहां नीतिगत उपायों से 'r' में हुई गिरावट के कारण 'c' में कुछ वृद्धि हुई है, वह व्यापक मुद्रा पर नीति के विस्तारक प्रभाव को आंशिक रूप से प्रतिलुलित कर सकता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद लोगों की बैंकिंग आदतों में परिवर्तन और वित्तीय गहराई के साथ, 1970 से ही 'c' अनुपात में निरपेक्ष गिरावट के परिणामस्वरूप भारत में मुद्रा गुणक उच्चतर रहे।

इस बॉक्स के पैनेल चार्ट क में वर्ष 2008-09 के दौरान गुणक की स्थिति है जो काफी अस्थिर है। तथापि, गुणक में आरक्षित मुद्रा में हुए सीआरआर परिवर्तनों के प्रथम दौर के प्रभाव हेतु समायोजन से काफी स्थिरता दिखाई दी और विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा के उपयोग की आवश्यकता स्पष्ट हुई। यह परिणाम मौद्रिक प्रबंधन में 'c' अनुपात की निर्णायक भूमिका को भी प्रकट करता है जो आरक्षित मुद्रा और गुणक दोनों में परिवर्तन कर सकता है।

संदर्भ :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (1988), "मुद्रा आपूर्ति : संकलन का विश्लेषण और प्रणाली विज्ञान" पर तीसरे कार्यकारी दल की रिपोर्ट: मुंबई, जून।

चार्ट क : समायोजित आरक्षित मुद्रा और मुद्रा गुणक



करने के लिए विदेशी मुद्रा चलनिधि प्रदान करना पड़ा, अतः उसकी निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों (एनएफईए) में कमी आयी। आरक्षित मुद्रा और देशी चलनिधि पर निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी के संकुचनकारी प्रभाव को खुले बाजार के परिचालनों (ओएमओ) के तहत खरीद, एमएसएस के तहत शेषों के मोचन और रुपया चलनिधि को बढ़ाने के अन्य उपाय करते हुए निवल विदेशी आस्तियों में विस्तार द्वारा प्रतितुलित किया गया। अतः स्रोत पक्ष में आरक्षित मुद्रा पूर्ववर्ती वर्षों में निवल विदेशी मुद्रा

आस्तियों (मूल्यन के लिए समायोजित) की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान काफी अधिक गिरी जबकि केन्द्र को रिजर्व बैंक के ऋण बढ़े (सारणी 2.21, परिशिष्ट सारणी 13 और 14)। केंद्र को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में 2008-09 के दौरान 1,76,397 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान इसमें 1,16,722 करोड़ रुपए की गिरावट हुई थी (चार्ट II.10)। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (मूल्यन के लिए समायोजित) में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि

सारणी 2.21 : आरक्षित मुद्रा घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2009 को बकाया	2007-08	2008-09	2008-09			
				ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा	9,88,001	2,19,412	59,698	3,416	25,218	-70,452	1,01,516
<i>समायोजित आरक्षित मुद्रा</i>	10,15,751	1,72,412	1,61,948	-24,584	-4,532	69,548	1,21,516
		(25.3)	(19.0)				
घटक (1+2+3)							
1. संचलन में मुद्रा	6,91,153	86,702	1,00,352	36,859	-14,516	38,277	39,733
		(17.2)	(17.0)				
2. भारिबैं के पास बैंकों की जमाराशियां	2,91,275	1,31,152	-37,172	-29,333	39,219	-1,15,773	68,714
		(66.5)	(-11.3)				
3. भारिबैं के पास 'अन्य' जमाराशियां	5,573	1,558	-3,482	-4,110	514	7,045	-6,931
		(20.8)	(-38.5)				
स्रोत (1+2+3+4-5)							
1. सरकार को रिजर्व बैंक निवल ऋण	61,580	-1,15,632	1,74,789	-13	51,360	30,230	93,212
<i>जिसमें से : केंद्र सरकार को (i+ii+iii+iv-v)</i>	61,761	-1,16,772	1,76,397	1,430	51,379	29,932	93,657
i. ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
ii. भारिबैं द्वारा धारित खजाना बिल	0	0	0	0	0	0	0
iii. भारिबैं द्वारा धारित दिनांकित प्रतिभूतियां	1,57,389	17,421	42,796	-39,239	56,975	-44,206	69,266
iv. भारिबैं द्वारा धारित रुपया सिक्के	99	121	-34	-1	-26	27	-33
v. केंद्र सरकार की जमाराशियां	95,727	1,34,314	-1,33,635	-40,670	5,570	-74,111	-24,424
2. बैंकों तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को भारिबैं का ऋण	24,177	-2,794	17,799	-3,358	4,963	5,032	11,163
3. भारिबैं का एनएफईए	12,80,116	3,69,977	43,986	1,03,932	10,336	-1,56,330	86,048
		(42.7)	(3.6)				
<i>जिसमें से : एफसीए, मूल्यन के लिए समायोजित</i>		3,70,550	-1,00,308	15,535	-31,641	-92,102	7,900
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	10,054	1,063	831	225	206	186	213
5. भारिबैं की निवल मुद्रेतर देयताएं	3,87,927	33,202	1,77,706	97,369	41,648	-50,431	89,120
ज्ञापन :							
निवल देशी आस्तियां	-2,92,115	-1,50,565	15,712	-1,00,516	14,882	85,878	15,468
एलएएफ- रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)	-1,485	21,165	-51,835	-45,350	51,480	-62,170	4,205
खुले बाजार में निवल बिक्री # *	-	-5,923	-94,548	-8,696	-10,535	-7,669	-67,649
केंद्र के अधिशेष	16,319	26,594	-60,367	-42,427	6,199	-32,830	8,691
एमएसएस के अंतर्गत संग्रहण	88,077	1,05,418	-80,315	6,040	-628	-53,754	-31,973
प्राधिकृत व्यापारियों से निवल खरीद (+)/बिक्री (-)	-	3,12,054	-1,78,592	3,956	-52,761	-1,11,877	-17,910
एनएफईए/आरक्षित मुद्रा @	129.6	133.2	129.6	143.8	141.1	134.7	129.6
एनएफईए/मुद्रा @	185.2	209.2	185.2	213.5	220.2	183.3	185.2
एनएफईए: निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां		एफसीए: विदेशी मुद्रा आस्तियां		एलएएफ: चलनिधि समायोजन सुविधा			
*: अंकित मूल्य पर		# : खजाना बिलों को छोड़कर		@ : समाप्त अवधि पर प्रतिशत			
टिप्पणी: 1. चौथी तिमाही के आंकड़े 31 मार्च पर आधारित हैं और अन्य तिमाहियों के आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।							
2. कोष्ठकों के आंकड़े राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।							

के दौरान हुई 3,70,550 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 1,00,308 करोड़ रुपए की कमी आयी। स्रोत पक्ष में, यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई बाजार में विपणनीय प्रतिभूतियों (जिनमें ओएमओ और एलएएफ दोनों शामिल हैं) में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। नवंबर 2008 की अवधि से, एमएसएस के अपेक्षकृत तीव्र अनवाइंडिंग के माध्यम से जारी की गई चलनिधि को रिवर्स रिपो (8 दिसंबर 2008 से रिवर्स रिपो दर में 2.75 प्रतिशत अंक की कटौती के बावजूद) का आश्रय लेते हुए आंशिक रूप से प्रतितुलित किया गया, जो ऋण के न्यूनतर उठाव तथा बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त अतिरिक्त चलनिधि की उपलब्धता को सूचित करता है।

II.3.9 एमएसएस को मुख्यतः बड़े पूंजी अंतर्वाहों की अवधि में अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एक नवोन्मेषी निष्प्रभावीकरण लिखत के रूप में लागू किया गया था। इसने मौद्रिक नीति को पूंजी के बहिर्वाहों की अवधि में भी काफी आवश्यक लचीलापन प्रदान किया क्योंकि एमएसएस के अंतर्गत शेषों को अनवाइंड करने मात्र से देशी चलनिधि को बढ़ाया जा सकता था।

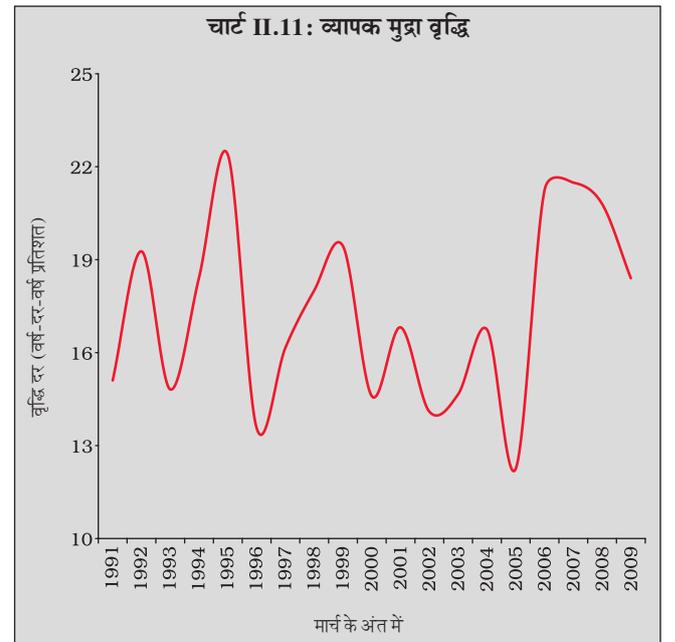
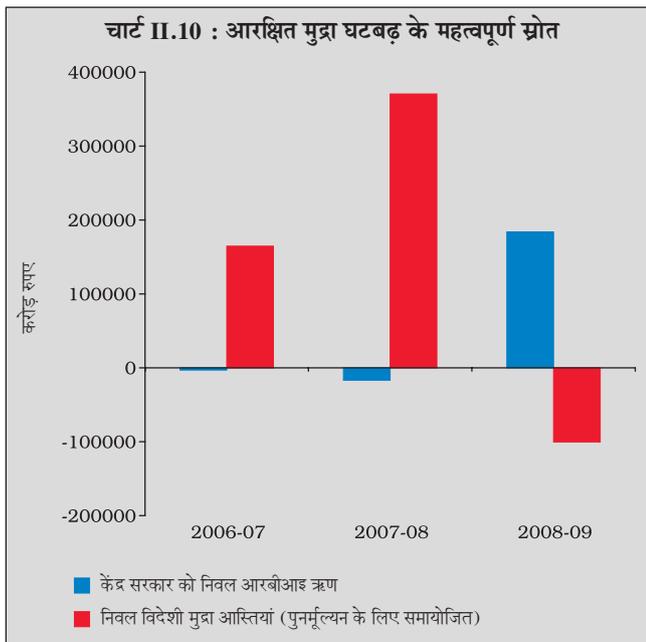
2009-10 की गतिविधियां

II.3.10 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आरक्षित मुद्रा में एक वर्ष पहले की 31.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14 अगस्त 2009 को

2.8 प्रतिशत की गिरावट हुई। सीआरआर में वृद्धि के प्रथम दौर के प्रभाव को समायोजित करने के पश्चात, आरक्षित मुद्रा में हुई वृद्धि एक वर्ष पहले के 24.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.7 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में (मूल्यन के लिए समायोजित) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले के 2,51,201 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 71,658 करोड़ रुपए की कमी आई। केंद्र को रिजर्व बैंक का निवल ऋण एक वर्ष पहले के 6,125 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 80,507 करोड़ रुपए बढ़ गया।

मौद्रिक सर्वेक्षण

II.3.11 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर व्यापक मुद्रा (एम₃) वृद्धि मार्च 2009 के अंत में 18.6 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 21.4 प्रतिशत से कम थी (चार्ट II.11, सारणी 2.22 और परिशिष्ट सारणी 15)। निवासी - आधारित नए मौद्रिक समुच्चय (एनएम₃) में विस्तार जो अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियों, यथा एफसीएनआर(बी) जमाराशियों, को सीधे हिसाब में नहीं लेता - एक वर्ष पूर्व के 21.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में (वर्ष-दर-वर्ष) 18.2 प्रतिशत पर न्यूनतर था। इसी प्रकार चलनिधि समुच्चय एल₁, में वृद्धि एक वर्ष पहले के 20.9 प्रतिशत की तुलना में 17.7 प्रतिशत पर कम थी (परिशिष्ट सारणी 16 और 17)।



सारणी 2.22: मौद्रिक संकेतक

(राशि करोड़ रूप में)

मद	31 मार्च 2009 को बकाया	घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष)			
		31 मार्च 2008		31 मार्च 2009	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. आरक्षित मुद्रा (समायोजित आरक्षित मुद्रा)	9,88,001	2,19,412	31.0	59,698	6.4
		1,72,412	25.3	1,61,948	19.0
II. संकीर्ण मुद्रा (एम ₁)	12,53,184	1,87,882	19.4	97,347	8.4
III. व्यापक मुद्रा (एम ₃)	47,64,019	7,07,815	21.4	7,46,136	18.6
क) जनता के पास मुद्रा	6,66,364	85,556	17.7	97,953	17.2
ख) कुल जमाराशियां	40,92,083	6,20,701	22.0	6,51,665	18.9
i) मांग जमाराशियां	5,81,247	1,00,768	21.1	2,875	0.5
ii) सावधि जमाराशियां	35,10,835	5,19,933	22.2	6,48,790	22.7
जिसमें से: अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियां	67,268	-10,525	-15.6	10,332	18.1
IV. एनएम ₃	47,81,333	7,19,019	21.6	73,73,93	18.2
जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं से मांग मीयादी निधायन	1,13,936	20,668	24.1	7,432	7.0
V. क) एल ₁	48,95,354	7,18,321	20.9	7,36,563	17.7
जिसमें से: डाकघर जमाराशियां	1,14,021	-698	-0.6	-830	-0.7
ख) एल ₂	48,98,286	7,18,321	20.9	7,36,563	17.7
ग) एल ₃	49,22,933	7,19,154	20.7	7,36,358	17.6
VI. व्यापक मुद्रा के प्रमुख स्रोत					
क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii)	12,77,199	71,891	8.7	3,77,681	42.0
i) सरकार को रिजर्व बैंक का निवल ऋण	61,580	-1,15,632	-	1,74,789	-
जिसमें से: केंद्र को	61,761	-1,16,772	-	1,76,397	-
ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण	12,15,619	1,87,523	22.7	2,02,892	20.0
ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	30,13,337	4,50,127	21.1	4,34,347	16.8
ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,52,184	3,81,952	41.8	57,053	4.4
घ) जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	10,054	1,063	13.0	831	9.0
ङ) बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	8,88,754	1,97,219	34.7	1,23,775	16.2
ज्ञापन:					
एससीबी की कुल जमाराशियां	38,34,110	5,85,006	22.4	6,37,170	19.9
एससीबी का खाद्येतर ऋण	27,29,338	4,32,846	23.0	4,11,824	17.8

एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक एफआइ: वित्तीय संस्थाएं एनबीएफसी: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
 एनएम₃ निवासी आधारित सकल व्यापक मुद्रा है और एल₁, एल₂ और एल₃ मुद्रा आपूर्ति पर कार्यकारी दल, 1998 की सिफारिशों के आधार पर संकलित चलनिधि समुच्चय हैं।
 एल₁ = एनएम₃ + डाकघर बचत बैंकों में चुनिंदा जमाराशियां।
 एल₂ = एल₁ + मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं तथा पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मीयादी जमाराशियां + वित्तीय संस्थाओं के सावधि उधार + वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र।
 एल₃ = एल₂ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियां।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं। जहां कहीं आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पिछले उपलब्ध माह के अनुमानों को दोहराया गया है।

II.3.12 व्यापक मुद्रा(एम₃) की वृद्धि में कमी से मुख्यतः आर्थिक गतिविधि में गिरावट के प्रतिसाद में 2008-09 के दौरान समग्र जमाराशियों के विस्तार में आयी कमी परिलक्षित हुई। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान जनता के पास मुद्रा अधिक मात्रा में बनी रही जो उस अवधि के दौरान विद्यमान उच्च मुद्रास्फीतिकारी स्थिति सहित किसानों की ऋण माफी योजना के

अंतर्गत संवितरण और छोटे वेतन आयोग के भुगतान के प्रभाव को परिलक्षित करती है (चार्ट II.12)। आर्थिक गतिविधि में कमी को परिलक्षित करते हुए तीसरी तिमाही से मुद्रा के विस्तार में कमी आने की शुरुआत हुई। जनता के पास की मुद्रा में एक वर्ष पहले के 17.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। फिर भी, संचलन में मौजूद

चार्ट II.12 : संचलन में मुद्रा तथा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति



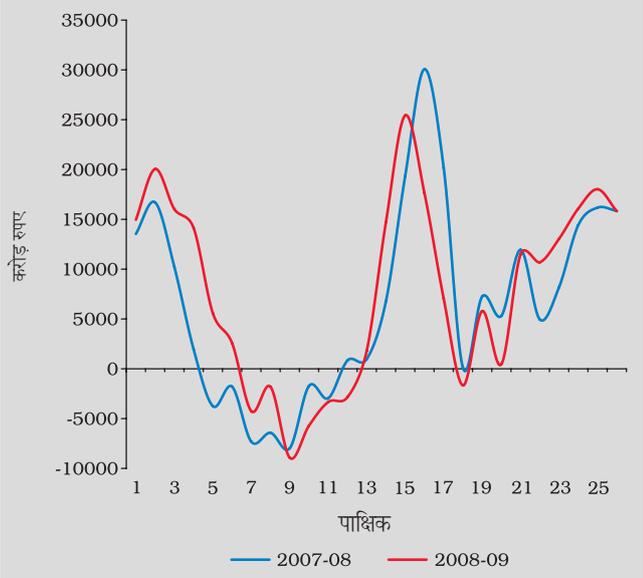
मुद्रा में पाक्षिक घट-बढ़ का पैटर्न वर्ष 2007-08 और 2008-09 में न्यूनधिक रूप से एक समान रहा (चार्ट II.13)।

II.3.13 आवधिक जमाराशियों की वृद्धि में वर्ष 2008-09 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान कमी आयी परंतु उसके बाद की मांग जमाराशियों और अन्य बचत लिखतों से मीयादी जमाराशियों के कुछ अंतरणों के साथ सुदृढ़ विस्तार दिखाई दिया। इक्विटी बाजार में मंदी के चलते बढ़ती अनिश्चितता के कारण जोखिम

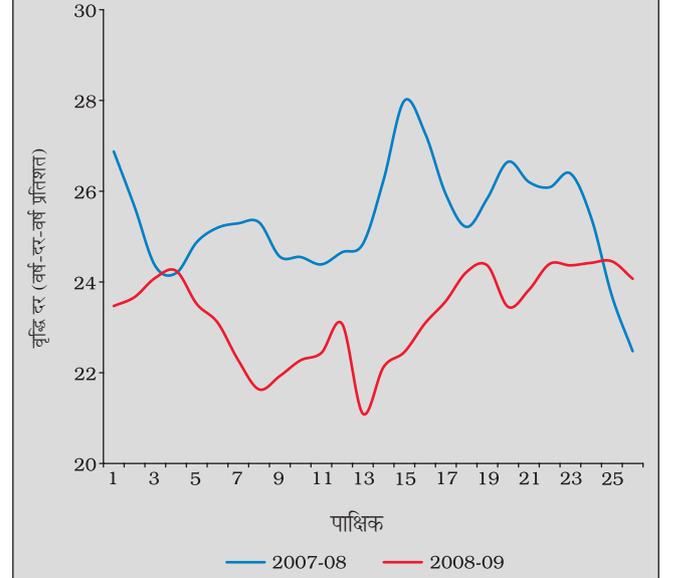
बोध में वृद्धि और अभी भी आवधिक जमाराशियों पर उपलब्ध जोखिम रहित उच्च ब्याज दर ने वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान निवेशकों को अपनी वित्तीय बचतों को आवधिक जमाराशियों में अंतरित करने के लिए प्रेरित किया। अल्पावधि में ब्याज दरों में कमी की प्रत्याशाओं ने भी मीयादी जमाराशियों के पक्ष में जमाराशियों के संरचनात्मक अंतरण में योगदान किया। आवधिक जमाराशियों ने एक वर्ष के पहले 22.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में 22.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की उच्च वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.14)। तदनुसार, पिछले वर्ष हुई मजबूत वृद्धि (21.1 प्रतिशत) की तुलना में मांग जमाराशियों में मामूली वृद्धि (0.5 प्रतिशत) दर्ज की गई। दिसंबर 2007 से अल्प बचत योजनाओं से आरंभ हुए निवल बहिर्वाह मार्च 2009 तक जारी रहे, इस अवधिके अद्यतन आकड़े उपलब्ध हैं (चार्ट II.15)।

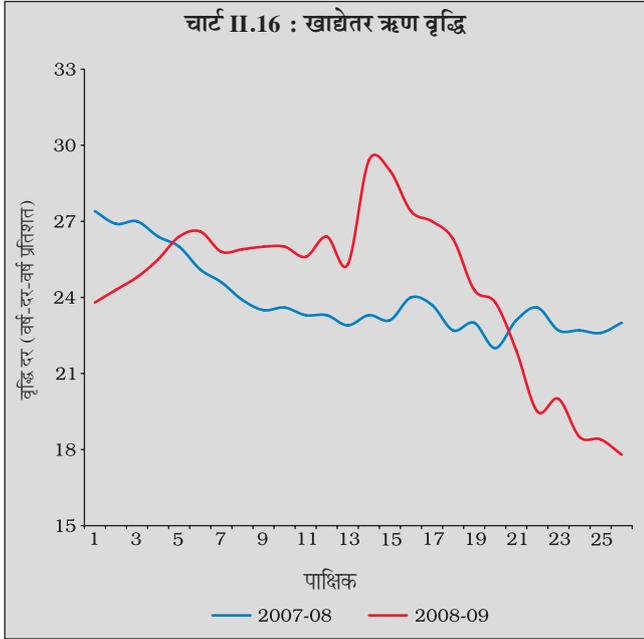
II.3.14 व्यापक मुद्रा (एम₃) के स्रोत पक्ष में, 2008-09 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की वृद्धि में गिरावट आयी और बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों के विस्तार में काफी अधिक कमी आई। दूसरी ओर, एमएसएस के अंतर्गत बकाया शेषों में कमी, खुले बाजार के परिचालनों के तहत खरीद (विशेष बाजार परिचालनों के अंतर्गत तेल बांडों की खरीद सहित) में वृद्धि और रिजर्व बैंक के पास रखे केंद्र के अतिरिक्त शेषों में कमी को दर्शाते हुए केंद्र को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वृद्धि हुई। तथापि, सरकार को अनुसूचित वाणिज्य

चार्ट II.13 : संचलन में मुद्रा में पाक्षिक घट-बढ़



चार्ट II.14 : मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर





कंपनियों ने पाया कि ऋण के बाहरी स्रोतों तक उनकी पहुंच सीमित हो गई है अतः उन्होंने उस मांग को देशी ऋण की मांग के रूप में अंतरित कर दिया। दूसरा, अप्रैल- अक्टूबर 2008 के दौरान तेल विपणन कंपनियों को दिए गए ऋण में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान आयी 1,146 करोड़ रुपए की कमी की तुलना में 36,208 करोड़ रुपए की तीव्र वृद्धि हुई। तथापि, बाद की अवधि में ऋण की मांग में नरमी दिखाई दी, जो सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था तथा विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मंदी का परिणाम थी। पण्यों की कीमतों में गिरावट और कंपनियों द्वारा स्टॉक में कमी किए जाने के कारण भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में कमी आई। तेल विपणक कंपनियों द्वारा ऋण की मांग में भी नरमी रही। इसके अतिरिक्त, निजी और विदेशी बैंकों के काफी कम ऋण विस्तार के कारण

भी वर्ष के दौरान बैंक ऋण के समग्र प्रवाह में नहीं के बराबर वृद्धि हुई (सारणी 2.24)। जमाराशियों में हुए विस्तार की तुलना में ऋण में कम विस्तार के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (वर्ष-दर-वर्ष) एक वर्ष पहले के 73.6 प्रतिशत की तुलना में कम होकर मार्च 2009 के अंत में 64.9 प्रतिशत रह गया।

II.3.16 बैंक ऋण वृद्धि, जिसमें 2006 के बाद नरमी आने लगी थी, में वर्ष 2008-09 के दौरान अत्यधिक गिरावट आ गई। ऋण वृद्धि में कमी और जीडीपी में कमी से 2008-09 के दौरान ऋण - जीडीपी वृद्धि एक वर्ष पहले के लगभग समान स्तर पर बनी रही। जीडीपी के प्रति बैंक ऋण का अनुपात मार्च 2000 के अंत के 30 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत के 47 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 51 प्रतिशत और मार्च 2008 के अंत में पुनः बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 2009 के अंत में यह 56 प्रतिशत पर बना रहा। सावधि जमा राशियों की वृद्धि के अनुरूप सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश बढ़े (चार्ट II.17)।

II.3.17 2003-04 से 2008-09 के दौरान भारत में औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत, औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत और औसत मुद्रा आपूर्ति वृद्धि दर 17.9 प्रतिशत रही। तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वृद्धि में नरमी तथा एक प्रतिशत से नीचे (वर्ष-दर-वर्ष) डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के चलते मार्च 2009 के अंत में व्यापक मुद्रा में हुई 18.6 प्रतिशत की वृद्धि को मुद्रा के संचलन वेग में उल्लेखनीय गिरावट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए (चार्ट II.18)।

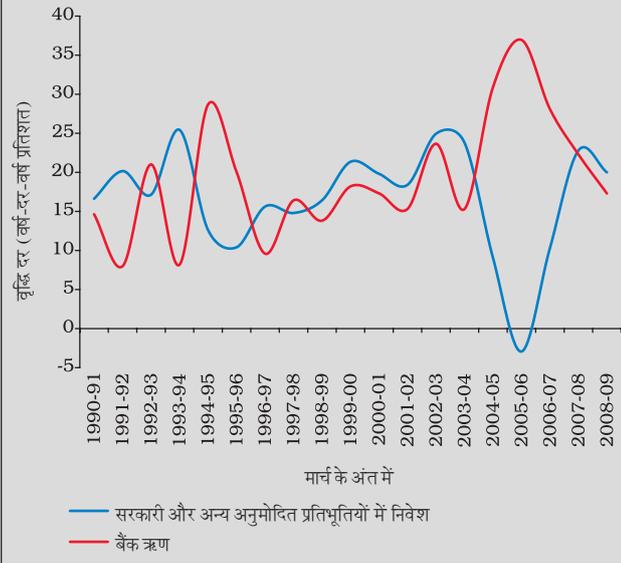
सारणी 2.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ऋण प्रवाह

(राशि करोड़ रुपए में)

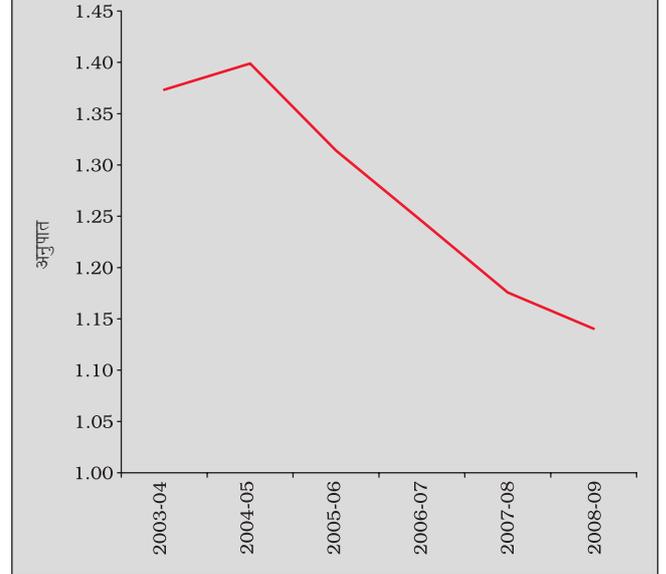
मद	27 मार्च 2009 को बकाया	घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष)			
		28 मार्च 2008 को		27 मार्च 2009 को	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक	20,18,711	3,07,310	22.5	3,48,562	20.9
2. विदेशी बैंक	1,69,335	36,116	28.5	6,467	4.0
3. निजी बैंक	5,23,492	78,301	19.9	52,013	11.0
4. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	27,75,549	4,30,724	22.3	4,13,636	17.5

* : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित।

चार्ट II.17 : बैंक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश



चार्ट II.18 : संचलन में मुद्रा का वेग



II.3.18 खाद्येतर बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन संबंधी अनंतिम आंकड़े 2008-09 में सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋणों की ऋण वृद्धि में हुई कमी को दर्शाते हैं। 2008-09 के दौरान वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि जारी रही

और कुल खाद्येतर ऋण के उसके अंश में भी वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान कुल खाद्येतर ऋण में कृषि को दिए गए ऋण का अंश भी बढ़कर 13.0 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.25, परिशिष्ट सारणी 20 और 21)।

सारणी 2.25: खाद्येतर बैंक ऋण - क्षेत्रवार नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र/उद्योग	27 मार्च 2009 को बकाया	वर्ष-दर-वर्ष में घटबढ़			
		2007-08		2008-09	
		कुल राशि	प्रतिशत	कुल राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 to 4)	26,02,290	4,01,650	22.3	3,99,400	18.1
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	3,38,656	44,966	19.5	63,313	23.0
2. उद्योग (लघु, मझोले और बड़े)	10,54,390	1,69,536	24.3	1,87,515	21.6
जिनमें से लघु उद्यम	2,57,027	76,932	65.2	62,185	31.9
3. वैयक्तिक ऋण	5,62,479	54,730	12.1	54,991	10.8
आवास	2,76,957	26,802	11.6	19,165	7.4
सावधि जमाराशियों पर दिए गए अग्रिम	48,676	4,170	10.2	3,671	8.2
क्रेडिट कार्ड	28,000	8,094	44.2	1,607	6.1
शिक्षा	28,579	5,324	35.0	8,047	39.2
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8,187	-390	-4.2	-612	-7.0
4. सेवाएं	6,46,765	1,32,419	31.5	93,580	16.9
परिवहन परिचालक	39,302	9,486	33.5	1,484	3.9
व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	45,373	3,201	13.4	18,240	67.2
व्यापार	1,44,377	17,059	16.0	20,656	16.7
स्थायर संपदा ऋण	91,575	19,235	43.6	28,261	44.6
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	98,853	30,094	61.5	19,835	25.1

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।
2. आंकड़ों में इन बैंकों के आंकड़े भी शामिल हैं: भारत ओवरसीज बैंक जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, अमरीकन एक्सप्रेस बैंक जिसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जिसका भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय हो गया था।

II.3.19 बैंकों के अलावा, वाणिज्यिक क्षेत्र ने विभिन्न अन्य स्रोतों से जैसे पूंजी बाजार, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), वित्तीय संस्थाओं, बाह्य वाणिज्यिक उधारों, अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संसाधन जुटाए। 2008-09 के दौरान देशी गैर-बैंक स्रोतों से संसाधनों का प्रवाह बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में बाह्य स्रोतों से संसाधनों का प्रवाह तेजी से घटा। देशी गैर-बैंक स्रोतों में से, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधन गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की कुल सकल वित्तीय सहायता और एलआइसी के सकल निवेश बढ़े, जबकि अन्य स्रोतों द्वारा जुटाए गए संसाधन घटे। बाह्य स्रोतों के अंतर्गत, बाह्य वाणिज्यिक उधारों, एडीआर/जीडीआर निर्गमों और अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन काफी अधिक घटे, जबकि एफडीआई मार्ग के माध्यम से निवेश बढ़े। इस प्रकार 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान खाद्येतर ऋण के प्रवाह में आई गिरावट के बावजूद, गैर-बैंक स्रोतों से संसाधनों का प्रवाह भी काफी अधिक कम हुआ, जिसका परिणाम

वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर वित्तीय संसाधनों का कम वार्षिक प्रवाह रहा (सारणी 2.26)।

II.3.20 निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश एक वर्ष पहले के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में 28.1 प्रतिशत हो गए। तथापि, बकाया आधार पर एलएएफ संपार्श्विकीकृत प्रतिभूतियों के लिए समायोजित करने के पश्चात, मार्च 2009 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश 11,10,820 करोड़ रुपए या एनडीटीएल का 26.8 प्रतिशत था, जो एनडीटीएल के 24.0 प्रतिशत के निर्धारित एसएलआर से 1,69,846 करोड़ रुपए या 4.1 प्रतिशत अधिक था (चार्ट II.19)।

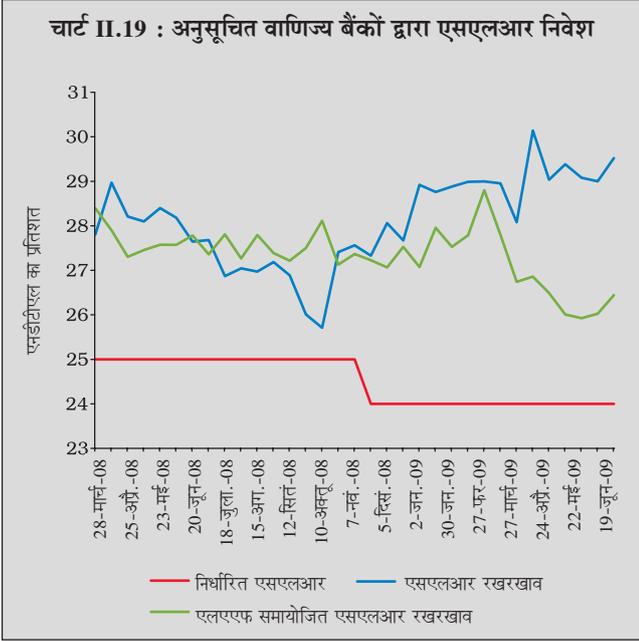
II.3.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर एसएलआर निवेशों (अर्थात् वाणिज्यिक पत्रों, शेयरों और बांडों तथा वित्तीय संस्थाओं एवं म्युच्युअल फंडों में निवेश) में 2008-09 के दौरान बड़ा विस्तार हुआ। आवधिक जमाराशियों में उच्च वृद्धि और ऋण विस्तार में कमी की अवधि में बैंकों ने गैर-एसएलआर निवेशों के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। गैर-एसएलआर

सारणी 2.26: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए संसाधनों का प्रवाह

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09
1	2	3
क. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण(एनएफसी)	4,44,807	4,21,091
i) खाद्येतर ऋण जिसमें से: पेट्रोलियम और उर्वरक ऋण	4,32,846 5,057	4,11,824 31,632
ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर निवेश	11,961	9,267
ख. गैर-बैंकिंग संस्थाओं से प्रवाह (ख1+ख2)	5,87,659	4,66,895
ख 1. देशी स्रोत	2,55,230	2,96,679
1 गैर-वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक निर्गम	51,478	14,205
2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल निजी स्थानन	68,249	76,184
3 गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अभिदत्त वाणिज्यिक पत्रों का निवल निर्गम	10,660	5,590
4 आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल उधार	41,841	26,634
5 भारिबैं द्वारा विनियमित 4 एआइएफआइ संस्थाओं - नाबार्ड, एनएचबी,सिडबी और एक्विज बैंक द्वारा कुल सकल वित्तीय सहायता	22,267	31,423
6 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल बैंक उधार	36,460	76,828
7 भारतीय जीवन बीमा निगम का कंपनी ऋण, आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में सकल निवेश	24,275	65,815
ख 2. विदेशी स्रोत	3,32,429	1,70,216
1 बाह्य वाणिज्यिक उधार/एफसीसीबी	91,180	38,009
2 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर एडीआर/जीडीआर निर्गम	34,937	4,788
3 विदेशों से अल्पावधि ऋण	68,878	-31,160
4 भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,37,434	1,58,579
ग. संसाधनों का कुल प्रवाह (क+ख)	10,32,466	8,87,986

चार्ट II.19 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एसएलआर निवेश



प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश 2007-08 के 21.5 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गए (सारणी 2.27)।

2009-10 की गतिविधियां

II.3.22 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर व्यापक मुद्रा (एम₃) में वृद्धि एक वर्ष पहले के 19.9 प्रतिशत की तुलना में 31 जुलाई 2009

को 20.0 प्रतिशत थी। प्रमुख घटकों में, कुल जमाओं में वृद्धि एक वर्ष पहले के 20.3 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गई। स्रोत पक्ष में, वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रति बैंक ऋण में विस्तार एक वर्ष पहले के 23.6 प्रतिशत की तुलना में 31 जुलाई 2009 को कम होकर 15.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया।

II.3.23 आरक्षित मुद्रा वृद्धि, जो 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान उच्च बनी रही, में अक्टूबर 2008 के अंत से तीव्र गिरावट दिखी जो आरआर में बाद में की गई कमी को दर्शाती है। चूंकि आरक्षित मुद्रा में यह कमी बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि डालने और उच्चतर मुद्रा गुणक के माध्यम से व्यापक मुद्रा में अधिक वृद्धि को सुनिश्चित करने की सुविचारित नीतिगत कार्रवाई का परिणाम थी, समायोजित आरक्षित मुद्रा में वृद्धि के अनुसार मौद्रिक स्थितियों का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा। 2008-09 के दौरान, समायोजित आरक्षित मुद्रा में एक वर्ष पहले के 25.3 प्रतिशत की तुलना में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान व्यापक मुद्रा (एम₃) वृद्धि कुछ कम हुई और एक वर्ष पहले की तुलना में कम बनी रही। सरकार को निवल बैंक ऋण व्यापक मुद्रा के प्रमुख प्रेरक स्रोत थे, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रति ऋण में गिरावट दिखी। निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों के विस्तार में भी गिरावट दिखी। गैर एसएलआर

सारणी 2.27: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	मार्च 2009
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	4,821	8,978	13,045	19,688
2. म्यूच्युअल फंडों के यूनिट	10,345	11,659	18,692	36,781
3. जारी शेयर:	15,044	20,178	28,454	30,753
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा	2,274	2,127	3,023	2,767
निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा	10,501	16,225	23,387	25,043
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा	2,270	1,826	2,044	2,943
4. द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	1,03,170	98,201	1,08,791	1,16,408
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा	32,345	28,595	27,382	24,182
निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा	29,523	27,620	28,669	33,093
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा	26,402	24,362	23,511	28,103
अन्य	14,899	17,623	29,230	31,030
कुल (1 to 4)	1,33,380	1,39,016	1,68,983	2,03,630

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश बढ़े। खाद्येतर ऋण में गिरावट के बावजूद वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रति गैर बैंक संसाधनों का प्रवाह में भी 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान कम हुआ।

मूल्य स्थिति

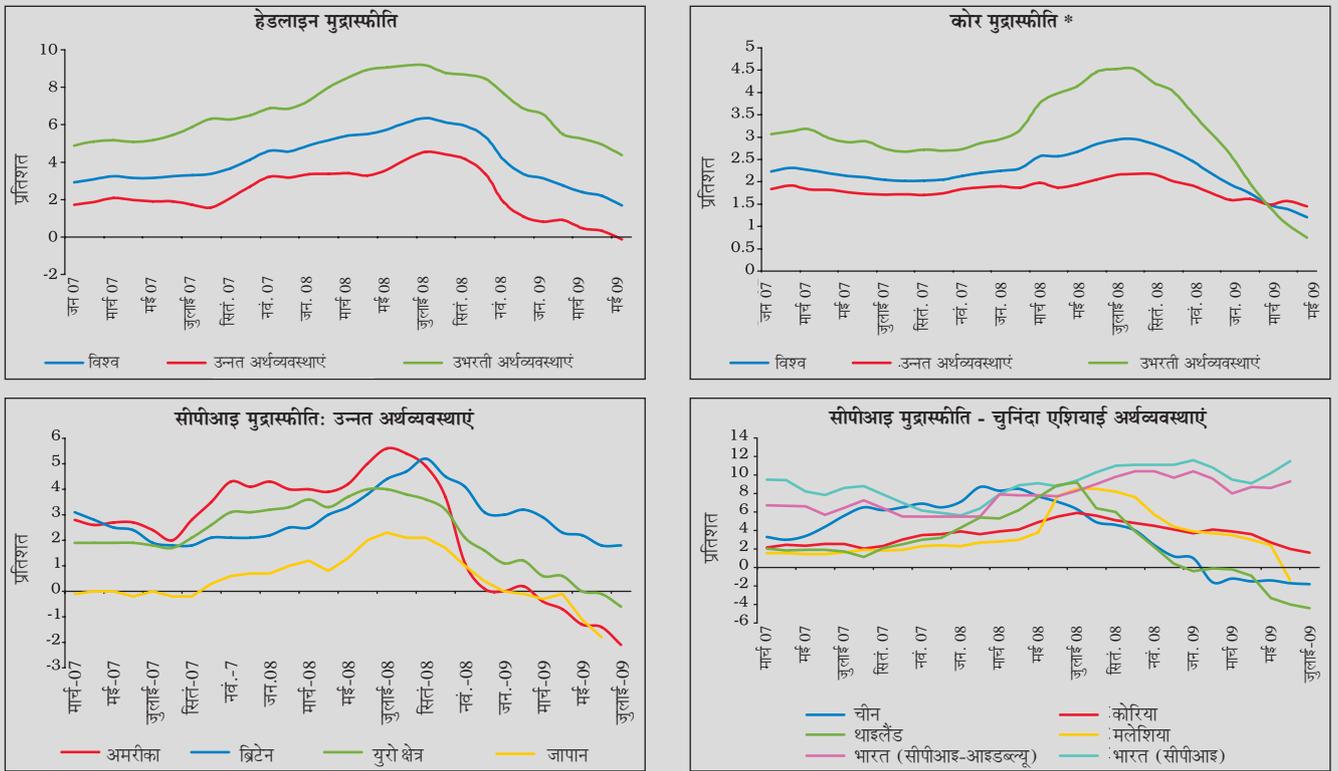
11.3.24 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय अस्थिरता देखी गई जो अभूतपूर्व है और वर्ष के भीतर विभिन्न विरोधी अवस्थाओं में मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अंतर्निहित घटकों के अनुसार विभिन्न गतिशीलताएं देखी गईं, जिन्होंने समान रूप से परस्पर विरोधी नीतिगत चुनौतियों को सामने रखा। मुद्रास्फीति में द्वि-अंक स्तर की वृद्धि के प्रथम चरण के दौरान और उसके बाद राजकोषीय वर्ष के अंत तक उसके तेजी से गिरकर एक प्रतिशत के नीचे चले जाने के दौरान बाह्य तथा आपूर्ति पक्ष के घटकों की प्रमुख भूमिका रही। वैश्विक प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हुए अगस्त

2008 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान 12.9 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुँच गई परंतु बाद में गिरकर मार्च 2009 के अंत तक 0.8 प्रतिशत रह गई। तदनुसार, वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीतिगत रुझान प्राथमिक रूप से मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को रोकने की तात्कालिकता पर निर्भर था, जबकि दूसरी छमाही में मंद मुद्रास्फीतिकारी चिंताओं ने स्पष्ट रूप से वृद्धि में कमी को रोकने और वित्तीय बाजारों की स्थिति सुव्यवस्थित बनाए रखने की ओर नीतिगत संतुलन को केंद्रित कर दिया।

वैश्विक स्फीतिकारक स्थितियां और मौद्रिक नीतिगत प्रतिक्रिया

11.3.25 पूरे विश्व में 2007-08 की दूसरी छमाही में जो स्फीतिकारक दबाव बढ़ रहे थे, वे 2008-09 की पहली छमाही में बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो प्रमुख रूप से अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में वृद्धि के कारण थे (चार्ट II.20)। यद्यपि, सबप्राइम

चार्ट II.20: वैश्विक मुद्रास्फीति



* खाद्य और ऊर्जा छोड़कर
 आइडब्ल्यू: औद्योगिक कामगार आइएएल: कृषि श्रमिक
 स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनैशनल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, आइएमएफ, संबंधित देशों की आधिकारिक वेबसाइटें.

संकट के धीरे-धीरे बढ़ते प्रभावों के कारण 2008-09 की पहली छमाही में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समग्र मांग दबावों में कुछ कमी होनी शुरू हो गई थी, फिर भी अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में लगातार दबाव के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति उच्च स्तरों पर बढ़ती रही। दूसरी ओर, विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं को न केवल बढ़ते अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों के कारण, बल्कि उनकी सुदृढ़ वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग संबंधी दबावों के कारण भी स्फीतिकारक दबाव झेलने पड़े। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य और ईंधन संबंधी पण्यों का स्फीतिकारक प्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर कुछ अधिक पड़ा क्योंकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में उपभोक्ता वस्तुओं के समूह में खाद्य और ईंधन संबंधी वस्तुओं का भार अधिक है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहे अधिकांश देशों ने भी 2008-09 की पहली छमाही में अपनी हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य से काफी अलग रहते हुए देखा।

11.3.26 वैश्विक वित्तीय संकट के गहरा जाने के प्रभाव के कारण वृद्धि की गति मंद हो जाने संबंधी बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए प्रति-स्फीतिकारी मौद्रिक नीति के रुझान के वृद्धि संबंधी निहितार्थों के संबंध में 2008-09 की पहली छमाही में उभरते स्फीतिकारक दबावों के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश केंद्रीय बैंकों को मंद आर्थिक गतिविधि और बढ़े हुए मुद्रास्फीतिकारक दबावों के संयोजन में तालमेल बिठाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्नत देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा के केंद्रीय बैंकों ने 2008 के प्रारंभ में नीति दरों को घटाया था, बाद में उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी ओर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं देशों के कई केंद्रीय बैंकों ने सितंबर 2008 तक मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने के लिए पूर्वक्रयात्मक मौद्रिक सख्ती को जारी रखी, क्योंकि उस समय तक यह आम धारणा बन चुकी थी कि अधिकांश विकासशील देशों की वास्तविक अर्थव्यवस्था पर अमरीकी सब-प्राइम संकट का प्रभाव न्यूनतम होगा।

11.3.27 वैश्विक मांग में कमी के दबाव के चलते अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में तेजी से गिरावट आने के कारण अगस्त 2008 से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारी दबाव उल्लेखनीय रूप से कम होने शुरू हो गए। 2008-09 की दूसरी छमाही के

दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी तीव्र थी जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मांग में गंभीर रूप से आई कमी का परिचायक है। साथ ही, चूंकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों के वृद्धिशील चरण के दौरान अंतरराष्ट्रीय पण्य और खाद्यान्न मूल्यों के देशी मुद्रास्फीति पर पूर्ण प्रभाव अंतरण को सीमित रखने के लिए विशिष्ट उपाय किये, अतः अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में आयी उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद विकासशील देशों के देशी मुद्रास्फीतिकारी दबावों पर तदनु रूप उतनी ही मात्रा में गिरावट नहीं हो पायी। तथापि, संभाव्य डी-कपलिंग संबंधी पहले के अनुमानों के विपरीत उभरते/विकासशील देशों को भी इसी प्रकार के संमिश्र परिणामों का, जो न्यूनतम मुद्रास्फीति के जोखिम के साथ धीमी वृद्धि के रूप में थे, सामना करना पड़ा, इनके कारण मौद्रिक नीति में नरम रुख रुझान अपनाने की गुंजाइश बढ़ गई। इस प्रकार 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान मौद्रिक नीति का अधिक बल आर्थिक वृद्धि और रोजगार पर पड़नेवाले वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रति रहा। इस कारण, विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने सितंबर 2008 से अपनी नीतिगत दरें काफी घटा दीं (सारणी 2.28)।

11.3.28 अधिकांश केंद्रीय बैंकों के सामने 2008-09 के दौरान आई एक प्रमुख चुनौती थी - मुद्रास्फीति में एक वर्ष के भीतर पाया गया तीव्र उतार-चढ़ाव। घट-बढ़ के गुणांक के रूप में मापा जानेवाला उतार-चढ़ाव, जिसमें वर्ष 2003 से गिरावट आ रही थी, वर्ष 2007 से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता गया। यह भी देखा जा सकता है कि मुद्रास्फीति का उतार-चढ़ाव उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में काफी उच्चतर रहा है (चार्ट 11.21) बावजूद इसके कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रास्फीति दर से निरंतर ऊपर ही रही है।

11.3.29 चूंकि मुद्रास्फीति घटकर शून्य स्तर के निकट आ गई और यहां तक कि अस्थायी रूप से ऋणात्मक भी बन गई थी, अतः अवस्फीति की स्थिति का सामना करने के लिए नीतिगत विकल्पों के बारे में चिंता बढ़ गई। अवस्फीति से मौद्रिक नीति की व्याप्ति तथा कारगरता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती थीं। कई उन्नत देशों में नीतिगत दरें पहले ही शून्य

सारणी 2.28: वैश्विक मुद्रास्फीति संकेतक

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	प्रमुख नीतिगत दर	नीतिगत दर (20 अगस्त 2009 को)	नीतिगत दरों में परिवर्तन (आधार अंक)			सीपीआइ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वर्ष-दर-वर्ष)		
			मार्च 08- सितं 08	सितं 08- मार्च 09	मार्च 09 के अंत से	जुला 2008	मार्च 2009	जुला 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकसित अर्थव्यवस्थाएं								
ऑस्ट्रेलिया	नकदी दर	3.00 (अप्रैल.8, 2009)	25	(-) 400	(-) 25	4.5 ^{Q2}	2.5 ^{Q1}	1.5 ^{Q2}
कनाडा	ओवरनाइट दर	0.25 (अप्रैल.21, 2009)	(-)100	(-) 250	(-) 25	3.4	1.2	-0.9
यूरो क्षेत्र	मुख्य पुनर्वित्तपोषण परिचालनों पर ब्याज दर	1.00 (मई 13, 2009)	25	(-) 275	(-) 50	4.0	0.6	-0.6
जापान	असंपाशिविक्रीकृत ओवरनाइट मांग दर	0.10 (दिसं.19, 2008)	0	(-) 40	0	2.0 *	-0.3	-1.8 *
यूके	अधिकारिक बैंक दर	0.50 (मार्च 5, 2009)	(-)25	(-) 450	0	4.4	2.9	1.8
यूएस	फेडरल निधि दर	0.00 to 0.25 (दिसं.16, 2008)	(-)25	(-) 200	0	5.6	-0.4	-2.1
विकसित अर्थव्यवस्थाएं								
ब्राजील	सेलिक दर	8.75 (जुला 23, 2009)	250	(-) 250	(-) 250	6.4	5.6	4.5
भारत	रिवर्स रिपो दर	3.25 (अप्रैल. 21, 2009)	0	(-) 250	(-) 25	7.7 *	8.0	9.3 *
	रिपो दर	4.75 (अप्रैल 21, 2009)	125	(-) 400	(-) 25			
चीन	बेचमार्क 1 वर्षीय उधार दर	5.31 (दिसं. 23, 2008)	0	(-) 216	0	6.3	-1.2	-1.8
			(200)	(-300)	0			
इंडोनेशिया	बैंक इंडोनेशिया (बीआइ) दर	6.50 (अग. 5, 2009)	100	(-) 150	(-) 125	11.9	7.9	-2.7
इजराइल	मूल दर	0.50 (अप्रैल.1, 2009)	50	(-) 350	(-) 25	4.8	3.6	3.5
कोरिया	आधार दर	2.00 (फर. 12, 2009)	25	(-) 325	0	5.9	3.9	1.6
फिलीपीन्स	रिवर्स रिपो दर	4.00 (जुला 9, 2009)	100	(-) 125	(-) 75	12.3	6.4	0.2
रूस	पुनर्वित्त दर	10.75 (अग. 10, 2009)	50	200	(-) 225	14.7	14.0	12.0
दक्षिण अफ्रीका	रिपो दर	7.00 (अग. 4, 2009)	100	(-) 250	(-) 250	12.2 *	8.5	6.9 *
थाईलैंड	1 दिवसीय पुनर्खरीद दर	1.25 (अप्रैल. 8, 2009)	50	(-) 225	(-) 25	9.2	-0.2	-4.4

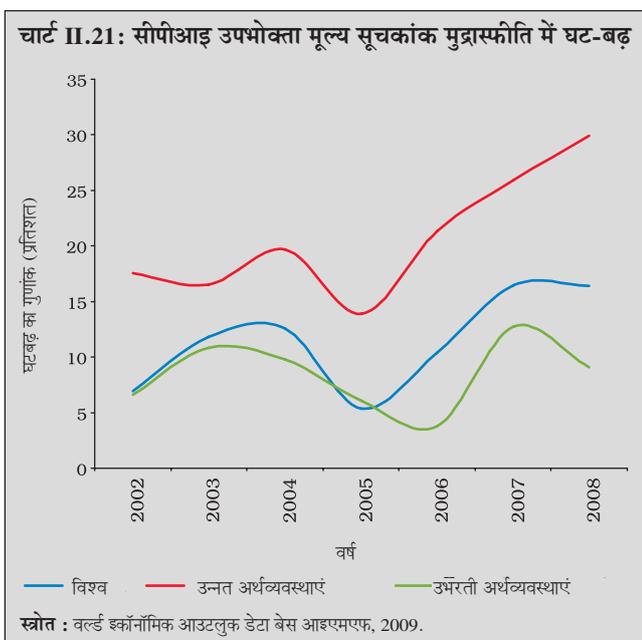
*: जून

टिप्पणी

1. भारत के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े औद्योगिक कामगारों के सीपीआइ से संबंधित हैं।
2. स्तंभ (3) के कोष्ठकों के आंकड़े उन तारीखों को दर्शाते हैं जब नीति दरों में अंतिम बार संशोधन किया गया।
3. स्तंभ (4) के कोष्ठकों के आंकड़े आलोच्य अवधि के दौरान नकदी आरक्षित अनुपात में घटबढ़ को सूचित करते हैं।

स्रोत

: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संबंधित केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें तथा दि इकॉनॉमिस्ट।



स्तर के निकट लाई जा चुकी थीं, ऐसी स्थिति में, अवस्फीतिकारी परिस्थितियां जारी रहने का अर्थ होगा मौद्रिक नीति वास्तविक ब्याज दर में ऐसी आवश्यक कटौती सुनिश्चित नहीं कर पा सकेगी जो अवस्फीति की प्रमुख स्थितियों (हेड विंड) का सामना करने के लिए जरूरी है। यदि अवस्फीतिकारी लक्षण बने रहते हैं तो उनके कारण और अधिक गंभीर ऋण अवस्फीति (डिफ्लेशन) की स्थिति आ सकती है, अर्थात् वास्तविक रूप में ऋण भार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके कारण चूकें व्यापक रूप से बढ़ेंगी जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था से वित्तीय क्षेत्र तक ऋणात्मक हेतुक प्रतिसाद में तेजी आयेगी, जो आगे चलकर परस्पर मिलकर संकट की तीव्रता को बढ़ाएगी। अधिकांश देशों में (कुछ को छोड़कर) वास्तविक नीति दर सितंबर 2008 से घट गई है, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक मौद्रिक नरमी का संकेत देती है (सारणी 2.29)।

सारणी 2.29: सांकेतिक और वास्तविक नीतिगत दरें : चुनिंदा देश

(प्रतिशत)

देश	सांकेतिक नीति दर			वास्तविक नीति दर		
	मार्च 2008	सितं. 2008	मार्च 2009	मार्च 2008	सितं. 2008	मार्च 2009
1	2	3	4	5	6	7
विकसित अर्थव्यवस्थाएं						
अमरीका	2.25	2.00	0.25	-1.75	-2.90	0.05
ब्रिटेन	5.25	5.00	0.50	2.75	0.20	-2.50
यूरो क्षेत्र	4.00	4.25	1.50	0.40	0.65	0.30
विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
ब्राजील	11.25	13.75	11.25	6.55	7.45	5.65
चीन	7.47	7.20	5.31	-0.83	2.60	6.91
भारत	7.75	9.00	5.00	-0.15	-0.80	-3.00
				(0.00)	(-3.10)	(4.16)
इंडोनेशिया	8.00	9.25	7.75	1.70	-2.85	-0.15
इजराइल	3.75	4.25	0.75	0.05	-1.25	-2.85
कोरिया	5.00	5.25	2.00	1.10	0.15	-1.90
फिलीपीन्स	5.00	6.00	4.75	-1.40	-5.90	-1.65
रूस	10.25	11.00	13.00	-3.05	-5.10	-1.00
दक्षिण अफ्रीका	11.00	12.00	9.50	0.40	-1.10	0.90
थाईलैंड	3.25	3.75	1.50	-2.05	-2.25	1.70

टिप्पणी : 1. वास्तविक नीति दर वह है जो नीति दर से वर्ष-दर-वर्ष उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फूर्ति घटाकर पाया जाता है। भारत में रिपो दर को नीति दर माना जाता है, जबकि मुद्रास्फूर्ति सीपीआई औद्योगिक कामगारों से संबंधित है।
2. भारत के लिए कोष्ठकों के आंकड़े थोक मूल्य मुद्रास्फूर्ति पर आधारित हैं।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दि इकॉनॉमिस्ट और संबंधित केंद्रीय बैंकों की आधिकारिक वेबसाइटें।

वैश्विक पण्य मूल्य

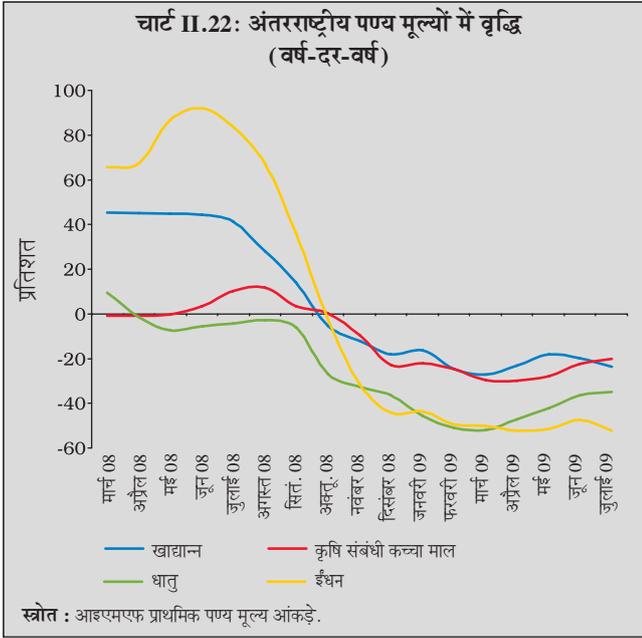
II.3.30 वर्ष 2008-09 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पण्य दरों में उसमें तेज गति से गिरावट देखी गयी (सारणी 2.30 और जुलाई 2008 तक तीव्र वृद्धि पायी गयी, परंतु उसके बाद चार्ट II.22)।

सारणी 2.30: अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें

पण्य	यूनिट	2004 बाजार मूल्य	सूचकांक (2004=100)								घट-बढ़ (प्रतिशत)	
			2005	2006	2007	2008-09				मार्च 08 की तुलना में मार्च 09	जुलाई 08 की तुलना में मार्च 09	
						मार्च	जून	सितं.	दिसं.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ऊर्जा												
कोयला	\$/एमटी	53.0	90	93	124	223	302	283	149	115	-48.4	-66.1
कच्चा तेल(औसत)	\$/बीबीएल	37.7	142	170	188	270	349	264	110	124	-54.2	-64.9
गैर ऊर्जा पण्य												
पामतेल	\$/एमटी	471.3	90	101	165	265	257	164	107	127	-52.2	-47.1
सोयाबीन तेल	\$/एमटी	616.0	88	97	143	240	250	199	120	118	-50.9	-52.0
सोयाबीन	\$/एमटी	306.5	90	88	125	188	203	166	117	123	-34.3	-40.4
चावल	\$/एमटी	237.7	120	128	137	250	318	288	224	247	-1.0	-19.6
गेहूं	\$/एमटी	156.9	97	122	163	280	222	188	140	147	-47.5	-29.6
मक्का	\$/एमटी	111.8	88	109	146	210	257	209	142	147	-29.8	-38.0
चीनी	सी/किग्रा	15.8	138	206	141	184	169	189	164	187	1.5	-5.8
कपास ए सूचकांक	सी/किग्रा	136.6	89	93	102	129	124	119	90	83	-35.8	-33.4
अल्यूमीनियम	\$/एमटी	1716.0	111	150	154	175	172	147	87	78	-55.5	-56.5
तांबा	\$/एमटी	2866.0	128	235	248	294	288	244	107	131	-55.6	-55.4
सोना	\$/टीओजेड	409.2	109	148	170	237	217	203	199	226	-4.6	-1.6
चांदी	\$/टीओजेड	669.0	110	173	200	287	255	182	154	196	-31.8	-27.4
स्टील हॉट- रोल्ड कॉइल शीट	\$/एमटी	607.1	121	114	107	132	181	181	181	148	12.5	-18.2
स्टील हॉट- रोल्ड कॉइल शीट	\$/एमटी	502.5	126	119	109	149	199	199	199	159	6.7	-20.0
टिन	सी/किग्रा	851.3	87	103	171	233	261	216	132	125	-46.1	-53.9
जिंक	सी/किग्रा	104.8	132	313	309	240	181	166	105	116	-51.5	-34.3

\$/ अमरीकी डॉलर सी : अमरीकी सेंट बीबीएल : बैरल एमटी : मैट्रिक टन किग्रा : किलो ग्राम टीओजेड : ट्रॉय औंस

स्रोत : विश्व बैंक के वास्तविक पण्य मूल्य आंकड़ों पर आधारित। संबंधित अवधि के दौरान मूल्य की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए वर्ष 2004 को आधार वर्ष मान लिया गया है।



II.3.31 जुलाई 2008 तक अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में कई कारणों से उछाल आयी। वर्ष 2007 से, कई पण्यों के लिए पहले से ही न्यून स्तर इन्वेंटरी की पृष्ठभूमि में बाजार में मांग आपूर्ति संतुलन तंग बना रहा। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं से आयी तीव्र मांग द्वारा और गहरा गया, जो पण्य उपभोग में वृद्धिशील वृद्धि में दिखी। जोतने लायक (कृष्य) भूमि का उपयोग जैव-ईंधन उत्पादन के लिए किए जाने के कारण मक्का तथा चीनी जैसे कतिपय खाद्य पण्यों की आपूर्ति प्रभावित हुई। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में प्रभावी मूल्यहास और पण्य फ्यूचर्स में वित्तीय बाजार सहभागियों की बढ़ी रुचि ने भी मूल्य वृद्धि में अंशदान किया।

II.3.32 जुलाई-दिसंबर 2008 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में आयी तीव्र गिरावट अधिकांशतः ऐसे संकेतों के कारण थी कि उन्नत तथा उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वृद्धि का धीमापन पहले से प्रत्याशित स्तर की तुलना में काफी गहरा तथा दीर्घकालीन सिद्ध हो सकता है। मूल्यों में गिरावट का आंशिक कारण वित्तीय बाजारों की तंग चलनिधि स्थितियों के कारण वित्तीय बाजार निवेशकों द्वारा पण्य निवेश का मोचन भी था।

भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति

II.3.33 रिजर्व बैंक का 2008-09 का वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) बढ़े हुए मुद्रास्फीति स्तरों की पृष्ठभूमि में घोषित

किया गया था और इस नीतिगत वक्तव्य में मुद्रास्फीति को वर्ष 2008-09 में घटाकर लगभग 5.5 प्रतिशत तक लाने के बैंक के संकल्प को दृढ़तापूर्वक दुहराया गया, तथा मुद्रास्फीति के अंतर्निहित निर्धारक तत्वों, जिसमें वैश्विक बाजार की उच्चतर मुद्रास्फीति के संप्रेषण का प्रभुत्व था, की उभरती जटिलताओं को स्वीकार करते हुए इसे यथासंभव शीघ्र 5.0 प्रतिशत तक लाने को तरजीह दी गई। तीव्र मांग तथा अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य के भारी दबावों के कारण 2008-09 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति और बढ़ गई। इस संदर्भ में यह माना गया कि अर्थव्यवस्था-व्यापी आधार पर समग्र कुल मांग का समायोजन करना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित हो कि एक सामान्यीकृत अस्थिरता न बने और भारत की वृद्धि की गतिशीलता पर परिणाम एवं सकारात्मक सोच दोनों ही के रूप में मुश्किल से हासिल उपलब्धियां खो न जाएं। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने मई और अगस्त 2008 के बीच प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कुल 125 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर उसे 9.0 प्रतिशत कर दिया और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिपो दर जून-जुलाई 2008 के दौरान कुल 125 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ 9.0 प्रतिशत कर दी गई।

II.3.34 थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अगस्त 2008 से घटने लगी, जो मुख्य रूप से मुक्त रूप से मूल्यन किये जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों और वस्त्रों के मूल्यों में गिरावट के कारण थी। वर्ष 2008-09 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह देखा गया कि और आघात न होने की स्थिति में सामान्यीकृत मुद्रास्फीति बनी नहीं रह पाई, विशेष रूप से तब जब मुद्रा आपूर्ति वर्ष 2003-08 की औसत दर पर सीमित रही थी, यह वह अवधि है जब मुद्रास्फीति न्यून और स्थिर थी। मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए पता लगाई गई चुनौतियां थीं - बनी हुई एवं मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं में सन्निहित मुद्रास्फीति के उस समय विद्यमान स्तरों की जोखिम के मुकाबले उत्पादन की अस्थिरता के रूप में मुद्रास्फीति को कम करने की लागत में संतुलन लाना। सितंबर 2008 से प्रारंभ कर, रिजर्व बैंक ने अपना नीतिगत रुख कुल मांग को सीमित रखने से बदलकर मांग विस्तार को समर्थन देने पर रखा ताकि वृद्धि में धीमेपन को रोका जा सके। तदनुसार, अक्टूबर 2008 और मार्च 2009 के बीच, रिजर्व बैंक ने एलएएफ के अधीन रिपो दर 9.0 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत, एलएएफ के अधीन रिवर्स रिपो दर 6.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत और सीआरआर 9.0

प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दी। इन उपायों उद्देश्य यह था कि देशी चलनिधि में वृद्धि की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण का प्रवाह अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के प्रति बना रहे। 2008-09 की मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही की समीक्षा में यह भी कहा गया कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में अभी भी कमी आनी थी तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं में आयी गिरावट थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में हुई तीव्र गिरावट के अनुपात में नहीं थी।

11.3.35 रिजर्व बैंक के 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह पाया गया कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर शून्य स्तर के निकट आ रही थी, संभवतः ऋणात्मक स्तर की बनने जा रही थी, हालांकि अल्प समय के लिए ही, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के यह संकेत करते हुए कम होने की आशा थी कि मुद्रास्फीतिकारी जोखिम स्पष्ट रूप से कम हो गए है। नीतिगत वक्तव्य में मार्च 2010 के अंत तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगभग 4.0 प्रतिशत आंकी गई थी। इस कम होते जा रहे स्फीतिकारी दबावों की पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने और प्रोत्साहनकारी मौद्रिक उपाय घोषित किये जो 21 अप्रैल 2009 को एलएएफ के अधीन रिपो दर में कटौती कर उसे 5.0 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत और एलएएफ के अधीन

रिवर्स रिपो दर को 3.5 प्रतिशत से 3.25 प्रतिशत कर देने के रूप में थे।

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

11.3.36 2008-09 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) में वर्ष-दर-वर्ष होनेवाले उतार-चढ़ाव के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति में मजबूती आई और यह मार्च 2008 के अंत के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 2 अगस्त 2008 को 12.9 प्रतिशत पर अंतर्वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के उच्च मूल्यों का आंशिक रूप में देशी मूल्यों में अंतरण प्रभाव और साथ ही, लोहा और इस्पात, मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायनों, मशीनरी तथा मशीन के औजारों, तिलहन/खली, कपास और वस्त्रों के बढ़े हुए मूल्य स्तर इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक थे (सारणी 2.31)। इस अवधि के दौरान हुई मुद्रास्फीति वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में आलोच्य अवधि के दौरान पाई गई उच्च वृद्धि से उत्पन्न भारी मांग संबंधी दबावों को भी दर्शाती है।

11.3.37 बढ़ती मुद्रास्फीति चिंताओं के उत्तर में ऊपर वर्णित मौद्रिक नीतिगत उपायों के अलावा, सरकार ने उच्च अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए कई राजकोषीय नीतिगत

सारणी 2.31 : प्रमुख पण्यों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव - वैश्विक बनाम देशी

(प्रतिशत)

मद	चरण I		चरण II		वार्षिक	
	मार्च 2008 के अंत से जुलाई 2008 तक		जुलाई 2008 से मार्च 2009 के अंत तक		मार्च 2008 के मुकाबले मार्च 2009	
	वैश्विक	भारत	वैश्विक	भारत*	वैश्विक	भारत*
1	2	3	4	5	6	7
1. चावल	23.2	1.2	-19.6	13.6	-1.0	12.8
2. गेहूं	-25.4	4.1	-29.6	0.5	-47.5	5.2
3. कपास	-3.6	24.3	-33.4	-17.6	-35.8	2.5
4. तिलहन	10.3	6.5	-40.4	-7.7	-34.3	-2.3
5. चीनी	7.8	0.1	-5.8	18.5	1.5	18.4
6. कोयला खनन	52.2	0.0	-66.1	-1.0	-48.4	-1.0
7. खनिज तेल	30.4	17.8	-64.9	-22.5	-54.2	-8.7
8. खाद्य तेल	2.4	2.5	51.9	-12.4	-50.7	-10.2
9. खली	14.7	21.2	-32.5	-9.9	-22.6	19.4
10. मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायन	..	8.5	..	-19.9	..	-13.7
11. लोहा और इस्पात	34.2	2.8	-23.5	-20.6	2.7	-18.4
12. गैर-लौह धातुएं #	34.2	0.1	-45.0	-9.1	-48.2	-9.1

* : 28 मार्च 2009 के डब्ल्यू पी आइ पर आधारित

: वैश्विक मूल्य आइएमएफ के धातु मूल्य सूचकांक के रूप में है जिसमें तांबा, अल्युमिनियम, लौह अयस्क, टिन, निकल, जिंक, सीसा और यूरेनियम शामिल हैं।

टिप्पणी: वैश्विक मूल्य वृद्धि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख पण्य कीमतों संबंधी आंकड़ों पर आधारित हैं।

पहले की। इनमें चावल, दालों, गेहूं, खाद्य तेल, मक्का, दूध, लोहा और इस्पात, कपास, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पण्यों के मामले में आयात शुल्क घटाना/समाप्त करना शामिल था। अप्रैल 2008 में दालों, खाद्य तेलों और गैर-बासमती चावल जैसे अत्यावश्यक पण्यों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोहा और इस्पात के उत्पादों जैसे पण्यों पर निर्यात शुल्क भी लगाया गया और कपास के निर्यातकों को उपलब्ध कर लाभ हटा लिये गये। इन प्रत्यक्ष उपायों के अलावा, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों के प्रभाव को नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के देशी मूल्यों पर पूर्णतः अंतरित न करते हुए तथा राज्यों द्वारा चलाई जानेवाली तेल कंपनियों को तेल बांड जारी करते हुए भार को बांटने की नीति अपनायी।

II.3.38 डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में अगस्त 2008 से भारी गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई और वह 28 मार्च 2009 को 0.8 प्रतिशत हो गई। 2 अगस्त 2008 से 28 मार्च 2009 के बीच की अवधि में डब्ल्यूपीआइ में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जो पेट्रोलियम उत्पादों एवं बिजली के नियंत्रित मूल्यों में कटौती तथा मुक्त रूप से मूल्य लगाई गई खनिज तेल मदों, लोहा और इस्पात, तिलहनों, खाद्य तेलों, खली और कच्ची रूई के मूल्यों में आयी गिरावट के कारण थी। आधारभूत प्रभाव भी वर्ष के अंत में डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में आई कमी का एक बड़ा कारण था जो वर्ष 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति में तेजी से दर्ज की गई वृद्धि का परिचायक है। तथापि, डब्ल्यूपीआइ में हुई यह गिरावट भारत में अपस्फीतिकारी स्थितियां बन जाना सूचित नहीं करती (बॉक्स II.16)।

II.3.39 हालांकि ईंधन मूल्यों में भारी अस्थिरता 2008-09 के दौरान मुद्रास्फीति के परिणाम का प्रमुख कारक थी, फिर भी, ईंधन के घटक को छोड़कर मुद्रास्फीति को देखने पर मुद्रास्फीति का सामान्यीकृत स्वरूप नजर आता है। ईंधन को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 28 मार्च 2009 को एक वर्ष पहले के 8.0 प्रतिशत की तुलना में 2.7 प्रतिशत थी। यह देखा जा सकता है कि जून-अक्टूबर 2008 की अवधि के दौरान, जब डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति काफ़ी उच्च स्तर की थी, ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर समग्र मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआइ से उच्चतर थी 1 अक्टूबर 2008 से समग्र मुद्रास्फीति ईंधन को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति की तुलना में न्यूनतर है (चार्ट II.23), जो दर्शाती है कि मुद्रास्फीति के ईंधनेतर घटक

ईंधन समूह की तुलना में उतने अस्थिर नहीं थे। औसत वार्षिक डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति दर (52 सप्ताहों का औसत) जून 2008 के अंत के 5.8 प्रतिशत और मार्च 2008 के अंत के 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 28 मार्च 2009 को 8.3 प्रतिशत हो गई।

II.3.40 प्रमुख पण्य समूहों में वर्ष-दर-वर्ष प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 15 नवंबर 2008 को 12.7 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। यह मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं तथा खाद्येतर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को इंगित करता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 2007 से भारत में खाद्य वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि दर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी न्यूनतर स्तर की थी (चार्ट II.24)। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि जुलाई 2008 में 9.6 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि के दौरान आईएमएफ खाद्य मूल्य सूचकांक में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह सरकार द्वारा आपूर्ति संबंधी किए गए विभिन्न उपायों तथा विश्व की आपूर्ति स्थिति की तुलना में कई मदों में बेहतर घरेलू आपूर्ति स्थितियों के कारण थी।

II.3.41 प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति में जनवरी 2009 से उल्लेखनीय रूप से नरमी आयी और वह खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जियों तथा फलों, और कच्ची रूई, तिलहन और खनिज जैसी खाद्येतर वस्तुओं के मामले में मूल्य गिर जाने के कारण 28 मार्च 2009 को 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। जहां खाद्य वस्तुओं के मूल्य में आयी गिरावट आंशिक रूप से 2008-09 के दौरान अच्छी *रबी फसल* तथा मौसमी स्वरूप को दर्शाती है, वहीं खाद्येतर प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में आयी गिरावट रूई, तिलहन और खनिज वस्तुओं के मूल्यों में आयी अंतरराष्ट्रीय गिरावट के कारण थी। चावल दालों तथा सब्जियों के मूल्य बढ़े हुए स्तर पर बने हुए हैं।

II.3.42 2008-09 की पहली छमाही के दौरान चूंकि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर्याप्त मात्रा में बढ़े थे, अतः ईंधन समूह मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2 अगस्त 2008 को 18.0 प्रतिशत के अंतर्वर्षीय सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। खनिज तेल के मूल्य में हुई वृद्धि इसका कारक थी जो 4 जून 2008 को की गई पेट्रोल (प्रति लीटर 5 रु.), डीजल (प्रति लीटर 3 रु.), और एलपीजी (प्रति सिलिंडर 50 रु.) के मूल्य और मुक्त रूप से मूल्यित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की वृद्धि में अधीन है।

बॉक्स II.16 अपस्फीति संबंधी धारणा

भारत में, मुद्रास्फीति की दर 2 अगस्त 2008 के 12.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर मार्च 2009 के अंत तक एक प्रतिशत से नीचे स्तर पर पहुंच गई, इसमें मुद्रास्फीति घटकर अस्थायी तौर पर या और भी लंबे समय के लिए शून्य से नीचे के स्तर पर पहुंचने की संभावना बन गई थी और इससे अपस्फीति की धारणा जोखिम उत्पन्न हो गई थी। वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जून 2009 के पहले सप्ताह से ऋणात्मक हो गई। तथापि, बढ़ती चिंताओं के बावजूद, कोई तकनीकी अपस्फीति या अपस्फीति के साथ अक्सर पाए जानेवाले गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाये गये।

बनकि (2002) के अनुसार अपस्फीति को मूल्यों में आनेवाली सामान्य गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें 'सामान्य' शब्द पर बल दिया जाता है। इस प्रकार, विशिष्ट सेक्टरों में मूल्य गिरावट, उदाहरण के लिए बढ़ती उत्पादकता या लागतों के घट जाने के कारण होनेवाली गिरावट, मूल्यों में होनेवाली सामान्य गिरावट नहीं होती है। प्रातिनिधिक दूर तक फैले व्यापक आधारवाले मूल्य सूचकांक में होनेवाली गिरावट ही अपस्फीति के संकेत दे सकती है। इस पर भी, अपस्फीति के रूप में माने जाने के लिए ऐसे घटते मूल्यों का कुछ समय तक बने रहना जरूरी है।

अपस्फीति के पीछे निहित प्राथमिक हेतुक कारक है कुल मांग में गिरावट है, हालांकि अपस्फीति उत्पादकता में तेजी से होनेवाली वृद्धि तथा लागतों में तीव्र गिरावट के कारण कुल आपूर्ति के अकस्मात एवं बड़े पैमाने पर बढ़ जाने के फलस्वरूप भी हो सकती है। तथापि, आपूर्ति पक्ष से होनेवाली अपस्फीति बहुत ही कम पायी जाती है।

अपस्फीति की तकनीकी परिभाषा तथा उसे उत्पन्न करने वाले प्राथमिक कारणों के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि भारत का डब्ल्यूपीआइ सितंबर 2008 से फरवरी 2009 के बीच की करीब-करीब छः महीनों की अवधि में घट गया था जो कुल घरेलू मांग में किसी तीव्र कमी के कारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र करेक्शन के कारण था। साथ ही, जिस समय डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति शून्य के आसपास स्थित थी, उस समय सीपीआइ आधारित मुद्रास्फीति में मूल्यों में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि बनी हुई थी।

कुल मांग में अकस्मात कमी आस्ति-मूल्य के बुलबुले के फट जाने के फलस्वरूप आशातीत वृद्धि तथा उत्पादकता अनुमानों में आये अकस्मात परिवर्तन अथवा भौगोलिक-राजनीतिक या अन्य कारणों से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ जाने का परिणाम हो सकती है। भारत के मामले में इनमें से कोई कारक मौजूद नहीं थे और वृद्धि में आई कुछ कमी के बावजूद ऋणात्मक मुद्रास्फीति के साथ साथ उत्पादन में आई कमी के बावजूद वर्ष 2008-09 में उत्पादन वास्तव में 6.7 प्रतिशत बढ़ा, जो विश्व में हुई उच्चतम वृद्धियों में से एक थी।

यह वास्तविकता है कि भारत में कभी भी अपस्फीति नहीं आयी, फिर भी, अपस्फीति के गंभीर प्रतिकूल प्रभावों को जानना तथा उन नीतियों का ज्ञान कर लेना महत्वपूर्ण है जिन्हें अपस्फीतिकारी स्थितियों का सामना करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अपस्फीति के कारण अनिवार्यतः ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ केंद्रीय बैंक के पारंपरिक नीतिगत साधन निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि घटती कुल मांग को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया में ब्याज दर कम होकर शून्य हो जाती है। 'शून्यवत' सांकेतिक ब्याज दर बाधाओं के साथ जुड़े 'चलनिधि ट्रैप' के कारण धनात्मक वास्तविक दरें उत्पन्न होती हैं, और घटते मूल्यों के कारण भविष्य में मुद्रास्फीति में और अधिक गिरावट की संभावना बन जाने से ये

और बदतर हो जाती हैं। इस परिदृश्य में उपभोग, विशेष रूप से ऋण वित्तपोषित उपभोग को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है परंतु इससे गंभीर 'ऋण अपस्फीति' भी निर्मित हो सकती है। उत्पादन और रोजगार की हानि के अलावा, ऋण अपस्फीति से चूक की स्थितियां बढ़ जाती हैं और यह स्थिति तेजी से बिगड़कर वित्तीय संकट उत्पन्न कर देती है। इसीलिए अपस्फीति को रोकना अक्सर मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

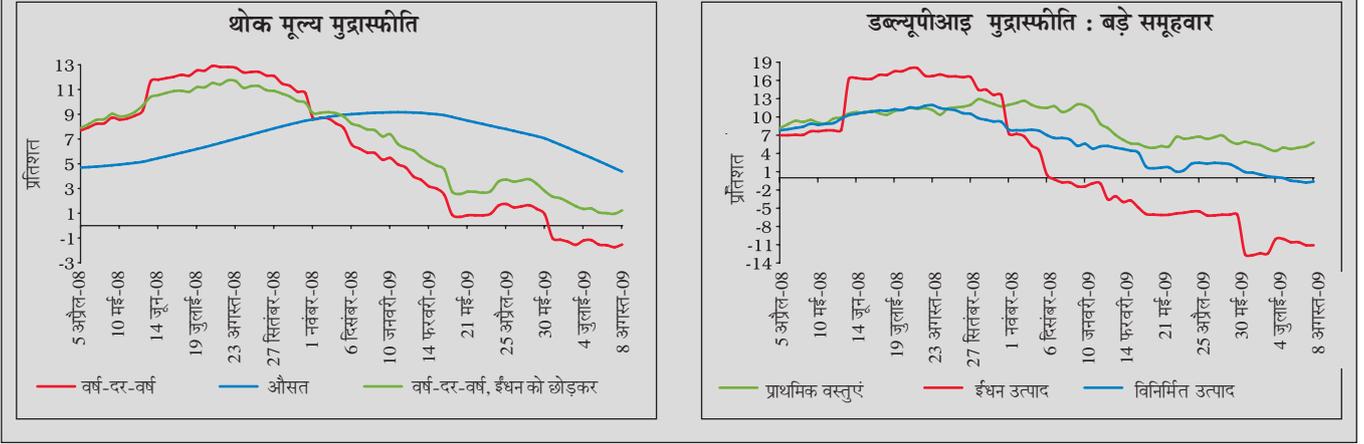
इस आम धारणा के बावजूद कि जब केंद्रीय बैंक की ब्याज दर कार्रवाइयों के लिए उसे 'शून्यवत' सीमा से जूझना पड़ता है, तब उसके पास कोई साधन ही नहीं बच जाता है, बनकि (2002) के मत में, कोई केंद्रीय बैंक "निश्चित रूप से साधनहीन (कभी) नहीं बनता है केंद्रीय बैंक अपने पास स्वयं ही या सरकार के अन्य अंगों के सहयोग से उसकी प्रचलित नीति दर 'शून्य' हो जाने पर भी कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने की पर्याप्त शक्ति रखता है"। बनकि के अनुसार, अपस्फीति के आघातों का सामना करने के लिए एक सुदृढ़, अच्छी पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली और सुचारु रूप से कार्य करनेवाले पूंजी बाजार एक महत्वपूर्ण रक्षा उपाय के रूप में उभर सकते हैं। अपस्फीति का सामना करने में सांकेतिक पारिश्रमिक लोच अर्थात् मुद्रास्फीति में आयी कमी से भी अधिक मात्रा में मजदूरी घट जाने से भी सहायता मिल सकती है। स्वेन्सन (2003) ने अपस्फीतिकारी स्थितियों से निपटने के विशिष्ट विकल्प सुझाए हैं: (क) मुद्रा से वित्तपोषित राजकोषीय विस्तार, (ख) मुद्रा का मूल्यहास, (ग) मुद्रा पर कर (जिससे शून्यवत बाधा से बचा जा सके), (घ) मुद्रा आधार को बढ़ाना (जब तक कि उनसे मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं अधिक न हो जाएं), और (ङ) एक सकारात्मक (विश्वसनीय) मुद्रास्फीति लक्ष्य घोषित करना।

भारत में नीतिगत दरें 'शून्यवत' दरों की जाल से कोसों दूर हैं और बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ तथा आघात सहने योग्य है और वित्तीय बाजार भी व्यवस्थित हैं। बैंकों के लिए एक असुरक्षितता के स्रोत के रूप में ऋण अपस्फीति का कोई सबूत नहीं है। साथ ही, डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद स्फीतिकारी प्रत्याशाओं के उसी दर से घट जाने के कोई प्रमाण नहीं हैं। नीतिगत न्यूनतर दरों से ऋण देने संबंधी दरों के बीच का संचारण अंतराल एवं वर्तमान मंदी की स्थिति के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर कुछ दबाव आने की संभावना जैसे चिंता के कुछ विषय हैं; परंतु, ऐसा भारत में अपस्फीतिकारी ताकतें होने के कारण नहीं है। जैसा कि रिजर्व बैंक के वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया था, ऋणात्मक मुद्रास्फीति की व्याख्या "नीति के प्रयोजन के लिए अपस्फीति के रूप नहीं की जानी चाहिए। भारत में इस प्रत्याशित ऋणात्मक मुद्रास्फीति का सिर्फ सांख्यिकीय महत्व है और यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तरह मांग में संकुचन का परिचायक नहीं है"।

संदर्भ :

1. बनकि, बेन एस. (2002) "डिफ्लेशन: मेकिंग श्यूर इट डजंट हैप्पन हियर", नेशनल इकानामिस्ट क्लब के सम्मुख की गई टिप्पणियां, वाशिंगटन डीसी, 21 नवंबर 2002।
2. स्वेन्सन, लार्स ई.ओ. (2003) एस्केपिंग फ्रॉम ए लिक्विडिटी ट्रैप एण्ड डिफ्लेशन: दि फूलपूफ वे एण्ड अदर्स, जर्नल ऑफ इकॉनामिक परस्पेक्टिव्स 17, 145-166।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (2009), वर्ष 2009-10 का वार्षिक नीति वक्तव्य, 21 अप्रैल 2009।

चार्ट II.23 : वार्षिक डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति



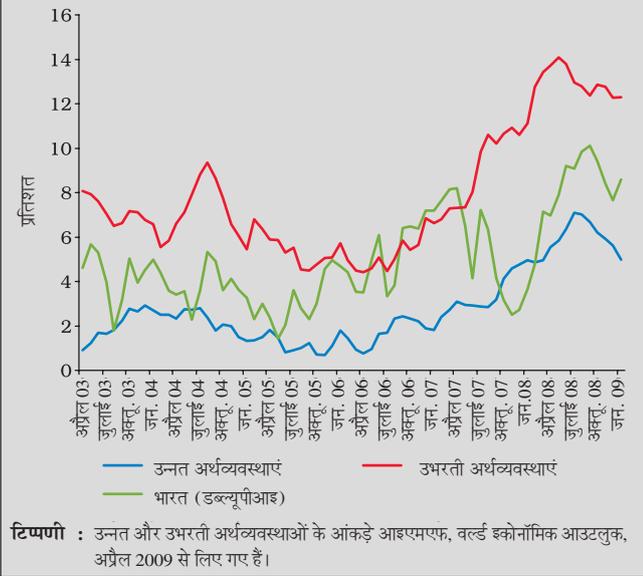
II.3.43 कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में जुलाई 2008 से गिरावट आनी प्रारंभ हुई और मुक्त रूप से मूल्य लगाए गए पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के समान प्रवृत्तियां देखी गई तथा वे काफी अधिक घट गए। चूंकि कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल पर काफी कम बना रहा, अतः सरकार ने नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में दो बार कटौती करने का निर्णय लिया (6 दिसंबर 2008 से पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 5 रुपए और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती तथा 28 जनवरी 2009 से पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 5 रुपए और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए एवं घरेलू उपयोग के एलपीजी के मूल्य में प्रति

सिलिंडर 25 रुपए की कटौती)। इसे दर्शाते हुए ईंधन समूह मुद्रास्फीति 28 मार्च 2009 को ऋणात्मक (-6.1 प्रतिशत) हो गई।

II.3.44 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2008 के मध्य तक 11.9 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई (सारणी 2.32)। यह मुख्यतः लोहा और इस्पात, चीनी, खाद्य तेल/खली, वस्त्र, रसायन और मशीनरी तथा मशीनी औजारों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण थी। सितंबर 2008 से विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आयी और यह 28 मार्च 2009 को 1.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।

II.3.45 प्रमुख विनिर्मित खाद्यान्न उत्पादों में, अगस्त 2008 तक घरेलू खाद्य तेल तथा खली के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि 2007-08 के दौरान मांग में वृद्धि न्यूनतर देशी रबी तिलहन उत्पादन तथा अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। उसके बाद तिलहनों और खाद्य तेलों/खली के मूल्यों में गिरावट आयी, जो राजकोषीय उपायों के प्रभाव तथा वैश्विक उत्पादन में अनुमानित वृद्धि की पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में नरमी के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, मूल्यों में और वृद्धि होने का जोखिम बना हुआ है क्योंकि 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमानों में देशी तिलहन उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की गिरावट बतायी गई है। 2008-09 के दौरान चीनी के मूल्यों में वृद्धि होती रही और ये अब मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक के रूप में उभरे हैं। बढ़ते चीनी मूल्य आंशिक रूप से सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय मूल्य और भारत में उत्पादन में आयी उल्लेखनीय गिरावट (2008-09 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 22.1 प्रतिशत की गिरावट) को दर्शाते

चार्ट II.24 : खाद्यान्न मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी : उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े आइएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2009 से लिए गए हैं।

सारणी 2.32 भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

पण्य	2007-08 (मार्च 29)		2008-09 (मार्च 28)		2009-10 (अगस्त 18) अ		
	भार	मुद्रास्फीति	भा.अं.	मुद्रास्फीति	भा.अं.	मुद्रास्फीति	भा.अं.
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.0	7.7	100.0	0.8	100.0	-1.5	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएं	22.0	9.7	28.2	5.2	141.4	5.8	85.7
खाद्यान्न वस्तुएं	15.4	6.5	13.2	7.0	128.9	10.5	104.1
i. चावल	2.4	9.1	2.5	14.9	38.7	15.4	20.8
ii. गेहूं	1.4	5.1	1.0	4.5	7.7	3.6	3.2
iii. दालें	0.6	-1.9	-0.2	9.4	7.4	17.6	7.6
iv. सब्जियां	1.5	14.2	2.3	-5.2	-8.2	39.7	37.6
v. फल	1.5	4.1	1.0	5.9	12.4	-0.5	-0.5
vi. दूध	4.4	8.7	4.7	7.0	35.6	4.2	11.2
vii. अंडे, मछली और मांस	2.2	2.4	0.8	3.2	8.9	8.7	12.8
खाद्येतर वस्तुएं	6.1	11.4	8.8	0.1	1.0	-1.5	-6.3
i. कच्चा कपास	1.4	14.0	2.0	2.5	3.5	-10.8	-9.5
ii. तिलहन	2.7	20.3	6.7	-1.6	-5.6	-1.1	-2.0
iii. गन्ना	1.3	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
खनिज	0.5	49.9	6.2	7.2	11.6	-14.4	-12.4
2. ईंधन, पॉवर, बिजली और लुब्रिकैंट	14.2	6.8	18.9	-6.1	-155.7	-11.1	-162.3
i. कोयला खनन	1.8	9.8	2.5	-1.0	-2.4	-1.0	-1.2
ii. खनिज तेल	7.0	9.3	15.1	-8.7	-132.8	-16.1	-150.6
iii. विद्युत	5.5	1.5	1.4	-2.6	-21.1	-2.6	-10.8
3. विनिर्मित उत्पाद	63.7	7.3	52.8	1.7	114.0	-0.6	-22.4
i. खाद्य उत्पाद	11.5	9.4	12.4	8.8	108.7	9.6	63.6
जिसमें से: चीनी	3.6	1.1	0.4	18.4	52.8	34.3	51.1
खाद्य तेल	2.8	20.0	5.5	-7.6	-21.6	-9.9	-14.5
खली	1.4	27.2	5.6	19.3	43.2	6.3	8.6
ii. सूती वस्त्र	4.2	-6.8	-2.8	16.2	53.5	-0.7	-1.5
iii. मानव निर्मित रेशे	4.4	2.8	0.7	-1.5	-3.2	-6.1	-7.4
iv. रसायन और उत्पाद	11.9	6.0	8.7	2.0	26.4	1.9	13.5
जिसमें से: उर्वरक	3.7	5.1	2.0	4.8	17.5	-0.5	-1.0
v. अधात्विक खनिज उत्पाद	2.5	6.4	2.0	1.9	5.4	4.5	6.7
जिसमें से: सीमेंट	1.7	5.1	1.1	2.2	4.4	3.4	3.5
vi. मूलभूत धातुएं, मिश्रित धातु और धात्विक उत्पाद	8.3	20.3	25.2	-12.2	-155.9	-15.0	-101.5
जिसमें से: लोहा और इस्पात	3.6	34.2	20.1	-18.4	-124.4	-21.1	-75.1
vii. मशीनरी और मशीनी यंत्र	8.4	3.5	2.9	2.6	18.9	-2.5	-9.9
जिसमें से: विद्युतीय मशीनरी	5.0	4.8	2.0	1.1	4.2	-4.6	-9.4
viii. परिवहन उपकरण और पुर्जे	4.3	3.9	1.7	3.1	12.0	-0.1	-0.1
ज्ञापन:							
खाद्य मर्दे (संमिश्र)	26.9	7.7	25.6	7.7	237.6	10.2	167.7
अनाज को छोड़कर डब्ल्यूपीआइ	73.1	7.8	74.4	-1.6	-137.6	-5.5	-267.7
ईंधन को छोड़कर डब्ल्यूपीआइ	85.8	8.0	81.1	2.7	255.7	1.2	62.3

भा.अ.: भारत अंशदान.

अ.:अनंतिम.

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.

हैं। उक्त मूल्य दबावों की प्रतिक्रिया में वायदा बाजार आयोग ने 26 मई 2009 के चीनी के फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी।

II.3.46 वर्ष 2008-09 के दौरान धातु मूल्य भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक रहे। देशी लोहा और इस्पात मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ती हुई अगस्त 2008 के अंत तक 36

प्रतिशत पर पहुंच गई, जो वैश्विक मूल्यों में तीव्र वृद्धि का द्योतक है। उस समय से, लोहा और इस्पात के मूल्यों में गिरावट आयी है और वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन ऋणात्मक (28 मार्च 2009 को -18.4 प्रतिशत) हो गया। लोहा और इस्पात के देशी मूल्यों में आयी उक्त गिरावट गिरते वैश्विक मूल्यों, देशी तथा बाह्य दोनों प्रकार की मांग में प्रत्याशित गिरावट एवं सरकार द्वारा अप्रैल

2008 से सीमा शुल्क में कटौती करने और विभिन्न इस्पात मर्दों पर निर्यात शुल्क लगाने के रूप में किए गए विभिन्न राजकोषीय उपायों के कारण आयी थी। इस प्रकार, समग्रतः, भारत में 2008-09 के दौरान डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के प्रमुख कारक प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के साथ साथ खनिज तेल, लोहा और इस्पात, खाद्य तेल/तिलहन और खली, रुई और चीनी के मूल्यों में हुए परिवर्तन थे।

II.3.47 2008-09 की मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की एक उल्लेखनीय विशेषता थी रूपए की विनिमय दर में होनेवाली घट-बढ़ के साथ उसकी संबद्धता। नवंबर 2007-अगस्त 2008 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, यह ऐसी अवधि है जब विदेशी पूंजी अधिकाधिक मात्रा में भारत में आने के कारण विनिमय दर में वृद्धि हुई, इससे अनुकूल अंतरण (पास-थ्रू) प्रभावों के जरिए मुद्रास्फीति के प्रबंधन का लाभ मिल सकता था। अगस्त 2008 से मुद्रास्फीतिकारी दबाव काफी में कम हुए,

वहीं विनिमय दर में मूल्यहास हुआ। एक ऐसे समय में जब बाह्य मांग कम होती जा रही थी तब इससे भारतीय निर्यातों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती थी, वहीं देशी मुद्रास्फीतिकारी स्थितियों पर अंतरण प्रभाव मूल्यों में तेजी से होती जा रही गिरावट को कम करने में कारगर सिद्ध हो सकते थे। सांकेतिक विनिमय दर और मुद्रास्फीति की रुख की प्रवृत्तियों के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह बात सामने आती है कि मूल्यों पर विनिमय दर के अंतरण प्रभाव प्रत्याशित सामान्य रुख के संबंध में विरुद्ध दिशा में असर दिखा रहे थे। तथापि, प्रभावों के विनिमय दर से मुद्रास्फीति में अंतरण (संक्रमण) की अग्रता एवं पश्चता (लीड्स एण्ड लैग्स) के परिप्रेक्ष्य में तथा 2008-09 के दौरान मुद्रास्फीति के प्राथमिक निर्धारक तत्वों में पायी गयी अभूतपूर्व अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में अर्थात् अंतरण के संबंध में पाए गए व्यावहारिक प्रमाण को एक गतिशील (डाइनैमिक) प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए (बॉक्स II.17)। पहले चरण के दौरान अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य विनिमय दर

बॉक्स II.17

भारत में विनिमय दर में घट-बढ़ का मुद्रास्फीति पर अंतरण

एक संकल्पना के रूप में विनिमय दर अंतरण देशी मुद्रा की विनिमय दरों में होनेवाली घट-बढ़ की प्रतिक्रिया में देशी मूल्यों में पाए जानेवाले परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ से आयात मूल्यों में तथा बाद में अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में अंतरण की मात्रा कई सारे व्यष्टि आर्थिक तथा समष्टि आर्थिक घटकों पर निर्भर करती है। व्यष्टि आर्थिक घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं; उत्पादकों द्वारा मूल्य विभेद, 'मार्क-अप' समायोजन, स्थानीय संवितरण लागतें, टैरिफ से इतर अवरोध, मान की तुलना में प्रतिलाभ मात्रा और आयातित वस्तुओं की मांग की कीमत लोच। समष्टि आर्थिक घटकों में मुद्रास्फीति का स्तर, विनिमय दर घट-बढ़ के स्वरूप का सही ज्ञान (अस्थायी या स्थायी), ट्रेड की इनवाइसिंग स्वरूप, टैरिफ संरचना, अर्थव्यवस्था का आकार तथा खुलापन और मौद्रिक नीति वातावरण शामिल हैं। इन घटकों के बीच अंतःक्रिया (इंटरएक्शन) के कारण अक्सर अधूरे अंतरण की स्थिति आ जाती है, जो इस बात को इंगित करती है कि देशी मूल्यों में सांकेतिक विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की दर की समान मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है।

भारत के संदर्भ में उपलब्ध आनुभाषिक निष्कर्षों में मोटे तौर पर उक्त विषय के साहित्य में सुझाए गए अनुसार इसी प्रकार के परिणाम उपलब्ध होते हैं, हालांकि अंतरण के गुणांक की मात्रा में भिन्नता होती है। 1970 से 2004 तक की अवधि के लिए देशी मूल्यों पर विनिमय दर के अंतरण के विश्लेषण में यह पाया गया कि विभिन्न मूल्य सूचकांकों के लिए विनिमय दर अंतरण का गुणांक 8-17 आधार अंकों के दायरे में था (रिजर्व बैंक 2004)। 1993-2004 की अवधि के लिए अलग पद्धति से किए गए एक दूसरे अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि विनिमय दर में 10 प्रतिशत मूल्यहास से थोक मूल्य 0.4 प्रतिशत बढ़ता है। इस अंतरण का करीब-करीब 60 प्रतिशत परिणाम

विनिमय दर के प्रति होनेवाले आघात के एक वर्ष के भीतर आ जाता है, वहीं अंतरण का 80 प्रतिशत परिणाम दो वर्षों के भीतर प्राप्त हो जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के प्रति मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता के संबंध में, यह अनुमान लगाया गया था कि आयात मूल्य मुद्रास्फीति में होनेवाली 10 प्रतिशत की वृद्धि से देशी मुद्रास्फीति 1.1 प्रतिशत अंकों से बढ़ जाती है। सीपीआइ मुद्रास्फीति में उक्त प्रभाव न्यूनतम (0.5 प्रतिशत अंक) होता है, इसके बाद जीडीपी का अपस्फीतिकारी तत्व (डिफ्लेटर) (0.8 प्रतिशत अंक), और थोक मूल्य मुद्रास्फीति (1.1 प्रतिशत अंक) का स्थान था। ये अंतर संबंधित समूहों (बास्केटों) में आयातित वस्तुओं के अलग-अलग महत्व के कारण हो सकते हैं। 1980-2005 तक की अवधि के संदर्भ में, घोष और राजन (2006) ने अपने निष्कर्षों में, सुधारों के बाद की अवधि में अधिक मजबूत अंतरण के परिणाम पाये। तथापि, सांकेतिक प्रभावी दर (एनईईआर) का प्रयोग करते हुए निकाले गये निष्कर्षों में अंतरण का गुणांक सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय नहीं पाया गया। साथ ही साथ, चूक सुधार मॉडल (ईसीएम) के अनुमानित परिणामों में अल्पकालीन अंतरण के कम प्रमाण देखे गए, चाहे वे सांकेतिक रुपया-डॉलर या एनईईआर के लिए हों।

उपर्युक्त परिणामों की संपुष्टि खुंद्रकपम (2007) द्वारा सुधारों के बाद की अवधि (अगस्त 1991 से मार्च 2005 तक) के लिए किये गये अध्ययन में भी की गई है। अध्ययन में अंतरण गुणांक का अनुमान लगाया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि विनिमय दर में होनेवाले 10 प्रतिशत के परिवर्तन से अंतिम मूल्यों में अल्पावधि में लगभग 0.6 प्रतिशत और दीर्घावधि में 0.9 प्रतिशत का अंतर आ जाता है। आवर्ती (रोलिंग) प्रत्यावर्तन पद्धति द्वारा अंतरण की अस्थायी प्रवृत्ति के संबंध में किए गए सांख्यिकीय परीक्षणों

(क्रमशः...)

(... समाप्त)

में पाया गया कि अधिकांश देशों की स्थिति से भिन्न रूप में, अंतरण में कमी के कोई प्रमाण नहीं थे। मिहालजेक और क्लाउ द्वारा किये गये हाल के बीआइएस अध्ययन (2008) में 1994 से 2006 के मध्य तक की अवधि के लिए 14 उभरते बाजारवाले देशों में विनिमय दर तथा विदेशी मूल्य परिवर्तनों के मुद्रास्फीति में अंतरण के अनुमान उपलब्ध कराये गये हैं। इस अध्ययन में, भारत के लिए सुझाव दिया गया है कि विनिमय दर में होनेवाले 10 प्रतिशत परिवर्तन से मुद्रास्फीति में 2 प्रतिशत तक परिवर्तन हो सकता है। रिक्सर्व वीएआर मॉडलों का प्रयोग करते हुए सामंतराय (2009) ने सीपीआई मुद्रास्फीति में अप्रैल 1993 से मार्च 2008 तक की अवधि में मामूली विनिमय दर अंतरण पाया। तथापि, प्रत्याशाओं के विपरीत, भारत में विनिमय दर में हुई मूल्यवृद्धि बढ़ती हुई डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ संबद्ध पायी गयी जिसके लिए कई कारक जिम्मेवार थे, जैसे कि नियंत्रित ईंधन मूल्य, आयात टैरिफों में क्रमिक रूप से कटौती और विनिमय दर में हुई बढोतरी की पृष्ठभूमि में देशी निर्यातकों को प्राप्त सरकारी प्रोत्साहन।

संक्षेप में, भारत के लिए किए गए विभिन्न अनुभवमूलक अध्ययन देशी मूल्यों पर अधूरे विनिमय दर अंतरण के प्रमाण दर्शाते हैं। क्योंकि नवंबर 2007 से दोनों ही परिवर्तनों में एक ही दिशा में चल रहे हैं (अर्थात् जब विनिमय दर बढ़ती जा रही थी तब मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और जब विनिमय दर घटती जा रही थी तब मुद्रास्फीति कम हो गयी थी)। हो सकता है, ऐसा देशी मुद्रास्फीति पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य की तीव्र घट-बढ़ के प्रमुख प्रभावों का परिणाम हो जिन्होंने विनिमय दर परिवर्तनों के अंतरण प्रभाव को अभिभूत कर दिया हो। अत्यधिक अस्थिर मुद्रास्फीति

के वातावरण में, विशेष रूप से उतनी ही मात्रा में अस्थिर अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों तथा विनिमय दरों की पृष्ठभूमि में, अंतरण के अनुभवजन्य अनुमान बड़बोले या यहां तक कि गुमराह करनेवाले हो सकते हैं जबतक कि अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों सहित अंतरण का आकलन मुद्रास्फीति के अन्य स्रोतों में घट-बढ़ का नियंत्रण करता है।

संदर्भ:

1. घोष अमित और आर.राजन (2006), “हाउ हाइ इज एक्सचेंज रेट पास-थ्रू इन इंडिया, हैज इट चेंज्ड ओवर टाइम?” जो www.freewebs.com/rrajan01/indiaerpt.pdf पर उपलब्ध है।
2. खुंद्रकपम जे.के.(2007), “इकॉनामिक रिफार्म्स एण्ड एक्सचेंज रेट पास-थ्रू डोमेस्टिक प्राइसेस इन इंडिया”, बीआइएस वर्किंग पेपर सं.225।
3. मिहालजेक, डी. और क्लाउ एम.(2008), “एक्सचेंज रेट पास-थ्रू इन इमर्जिंग मार्केट इकॉनामीज: वॉट हैज चेंजेस एण्ड व्हाई?”, बीआइएस वर्किंग पेपर सं.35।
4. सामंतराय, अमरेश (2009), “ऐन एम्पायरिकल एनालिसिस ऑफ एक्सचेंज रेट पास-थ्रू इन इंडिया: रेलिवैंस फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट”, मौद्रिक अर्थशास्त्र पर आईसीएफएआई विश्वविद्यालय की पत्रिका खंड VII, सं.2।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (2004) मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2003-04।

मूल्यवृद्धि दर की तुलना में बहुत अधिक तेज गति से बढ़े और फलस्वरूप आयात मूल्यों के जरिए मुद्रास्फीति पर इनका निवल प्रभाव फिर भी सकारात्मक एवं तीव्र रहा। इसी प्रकार, अगस्त 2008 से वैश्विक पण्य मूल्यों में गिरावट विनिमय दर के मूल्यहास की तुलना में काफ़ी तीव्र रही है, जिसके परिणामस्वरूप आयात लागतों पर इनका निवल प्रभाव ऋणात्मक और उल्लेखनीय रहा।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

II.3.48 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वर्ष-दर-वर्ष की घट-बढ़ के आधार पर मुद्रास्फीति जून 2008 की शुरुआत से बढ़ती गई, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, ईंधन और सेवाओं (‘विविध’ समूह के रूप में दर्शाया गया) के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण थी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के संबंध में किए गए विभिन्न उपाय मार्च 2009 में 8.0 - 9.7 के दायरे में रहे जबकि ये जून 2008 में 7.3 - 8.8 प्रतिशत तथा मार्च 2008 में 6.0-7.9 प्रतिशत के दायरे में थे (सारणी 2.33)। हाल के महीनों में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में हुई यह

उच्च मात्रा की वृद्धि सीपीआई में शामिल खाद्य वस्तुओं के उच्चतर भार तथा खाद्य वस्तुओं के उच्चतर मूल्यों के कारण थी।

II.3.49 थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों द्वारा मापी जानेवाली मुद्रास्फीति के बीच हाल में पाई गई भिन्नता को कई क्षेत्रों में मौद्रिक नीति के संचालन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच बड़े अंतर की दृष्टि से और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के मार्ग पर न चलने से रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पर उपलब्ध सभी जानकारी का प्रयोग करता है। नीति के संचालन के लिए ऐसा कोई सूचकांक जो प्रमुख जानकारी उपलब्ध कराता हो और वह भी अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप का हो तो वह किसी मूल्य श्रृंखला की जरूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। नीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दा होता है इसकी जांच करना कि मूल्य सूचकांकों के बीच भिन्नता व्यापक क्यों हो गयी और विशेष रूप से यदि भिन्नता लंबे समय तक बनी रहे तो यह देखना कि थोक मूल्य परिवर्तनों का संचारण खुदरा मूल्य में होने में क्या पश्चताएं हैं (बॉक्स II.18)।

सारणी 2.33: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति- प्रमुख समूह

(वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत में)

सीपीआइ मापक	भार	मार्च-07	मार्च-08	जून-08	सितं-08	दिसं-08	मार्च-09	अप्रैल-09	मई-09	जून-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सीपीआइ-आइ डब्ल्यू (आधार : 2001=100)										
सामान्य	100.0	6.7	7.9	7.7	9.8	9.7	8.0	8.7	8.6	9.3
खाद्य समूह	46.2	12.2	9.3	10.5	13.1	13.1	10.6	10.4	11.7	-
पान, सुपारी आदि	2.3	4.4	10.9	7.1	7.8	8.5	8.3	6.7	7.5	-
ईंधन और बिजली	6.4	3.2	4.6	8.4	9.1	9.7	7.4	6.6	5.9	-
आवास	15.3	4.1	4.7	4.7	3.8	3.8	6.0	6.0	6.0	-
वस्त्र,बिस्तर आदि	6.6	3.7	2.6	2.5	2.5	4.2	5.0	4.2	4.1	-
विविध	23.3	3.3	6.3	6.2	7.6	8.3	7.4	7.4	7.4	-
सीपीआइ - यूएनएमई (आधार : 1984-85=100)										
सामान्य	100.0	7.6	6.0	7.3	9.5	9.8	9.3	8.8	9.7	9.6
खाद्य समूह	47.1	10.9	7.8	9.6	13.2	13.4	12.2	11.1	12.9	13.6
ईंधन और बिजली	5.5	6.4	4.6	5.3	6.2	7.7	5.9	6.7	5.8	1.3
आवास	16.4	5.6	4.0	3.8	3.5	3.5	5.8	6.0	6.0	6.0
वस्त्र,बिस्तर आदि	7.0	3.6	4.3	3.4	3.1	2.7	3.3	4.2	4.2	4.2
विविध	24.0	4.4	4.8	6.6	8.4	9.3	8.6	7.6	8.1	7.3
सीपीआइ - एएल (आधार : 1986-87=100)										
सामान्य	100.0	9.5	7.9	8.8	11.0	11.1	9.5	9.1	10.2	11.5
खाद्य समूह	69.2	11.8	8.5	9.6	12.0	11.9	9.7	9.1	11.2	12.4
पान, सुपारी आदि	3.8	5.7	10.4	11.2	12.8	13.7	15.3	14.5	14.4	14.2
ईंधन और बिजली	8.4	6.9	8.0	8.9	10.2	11.3	11.5	10.9	10.6	11.0
वस्त्र,बिस्तर आदि	7.0	3.5	1.8	3.1	6.0	7.0	7.4	7.9	7.6	8.3
विविध	11.7	6.8	6.1	6.5	7.1	7.0	6.5	6.2	6.6	6.1
सीपीआइ - आरएल (आधार : 1986-87=100)										
सामान्य	100.0	9.2	7.6	8.7	11.0	11.1	9.7	9.1	10.2	11.3
खाद्य समूह	66.8	11.5	8.2	9.6	12.0	11.9	10.0	9.1	11.2	12.4
पान, सुपारी आदि	3.7	5.7	10.6	10.9	12.5	13.4	15.0	14.0	14.1	14.1
ईंधन और बिजली	7.9	6.9	8.0	8.9	10.5	11.3	11.5	10.9	10.6	11.0
वस्त्र,बिस्तर आदि	9.8	3.1	2.8	4.1	6.5	7.3	8.2	8.4	8.3	8.8
विविध	11.9	6.3	6.2	6.8	7.4	7.5	6.7	6.2	6.4	6.2
जापन:										
डब्ल्यू पी आइ मुद्रास्फीति (अवधि के अंत में)		5.9	7.7	12.0	12.1	5.9	0.8	1.7	0.9	-1.6
मुद्रास्फीति पर आधारित जीडीपी अवस्फीतिकारक *		5.5	4.9	8.0	10.6	8.3	7.8	-	-	-
* : मार्च के आंकड़े पूरे वर्ष के हैं।										
आइडब्ल्यू : औद्योगिक कामगार. यूएनएमई : शहरी श्रेयतर कर्मचारी एएल : कृषि श्रमिक आरएल : ग्रामीण श्रमिक.										
स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, श्रम ब्यूरो और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार.										

आस्ति मूल्य

II.3.50 सब-प्राइम संकट के पश्चात आस्ति मूल्य चक्र में पुनः दिलचस्पी बढ़ी तथा इस बात का अधिकाधिक अहसास किया जाने लगा कि आस्ति मूल्य चक्र कारोबार चक्र के प्रमुख हो सकते हैं और उनको कुछ सीमा तक प्रभावित भी कर सकते हैं। आस्ति मूल्य चक्रों पर मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया के संबंध में किसी एक केंद्रित दृष्टिकोण के अभाव के बावजूद, आस्ति मूल्य वृद्धि एवं

मुद्रास्फीति परिणाम के प्रमुख संकेतकों का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही मुद्रास्फीति एवं वृद्धि पर आस्ति मूल्य चक्रों के प्रभाव का वास्तविक परिमाण तथा प्रभाव का समय एवं समयावधि देश विशिष्ट और प्रायोगिक स्वरूप की हो। भारत के संदर्भ में वैश्विक संकट के दौरान स्टॉक के मूल्यों में उल्लेखनीय करेक्शन के साथ प्रभावों को बहुत ज्यादा उल्लेखनीय रूप में नहीं लिया जा सकता (बॉक्स.II.20)।

बॉक्स II.18

सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति की भिन्नता

भारत में, डब्ल्यूपीआइ आधारित मुद्रास्फीति को सामान्यतया हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप के रूप में माना जाता है, यद्यपि रिजर्व बैंक अपने समग्र समष्टि आर्थिक मूल्यांकन के लिए उपलब्ध मूल्य सूचकांकों के पूरे सेट की निगरानी करता है। डब्ल्यूपीआइ के अलावा, श्रमशक्ति के विभिन्न भागों अर्थात् औद्योगिक कामगारों (आइडब्ल्यू), शहरी श्रमेतर कर्मचारी (यूएनएमई), कृषि श्रमिक (एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (आरएल) को लक्षित करनेवाले चार भिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी भारत में उपलब्ध हैं।

हाल की अवधि में, डब्ल्यूपीआइ आधारित और सीपीआइ आधारित मुद्रास्फीति के बीच विद्यमान भारी अंतर के कारण सोदेश्यपूर्ण आर्थिक विश्लेषण के लिए ऐसे आंकड़ों की जानकारी संबंधी विशिष्टताओं के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ है। सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में अंतर काफी सीमा तक भिन्न-भिन्न संकेतकों में पण्य/लक्षित समूहों की व्याप्ति में विद्यमान अंतर के कारण उभर सकता है (सारणी क)।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उनके भारांकन स्वरूप के अनुसार अलग-अलग होते हैं। जहां खाद्यान्न मदों को सीपीआइ - आइडब्ल्यू में 46 प्रतिशत से सीपीआइ-एएल में 69 प्रतिशत के बीच अधिकतम भारांक मिलता है वहीं थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में प्राथमिक समूह में खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित समूह में खाद्य उत्पादों को मिलाकर मात्र 27 प्रतिशत भारांक मिलता है। अतः खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होनेवाले परिवर्तन के प्रति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिक संवेदनशील होते हैं। दूसरी ओर, ईंधन समूह को सीपीआइ (5.5 से 8.4 के बीच) की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में अधिक उच्चतर भार (14.23) प्राप्त होता है। जहां वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक की परिधि में सेवाएं नहीं आती हैं, वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में कृषीतर उत्पाद या लेनदेन योग्य मदों की व्याप्ति बेहतर है।

प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की कीमतें 2008-09 के दौरान डब्ल्यूपीआइ और सीपीआइ दोनों में उँची रहीं। चूंकि सीपीआइ में उच्च भारांक हैं, अतः वर्तमान मुद्रास्फीति में डब्ल्यूपीआइ की तुलना में सीपीआइ में खाद्य पदार्थों की कीमतें ज्यादा हावी रहीं। इसके अलावा, विनिर्मित खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान डब्ल्यूपीआइ की गिरावट के एक हिस्से

में योगदान दिया, पर यह अपने निम्न भारांक के कारण सीपीआइ में उसी प्रभाव के साथ प्रतिबिंबित नहीं हुई। सीपीआइ के ईंधन समूह ने एलपीजी के वर्तमान उच्च मूल्यों के कारण 9 प्रतिशत के आस-पास मुद्रास्फीति दर्ज करना जारी रखा है। यह उल्लेखनीय है कि एलपीजी की कीमतों में हाल में संशोधन कर की गयी कमी (प्रति सिलिंडर 50 रु. की वृद्धि को कम कर 25 रु. करना) के बावजूद यह अभी भी एक वर्ष पहले के स्तर से अधिक है।

सीपीआइ मुद्रास्फीति में सामान्यतः डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के पीछे रहने की प्रवृत्ति है, और पीछे रहने का स्वरूप स्थिर प्रकृति का नहीं है। सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ के बीच अंतर के कुछ अंश के लिए थोक और खुदरा स्तरों पर वास्तविक मूल्य अंतर भी जिम्मेदार हो सकते हैं। चूंकि खुदरा बाजार थोक बाजार से पण्य प्राप्त करता है, अतः यह आशा की जाती है कि थोक बाजार में पण्यों की कीमतों में परिवर्तन कुछ अंतराल के बाद खुदरा बाजार में परिलक्षित होता है।

अर्थमितिपरक साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि सीपीआइ-आइडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआइ के बीच अंतर शून्य माध्य के साथ स्थिर श्रृंखला है (अर्थात् विचलन माध्य के आस-पास होते हैं) जो यह बताता है कि सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ के बीच अंतर में कोई दीर्घकालिक ऊर्ध्वगामी और अधोगामी उतार-चढ़ाव नहीं होता है। डब्ल्यूपीआइ और सीपीआइ के बीच समकालीन सहसंबंध उच्च और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि उनका संबंध कुछ सालों से धीरे-धीरे कम हो रहा है। इस प्रकार पण्य समूह और भारांक के बीच का अंतर भारत में डब्ल्यूपीआइ और सीपीआइ आधारित मुद्रास्फीति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इसके अलावा, पिछले प्रायोगिक व्यवहार बताते हैं कि अंतराल के साथ सीपीआइ डब्ल्यूपीआइ के साथ बेहतर सहसंबंध दर्शाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के तौर पर, डब्ल्यूपीआइ भारत में मुद्रास्फीति का प्रासंगिक संकेतक बना हुआ है, यद्यपि अलग मूल्य श्रृंखलाओं के बीच लगातार अंतर मूल्य विश्लेषण के लिए केवल डब्ल्यूपीआइ के प्रयोग के मामले को कमजोर कर सकता है। इस संदर्भ में, सीपीआइ (ग्रामीण) और सीपीआइ (शहरी) नाम से दो नए मूल्य श्रृंखलाओं के आधार पर आंकड़ा तैयार करने की योजना उपयोगी हो सकती है (बॉक्स II.19)।

सारणी क: मूल्य सूचकांकों की मुख्य मुख्य बातें

क्रम सं. मद	सीपीआइ-यूएनएमई *	सीपीआइ-आइडब्ल्यू	सीपीआइ-एएल	सीपीआइ-आरएल	डब्ल्यूपीआइ	
1	2	3	4	5	6	
1	निम्न के आधार पर आबंटित भारांक				उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण	थोक लेनदेनों पर आधारित आबंटित भार
	प्रथम:1958-59 अद्यतन: 1982-83	प्रथम:1958-59 अद्यतन: 2001	प्रथम:1956-57 अद्यतन: 1983	प्रथम:1983 अद्यतन: 1983		
2	वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष	1984-85	2001	1986-87	1986-87	1993-94
3	मदों की संख्या/ बास्केट में पण्य	146-365	120-160	260	260	435
4	केंद्रों/ गांवों की संख्या	59	76	600	600	1918
5	सूचकांक का समय अंतराल	2 सप्ताह	1 मासिक	3 सप्ताह	3 सप्ताह	2 सप्ताह
6	बारंबारता	मासिक	मासिक	मासिक	मासिक	मासिक

* : अप्रैल 2008 से सीपीआइ-यूएनएमई के लिए मूल्य संग्रहण समाप्त किया गया और अब सीपीआइ-यूएनएमई को अनुपात आधार पर संकलित किया जाता है जो अखिल भारत के लिए समूह/उप समूह स्तर पर सीपीआइ-यूएनएमई को प्रयुक्त करते हुए सीपीआइ-आइडब्ल्यू के सूचकांक के उप समूह स्तर को जोड़कर निकाला जाता है।

स्रोत: भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

बॉक्स II.19

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के लिए सीपीआइ: दृष्टिकोण

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (2001) ने, *अन्य बातों के साथ-साथ*, सिफारिश की है कि वर्तमान सीपीआइ संपूर्ण ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए कीमतों में बदलाव प्रदान नहीं करती है क्योंकि वह जनसंख्या के विशिष्ट खण्ड द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए डिजाइन की गई हैं और इसलिए संपूर्ण ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए अलग से सीपीआइ के संकलन की आवश्यकता है। आदर्श रूप में, मुद्रास्फीति को मापने में देशी बाजार में औसत ग्राहक द्वारा खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के समूचे दायरे को शामिल करना चाहिए। वर्तमान में, भारत में उपभोक्ता मूल्यों से उभरने वाली मुद्रास्फीति का कोई सामान्य माप नहीं है जो सभी जनसंख्या समूहों और सामान्य लेन-देनों को शामिल करता हो। वर्तमान सीपीआइ माप वस्तुओं और सेवाओं के समूहों और उनके भारांक, भौगोलिक क्षेत्र, आधार अवधि इत्यादि के संदर्भ में भी अंतर रखते हैं। इस प्रकार ये सूचकांक देश में कीमतों के रुख में परिवर्तन और देश की जनता द्वारा उपभोज्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। अतः सीपीआइ के सामंजस्यपूर्ण माप का निर्माण आवश्यक है जो समूचे देश के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति का सामान्य माप उपलब्ध करा सके। सीपीआइ (शहरी (यू)) का संकलन इस दिशा में बड़ा कदम होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सीपीआइ(कृषि श्रमिक (एएल)) और सीपीआइ (ग्रामीण श्रमिक (आरएल)) के संशोधन के समय सीपीआइ (ग्रामीण (आर)) के लिए इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

देशी बाजार में देशी मुद्रा की क्रय शक्ति को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित करने वाली मुद्रास्फीति का माप मौद्रिक नीति के प्रयोजन के लिए उचित होगा। जिस तरह से मौजूदा सीपीआइ का संकलन किया जाता है वह मुद्रास्फीति के दबावों की व्याख्या करने में दिक्कत पैदा करता है। यदि व्यापित उपभोक्ता की संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करती हो तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए सीपीआइ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के विश्लेषणात्मक मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। सीपीआइ(यू) इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा और लक्षित समूह की अंतर्निहित कीमतों में उतार-चढ़ाव पर निगरानी के लिए इससे एक उपयोगी साधन उपलब्ध होने की आशा की जाती है। चूंकि हर पांच साल में एक बार एनएसएसओ द्वारा उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) किया जाता है, अतः हर बार इस सर्वेक्षण के समय नए सिरे से सीपीआइ (यू) के भारांक डायग्राम का निर्माण संभव है। चूंकि विस्तृत पंचवर्षीय सीईएस का नमूना आकार काफी बड़ा है, अतः सीपीआइ(यू) से शहरी आबादी की अंतर्निहित कीमतों के उतार-चढ़ाव को पर्याप्त रूप से मापने की आशा की जाती है।

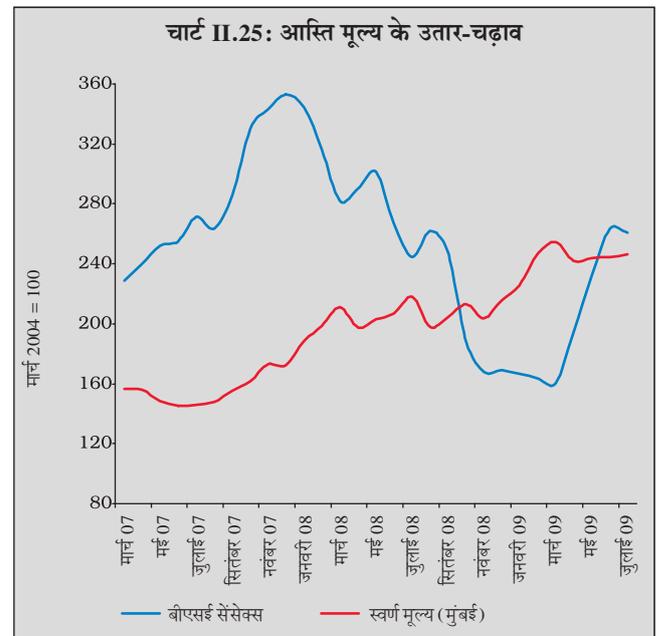
संदर्भ:

1. “सीपीआइ (यू) और सीपीआइ (यूएनएमई) के एकीकरण पर उप-दल की रिपोर्ट”, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, सितंबर 2006।
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट, खंड-II, अगस्त 2001, पृष्ठ - 333-334।

II.3.51 2008-09 के दौरान इक्विटी मूल्यों का रुख प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के रुख के अनुरूप रहा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारी उथल-पुथल के कारण बड़ी तेजी से कमी आई, और देशी अर्थव्यवस्था (विस्तृत विश्लेषण के लिए इस अध्याय में वित्तीय बाजार पर खंड V) में मंदी के बारे में संबद्ध चिंताएं उत्पन्न हो गईं। अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप 2008-09 की दूसरी तिमाही के दौरान कुछ नरम पड़ी सोने की देशी कीमतें बाद में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और अधिक वृद्धि के कारण मार्च 2009 में बढ़कर 15,255 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं (चार्ट II 25)।

II.3.52 इक्विटी और सोने के मूल्यों के संबंध में सूचना के अलावा मकानों की कीमतों जैसी अन्य प्रमुख घरेलू आस्तियों के संबंध में सूचनाएं इन क्षेत्रों में मूल्य की प्रवृत्तियों पर नजर रखने और आर्थिक गतिविधि के प्रमुख संकेतक दोनों के तौर पर अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाल के वर्षों में आवास कीमतों से संबंधित

आकड़ों के संग्रहण और संकलन के संदर्भ में प्रणालीगत तौर पर काफी सुधार आया है (बॉक्स -II.21)



बॉक्स II.20

भारत में शेयर के मूल्यों में करेक्शन का धन प्रभाव

वैश्विक संकट के उभरने के समय से विश्व भर के शेयर बाजारों ने उल्लेखनीय ऋणात्मक धन प्रभाव दिखाया है और देश विशेष की स्थितियों में कुल मांग, विशेषकर उपभोग मांग पर संबद्ध प्रभाव भिन्न हो सकता है। धन प्रभाव के माध्यम से आस्ति मूल्य चक्रों का कारोबारी चक्रों की ओर तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति तक भी संचरण एक ऐसा मुद्दा है जो सब-प्राइम संकट के पश्चात नीतिगत तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

शेयर बाजार में उछाल उपभोग मांग को बढ़ा सकती है, जबकि शेयर बाजार संबंधी धन में गिरावट या तो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट ला सकती है या वर्तमान मंदी में बढ़ोत्तरी कर सकती है (डेअटन 1992)। इक्विटी मूल्यों में 10 प्रतिशत परिवर्तन के लिए शेयर बाजार धन प्रभावों का अनुमान जापान में 0.15 से 0.30 प्रतिशत के बीच, विभिन्न यूरोपीय देशों में 0.1 से 0.3 प्रतिशत के बीच और अमरीका में 0.3 से 0.7 प्रतिशत के बीच है (आइएमएफ 2002)।

भारत में शेयर बाजार धन प्रभाव का यह मुद्दा अप्रैल 2003 से नवंबर 2008 के बीच शेयर के मूल्यों में तीव्र उछाल एवं उसके पश्चात इसमें तीव्र गिरावट के संदर्भ में प्रासंगिक है। बीएसई सेंसेक्स औसत मासिक सूचकांक में दिसंबर 2007 (उच्चतम) और मार्च 2009 (न्यूनतम) के बीच लगभग 55 प्रतिशत की गिरावट आई जो 19,827 से गिरकर 8,96 पर पहुँच गया। शेयर की कीमतों में ऐसे बड़े अंतर के परिणामस्वरूप उपभोग मांग के लिए संबद्ध निहितार्थों के साथ-साथ घरेलू धन में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है जो प्रतिचक्रिय मांग प्रबंधन नीतियों के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

संरचनागत वीएआर मॉडल में, उपभोग मांग पर शेयर बाजार धन प्रभाव में परिवर्तनों के असर की जांच के लिए चार परिवर्तियों अर्थात्, वाइ=वास्तविक आय, सी= वास्तविक उपभोग मांग, आर= अल्पावधि ब्याज दर, और डब्ल्यू = वास्तविक शेयर मूल्य, का प्रयोग किया जाता है। ये प्रमुख परिवर्ती हैं जो वास्तविक उपभोग मांग को प्रभावित कर सकते हैं; सांकेतिक ब्याज दर का मुद्रास्फीति और वास्तविक ब्याज दर पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है एवं दोनों उपभोग मांग को विपरीत दिशाओं में प्रभावित कर सकते हैं। 1996 की दूसरी तिमाही से 2008 की चौथी तिमाही की अवधि अर्थात् भारतीय शेयर मूल्य चक्रों में पाये गये उल्लेखनीय परिवर्तनों के साथ मेल खानेवाली अवधि के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्राक्कलित मॉडल यह दर्शाता है कि धनात्मक वास्तविक आय आघात वास्तविक उपभोग मांग में निरंतर वृद्धि करता है। आघात की मात्रा यह उजागर करती है कि वास्तविक आय में एक प्रतिशत की वृद्धि के कारण वास्तविक उपभोग मांग में 0.57 प्रतिशत की वृद्धि होती है। शेयर बाजार धन प्रभाव को दर्शाने वाले शेयर मूल्य आघात का उपभोग मांग पर केवल अल्पावधि एवं नाममात्र का प्रभाव पड़ता है। उक्त प्राक्कलन सुझाता है कि शेयर मूल्यों में 10 प्रतिशत का धनात्मक आघात (वृद्धि) अगली तिमाही में उपभोग मांग को 0.44 प्रतिशत बढ़ा देता है। उपभोग मांग पर शेयर बाजार धन प्रभाव का कोई दीर्घावधि प्रभाव पड़ता नहीं दिखता है। घट-बढ़ वियोजन विश्लेषण वास्तविक उपभोग मांग में समग्र उतार-चढ़ाव में विभिन्न कारक विशिष्ट आघातों के योगदान पर प्रकाश

डालता है। वास्तविक आय आघात ही मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक वास्तविक उपभोग मांग के उतार-चढ़ाव की व्याख्या करता है (सारणी क)। अल्पावधि ब्याज दर और शेयर धन आघात वास्तविक उपभोग मांग में केवल नाममात्र के उतार-चढ़ावों की व्याख्या करते हैं।

सारणी क: विभिन्न आघातों द्वारा दर्शाए गए उपभोग मांग की प्रतिशत भिन्नता

तिमाही	आय आघात	ब्याज दर	शेयर धन	उपभोग मांग आघात
1	13.1	0.0	0.0	86.9
4	29.8	4.4	5.9	59.9
8	46.9	3.8	6.5	42.9
12	57.4	3.1	7.4	32.1
16	63.9	2.7	8.2	25.2
20	68.5	2.5	8.7	20.4

टिप्पणी - वास्तविक उपभोग मांग पर आघात स्वयं ही अनुपस्थित परिवर्ती (जिसमें गृह संपत्ति को शामिल किया जा सकता है) की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, और सभी कारकों के कारण उपभोग मांग में घट-बढ़ के जोड़ को 100 (अर्थात् प्रत्येक पंक्ति के लिए कुल) में जोड़ा जाए।

आस्ति मूल्य में बड़े करेक्शन के प्रतिकूल प्रभावों को स्पष्ट करने एवं उनके प्रचार-प्रसार में लीवरेज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और भारतीय शेयर बाजार में बड़ी लीवरेज स्थितियों की संभावित अनुपस्थिति (विकसित देशों से भिन्न) एक ऐसा प्रमुख तत्व हो सकता है जो उपभोग मांग पर हल्का प्रभाव डाल सकता है। जब आस्ति निर्माण के लिए लीवरेज का प्रयोग होता है, तब आस्ति मूल्यों में होने वाला करेक्शन ऋणात्मक धन प्रभाव छोड़ सकता है, लेकिन संविदागत देयताओं को संविदागत दर पर ही चुकाना होगा। ऐसी संभाव्यताओं के केंद्रीय बैंक के लिए दो प्रमुख महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं: (क) निम्न आस्ति मूल्यों (संपार्श्विकों के निम्न मूल्यांकन को मानकर) के कारण, एक तरफ उधारकर्ताओं की उधार लेने की क्षमता में कमी आएगी, और दूसरी तरफ, बैंक ऋण मानकों को कठोर भी बना सकते हैं, (अधिक मार्जिन और संपार्श्विकों की मांग करके क्योंकि बैंक संपार्श्विकों के माध्यम से काफी सीमा तक सूचना विषमता की समस्या को दूर करते हैं), जिससे ऋण वृद्धि की गति और धीमी हो सकती है तथा (ख) आस्ति के मूल्य में गिरावट के कारण धन में कमी के ऋणात्मक प्रभाव को प्रतिलुलित करने के लिए जनता वर्तमान आय में से सामान्यतः ज्यादा बचत करेगी और डिलीवरेज भी करेगी जिससे सुधार की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। मंदी से उबरने की गति एवं समय पर प्रकाश डालने के लिए आस्ति मूल्य चक्र सहित धन प्रभाव फायदेमंद हो सकते हैं।

संदर्भ:

1. डीटन, ए. (1992): अंडरस्टैंडिंग कंजम्पशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. आइएमएफ (2002): “श्री एसेज ऑन हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स एफेक्ट रियल एक्टिविटी”, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट लुक, वाशिंगटन डीसी, अप्रैल।
3. स्लेकलेक (2006): “इंटरनेशनल वेल्थ एफेक्ट्स”, डीआइडब्ल्यू डिस्कशन पेपर सं.596, जर्मन इस्टीमेट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, बर्लिन।

बॉक्स -II.21

आवास मूल्य सूचकांक: हाल की गतिविधियां

हाल के वर्षों में, अनेक देशों में आवास के मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव हुए। सब-प्राइम संकट के संदर्भ में, आवास मूल्य सूचकांक पर प्रतिनिधि आंकड़ों का संग्रहण और देश की समष्टि आर्थिक स्थितियों के संबंध में आवास की कीमतों में परिवर्तन की दिशा की विश्लेषणात्मक व्याख्या नीतियों के संचालन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आवास व्यक्तिगत धन का एक प्रमुख अंग है। अतः इसके मूल्य में परिवर्तन उपभोक्ता के खर्च और बचत निर्णय को प्रभावित कर सकता है, इस कारण से समग्र आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। आवास कीमतों में परिवर्तन आवासीय निवेश क्षेत्र को प्रभावित और इसकी स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकता है जो रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा, आवास की कीमतें आवास खरीदने के सामर्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक तत्व हैं जो अनेक देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिगत लक्ष्य हैं। आवास की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को समझने के लिए सकल आवास कीमतों को सही ढंग से आंकना महत्वपूर्ण है। तथापि, व्यवहार में ऐसे उपाय विकसित करना कठिन है। आवास अत्यन्त विषम उत्पाद है और आवास जल्दी-जल्दी बेचे नहीं जा सकते हैं। इसकी विषमता के कारण इसकी समग्र और अलग-अलग कीमत विविधता के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आवास का जल्दी-जल्दी न बेचा जाना संकेत करता है कि किसी भी समयावधि में अधिकांश मकानों की कीमतें तय नहीं होती हैं।

शैक्षणिक अनुसंधान दर्शाते हैं कि आवास मूल्य सूचकांक का अनुमान यथासंभव समय परिवर्तियों के बेहतर विमूर्हन का प्रयोग कर लगाया जाना चाहिए। अनुभवजन्य अनुसंधान करने एवं नीतियां संचालित करने के लिए उच्च आवृत्ति स्तर पर एक सूचकांक निर्मित करने से निश्चित लाभ होता है। समय पर एवं बार-बार से रिपोर्ट किया गया सूचकांक वास्तविक मूल्य उतार-चढ़ाव को असहज बना सकता है और इससे बाजार की कारगरता के प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। सूचकांक रिपोर्टिंग के लिए उच्च आवृत्ति स्तर पर छोटे आंकड़ा सेट का प्रयोग करते समय दो मानदंडों को ध्यान में रखना होगा। पहला मानदंड है - नमूना के विभिन्न आकारों के स्तर पर सूचकांक की स्थिरता। दूसरा मानदंड है - अद्यतन करने के समय सूचकांक की सुसंगति। दूसरे शब्दों में, सूचकांक का समग्र उतार-चढ़ाव क्या होगा जब अगली अवधि की बिक्री या पिछली अवधि की विलंब से बिक्री इसमें शामिल हो जाएगी एवं अद्यतन हो जाएगी।

सांख्यिकी दृष्टि से, आंकड़ा संग्रहण समय में कमी करने का यह मतलब निकल सकता है कि : नमूना के छोटे आकार (उप-नमूने) का प्रयोग करना पड़ेगा; और एकत्रित किए गए ऐसे उप-नमूने केवल जनसंख्या के कुछ अंश का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। नमूने का आकार अनुमान की परिशुद्धता से संबंधित होता है (साधारणतः परिशुद्धता नमूना आकार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है)। प्रायः यह परिशुद्धता को दर्शाने के लिए विश्वसनीय अंतराल का प्रयोग करता है। जब नमूने के छोटे आकार का प्रयोग किया जाता है तब हमें एक और बात के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है कि क्या हम जनसंख्या के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। असममितिक सामान्यता अनेक अर्थमिति आंकलनकर्ताओं के लिए स्वीकार कर ली जाती है लेकिन ये तभी स्वीकार्य होते हैं यदि नमूने में बड़ी संख्या में निष्कर्ष दिये गए हों। असममितिक विश्लेषण के लिए नमूने का आकार कितना बड़ा होना चाहिए यह उसमें निहित जनसंख्या विस्तार पर निर्भर करता है। निःसंदेह नमूने के आकार और स्थावर-संपदा सूचकांक निर्माण में अस्थायी समुच्चयन के बीच सामंजस्य है।

ऐसी चुनौतियों के रहते, आवास के सकल मूल्य को मापने के लिए तीन पद्धतियां विकसित की गई हैं। पहले दृष्टिकोण में उस अवधि में सभी आवास कीमतों का सामान्य औसत लिया जाता है - साधारणतः माध्य या माध्यिका। ऐसा करने से विषमता और कभी कभी होने वाले विक्रय की समस्या की अवश्य उपेक्षा हो जाती है। इससे लाभ यह है कि इस औसत तरीके को व्यवहार में लाने से मूल्य श्रृंखला तात्कालिक आधार पर बहुत बड़ी संख्या में लेन-देनों का प्रायः सार तैयार कर सकती है। दूसरा दृष्टिकोण - पुनरावृत्ति विक्रय तरीका है जो उन आवासों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें एक बार से ज्यादा बेचा गया हो। जब तक कि आवास की गुणवत्ता अपरिवर्तित रहती है, उनके मूल्य में बढ़ोतरी की दर सकल आवास मूल्य की बढ़ोतरी के बराबर रहने की आशा व्यक्त की जाती है। पुनरावृत्ति विक्रय तरीके का इस्तेमाल करने पर मूल्य आंकड़े विषमता को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा कार्य करने के साथ-साथ अनेक भू-स्थितियों के लिए सकल मूल्य अनुमान उपलब्ध कराते हैं। तीसरा दृष्टिकोण उपयोग संबंधी तरीका है जो गुणवत्ता में अंतर के नियंत्रण की सांख्यिकी तकनीक है। विशेष रूप से, आवास के विक्रय मूल्य और उनकी विशेषता के बीच सह-संबंधों का प्रयोग विभिन्न विशेषताओं के लिए आकलित ‘‘मूल्य’’ में किया जाता है जिनका प्रयोग विशेषताओं को दर्शाने वाले समूह के कुल मूल्यों की गणना के लिए किया जाता है। दुर्भाग्यवश, उपयोग संबंधी दृष्टिकोण के सही कार्यान्वयन के लिए सामान्यतः उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में विस्तृत आंकड़ा विशेषता की आवश्यकता होती है। तथापि, उपयोग संबंधी दृष्टिकोण को प्रयोग करने वाली अग्रणी श्रृंखला ने कुछ समय में लगभग एक समान भौतिक-गुणवत्ता वाले नए आवासों के कीमत निर्धारण में बेहतर कार्य किया है।

इन उपायों में से कौन सर्वश्रेष्ठ आकलन प्रदान कर सकता है वह उसके उद्देश्यों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। नीति की दृष्टि से एक संभाव्य उद्देश्य आवास कीमतों में बढ़ोतरी से आवास मालिकों की संपत्ति में बढ़ोत्तरी का आकलन करना है। ऐसे सकल मूल्य बढ़ोतरी के आकलन के लिए पुनरावृत्ति विक्रय सूचकांक सबसे अच्छा है, इसने गुणवत्ता वाले आवासों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरह किया है। प्रमुख सतर्कता यह है कि इस उपाय के अनुसार कीमतों में परिवर्तनों की प्रतिरूपी दर आवास में सुधार को आंकने में विफलता और बार-बार बिकने वाले मकानों की गैर-प्रतिनिधिक प्रकृति के कारण कुछ बढ़ा-चढ़ा कर दर्शाई हो सकती है। दूसरा संबंधित उद्देश्य आवास की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू निवल मालियत में सकल परिवर्तन का आकलन करना हो सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिरूपी लाभ के आकलन के बजाय, इसका उद्देश्य कुल मुनाफे का आकलन करना है। तीसरा संभावित उद्देश्य गृह निर्माण क्षेत्र की स्थिति को आंकना हो सकता है। बढ़ती हुई कीमतें आवास में निवेश को बढ़ाने वाला स्पष्ट उत्प्रेरक हैं। एक तरफ डेवलपर को मकान बनाने में बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी तरफ, वर्तमान मकानों के मालिक समता प्राप्त कर सकते हैं और वर्तमान मकानों में सुधार कर सकते हैं। आवास के सकल मूल्यों के आकलन का चौथा उद्देश्य औसत खरीद क्षमता को मापना हो सकता है।

संदर्भ :

1. मीसे, आर., वलेस, एन., 1997. रिहाइशी आवास मूल्य सूचकांक निर्माण: दुबारा बिक्री, उपयोग संबंधी प्रतिगमन और संकर दृष्टिकोण की तुलना। जर्नल ऑफ रियल एस्टेट फाइनेंस एण्ड इकॉनॉमिक्स 14, 51-74।
2. वीकेन, ओ. (2004), ‘‘आस्ति मूल्य और आवास बाजार’’, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिमाही बुलेटिन, सिंग्रग।

II.3.53 आवास जैसी अन्य आस्तियों के मूल्य पर सूचनाएं भारत में सतत आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार में हाल के वर्षों में भारत के चुनिंदा शहरों के आवास मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। आवास मूल्यों पर आंकड़ों की उपलब्धता में सुधार के लिए रिजर्व बैंक ने आवास

कार्यारंभ सूचकांक (एचएसयूआइ) के विकास पर एक तकनीकी परामर्शदात्री समूह (टीएजी) का गठन किया। टीएजी की सिफारिशों के साथ-साथ आवास मूल्य सूचकांक के निर्माण के बारे में की गई पहलों की हाल की गतिविधियों का विवरण बॉक्स II.22 में दिया गया है।

बॉक्स- II.22 भारत में आवास संबंधी कार्यारंभ सूचकांक

आवास संबंधी कार्यारंभ के बारे में जानकारी को अग्रणी आर्थिक संकेतकों में से एक माना जाता है। निर्माण की नई परियोजनाओं में उच्च वित्तीय परिव्यय निहित होते हैं, जो कि निवेश, व्यवसाय और ग्राहक के भरोसे की संभावना को प्रकट करते हैं। आवास संबंधी कार्यारंभ की प्रवृत्तियों से गृहनिर्माताओं, बैंकों, उधारदाताओं, और गृह-सज्जा कम्पनियों को मूल्यवान संकेत प्राप्त होते हैं।

केन्द्रीय बैंकों के लिए एक ऐसे संकेतक के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास संबंधी कार्यारंभ सूचकांक विकसित करने पर तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी ऑन एचएसयूआइ) का गठन प्रो. अमिताभ कुंडू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया। इस तकनीकी सलाहकार दल में भारतीय रिजर्व बैंक, सीएसओ, एनएसएसओ, एनएचबी, एनबीओ, हुडको, भारतीय स्टेट बैंक, चार राज्य डीईएस के शीर्ष अधिकारी और इस क्षेत्र के विख्यात अकादमिशियन शामिल किए गये हैं। इस दल ने अपनी रिपोर्ट टीएजी ऑन एचएसयूआइ की अंतिम बैठक में प्रस्तुत की, जो 3 मार्च 2009 को सम्पन्न हुई थी। दल की प्रमुख सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है:

एचएसयूआइ का निर्माण आंकड़ों के दो समूहों के आधार पर किया जा सकता है: (क) आवासन परमिटों को आवास निर्माण की शुरुआत में तब्दील होने के नवीनतम अनुभव को प्रकट करने के लिए कार्यारंभ-गुणांक, और (ख) विगत दो वर्ष के दौरान या इसके आसपास जारी परमिटों की संख्या। दल ने महसूस किया कि राष्ट्रीय भवन संगठन, (एनबीओ), आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार आँकड़ा संग्रह की वर्तमान प्रणाली को उसके प्रपत्र सहित उत्कृष्ट बनाया जाए ताकि भवन-निर्माण परमिटों के बारे में अपेक्षित आँकड़े तिमाही आधार पर प्राप्त किए जा सकें। एचएसयूआइ के नियमित प्रकाशन हेतु प्रणाली को संस्थाबद्ध रूप देने के लिए पहला कदम यह होगा कि शहरी केन्द्रों को पर्याप्त रूप से दायरे में लाते हुए फील्ड-सर्वेक्षण किया जाए, जो कि समग्र देश के लिए प्रतिनिधि स्वरूप हो सकता है। दल ने सिफारिश की कि प्रत्येक चुनिंदा केन्द्र के लिए कार्यारंभ की दर के मैट्रिक्स के अनुमान को / अद्यतन करने के लिए यह सर्वेक्षण तीन साल में एक बार किया जाए। दल ने सिफारिश की कि प्रारंभिक प्रयास के रूप में छह महानगरों और श्रेणी-I के चुनिंदा नगरों में एचएसयूआइ की शुरुआत की जाए। कार्यारंभ दर मैट्रिक्स के आकलन हेतु फील्ड सर्वेक्षण दो चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण में भवन निर्माण परमिटों के सर्वेक्षण (एसबीपी) का प्रयोग करते हुए चुनिंदा केंद्रों में भवन-निर्माण परमिटों के आंकड़ों का संग्रह किया जा सकता है। चुनिंदा केंद्रों पर परमिट जारीकर्ता प्राधिकरणों से नए आवासीय निर्माण के लिए जारी सभी परमिटों के विवरणों का संग्रह करके एसबीपी किया जा सकता है। दूसरे चरण में नए आवासीय भवनों के लिए जारी परमिटों के नमूने पर आधारित आवास निर्माण कार्यारंभ सर्वेक्षण की पहचान की जा सकती है। इन नमूना परमिटों के अनुसरण हेतु कार्यक्रम के तहत मतसंग्रह किया जा सकता है।

किसी भी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के तदनु रूप इस आंकड़े के आधार पर, कार्यारंभ की 9 दरें (जिस तिमाही में परमिट दिए गए उसके लिए 1+7 अनुवर्ती तिमाहियों के लिए 7+ दो वर्ष के बाद सभी शुरुआतों के लिए 1) एक वर्ष की 4 अलग-अलग तदनु रूप तिमाहियों के लिए निकाली जा सकती हैं और कार्यारंभ दरों का 4 x 9 मैट्रिक्स (गुणांक) प्राप्त किया जा सकता है। इन कार्यारंभ दर (गुणांक) मैट्रिक्स का प्रयोग चुनिंदा महानगरों और श्रेणी-I नगरों के लिए आवास कार्यारंभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिनके लिए भवन निर्माण परमिटों के नियमित आंकड़े तिमाही आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर के सूचकांक के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग तिमाही के लिए एचएसयूआइ अनुमान लगाने में किया जा सकता है।

$$HSUI_t = \frac{\sum_{i=1}^n A_{i0} S_{it}}{\sum_{i=1}^n A_{i0} S_{i0}}$$

इस सूत्र में n = केंद्रों की संख्या, A_{i0} आधार अवधि में $i^{\text{वें}}$ केंद्र की औसत एफएसए; $S_{it} = i^{\text{वें}}$ केंद्र में $t^{\text{वें}}$ तिमाही में आवास कार्यारंभ की संख्या; S_{i0} $i^{\text{वें}}$ केंद्र में आधार अवधि में आवास कार्यारंभ की संख्या है।

दल ने सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया जाए जो कार्यारंभ मैट्रिक्स तैयार करने के लिए सर्वेक्षणों की पहल करे, इसकी प्रगति की निगरानी करे, शुरुआत करे और उसका विहगावलोकन करे और समय के साथ एचएसयूआइ के दायरे और व्यापि को बढ़ाने पर विचार करे। इसने यह भी सुझाव दिया कि एनबीओ में एचएसयूआइ पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए, जो संबंधित स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग से नियमित आधार पर आवास निर्माण परमिटों के आंकड़ों के संकलन की समग्र प्रक्रिया का मार्गदर्शन करे और उसका पर्यवेक्षण रखे।

संदर्भ:

1. भारतीय रिजर्व बैंक, “भारत में आवास संबंधी कार्यारंभ सूचकांक के विकास पर तकनीकी सलाहकार दल की रिपोर्ट” <http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?FromDate=03/05/2009> पर उपलब्ध है।
2. अमरीकी जनसंख्या ब्यूरो, “नये आवासीय निर्माण” <http://www.census.gov/const/www/newresconstdoc.html> पर उपलब्ध है।
3. सांख्यिकीय कनाडा, “भवन परमिट सर्वेक्षण” <http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=2802&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2#2> पर उपलब्ध है।

2009-10 की गतिविधियां

11.3.54 मार्च 2009 के अंत में डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गिरकर 0.8 प्रतिशत हो गई और जून 2009 में ऋणात्मक हो गई तथा सबसे ऋणात्मक बनी रही (8 अगस्त 2009 को - 1.5 प्रतिशत) जो 2008-09 की पहली छमाही के दौरान मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि के आधार प्रभाव को दर्शाती है। तथापि, 2009-10 के दौरान (8 अगस्त 2009 तक) डब्ल्यूपीआइ 3.8 प्रतिशत बढ़ी जो मूल्य दबावों की विद्यमानता को दर्शाती है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, जैसा कि विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में परिलक्षित हुआ, और बढ़ी तथा जून 2009 में वह 9.3 - 11.5 प्रतिशत के दायरे में बनी रही।

11.3.55 कुल मिलाकर, 2008-09 के दौरान गैर-मौद्रिक कारकों द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित मुद्रास्फीति की स्थितियों में बड़ी मात्रा में मौजूद अस्थिरता ने भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में जटिल चुनौतियां खड़ी कीं। सीपीआइ और डब्ल्यूपीआइ आधारित मुद्रास्फीति के बीच बड़े अंतर और आस्ति की कीमतों में अत्यधिक गिरावट ने चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया। वित्तीय संकट के व्यापक प्रभावों के सामने आने से पहले ही वैश्विक पण्य एवं खाद्य पदार्थों की कीमतों ने बढ़कर संकट की स्थिति का रूप ग्रहण कर लिया, जो वैश्विक मंदी के गहराने के साथ वर्ष की दूसरी छमाही में उसी तीव्रता से गिर गयीं। इस चक्र के दोनों चरणों में, भारतीय मुद्रास्फीति में वैश्विक मुद्रास्फीति का संचरण तीव्र और बड़ी मात्रा में हुआ, भले ही कुछ मूल्य संवेदनशील वस्तुओं की आयात लागत को कम करने के लिए राजकोषीय उपाय किए गए और कुछ वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों के कारण उनका सीमित अंतरण हुआ। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण में भी वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से हटाकर वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में मंदी के असर को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर फोकस किया गया। 2009-10 के दौरान, वर्ष-दर-वर्ष डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति कम बनी रही और जून 2009 से ऋणात्मक कम बनी रही और जून 2009 से ऋणात्मक हो गई, जो 2008-09 की पहली छमाही के दौरान मूल्यों में तीव्र वृद्धि के उच्च आधार के कारण थी। इस प्रकार, कम डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति अधिकांश तथा सांख्यिकीय परिदृश्य प्रस्तुत करती है और इसे मांग संकुचन से उपजी संरचनात्मक अपस्फीति के रूप में न समझा जाए।

IV. सरकारी वित्त

11.4.1 बाह्य मांग के साथ-साथ देशी निजी मांग में गिरावट से जूझ रही धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए राजकोषीय नीति की स्थिरीकरण की भूमिका ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इससे राजकोषीय दृष्टिकोण में विगत वर्षों में क्रमिक समेकन पर बल के रास्ते से हटाकर 2008-09 में सक्रिय प्रतिचक्रीय विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण और तुरंत बदलाव लाने की जरूरत पैदा हुई। इसके फलस्वरूप घाटे के सभी मानदंडों की हाल ही की प्रवृत्तियों में काफी विपथन हुए।

11.4.2 वर्ष की पहली छमाही में उच्च मुद्रास्फीति से संबंधित चिंता का निवारण करों में कटौती और सब्सिडी के रूप में उपयुक्त मौद्रिक उपायों द्वारा किया गया। दूसरी छमाही के दौरान, वृद्धि में कमी से संबंधित चिंताओं और सरकार के समर्थन की संबंधित व्यापक मांग के कारण अधिक खर्च और करों में कटौती दोनों की संयुक्त राजकोषीय रणनीति के प्रयोग को बल मिला जिसकी मात्रा सकल देशी उत्पाद की 3.1% के बराबर थी। एक जैसी मंदी का भार झेल रहे विश्व के अनेक देशों में उचित विवेकपूर्ण राजकोषीय स्थिरीकरण का सर्वनिष्ठ प्रयोग किया गया हालांकि उपायों की मात्रा एवं परिमाण देश विशेष की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार थे।

11.4.3 केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में 2008-09 के संशोधित अनुमानों में बहुत ज्यादा कमी आई। यह कमी वैश्विक आर्थिक मंदी और विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष करों में कटौती और अनुदान के लिए की गयी तीन अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त व्यय के कारण हुई। परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में बहुत ज्यादा कमी होने से जीडीपी अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कम हुईं, जबकि जीडीपी अनुपात की तुलना में कुल व्यय में तेज वृद्धि हुई (सारणी 2.34)। इसके फलस्वरूप 2008-09 (संअ) में प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात् सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी), राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे में बजट स्तर से तेज बढ़ोतरी हुई और वे 2007-08 की तुलना में जीडीपी के 4.2 से 4.8 प्रतिशत की सीमा में अधिक रहे। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र और

सारणी 2.34: प्रमुख राजकोषीय संकेतक: संयुक्त वित्त

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	1990-91	1995-96	2007-08	2008-09 स.अ.
1	2	3	4	5
1. सकल राजकोषीय घाटा	9.4	6.5	4.2	8.9
2. राजस्व घाटा	4.2	3.2	0.2	4.4
3. प्राथमिक घाटा	5.0	1.6	-1.3	3.5
4. राजस्व प्राप्तियां	18.6	18.3	22.2	21.9
(i) कर राजस्व	15.4	14.7	18.5	18.1
प्रत्यक्ष कर	2.5	3.5	7.5	7.4
अप्रत्यक्ष कर	12.9	11.2	11.0	10.7
(ii) करेतर राजस्व	3.2	3.6	3.7	3.8
5. कुल व्यय	28.7	25.4	27.4*	31.2
(i) विकास व्यय	17.1	13.9	14.7*	18.6
(ii) विकासेतर व्यय	11.5	11.5	12.7	12.6
जिनमें:				
ब्याज भुगतान	4.4	5.0	5.5	5.4
6. ऋण @	64.7	61.0	75.1	74.7
	प्रतिशत			
बजटेतर मदें	0.2	0.3	0.8	1.8
पूँजी परिव्यय/ कुल व्यय	13.1	10.8	17.0	14.2
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियां	23.6	27.2	24.6	24.5
राजस्व घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा	44.6	48.8	4.7	49.6

सं अ : संशोधित अनुमान।

* : भारत सरकार को एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अंतरण संबंधी लेनदेनों की 35,531 करोड़ रुपये की राशि सहित।

@ : 'आरक्षित निधि' और 'जमाराशियां और अग्रिम' सहित।

टिप्पणी : 1. सभी संकेतक अंतर सरकारी लेनदेन को घटाकर केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित आंकड़े हैं।

2. राज्य सरकारों से संबंधित आंकड़े वर्ष 2007-08 के लिए अनंतिम हैं और 27 राज्य सरकारों के बजट से संबंधित हैं जिनमें से 2 लेखानुदान हैं।

3. संयुक्त वित्तों के राजकोषीय अनुपात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों पर आधारित हैं।

राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के माध्यम से हाल के वर्षों में वित्तीय समेकन से प्राप्त लाभों ने प्रति-चक्र्रीय राजकोषीय नीति को जारी रखने में सरकार को वित्तीय गुंजाइश उपलब्ध कराई।

केंद्र सरकार के वित्त - 2008-09

संशोधित अनुमान

11.4.4 वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि के 8.8 प्रतिशत की मजबूत औसत जीडीपी वृद्धि की पृष्ठभूमि में 2008-09 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया और तदनुसार 2008-09 के लिए प्रमुख घाटे के संकेतकों के लिए आशावादी लक्ष्य तय किए गए। संशोधित अनुमानों में केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक बजट अनुमानों की तुलना में काफी अधिक हैं (सारणी 2.35 और चार्ट II.26) और पर्याप्त राजकोषीय उपायों के प्रभावों को दर्शाते हैं जो पहली छमाही में उच्च मुद्रास्फीति और दूसरी छमाही की मंद अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक हो गये थे। घाटा संकेतकों में अपने बजट के स्तर से संशोधित अनुमानों में विचलन को अर्थव्यवस्था में बजट पश्चात अप्रत्याशित गतिविधियों और उसके लिए किये गए वित्तीय उपाय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक पण्यों की उच्च कीमतों के कारण आ रहे मुद्रास्फीति दबावों को कम करने के लिए सरकार ने प्राथमिक और निर्मित उत्पादों के कर में कटौती के रूप में वित्तीय उपाय किए जिसके कारण कुछ राजस्व हानि हुई। वर्ष की दूसरी छमाही में, वृद्धि में कमी से संबंधित चिंताएं जैसे ही बढ़ीं, सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ा और निजी उपभोग मांग में तेज गिरावट को देखते हुए सकल मांग को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के रूप में कर में और कटौती करनी पड़ी।

11.4.5 जब निजी मांग में संकुचन से उत्पादन अपनी क्षमता से नीचे गिर जाता है तब निजी मांग में गिरावट के कारण अतिरिक्त क्षमता की मौजूदगी को देखते हुए उच्चतर सरकारी व्यय आपूर्ति प्रतिक्रिया पैदा करने में सीधे सहायक होता है। परिणामस्वरूप, उत्पादन अंतराल संकीर्ण हो जाता है। यह राजकोषीय नीति के सामान्य प्रति-चक्र्रीय स्थिरक प्रभाव के अनुसार है। फिर भी, राष्ट्रीय आय की लेखांकन प्रथाएं सरकारी सेवाओं के प्रावधान हेतु सरकार द्वारा किए जाने व्यय के बराबर सरकार के निष्पादन को प्रेरित करती हैं। जहां 2008-09 में सरकारी व्यय में कुल वृद्धि का एक भाग अंतरणों से संबंधित है वहीं शेष भाग उपभोग और निवेश मांग दोनों में ही विस्तार से

सारणी 2.35: केंद्र के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09	2008-09	2009-10	घट-बढ़ (2 की तुलना में 3)		घट-बढ़ (3 की तुलना में 4)	
	(बअ)	(संअ)	(बअ)	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्राप्तियां	6,02,935	5,62,173	6,14,497	-40,762	-6.8	52,324	9.3
2. विनिवेश	10,165	2,567	1,120	-7,598	-74.7	-1,447	-56.4
3. राजस्व व्यय	6,58,119	8,03,446	8,97,232	1,45,327	22.1	93,786	11.7
जिसमें से:							
(क) ब्याज भुगतान	1,90,807	1,92,694	2,25,511	1,887	1.0	32,817	17.0
4. पूंजी परिव्यय	84,522	83,305	1,11,267	-1,217	-1.4	27,962	33.6
जिसमें से:							
रक्षा	48,007	41,000	54,824	-7,007	-14.6	13,824	33.7
5. निवल उधार	3,746	4,504	8,114	758	20.2	3,610	80.2
6. कुल व्यय	7,50,884	9,00,953	10,20,838	1,50,069	20.0	1,19,885	13.3
7. राजस्व घाटा (3-1)	55,184	2,41,273	2,82,735	1,86,089	337.2	41,462	17.2
	(1.0)	(4.4)	(4.8)				
8. सकल राजकोषीय घाटा (4+5+7-2)	1,33,287	3,26,515	4,00,996	1,93,228	145.0	74,481	22.8
	(2.5)	(6.0)	(6.8)				
9. प्राथमिक घाटा (8-3क)	-57,520	1,33,821	1,75,485	1,91,341	332.7	41,664	31.1
	(-1.1)	(2.5)	(3.0)				

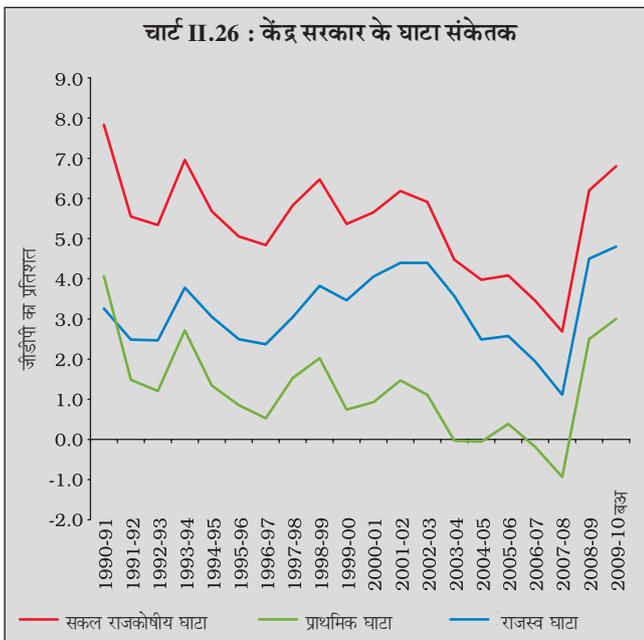
बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान.

टिप्पणी: 1. 2006-07 से, विनिवेश से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय निवेश निधि में ही रखा जाएगा ताकि इस तरह के लेन-देनों का राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव न पड़े।
2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

संबंधित है। 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार के रु.1,58,858 करोड़ रुपए के निवल अतिरिक्त व्यय में अंतरण शामिल हैं,

जैसे कि उर्वरक सब्सिडियां (रु.38,863 करोड़) और कृषि ऋण माफी (रु.15,000 करोड़)। रु.1,04,995 करोड़ के निवल अतिरिक्त व्यय को मोटे तौर पर माल और सेवाओं के उपभोग (रु.66,255 करोड़) और निवेश घटक (रु.38,740 करोड़) में अलग-अलग रखा जा सकता है। सामान्यतया राजकोषीय गुणक उपभोग व्यय की तुलना में निवेश व्यय के लिए ऊंचे पाए जाते हैं, हालांकि, इस निवेश व्यय का प्रभाव दीर्घावधि में महसूस किया जा सकेगा।

11.4.6 वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति में बड़े उतार-चढ़ावों को दर्शाते हुए, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में वर्ष 2008-09 की पहली छमाही में 25.3 प्रतिशत की हुई थी जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में इस वर्ष की तीसरी तिमाही में 11.6 प्रतिशत की कमी आई। यह कमी बजट पश्चात कर में कटौती के साथ-साथ विकास में मंदी के कारण निराशाजनक राजस्व उगाही के कारण आई। इस प्रकार सीमा और उत्पाद शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर में परिवर्तन और आर्थिक मंदी के चलते



प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी के कारण 2008-09 के संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व को बजट अनुमानों की तुलना में कम रखा गया जिसने सभी प्रकार के प्रमुख करों के अधीन संग्रहण को प्रभावित किया। सेवा कर, और बैंकिंग नकद लेन-देन कर, अनुषंगी लाभकर, यू.टी. कर जैसे करों और अन्य करों एवं शुल्कों के अधीन संग्रहण बजट स्तर (सारणी 2.43 देखें) से कुछ ज्यादा था जो सकल कर का बहुत छोटा अंश है। परिणामस्वरूप निवल कर राजस्व (अर्थात् राज्यों को अंतरित कर राजस्व का निवल) को भी बजट स्तर से नीचे रखा गया। हालांकि, आर्थिक सेवाओं, अन्य सामान्य सेवाओं और सहायता अनुदान एवं अंशदान जैसे 'अन्य करैतर राजस्व' में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तुलना में 2008-09 में करैतर राजस्व के अनुमान को अपेक्षाकृत अधिक रखा गया था। अन्य प्रमुख घटक जैसे लाभांश और लाभ एवं ब्याज प्राप्ति के अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में कम रखे गए। अतः वर्ष 2008-09 के लिए केंद्र के राजस्व प्राप्ति (निवल) के संशोधित अनुमान बजट स्तर से कम थे।

II.4.7 व्यय के मोर्चे पर, वित्तीय प्रोत्साहन उपायों और अन्य व्ययों की संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अनुदानों के लिए तीन अनुपूरक मांगों के तहत बड़ी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09

के बजट अनुमानों में विशेषकर राजस्व खाते के मुकाबले संशोधित अनुमानों में केंद्र सरकार के कुल व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई (सारणी 2.35)। योजनेतर उपादानों में सब्सिडी और रक्षा व्यय तथा योजना घटक के अंतर्गत ग्रामीण विकास पर व्यय के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। मुख्य रूप से खाद्य और खाद्य सब्सिडी के कारण संशोधित अनुमानों में सब्सिडी में 80.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए आवश्यक हो गई थी (सारणी 2.36)। रक्षा कार्मिकों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रक्षा राजस्व व्यय बढ़ गया। पूंजीगत व्यय के संबंध में, हालांकि 2008-09 के दौरान रक्षा पूंजीगत परिव्यय में गिरावट आई, गैर-रक्षा पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान में निवल उधार भी अधिक थे जिसमें ऋण वसूली से अधिक ऋण संवितरण थे।

II.4.8 व्यय में तीव्र वृद्धि और कर राजस्व में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख घाटा संकेतकों, अर्थात् राजस्व घाटे, जीडीपी की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे में 2008-09 के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में काफी वृद्धि हुई और 2008-09 के लिए प्राथमिक शेष बजट में अनुमानित प्राथमिक अधिशेष के विपरीत उच्च घाटे वाला था (सारणी 2.35)।

सारणी 2.36: केंद्र की सब्सिडी

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09बअ	2008-09संअ	2009-10बअ
1	2	3	4	5	6	7
सब्सिडी	47,522 (1.3)	57,125 (1.4)	70,926 (1.5)	71,431 (1.3)	1,29,243 (2.4)	111,276 (1.9)
जिसमें से:						
i. खाद्य	23,077 (0.6)	24,014 (0.6)	31,328 (0.7)	32,667 (0.6)	43,627 (0.8)	52,490 (0.9)
ii. उर्वरक	18,460 (0.5)	26,222 (0.6)	32,490 (0.7)	30,986 (0.6)	75,849 (1.4)	49,980 (0.8)
iii. पेट्रोलियम	2,683 (0.1)	2,699 (0.1)	2,820 (0.1)	2,884 (0.1)	2,877 (0.1)	3,109 (0.1)

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।

11.4.9 बड़े राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण जरूरतों को देखते हुए, निवल बाजार उधार अनुमानित स्तर से ढाई गुना था और 2008-09 के दौरान जीएफडी के लगभग तीन चौथाई के बजट में अनुमानित वित्तपोषण की तुलना में उन्होंने संशोधित अनुमानों में जीएफडी के 4/5 हिस्से से अधिक का वित्तपोषण किया। अल्पावधि ऋण ने संशोधित अनुमानों (बजट अनुमान 9.3 प्रतिशत) में जीएफडी के लगभग पांचवें हिस्से का वित्त पोषण किया। नकदी शेषों के आहरण द्वारा जीएफडी (बजट अनुमानों में 5.4 प्रतिशत) के लगभग दसवें भाग का वित्तपोषण किया गया। 'जमाराशियों एवं अग्रिमों' और 'बाह्य सहायता' से जीएफडी वित्तपोषण को सहायता बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों से कम थी (सारणी 2.47 देखें)।

11.4.10 2008-09 के दौरान प्रमुख घाटा-संकेतकों में विस्तार आर्थिक मंदी के कारण स्वचालित स्थिरकर्ता और मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत उपायों के संयुक्त प्रभावों के परिणामस्वरूप हुआ। इसी प्रकार, जहां आर्थिक मंदी ने कम हो रही राजस्व प्राप्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से घाटा-संकेतकों में विस्तार किया, वहीं मंदी से निपटने के लिए किए गए राजकोषीय उपाय उच्च व्यय और कर में कटौतियों के रूप में सामने आए, जिन्होंने घाटे को बढ़ाने में संयुक्त रूप से योगदान दिया। विभिन्न देशों के संदर्भ में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहन आकार आंशिक रूप से आर्थिक मंदी के परिमाण पर तय किए गए, जैसा कि जी-20 देशों में देखा गया और ये अंशतः स्वचालित स्थिरकर्ता के आकार पर निर्भर था जैसा कि आईसीडी देशों में देखा गया (बॉक्स II.23)। वृद्धि की गति में आयी मंदी के स्तर की दृष्टि से भारत अन्य जी-20 देशों की तुलना में कम प्रभावित देशों में होने के बावजूद भारत द्वारा प्रयुक्त राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर सबसे बड़े प्रोत्साहनों में से एक थे। इन विवेकपूर्ण उपायों का आकार विभिन्न देशों में बहुत अलग-अलग है। जी-20 देशों के लिए, 2009 में प्रोत्साहन का भारित औसत जीडीपी का लगभग 2.0 प्रतिशत है जो तुर्की में शून्य प्रोत्साहन से सऊदी अरब में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बीच है (चार्ट क)।

11.4.11 भारत में विवेकपूर्ण प्रोत्साहनों के बड़े आकार की तुलना में 2008-09 में स्वचालित स्थिरक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के

आसपास जितना निम्न हो सकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ये कम प्रतीत हो सकते हैं लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में ये तुलनीय लगते हैं (बॉक्स II.24)।

अनंतिम लेखे

11.4.12 महालेखा नियंत्रक द्वारा 2008-09 के लिए जारी किए गए अनंतिम लेखे यह दर्शाते हैं कि मुख्य रूप से कम राजस्व प्राप्त के कारण संशोधित अनुमान की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे प्रत्येक में 0.2 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है (सारणी 2.36)। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि अनंतिम लेखे में कुल व्यय संशोधित अनुमान से 19,484 करोड़ रुपए कम था, तथापि राजस्व प्राप्त में (17,522 करोड़ रुपए की), ऋण वसूली में (3,540 करोड़ रुपए की) और अन्य प्राप्तियों में (2,021 करोड़ रुपए की) गिरावट से घाटा-संकेतक और अधिक विस्तृत हुए।

केंद्र सरकार की ऋण स्थिति

11.4.13 केंद्र सरकार की बकाया घरेलू देयताएं, जिसमें आंतरिक ऋण और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन एस एस एफ), राज्य भविष्य निधि, अन्य लेखे, आरक्षित निधि और जमाराशियों जैसी अन्य देयताएं शामिल हैं, मार्च 2008 अंत के 57.7 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 56.6 प्रतिशत हो गयीं। बढ़ते घाटे के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा उधार लेने में आई तेजी और तेल विपणन एवं उर्वरक कंपनियों को विशेष प्रतिभूतियां देने जैसी बजटेतर देयताओं में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू देयताओं में बढ़ोतरी की तुलना में उच्चतर नॉमिनल जीडीपी बढ़ोतरी और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत सरकारी देयताओं में तीव्र कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण अनुपात कम हुआ। केंद्र सरकार की बकाया देयताओं में आंतरिक ऋण सबसे बड़ा घटक बना रहा (मार्च 2009 अंत में कुल ऋण का 64.2 प्रतिशत) और इसके बाद राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएस एसएफ) और अन्य लेखों (क्रमशः 15.2 और 10.2 प्रतिशत) के कारण बकाया देयताओं का स्थान था।

बॉक्स. II.23

राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय: विभिन्न देशों के अनुभव

वर्तमान संकट के प्रति राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में विवेकाधीन राजकोषीय नीति की भूमिका पर पुनः चर्चा हो रही है। कई देशों ने कुल मांग और तदनुसार वृद्धि को तेज करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय किए हैं। तथापि, प्रयोग में लाए गए माध्यमों और प्रोत्साहनों की मात्रा में विभिन्न देशों में अंतर रहा है, यह संकट की गंभीरता, देश विशेष में स्वचालित स्थिरकों के महत्व, इस परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति कार्रवाई और सबसे महत्वपूर्ण राजकोषीय गुंजाइश की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ओईसीडी देशों में, यद्यपि अधिकांश ने विस्तृत प्रोत्साहन कार्यक्रम अपनाए हैं जिनमें विभिन्न करों और खर्चों को एक साथ समायोजित करना शामिल है, तथापि, कई देशों ने व्यय बढ़ाने की अपेक्षा कर में कटौती को प्राथमिकता दी। अधिकांश देशों ने वैयक्तिक आय कर में कटौती पर ध्यान केंद्रित किया और कारोबारी कर में कटौती अपेक्षाकृत कम की। व्यय उपायों में अनेक देशों ने निवेश (बुनियादी ढांचा) और अंतरण के माध्यम से सुरक्षा नेट के प्रावधानों पर व्यय को बढ़ाया। जी-20 देशों में घोषित किए गए लगभग सभी व्यय उपाय अस्थायी हैं। दूसरी तरफ, लगभग सभी देशों में वैयक्तिक आयकर में की गई कटौती स्थायी है। अप्रत्यक्ष कर में छूट कुछ देशों में स्थायी है और अन्य देशों में अस्थायी या स्वयं दुबारा उसी रूप में वापस आने वाली है। (आइएमएफ, 2009)

इन विवेकपूर्ण उपायों का आकार विभिन्न देशों में बहुत अलग-अलग है। जी-20 देशों के लिए, 2009 में प्रोत्साहन का भारत औसत जीडीपी का लगभग 2.0 प्रतिशत है जो तुर्की में शून्य प्रोत्साहन से सऊदी अरब में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बीच है (चार्ट क)।

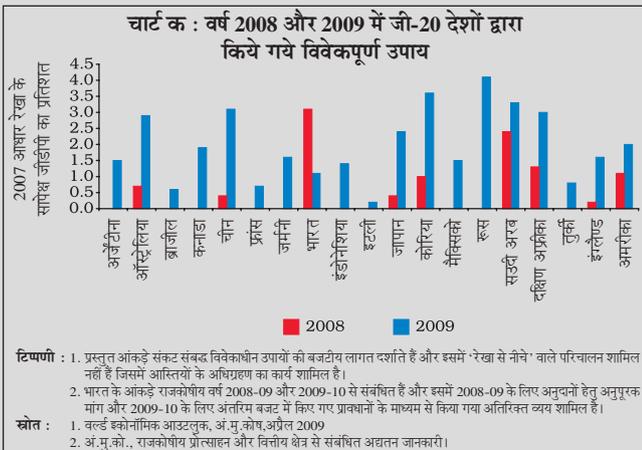
राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के आकार के विपरीत आर्थिक कार्यकलापों पर इन उपायों के वास्तविक प्रभावों को आंकना मुश्किल है क्योंकि इस तरह की गंभीरता वाले वैश्विक संकट के दौरान गुणक गतिवर्धक पारस्परिक प्रभाव अत्यधिक अनिश्चित हो सकते हैं। यह राजकोषीय मल्टीप्लायर को आंकने के लिए अर्थमितीय मॉडलों और विनिर्दिष्टियों के ऊपर निर्भर विभिन्न अनुभवजन्य अध्ययनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के

नतीजों के परिणामों से परिलक्षित होता है। विभिन्न प्रकार के नतीजे विभिन्न अनुभवजन्य समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, विशेषकर राजकोषीय नीति में वास्तविक विवेकपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाने वाले परिवर्तनों की तुलना में करों, अंतरणों और खर्च में निष्क्रिय परिवर्तन में अंतर करना। मल्टीप्लायर देश की परिस्थिति पर निर्भर होता है; जिसमें प्रयोग किए गए साधन, व्यापार संबंधी खुलापन, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, मौद्रिक नीति पर प्रतिक्रिया, और दीर्घावधि निरंतरता शामिल है। उपर्युक्त निर्दिष्ट बातों के साथ, समूह के तौर पर जी-20 के लिए मल्टीप्लायर के लिए आइएमएफ के मोटे अनुमान कर कटौतियों के लिए 0.3 से 0.6 तक, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 0.5 से 1.8 प्रतिशत तथा अन्य उपायों के लिए 0.3 से 1.0 प्रतिशत की सीमा में हैं। ऐसी ही सावधानियों के साथ, ओईसीडी देशों के लिए आकलित राजकोषीय मल्टीप्लायर दर्शाते हैं कि खर्च उपायों का राजस्व उपायों की तुलना में उच्च मल्टीप्लायर है और यह मल्टीप्लायर पहले वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष अधिक है। खर्च उपायों में बुनियादी ढांचे पर निवेश का उच्च मल्टीप्लायर है जिसके बाद सरकार द्वारा वस्तुओं की सीधी खरीद और सरकारी अंतरण का स्थान आता है। राजस्व उपायों में, वैयक्तिक आयकर में कटौती का अप्रत्यक्ष कर में कटौती की तुलना में अधिक मल्टीप्लायर प्रभाव है। छः देशों (आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन और अमेरिका) को छोड़कर ओईसीडी देशों में घोषित प्रोत्साहन पैकेजों का वृद्धि प्रभाव विद्यमान उत्पादन अंतर के परिमाण की तुलना में कम (जीडीपी के 1.0 प्रतिशत से कम) था (ओईसीडी, 2009)।

आइएमएफ(2009) के अनुसरण में, भारत में, केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2008- फरवरी 2009 के दौरान तीन प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए गए और अक्टूबर-दिसंबर 2008 और फरवरी 2009 के दौरान अनुदान के लिए तीन अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त व्यय को तीन श्रेणियों अर्थात्, कर में कमी के कारण राजस्व हानि, निवेश व्यय और अन्य व्यय में बांटा गया। वर्ष 2008-09 में, कर में कमी, निवेश और अन्य व्यय जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर क्रमशः 0.2 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत रहा। आइएमएफ के अनुमानित मल्टीप्लायर पर आधारित भारत द्वारा अपनाए गए प्रोत्साहन उपायों ने वृद्धि में गिरावट को 0.7 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत के बीच रखने में सहायता की। हालांकि व्यापक रेंज प्रभावों का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं बताते हैं, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृद्धि में मंदी की गति राजकोषीय प्रोत्साहन के बिना ज्यादा तीव्र हो सकती थी।

संदर्भ:

1. एंटोनियो एस, सैमनेस्की एस, ब्लांकार्ड ओ और कोटरेल्ली सी (2008), 'संकट के लिए राजकोषीय नीति' दिसंबर 2009.
2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2009), 'जी-20 के प्रमुखों की बैठक के लिए आइएमएफ के कर्मचारियों का नोट', 31 जनवरी -1 फरवरी 2009.
3. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (2009), 'वित्तीय प्रोत्साहन की प्रभावशालिता और दायरा', ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक।



बॉक्स II.24

स्वचालित राजकोषीय स्थिरकर्ता की भूमिका

कुल मांग सरकारी खरीद, कर और अंतरण भुगतान जैसे राजकोषीय उपायों से प्रभावित की जा सकती है। जब कुल मांग को प्रभावित करने के लिए सरकार जानबूझकर अपने खर्च या कराधान नीति में परिवर्तन करती है, तब इसे 'विवेकाधीन राजकोषीय नीति' कहा जाता है। व्यापार चक्र के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में उतार-चढ़ाव के कारण खर्च और कराधान में स्वतः परिवर्तन हो सकता है। किसी प्रगतिशील कर प्रणाली में जब आर्थिक तेजी के दौरान आय बढ़ती है तब उच्च आय पर उच्चतर कर दर और उच्चतर कर श्रेणी में अधिक लोगों के आने के कारण वसूली आनुपतिक रूप से अधिक बढ़ सकती है और आर्थिक गिरावट के दौरान स्थिति ठीक इसके विपरीत हो सकती है। इसके विपरीत, आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगार मुआवजा, सरकारी खरीद और गरीबों के लिए आय अनुपूरकों के तहत अंतरण भुगतान बढ़ सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिक लोग ऐसी सेवाओं और अंतरण हेतु पात्र हो जाते हैं और आर्थिक तेजी के दौरान स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों से प्रभावित होकर कर, अंतरण और खरीद में होनेवाले ऐसे स्वचालित परिवर्तन अक्सर कुल मांग के बढ़ने/घटने से उत्पन्न आर्थिक तेजी / मंदी के दौरान घाटे को संकुचित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करते हैं।

स्वचालित स्थिरक का परिमाण सार्वजनिक क्षेत्र के आकार, कर आधार की चक्रीयता, सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की डिजाइन, कर प्रणाली की प्रगतिशील प्रकृति और उत्पादन उतार-चढ़ाव का स्तर जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। चूंकि ये परिस्थितियां समूचे देश में फैली हुई हैं, इसलिए राजकोषीय परिणाम पर स्वचालित स्थिरक का प्रभाव समूचे देश में अलग-अलग पड़ता है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में स्वचालित स्थिरक छोटे होते हैं, जो सामाजिक अंतरणों की कम मात्रा और कम प्रगतिशील आयकरों को दर्शाते हैं। ओईसीडी देशों में, यह पाया गया कि विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन का आकार विपरीत रूप से स्वचालित स्थिरकर्ता (ओईसीडी, 2009) के आकार से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में, स्वचालित स्थिरकर्ता का प्रचालन जितना अधिक होगा, विवेकाधीन राजकोषीय हस्तक्षेप की अपेक्षित मात्रा उतनी ही कम होगी।

ऐसा माना जाता है कि जी-20 देशों में व्यापार मंदी की पूर्व घटनाओं में स्वचालित स्थिरक ने स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कई

देशों में, विवेकाधीन नीति में परिवर्तन व्यापार चक्र के अनुरूप नहीं पाये गये, जो यह बताता है कि स्वचालित स्थिरक अक्सर प्रणालीगत प्रतिचक्रिय नीति कार्रवाई का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इस प्रकार, राजकोषीय नीति की प्रतिचक्रिय भूमिका में, स्वचालित स्थिरक की भूमिका और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है जो कई वैकल्पिक तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान मंदी, जो गहरी है और दीर्घ समय तक रह सकती है, के परिप्रेक्ष्य में, इस बात पर अक्सर जोर दिया गया कि स्वचालित स्थिरक का प्रचालन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में पर्याप्त नहीं होगा और इसलिए अच्छी तरह तैयारी की गई विवेकाधीन राजकोषीय नीति लागू करनी होगी (देखें बॉक्स II.1)।

भारत के लिए लगातार दो वर्षों के बीच चक्रीय घाटे में हुए परिवर्तन (सीओबी) को स्वचालित स्थिरक (एएस) माना गया और इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया।

$$AS_t = \Delta COB_t = \Delta [(\eta_{Rt} - \eta_{Gt}) * GAP_t]$$

जहां $\eta_{Rt} = (\epsilon_R - 1) \frac{R_t}{Y_t}$ और $\eta_{Gt} = (\epsilon_G - 1) \frac{G_t}{Y_t}$, ϵ_R और ϵ_G आउटपुट अंतर के संदर्भ में ब्याज रहित राजस्व और खर्च लचीलापन है और यह समय के साथ स्थिर रहता है तथा $\frac{R_t}{Y_t}$ एवं $\frac{G_t}{Y_t}$ सकल घरेलू उत्पाद के प्राथमिक राजस्व और व्यय का अनुपात है।

वर्ष 2008-09 में स्वचालित स्थिरक जीडीपी का 0.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जी-20 देशों के अनुमान के अनुरूप है (2009)।

संदर्भ

1. अतिश आर. घोष (2009), 'कोपिंग विद द क्राइसिस: पॉलिसी ऑप्शन्स फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज', अप्रैल।
2. आईएमएफ (2009), 'कंपेनियन पेपर- द स्टेट ऑफ पब्लिक फायनेंस: आउटलुक एंड मीडियम टर्म पॉलिसी आफ्टर द 2008 क्राइसिस, मार्च 6।
3. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (2009), 'द इफेक्टिवनेस एंड स्कोप ऑफ फिस्कल स्टिमुलस'; ओईसीडी इकॉनॉमिक आउटलुक।

बजटेंतर मंदें

II.4.14 मुख्यतया, एक ओर सकल बाजार उधार में बढ़ोतरी और दूसरी ओर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि में आई कमी के कारण राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात 2007-08 के 31.6 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 (सं अ) में 34.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.27)। तथापि, वर्ष के दौरान बकाया बाजार ऋण पर औसत ब्याज दर में कमी आई (सारणी 2.38)।

II.4.15 बजट द्वारा सुनिश्चित सब्सिडी उपलब्ध कराने के अलावा केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक और तेल विपणन कंपनियों को खुदरा कीमतें इन्पुट लागत से नीचे रखने के कारण हुई कम वसूली को पूरा करने के लिए विशेष बांड

सारणी 2.37 : वर्ष 2008-09 के लिए केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक - अंतिम लेखे

(करोड़ रुपये)

संकेतक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम लेखे	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	55,184 (1.0)	2,41,273 (4.4)	2,47,046 (4.6)	2.4	347.7
सकल राजकोषीय घाटा	1,33,287 (2.5)	3,26,515 (6.0)	3,30,114 (6.2)	1.1	147.7
प्राथमिक घाटा	-57,520 (-1.1)	1,33,821 (2.5)	1,39,629 (2.6)	4.3	-342.7

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं। स्तंभ 3 और 4 के कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जीडीपी के संशोधित अनुमान पर आधारित हैं।

जारी कर अंतर्निहित सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। ये बांड राजकोषीय घाटे की दृष्टि से तटस्थ माने जाते हैं क्योंकि इनमें तत्काल कोई नकद बर्हिगमन नहीं होता और इसलिए इन्हें बजट व्यय/प्राप्ति के रूप में नहीं माना जाता। तथापि, इन बांडों से राजकोष पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनमें कालांतर में भुगतान करने की बाध्यता होती है और इस प्रकार यह सरकार की राजकोषीय देयताओं में जुड़ जाता है। इसके अलावा, चूंकि ऐसे बांडों पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय के एक अंग के रूप में माना जाता है, अतः वे राजस्व घाटे और तदनुसार राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। 2008-09 के दौरान, तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कंपनियों को क्रमशः 75,942 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए और दोनों मिलाकर

यह सकल देशी उत्पाद का 1.8 प्रतिशत था। बजट में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम को दी गई सुनिश्चित सब्सिडी सहित 2008-09 में केंद्र सरकार का कुल सब्सिडी बोझ सकल देशी उत्पाद का लगभग 4.2 प्रतिशत था।

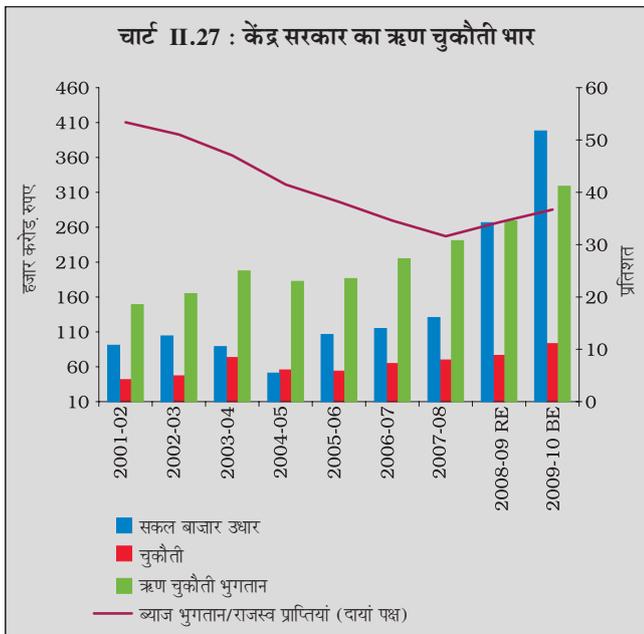
सारणी 2.38: केंद्र की बकाया देशी देयताओं की औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचतें/ एनएस एसएफ	राज्य भविष्य निधिया	विशेष जमाराशियां
1	2	3	4	5
1990-91 to 1994-95 (औसत)	10.86	10.85	11.63	11.53
1995-96 से 1999-2000 (औसत)	12.39	11.62	11.62	10.93
2000-01	12.99	11.6	10.54	9.87
2001-02	12.83	11.61	9.09	10.5
2002-03	12.11	11.56	8.53	8.82
2003-04	11.11	10.88	7.39	7.94
2004-05	9.87	9.37	7.99	7.65
2005-06	10.07	8.90	7.46	7.25
2006-07	8.90	8.91	7.63	6.85
2007-08	9.89	8.37	7.26	5.60
2008-09(संअ)	9.14	8.86	8.04	4.73

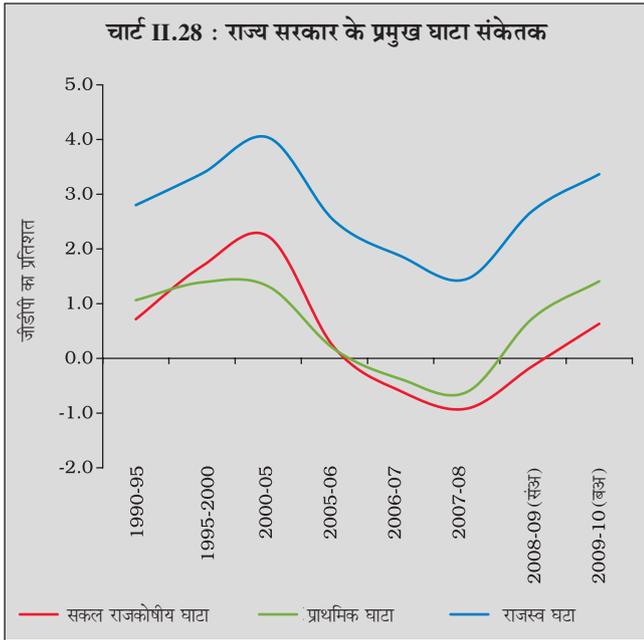
सं.अ. : संशोधित अनुमान

- टिप्पणी:**
1. बाजार ऋण दिनांकित प्रतिभूति दर्शाते हैं।
 2. अल्प बचतें, अल्प बचत जमाराशि, प्रमाणपत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि दर्शाती हैं। 1999-2000 से अल्प बचतों पर देय ब्याज राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज को दर्शाता है।
 3. सरकार ने 30 जून 2003 को विशेष जमाराशि योजना की निधि पर रोक को अधिसूचित किया।
 4. प्रत्येक घटक के लिए ब्याज दर की गणना वर्ष में ब्याज भुगतान को गत वर्ष के अंत में बकाया देयताओं से भाग देकर की जाती है।



राज्य सरकार के वित्त : 2008-09¹⁰

11.4.16 राज्य सरकारों के कुछ महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों की गिरावट में आर्थिक मंदी का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा हाल के वर्षों में राजकोषीय सुधार और समेकन के रास्ते अपनाए जाने के फलस्वरूप वे 2007-08 तक अपने वित्त में उल्लेखनीय सुधार करने में समर्थ हुए हैं, इनमें राज्यों का राजस्व अधिशेष जीडीपी के 0.9 प्रतिशत तक होना और 2007-08 में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 1.5 तक नियंत्रित रहना शामिल है। तथापि समग्र समष्टि आर्थिक मंदी के प्रभाव को दर्शाते हुए राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में बजट अनुमान की तुलना में 2008-09 के संशोधित अनुमान में गिरावट आई। 2008-09 में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत पर सत्ताइस राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष वर्ष के बजट अनुमान से 0.4 प्रतिशत कम रहा (देखें चार्ट II.28 और सारणी 2.49)। 27 राज्यों में से 23 राज्यों के राजस्व खाते 2008-09 (संशोधित अनुमान) में अधिशेष बने रहे हालांकि उनका स्तर कम था। 2008-09 (संशोधित अनुमान) में बजट अनुमान की तुलना में राजस्व अधिशेष में गिरावट मुख्यतया राजस्व प्राप्ति (बजट स्तर से 2.5 प्रतिशत अधिक) के मुकाबले राजस्व व्यय (बजट स्तर से 5.2 प्रतिशत अधिक) में अधिक वृद्धि के कारण रही।



11.4.17 वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) के दौरान अपने संबंधित बजट स्तरों की तुलना में केंद्र (8.2 प्रतिशत) से सहायता अनुदानों और राज्यों के स्व-करेतर राजस्व (19.4 प्रतिशत) में वृद्धि ने राज्यों के अपने कर राजस्व (1.9 प्रतिशत) में गिरावट के बावजूद बजट में निर्धारित राजस्व प्राप्ति से अधिक योगदान दिया। बजट स्तर की तुलना में 2008-09 (संशोधित अनुमान) में राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतया शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं और बिजली तथा परिवहन पर अधिक विकासात्मक व्यय (10.9 प्रतिशत) के कारण थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा छोटे/ राज्य वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण भी राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई।

11.4.18 राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2008-09 (संशोधित अनुमान) में सकल देशी अनुपात का 2.7 प्रतिशत था जो कि बजट अनुमान से लगभग 30.3 प्रतिशत अधिक था। राजस्व अधिशेष में गिरावट के अलावा, 2008-09 (संशोधित अनुमान) में सकल राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी बजट अनुमान की तुलना में पूंजी परिव्यय में वृद्धि (8.6 प्रतिशत) और ऋणेतर पूंजी प्राप्ति (64.6 प्रतिशत) में कमी के कारण थी। पूंजी परिव्यय संचाई, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर व्यय में बढ़ोतरी के कारण ऊंचा था। समग्र समष्टि आर्थिक मंदी को दूर करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश करने के लिए 2008-09 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति प्रदान की। कई राज्य सरकारों ने विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय कार्यान्वित किए। राजकोषीय स्थिति की गिरती अवस्था को दर्शाते हुए, पिछले दो वर्षों में अधिशेष में बने रहने के बाद 2008-09 (संशोधित अनुमान) में प्राथमिक घाटा पुनः उभरकर सकल देशी उत्पाद का 0.7 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारणी 30)।

11.4.19 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के तहत संग्रहों में गिरावट के कारण हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न में महत्वपूर्ण में परिवर्तन हुए हैं। 2008-09 (संशोधित अनुमान) में सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधार प्रमुख स्रोत बने रहे तथा वित्तपोषण आवश्यकताओं में इनका दो-तिहाई से अधिक योगदान रहा, जबकि राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष

¹⁰ 27 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित, जिसमें से 2 लेखानुदान हैं।

प्रतिभूतियों ने सकल राजकोषीय घाटे के महज 1.5 प्रतिशत का वित्तपोषण किया (परिशिष्ट सारणी 31)।

केंद्र और राज्यों की संयुक्त सरकारी बजट स्थिति - 2008-09

11.4.20 राजस्व प्राप्ति में कमी और व्यय में तेज बढ़ोतरी के कारण 2008-09 (संशोधित अनुमान) के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों की दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में महत्वपूर्ण कमी आई (सारणी 2.39)। संशोधित अनुमानों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्ति में कमी आयी और ऐसा आर्थिक मंदी तथा वृद्धि को तेज करने के प्रयोजन से कर कटौती के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ। औसत व्यय बजट अनुमान से अधिक था और यह मुख्यतया केंद्र सरकार द्वारा छोटे वेतन आयोग के निर्णय, कृषि ऋण माफी योजना,

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आधारभूत ढांचे के कार्यान्वयन के फलस्वरूप किये गये अतिरिक्त खर्च के कारण हुआ। कुछ राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार की भांति उपायों की घोषणा की और केंद्र सरकार द्वारा छोटे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वेतन संशोधन लागू किये।

संयुक्त उधार

11.4.21 राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि के बावजूद 74.7 प्रतिशत पर जीडीपी के अनुपात के रूप में संयुक्त बकाया देयताओं ने मार्च 2008 के अंत की तुलना में सीमांत गिरावट दर्शायी। इस गिरावट का मुख्य कारण सांकेतिक जीडीपी में वृद्धि थी, जो देयताओं में वृद्धि से अत्युत्तम थी (सारणी 2.40)।

11.4.22 प्रतिचक्रीय विस्तारकारी राजकोषीय नीति से जुड़े बढ़ते घाटों और आर्थिक मंदी से उपजी राजस्व हानि निकट अवधि में

सारणी 2.39: केंद्र और राज्यों के संयुक्त वित्त के संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मदे	1990-91	1995-96	2000-01	2007-08	2008-09 ब.अ.	2008-09 सं.अ.	घट-बढ़ (बअ की तुलना में सं.अ.)	
							राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा [11-अ-आ(क)]	53,580	77,671	1,99,852	1,97,037	2,42,273	4,71,520	2,29,247	94.6
	(9.4)	(6.5)	(9.5)	(4.2)	(4.6)	(8.9)		
राजस्व घाटा [11-अ]	23,871	37,932	1,38,803	9,163	30,147	2,33,938	2,03,791	676.0
	(4.2)	(3.2)	(6.6)	(0.2)	(0.6)	(4.4)		
प्राथमिक घाटा	28,585	18,598	75,035	-60,495	-43,604	1,86,034	2,29,638	-526.6
	(5.0)	(1.6)	(3.6)	(-1.3)	(-0.8)	(3.5)		
I. कुल प्राप्तियां (क+ख)	1,51,593	2,96,629	5,94,804	13,11,589	14,70,354	16,42,815	1,72,461	11.7
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	1,05,757	2,17,526	3,78,817	10,48,406	11,93,487	11,66,470	-27,017	-2.3
1. कर प्राप्तियां (क+ख)	87,564	1,74,851	3,05,374	8,73,779	10,12,456	9,65,102	-47,354	-4.7
क) प्रत्यक्ष कर	14,267	41,603	80,215	3,55,929	4,08,571	3,93,060	-15,511	-3.8
ख) अप्रत्यक्ष कर	73,297	1,33,248	2,25,159	5,17,850	6,03,885	5,72,042	-31,843	-5.3
2. करेतर प्राप्तियां	18,193	42,675	73,443	1,74,627	1,81,031	2,01,368	20,337	11.2
आ. पूंजी प्राप्तियां	45,836	79,102	2,15,987	2,63,183	2,76,867	4,76,345	1,99,478	72.0
क) गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	3,531	6,968	12,591	50,460	32,267	21,119	-11,148	-34.5
ख) ऋण पूंजी प्राप्तियां	42,305	72,134	2,03,396	2,12,723	2,44,600	4,55,226	2,10,626	86.1
II. कुल खर्च (1+2+3 = 4+5)	1,62,868	3,02,166	5,91,258	12,95,903	14,68,027	16,59,109	1,91,082	13.0
1. राजस्व व्यय	1,29,628	2,55,457	5,17,618	10,57,569	12,23,634	14,00,408	1,76,774	14.4
2. पूंजी परिव्यय	21,353	32,594	55,875	2,19,853	2,24,159	2,34,906	10,747	4.8
3. ऋण एवं अग्रिम	11,887	14,115	17,766	18,481	20,234	23,795	3,561	17.6
4. विकास व्यय	97,149	1,65,361	3,08,546	6,96,200	8,22,517	9,88,513	1,65,996	20.2
5. विकासेतर व्यय	65,719	1,36,805	2,82,712	5,99,703	6,45,510	6,70,596	25,086	3.9

सं.अ: संशोधित अनुमान.

बअ: बजट अनुमान

टिप्पणी: 1. अंतर- सरकारी लेन-देन की निवल राशि प्राप्त की गई है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।

3. राज्यों से संबंधित आंकड़े 2007-08 से अनंतिम हैं और 22 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 14 लेखानुदान हैं।

सारणी 2.40: केंद्र और राज्यों की संयुक्त देयताएं

मार्च अंत	बकाया देयताएं (करोड़ रुपए)			ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)		
	केंद्र	राज्य	संयुक्त	केंद्र	राज्य	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,28,155	3,68,824	55.2	22.5	64.7
1995-96	6,06,232	2,49,535	7,26,854	50.9	20.9	61.0
2000-01	11,68,541	5,94,147	14,84,106	55.6	28.3	70.6
2005-06	22,60,145	11,67,866	28,79,705	63.0	32.6	80.3
2006-07	25,38,596	12,50,819	31,90,698	61.5	30.3	77.3
2007-08	28,37,425	13,14,355	35,47,790	60.1	27.8	75.1
2008-09 संअ.	31,36,075	14,44,165	39,73,203	58.9	27.1	74.7
2009-10 बअ.	34,95,452	16,12,377	44,85,955	59.7	27.5	76.6

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

टिप्पणी: 1. राज्यों से संबंधित आंकड़े 2007-08 से अंतिम हैं और 22 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें से 14 लेखा अनुदान हैं।
2. संयुक्त देयताओं, के अंतर्गत अंतर-सरकारी लेनदेनों को घटाया गया है।
3. आंकड़ों में 'आरक्षित निधियां' और 'जमाराशि तथा अग्रिम' शामिल हैं।

ऋण की सततता को प्रभावित कर सकती है। इससे बाजार की प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो सकती है और तदनुसार राजकोषीय

प्रोत्साहन पर आंशिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऋण गतिशीलता की सुस्थिर अवस्था दर्शाती है कि बजटतर सभी उधार शामिल करने के बाद भी 2007-08 में कर्ज-जीडीपी अनुपात स्थिर बनाए रखने की दृष्टि से ऋण धारणीयता की स्थिति संतोषप्रद रही, लेकिन 2008-09 में यह स्थिति काफी बदल जायेगी। राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतानों के अनुपात की दृष्टि से जो कर्ज चुकौती बोझ 2001-2002 के बाद लगातार कम हुआ था, वह भी 2008-09 के दौरान उल्टा हो गया। इसलिए, मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन की ओर फिर से लौटने की आवश्यकता है जैसा कि राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में रेखांकित किया गया है। भारत में, राजकोषीय समेकन की प्रगति वृद्धि की तेज गति से संबंधित रही है और जब एक बार मंदी के वर्तमान चरण से बाहर आने की स्थिति दिखने लगेगी, तब नए सिरे से पूरा ध्यान केंद्रित कर समेकन का कार्य करना होगा (बॉक्स II.25)।

बॉक्स II.25

भारत में राजकोषीय प्रोत्साहन और उधार की धारणीयता

राजकोषीय शोधक्षमता में आवश्यक है कि सरकारी कर्ज एक विस्फोटक रास्ते पर न चला जाए। राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण घाटा संकेतकों में महत्वपूर्ण विस्तार ऋण धारणीयता स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है जिसे आर्थिक स्थिति सामान्य होते ही अवश्य उलट जाना चाहिए। ऋण स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2007-08 तथा 2008-09 (सं. अनु.) के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि और ऋण पर सामान्य ब्याज, इन दोनों वर्षों के लिए कर्ज - जीडीपी अनुपात को स्थिर रखने के लिए अपेक्षित प्राथमिक शेष का अनुमान निम्नलिखित अवस्था द्वारा लगाया जा सकता है।

$$\Delta \left(\frac{D}{Y} \right)_t = \left\{ \frac{r-g}{1+g} \right\} \left\{ \frac{D}{Y} \right\}_{t-1} - pb \quad (1)$$

जहां D डेट स्टॉक¹¹ है, Y जीडीपी है, r सांकेतिक ब्याज दर है, वहीं g सांकेतिक वृद्धि दर है, pb जीडीपी के भाग के रूप में प्राथमिक राजकोषीय संतुलन है, Δ पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन दर्शाता है। (1) से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कर्ज अनुपात स्थिर है जब

$$(D/Y) (r - g) / (1 + g) = pb \quad (2)$$

प्राथमिक शेष में बजटतर सभी उधार जैसे तेल एवं उर्वरक बांड शामिल हैं क्योंकि ये उधार बकाया देयताओं में शामिल होते हैं। ये अनुमान

बताते हैं कि 2007-08 के लिए सांकेतिक ब्याज दर से सांकेतिक वृद्धि दर अधिक होने पर कर्ज-जीडीपी अनुपात स्थिर रखने के लिए जीडीपी के 2.72 प्रतिशत तक प्राथमिक घाटा अपेक्षित था। जीडीपी के 0.1 प्रतिशत का अधिशेष दर्ज होने से प्राथमिक शेष के साथ ही ऋण की धारणीयता स्थिति संतोषप्रद बनी रही। तथापि, 2008-09 के लिए कर्ज-जीडीपी अनुपात स्थिर रखने के लिए दर्ज किया गया जीडीपी का 4.3 प्रतिशत प्राथमिक घाटा उल्लेखनीय रूप से जीडीपी के अपेक्षित 2.73 प्रतिशत प्राथमिक घाटे से अधिक होगा।

ऋण धारणीयता का अन्य संकेतक ऋण चुकौती बोझ है जिसकी गणना राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात के संदर्भ में की जाती है। यह सरकार के पिछले राजकोषीय कार्यों से उसकी वर्तमान प्राप्तियों की पूर्व अधिकृत प्राप्ति की सीमा दर्शाता है। यह अनुपात जो 2001-02 के बाद लगातार गिरता रहा, 2008-09 के दौरान उलट गया, जो 2009-10 में जारी रह सकता है।

इसलिए, कर्ज-जीडीपी अनुपात को स्थिर रखने और राजस्व प्राप्ति के ब्याज भुगतान के अनुपात के संदर्भ में अपेक्षित प्राथमिक शेष और वास्तविक प्राथमिक शेष की सापेक्षता के मद्देनजर मापे गए ऋण धारणीयता मापदंड 2008-09 में कुछ गिरावट दर्शाते हैं।

¹¹ समायोजित डेट स्टॉक की अवधारणा जिसमें कुल बकाया में राजकोषीय घाटा की मात्रा से संबंधित घटक शामिल नहीं किए गए हैं, पर विचार किया गया है। ये घटक राज्यों द्वारा प्रयुक्त राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) और बाजार स्थिरीकरण योजना के बकाया स्टॉक हैं। राज्यों द्वारा उपयोग किया गया एनएसएसएफ पहले ही राज्य सरकारों के बकाया डेट स्टॉक में परिलक्षित हुआ है और देय ब्याज भी राज्यों द्वारा पूरे किए गए हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना को रिजर्व बैंक के नकद शेष की तदनु रूपी समतुल्य राशि से सहायता मिली और राजकोषीय घाटा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एमएसएस पर देय ब्याज भुगतान को कुल ब्याज भुगतान में शामिल नहीं किया गया है।

सरकार की आकस्मिक देयताएं/गारंटियां

11.4.23 वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार की गारंटी के तहत बकाया राशि में कमी जारी रही और मार्च 2008 के अंत में यह 1,04,872 करोड़ रुपए थी (सारणी 2.41)। केंद्र सरकार द्वारा गारंटी के रूप में दी जानेवाली आकस्मिक देयताओं के स्टॉक में निवल कमी जीडीपी का 0.5 प्रतिशत अंक थी। 2008-09 के दौरान, गारंटी के रूप में आकस्मिक देयता का अनुमान 36,606 करोड़ रुपए है जिसमें सरकारी निजी भागीदारी के जरिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन (आइआइएफसीएल) को प्रदत्त 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। यद्यपि इससे राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध नियमों के तहत आकस्मिक देयताओं में निवल अभिवृद्धि पर जीडीपी के 0.50 प्रतिशत की सीमा से हटने की स्थिति आयेगी, फिर भी यह आवश्यक था कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जाए और मांग तेज की जाए जिससे अर्थव्यवस्था में फिर से गति आने और राजस्व प्राप्त में वृद्धि होने की संभावना होगी।

2009-10 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण¹²

केंद्र सरकार

11.4.24 वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताओं और इसके जुड़े प्रभावों

की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया। इसने चुनिंदा क्षेत्रों में सरकारी खर्च में वृद्धि कर मांग उत्पन्न करते हुए वैश्विक मंदी के बीच अर्थव्यवस्था को उच्चतर पथ पर रखने के सरकार के लक्ष्यों को पुनः दोहराया। राजकोषीय प्रोत्साहन में ऐसा करने हेतु वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध लक्ष्यों को टाला जाना अपेक्षित हो सकता है। तथापि, मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया फिर शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई। महत्वपूर्ण घाटा संकेतक, जैसे सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, गत वर्ष के संशोधित अनुमान से बाजार में कमोबेश कम रखे गये (देखें सारणी 2.35)। राजस्व घाटे की भागीदारी जो 2003-04 से गिरती रही थी, वह 2008-09 में सकल राजकोषीय घाटे का लगभग तीन चौथाई बढ़ गयी और 2009-10 में ऊंची बनी रही (सारणी 2.42)।

प्राप्तियों का स्वरूप

11.4.25 राजस्व प्राप्ति पर आर्थिक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव 2009-10 के दौरान जारी रहने की संभावना है, यद्यपि यह थोड़ी नियंत्रित रह सकती है। मुख्य रूप से करेतर राजस्व के कारण 2009-10 में राजस्व प्राप्ति 2008-09 से अधिक रह सकती है

सारणी 2.41: बकाया सरकारी गारंटी

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च- अंत	केंद्र		राज्य		कुल		मार्च- अंत	केंद्र		राज्य		कुल	
	राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत		राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत	राशि	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1995	62,468	6.1	48,479	4.8	1,10,947	10.9	2002	95,859	4.2	1,65,386	7.3	2,61,245	11.5
1996	65,573	5.5	52,631	4.4	1,18,204	9.9	2003	90,617	3.7	1,84,294	7.5	2,74,911	11.2
1997	69,748	5.1	65,339	4.7	1,35,087	9.8	2004	87,780	3.2	2,19,658	8.0	3,07,438	11.2
1998	73,877	4.8	73,751	4.8	1,47,628	9.7	2005	1,07,957	3.4	2,04,426	6.5	3,12,383	9.9
1999	74,606	4.3	79,457	4.5	1,54,063	8.8	2006	1,10,626	3.1	1,96,914	5.5	3,07,540	8.6
2000	83,954	4.3	1,32,029	6.8	2,15,983	11.1	2007	1,09,826	2.7	1,54,183	3.7	2,64,009	6.4
2001	86,862	4.1	1,68,719	8.0	2,55,581	12.2	2008	1,04,872	2.2	1,71,058 P	3.6	2,75,930 P	5.8

अ : अनंतिम.

टिप्पणी : पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है कि जीडीपी के अनुपातों का जोड़ कुल से मूल न खाए।

स्रोत : 1. केंद्र की गारंटी से संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं।

2. राज्यों की गारंटियों से संबंधित आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं और ये 17 बड़े राज्यों से संबंधित हैं। 2004 तथा 2005 के आंकड़े क्रमशः 15 बड़े राज्यों और 12 बड़े राज्यों से संबंधित हैं।

¹² जब तक कि अन्यथा उद्धृत न किया गया हो, इस खंड में 2009-10 की सभी तुलनाएं 2008-09 के संशोधित अनुमान के अनुसार हैं।

सारणी 2.42 : केंद्र के जीएफडी का वियोजन

(प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	अन्य
1	2	3	4	5
1990-91	41.6	27.2	31.9	-0.7
1995-96	49.4	23.4	29.6	-2.3
2000-01	71.7	20.8	9.2	-1.8
2005-06	63.0	37.6	0.5	-1.1
2006-07	56.3	42.3	1.8	-0.4
2007-08	41.4	56.3 *	4.9	-2.6
2008-09 (संअ)	73.9	25.5	1.4	-0.8
2009-10 (बअ)	70.5	27.7	2.0	-0.2

* : भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी 35,531 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार को अंतरित करने की अभिग्रहण लागत घटाकर ।

(सारणी 2.43)। यद्यपि, सकल कर राजस्व 2008-09 से कम रह सकता है, तथापि जीडीपी से अनुपात के रूप में 2009-10 में इसमें और गिरावट हो सकती है (सारणी 2.44)। हालांकि, करेतर राजस्व में 2008-09 में आयी गिरावट के विपरीत स्थिति रहने का अनुमान है तथा इसमें 2009-10 में काफी ऊंची वृद्धि दर्ज हो सकती है जिसका मुख्य कारण थर्ड जेनरेशन (3 जी) स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्तियां और रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 28,000 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की तुलना में 58 प्रतिशत) लाभांश अधिशेष अंतरण के रूप में मिलनेवाली प्राप्तियां हैं। परिणामस्वरूप, जीडीपी से करेतर राजस्व अनुपात जीडीपी के 2.4 प्रतिशत पर (2008-09 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में) ऊंचा अनुमानित किया गया है। 2008-09 की अपेक्षा 2009-10 के दौरान कम विनिवेश की प्रक्रिया के कारण पूँजीगत ऋणोत्तर प्राप्तियों में भी गिरावट का अनुमान है।

व्यय का स्वरूप

11.4.26 अनुमान है कि कुल व्यय की वृद्धि में (कमी के बावजूद बीते वर्ष के 16.9 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के जीडीपी के 17.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो 2009-10 में राजकोषीय प्रोत्साहन के सतत जोर को दर्शाता है। अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी से अनुपात के रूप में राजस्व व्यय और पूँजी व्यय दोनों में ही वृद्धि होगी (सारणी 2.45)। 2009-10 में

कुल व्यय की वृद्धि में कमी मुख्यतः राजस्व व्यय से उत्पन्न होगी, विशेषकर उर्वरक सब्सिडी में कटौती से, जो 2008-09 में उर्वरक की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के तेजी से बढ़ने के कारण बढ़ी थीं।

11.4.27 वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि आने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण वर्ष 2008-09 की 22.1 प्रतिशत की पूँजीगत परिव्यय में गिरावट की तुलना में 2009-10 में 33.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि है। रक्षा परिव्यय पूँजी परिव्यय में होनेवाली अनुमानित वृद्धि के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार होगा और रक्षेतर पूँजी परिव्यय में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं को दिया जा सकता है। योजना और योजनेतर घटकों के अर्थ में व्यय पैटर्न का विश्लेषण दर्शाता है कि 2009-10 में योजना व्यय की वृद्धि में अनुमानित कमी योजनेतर व्यय की तुलना में अधिक होगी। मुख्य रूप से ब्याज भुगतान और रक्षा के कारण गैर-योजना खर्च बढ़ेगा। सरकारी उधार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि और 2008-09 के दौरान तेल विपणन और उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों के परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान बढ़ेगा। रक्षा सेवाओं में गैर योजना खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण वेतन एवं भत्ते, अनुरक्षण व्यय और रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए बढ़ाया गया प्रावधान है। बजट में राज्यों को अधिक अनुदान देने का भी प्रस्ताव है। अन्य प्रमुख विकास व्ययों में अनुमान है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सिंचाई पर होनेवाले व्यय के स्तर में 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2009-10 में वृद्धि होगी। कृषि और ग्रामीण विकास को छोड़कर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख विकास व्यय बढ़ेंगे (सारणी 2.46)।

घाटे का वित्तपोषण

11.4.28 सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप बताता है कि सरकार 2009-10 के दौरान घाटे के अधिकांश भाग का वित्तपोषण बाजार के उधारों (दिनांकित प्रतिभूतियां और 364-दिवसीय खजाना बिल) के जरिए करेगी। वर्ष 2008-09 के मुकाबले 2009-10 में अल्प बचत की तुलना में बाह्य उधार और प्रतिभूतियां जीएफएफडी वित्तपोषण में अधिक योगदान देंगी। जमाराशियों और अग्रिमों का योगदान पिछले वर्ष की तुलना

सारणी 2.43: केंद्र की राजस्व स्थिति

(राशि करोड़ में)

मद	2007-08	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)	घट-बढ़			
				2008-09		2009-10	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल प्राप्तियां (1+2)	6,78,362*	9,00,953	10,20,838	2,22,591	32.8	1,19,885	13.3
	(14.4)	(16.9)	(17.4)				
1. राजस्व प्राप्तियां	5,41,864	5,62,173	6,14,497	20,309	3.7	52,324	9.3
कर राजस्व (निवल)	4,39,547	4,65,970	4,74,218	26,423	6.0	8,248	1.8
करेतर राजस्व	1,02,317	96,203	1,40,279	-6,114	-6.0	44,076	45.8
	(2.2)	(1.8)	(2.4)				
2. पूंजीगत प्राप्तियां	1,36,498*	3,38,780	4,06,341	2,02,282	148.2	67,561	19.9
	(2.9)	(6.4)	(6.9)				
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	9,586*	12,265	5345	2,679	27.9	-6,920	-56.4
	(0.2)	(0.2)	(0.1)				
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	1,26,912	3,26,515	4,00,996	1,99,603	157.3	74,481	22.8
	(2.7)	(6.1)	(6.8)				
जापन :							
सकल कर राजस्व	5,93,147	6,27,949	6,41,079	34,802	5.9	13,130	2.1
	(12.6)	(11.8)	(10.9)				
i) कंपनी कर	1,92,911	2,22,000	2,56,725	29,089	15.1	34,725	15.6
	(4.1)	(4.2)	(4.4)				
ii) आय कर@	1,02,644	1,08,000	1,06,800	5,356	5.2	-1,200	-1.1
	(2.2)	(2.0)	(1.8)				
iii) सीमा शुल्क	1,04,119	1,08,000	98,000	3,881	3.7	-10,000	-9.3
	(2.2)	(2.0)	(1.7)				
iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,23,425	1,08,359	1,06,477	-15,066	-12.2	-1,882	-1.7
	(2.6)	(2.0)	(1.8)				
v) सेवा कर	51,301	65,000	65,000	13,699	26.7	0	0.0
	(1.1)	(1.2)	(1.1)				
vi) प्रतिभूति लेनदेन कर	8,576	5,500	6,000	-3,076	-35.9	500	9.1
	(0.2)	(0.1)	(0.1)				
vii) बैंकिंग नकद लेनदेन कर	586	600	50	14	2.4	-550	-91.7
	(0.0)	(0.0)	(0.0)				
viii) अनुषंगी हितलाभ कर	7,098	8,500	-	1,402	19.8	-8,500	-
	(0.2)	(0.2)	(0.0)				

ब.अ. : बजट अनुमान.

सं.अ. : संशोधित अनुमान.

* : 34,309 करोड़ रुपए की राशि समायोजित की गई जो भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के कारण रिजर्व बैंक को हुआ लाभ दर्शाती है।

@ : अनुषंगी लाभ कर को छोड़कर।

टिप्पणी : कोषक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।

सारणी 2.44 : केंद्र का सकल कर राजस्व

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	कुल
1	2	3	4
1991-92	2.3	8.0	10.3
1995-96	2.8	6.5	9.3
2001-02	3.0	5.2	8.2
2002-03	3.4	5.4	8.8
2003-04	3.8	5.4	9.2
2004-05	4.2	5.5	9.7
2005-06	4.6	5.6	10.2
2006-07	5.6	5.9	11.5
2007-08	6.6	5.9	12.6
2008-09 (संअ)	6.5	5.3	11.8
2009-10 (बअ)	6.3	4.6	10.9
सं.अ. : संशोधित अनुमान.		बअ: बजट अनुमान.	

में कम होगा। नकद शेष जिसने 2008-09 में जीएफडी के लगभग दसवें भाग का वित्तपोषण किया, से आहरण के लिए 2009-10 के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है (सारणी 2.47)।

II.4.29 2009-10 के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों के ग्यारहवीं योजना अनुमानों से अधिक रहने की संभावना है, जिसमें कुल खर्च संबंधित योजना अनुमानों के मुकाबले जीडीपी के 3.6 प्रतिशत अंक से अधिक होने और राजस्व प्राप्त जीडीपी के 0.1 प्रतिशत अंक कम होने की संभावना है। गैर-योजना घटकों (प्राथमिक रूप से ब्याज भुगतान और सब्सिडी) के कारण व्यय अनुमान से अधिक होगा। हालांकि योजना हेतु मदद मुहैया

सारणी 2.45 : केंद्र के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08	2008-09 सं.अ.	2009-10 ब.अ.	घट-बढ़			
				2008-09		2009-10	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल व्यय (क+ख=1+2)	6,77,140 *	9,00,953	10,20,838	2,23,813	33.1	1,19,885	13.3
	(14.3)	(16.9)	(17.4)				
क. राजस्व व्यय	5,94,433	8,03,446	8,97,232	2,09,013	35.2	93,786	11.7
	(12.6)	(15.1)	(15.3)				
ख. पूंजीगत व्यय	82,707 *	97,507	1,23,606	14,800	17.9 *	26,099	26.8
	(1.8)	(1.8)	(2.1)				
1. गैर योजना व्यय	4,72,058 *	6,17,996	6,95,689	1,45,938	30.9	77,693	12.6
	(10.0)	(11.6)	(11.9)				
i) ब्याज भुगतान	1,71,030	1,92,694	2,25,511	21,664	12.7	32,817	17.0
	(3.6)	(3.6)	(3.9)				
ii) रक्षा व्यय	91,681	1,14,600	1,41,703	22,919	25.0	27,103	23.7
	(1.9)	(2.2)	(2.4)				
iii) सब्सिडी	70,926	1,29,243	1,11,276	58,317	82.2	-17,967	-13.9
	(1.5)	(2.4)	(1.9)				
iv) राज्यों को अनुदान	35,769	38,421	48,570	2,652	7.4	10,149	26.4
	(0.8)	(0.7)	(0.8)				
v) अन्य गैर योजना व्यय	1,02,652 *	1,43,038	1,68,629	4,0386	39.3 *	25,591	17.9
	(2.2)	(2.7)	(2.9)				
2. योजना व्यय	2,05,082	2,82,957	3,25,149	77,875	38.0	42,192	14.9
	(4.3)	(5.3)	(5.6)				
i) केंद्रीय योजना को बजट समर्थन	1,48,669	2,04,129	2,39,840	55,460	37.3	35,711	17.5
	(3.1)	(3.8)	(4.1)				
ii) राज्य और संघशासित क्षेत्र योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता	61,614	78,828	85,309	17,214	27.9	6,481	8.2
	(1.3)	(1.5)	(1.5)				
जापन :							
अनुदान	1,09,978	1,26,132	1,46,147	16,154	14.7	20,015	15.9
ऋण	11,298	14,202	12,339	2,904	25.7	-1,863	-13.1
बअ: बजट अनुमान. संअ: संशोधित अनुमान.							
* : 35,531 करोड़ रुपए पर भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की अभिग्रहण लागत को छोड़कर।							
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं।							

सारणी 2.46 : केंद्र के चुनिंदा विकास शीर्षों पर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09(संअ)	2009-10(बअ)
1	2	3
कृषि	1,23,038	1,07,441
	(2.3)	(1.8)
शिक्षा	34,429	42,339
	(0.6)	(0.7)
स्वास्थ्य	16,277	22,733
	(0.3)	(0.4)
ग्रामीण विकास	40,799	43,554
	(0.8)	(0.7)
सिंचाई	579	664
	(0.0)	(0.0)
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।		

कराने के प्रयोजन से योजनागत व्यय या सकल बजट सहायता ग्यारहवीं योजना अनुमानों से अधिक होगा। योजनागत व्यय का राजस्व घटक उल्लेखनीय रूप से अनुमानों से काफी अधिक होगा जिससे योजनागत व्यय के पूंजी घटक में बड़ी गिरावट होगी(सारणी 2.48)।

II.4.30 वर्ष 2008 में भारत की केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और कर्ज एशिया की कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से अधिक रहा (सारणी 2.49)। भारत के घाटे की स्थिति में भी तीव्र गिरावट प्रतीत हुई जो भारत के राजकोषीय प्रोत्साहनों के भारी आकार को दर्शाता है।

सारणी 2.47 : केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप

(राशि करोड़ रूप में)

Item	2008-09 (बअ)	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	1,33,287	3,26,515	4,00,996
<i>निम्नलिखित द्वारा वित्तपोषित:</i>			
बाजार उधार	99,000 (74.3)	2,66,539 (81.6)	3,97,957 (99.2)
अल्प बचतों के प्रति प्रतिभूतियां	9,873 (7.4)	1,323 (0.4)	13,256 (3.3)
बाह्य सहायता	10,989 (8.2)	9,603 (2.9)	16,047 (4.0)
राज्य भविष्य निधि	4,800 (3.6)	4,800 (1.5)	5,000 (1.2)
एनएसएसएफ	53 (0.0)	11,206 (3.4)	-103 (0.0)
आरक्षित निधियां	-972 (-0.7)	-16,808 (-5.1)	-8,428 (-2.1)
जमाराशि एवं अग्रिम	8,629 (6.5)	12,788 (3.9)	9,026 (2.3)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	4,123 (3.1)	2,594 (0.8)	2,672 (0.7)
नकद शेष से आहरण	7,225 (5.4)	29,984 (9.2)	0 (0.0)
अन्य	-10,433 (-7.8)	4,486 (1.4)	-34,431 (-8.6)
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीएफडी का प्रतिशत हैं।			

सारणी 2.48 : बजट अनुमान की तुलना में केंद्र सरकार की ग्यारहवीं योजना के पूर्वानुमान

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2009-10	
	ग्यारहवीं योजना के पूर्वानुमान	बजट अनुमान
1	2	3
1. योजना को सकल बजट समर्थन	5.0	5.6
<i>जिसमें से:</i>		
(i) योजनागत राजस्व व्यय	2.9	4.8
2. कुल गैर योजना	8.9	11.9
<i>जिसमें से:</i>		
(i) ब्याज भुगतान	3.0	3.9
(ii) रक्षा	2.3	2.4
(iv) राज्यों को गैर योजना अनुदान	0.6	0.8
(v) सब्सिडी	1.0	1.9
3. कुल व्यय (1+2)	13.8	17.4
4. सकल कर राजस्व	12.2	11.0
घटाएं: राज्यों का हिस्सा	3.3	2.8
5. केंद्र को निवल कर	8.9	8.1
6. करेतर राजस्व	1.8	2.4
7. कुल राजस्व प्राप्तियां	10.6	10.5
8. सकल राजकोषीय घाटा	3.0	6.9
9. राजस्व घाटा	0.0	4.8

राज्य बजट 2009-10

11.4.31 गत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकार के स्तर पर किये गये राजकोषीय सुधार और समेकन को आर्थिक कार्यकलापों

में कमी के मद्देनजर आघात पहुंचा। राज्य सरकारों का समेकित राजस्व खाता पिछले तीन वर्ष अधिशेष में रहने के बाद जीडीपी के 0.6 प्रतिशत घाटे में बदलने का अनुमान है (देखें सारणी 2.50 और परिशिष्ट सारणी 30)। परिणामस्वरूप, 2008-09

सारणी 2.48: केंद्र सरकार के घाटे और उधार के संकेतक: चुनिंदा देश

(जीडीपी का प्रतिशत)

	राजकोषीय घाटा				लोक ऋण			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चीन	1.2	0.8	-0.6	0.4	17.9	17.3	n.a.	n.a.
कोरिया गणतंत्र	-0.4	-0.4	-3.8	-1.2	29.5	32.2	32.1	29.1
भारत	4.1	3.5	2.7	6.1	63.0	61.5	60.1	58.9
इंडोनेशिया	0.2	0.9	1.2	0.0	45.6	39.0	35.0	31.2
मलेशिया	3.6	3.3	3.2	4.8	43.8	42.2	41.6	41.4
थाइलैंड	-0.2	-0.1	1.1	0.3	47.3	40.3	37.5	38.1

-: उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाते हैं।

स्रोत: 1) एशिया इकोनॉमिक मॉनिटर, दिसंबर, 2008 और जुलाई 2009, एशियाई विकास बैंक
2) केंद्रीय बजट दस्तावेज और भारत सरकार के अनंतिम खाते।

सारणी 2.50 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09* बअ	2008-09* संअ	2009-10* बअ
1	2	3	4	5	6	7
सकल राजकोषीय घाटा	90,084 (2.5)	77,509 (1.9)	68,572 (1.5)	1,10,465 (2.1)	1,43,924 (2.7)	1,97,186 (3.4)
राजस्व घाटा	7,013 (0.2)	-24,857 (-0.6)	-43,405 (-0.9)	-25,036 (-0.5)	-7,336 (-0.1)	37,058 (0.6)
प्राथमिक घाटा	6,060 (0.2)	-15,672 (-0.4)	-29,044 (-0.6)	3,681 (0.1)	39,283 (0.7)	82,488 (1.4)

बअ-बजट अनुमान. संअ: संशोधित अनुमान.

*: 2007-08 से आगे के आंकड़े 27 राज्य सरकारों से संबंधित हैं।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष दर्शाते हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।

3. 2007-08 के जीडीपी आंकड़े सीएसओ के तत्काल अनुमान पर आधारित हैं, जबकि 2008-09 के आंकड़े संशोधित अनुमान पर आधारित हैं। 2009-10 के जीडीपी आंकड़े केंद्रीय बजट दस्तावेज, 2009-10 के अनुसार हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

(संअ) की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है। समेकित प्राथमिक घाटा 2008-09 (संअ), जीडीपी के 0.7 से प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 (संअ) के दौरान 23 राज्यों की तुलना में 2009-10 में 27 राज्यों में से 13 राज्यों में राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है। इस प्रकार, राज्य स्तर पर राजकोषीय जवाबदेही विधान (एफआरएल) के कार्यान्वयन की प्रगति को धक्का लगा (बॉक्स II.26)।

II.4.32 वर्ष 2008-09 (संअ) और 2009-10 (बअ) के दौरान राज्य सरकारों के राजस्व खाते में कमी कई राज्य सरकारों द्वारा छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों कार्यान्वित करने के लिए व्यय की उच्च प्रतिबद्धता सहित कर वसूली और केंद्र से अंतरण की धीमी गति का संयुक्त प्रभाव दर्शाती है। 2009-10 के दौरान, राजस्व प्राप्ति के मुकाबले राजस्व व्यय में अधिक वृद्धि रहने का अनुमान है। राज्यों के अपने कर, केंद्रीय करों में भागीदारी और केंद्र के अनुदान से राजस्व प्राप्ति बढ़ेंगी (सारणी 2.51)।

II.4.33 वर्ष 2008-09 (संअ) के मुकाबले 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय तेजी से बढ़ने का अनुमान है (सारणी 2.52)। यह मुख्यतया गैर-विकासात्मक व्यय (राजस्व व्यय में इस वृद्धि ने

लगभग 56.0 प्रतिशत योगदान दिया) में वृद्धि के कारण होगा। 2009-10 के दौरान प्रशासनिक सेवाओं (जैसे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों कार्यान्वित करने के कारण मजदूरी और वेतन पर व्यय), पेंशन और ब्याज भुगतान मिलकर राजस्व व्यय में लगभग 63.1 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान देंगे। विकासात्मक व्यय में यह वृद्धि मुख्यतया शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास एवं सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के कारण होगी।

II.4.34 सकल राजकोषीय घाटे के 2008-09 (सं.अ.) के 2.7 प्रतिशत से 2009-10 (ब.अ.) में जीडीपी के 3.4 प्रतिशत होकर बढ़ने का मुख्य कारण निवल उधार में वृद्धि के साथ जुड़ी राजस्व लेखे में गिरावट थी। अनुमान है कि जीडीपी से प्रतिशत के रूप में समेकित पूंजी परिव्यय 2009-10 में 0.2 प्रतिशत अंक गिरकर 2.6 प्रतिशत रह जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वे 2009-10 के दौरान अपने जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त बाजार उधार जुटा सकते हैं। सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः बाजार से उधार (57.7 प्रतिशत) और भविष्य निधियों (10.5 प्रतिशत) से किया जाएगा (सारणी 2.53 और परिशिष्ट सारणी 31)।

बॉक्स II.26

राज्य स्तर पर राजकोषीय जवाबदेही विधान का कार्यान्वयन - हाल की गतिविधियाँ

राज्य स्तर पर राजकोषीय जवाबदेही विधान (एफआरएल) का अधिनियमन ग्रामीण आधारित राजकोषीय नीति के संवर्धन में किए जाने वाले प्रमुख संस्थागत सुधारों में से एक है। अगस्त 2002 में कर्नाटक राजकोषीय जवाबदेही विधान लागू करने वाला पहला राज्य था जिसके बाद तमिलनाडु, केरल और पंजाब ने 2003 में इसे लागू किया। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी), जिसने राजकोषीय जवाबदेही विधान के अधिनियमन के साथ ऋण राहत को जोड़ते हुए राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय जवाबदेही ढांचा अपनाने को प्रोत्साहित किया था, की सिफारिशें मानते हुए 22 अन्य राज्यों ने बाद के वर्षों में एफआरएल को लागू किया। हालांकि लक्ष्य चुनने और लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा को लेकर राज्यों में अंतर है, अधिकांश राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही विधान ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटा खत्म करने और 31 मार्च 2010 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में जीएफडी में 3 प्रतिशत तक कमी करने का निर्धारण किया। इसके अलावा, कई राज्यों ने अपनी देयताएं घटाने का लक्ष्य भी रखा।

राज्यों द्वारा राजकोषीय जवाबदेही विधान के क्रमिक अधिनियमन (सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) ने राजकोषीय सुदृढ़ता प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रेरक का काम किया है। महत्वपूर्ण घाटा-संकेतकों की गतिविधियाँ दर्शाती हैं कि समेकित स्तर पर राज्य 2007-08 तक अपने घाटे को कम करने में उल्लेखनीय रूप से सफल हुए हैं। राज्यों के समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार के बावजूद, राजकोषीय निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों के बीच काफी अंतर पाया गया। जबकि कुछ राज्य सरकारें समय सीमा से काफी पहले कई संकेतकों के संदर्भ में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहीं, ऐसे कुछ अन्य राज्य थे जिनमें राजकोषीय सुधार कम हुए। वर्ष 2009-10 के लिए जिन 22 राज्यों के विस्तृत बजट दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनमें से 19 राज्यों ने 2007-08 में राजस्व खाते में अधिशेष प्राप्त कर लिया है और 11 राज्यों ने 2007-08 तक जीएफडी- जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत तक कम करने के बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, अर्थात् सिफारिश की गयी समय सीमा से दो वर्ष पहले। राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्र द्वारा किये गये उच्च अंतरणों से सहायता मिली।

इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश राज्यों द्वारा राजकोषीय जवाबदेही विधान का अधिनियमन राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय नीति ढांचे के आधार पर शुरू किया गया है, वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के परिप्रेक्ष्य में राज्यों की राजकोषीय स्थिति दबाव में रही। 2008-09 में आर्थिक वृद्धि कम रहने के मद्देनजर 2007-08 तक राजस्व में वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। इस प्रकार, हाल के वर्षों में परिलक्षित हुई राजकोषीय सुधार और समेकन की गति के विकास में गिरावट के कारण ठहराव आने की संभावना है और यह रुक भी सकती है और कई राज्य जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत तक बनाए रखने के लक्ष्य से ऊपर जा सकते हैं। राज्यों पर यह भी दबाव है कि अर्थव्यवस्था में मांग को तेज करने के लिए वे अपने राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय बढ़ाएं। वास्तव में, केंद्र सरकार ने राज्यों को 2008-09 के दौरान जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत सीमा तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी और पूंजीगत व्यय हेतु राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए उन्हें अतिरिक्त राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराया। केंद्रीय बजट 2009-10 में राज्यों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार जीएफडी की सीमा जीएसडीपी के 4.0 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

राज्य वित्त पर समग्र समष्टि आर्थिक मंदी का प्रभाव राज्यों के घाटा-संकेतकों में गिरावट से परिलक्षित हुआ है। जहाँ कई राज्यों में 2007-08 की तुलना में 2008-09 (संशोधित अनुमान) में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में कमी आई है, वहीं राजस्थान में राजस्व अधिशेष घाटे में बदल गए। राज्यों के राजस्व अधिशेष में गिरावट दर्शाते हुए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 2008-09 (संशोधित अनुमान) में अधिकांश राज्यों में बढ़ गया। 22 राज्यों में से 15 राज्यों में 2008-09 (संशोधित अनुमान) में 3.00 प्रतिशत से अधिक जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज हुआ। राज्यों की राजकोषीय स्थिति आगे 2009-10 में कमजोर रहने का अनुमान है। 22 राज्यों में से 09 राज्यों ने 2009-10 हेतु राजस्व घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यह दर्शाता है कि कुछ राज्यों को घाटा-लक्ष्यों में कमी का प्रावधान करने के लिए अपने संबंधित राजकोषीय जवाबदेही विधानों में संशोधन करना पड़ सकता है।

एक बार जब आर्थिक स्थिति में सुधार प्रक्रिया तेज हो जाती है, तब राज्य सरकारों के लिए सबसे पहला कार्य होगा कि वे राजकोषीय सुधार के रास्ते पर पुनः वापस लौटें। राज्य स्तर पर राजकोषीय जवाबदेही विधान के उपरांत ढांचे का डिजाइन राजकोषीय सुधार प्राप्त करने और उसे बनाए रखने पर केंद्रित होना चाहिए। 2003-04 से राज्य सरकारों की राजकोषीय जवाबदेही विधान की स्थिति उच्च जीडीपी वृद्धि से संबंधित रही है। उनके अपने कर राजस्व में परिणामी वृद्धि और केंद्र से अधिक अंतरण तथा राजस्व खर्चों में कमी ने कुछ हद तक सहायता की और राज्य घाटे कम करने में सक्षम हुए तथा पूंजीगत परिव्यय तथा विकासात्मक व्यय में बढ़ोतरी हुई। ऐसी सहायक आर्थिक परिस्थितियों की अनुपस्थिति में राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे बेकार के खर्चों रोकने और अधिक उत्पादक खर्च की ओर उन्मुख होते हुए व्यय को कुशलसंगत बनाने पर अधिक जोर दें। वर्तमान में राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही विधान में कोई व्यय नियमावली उपलब्ध नहीं है। राजकोषीय जवाबदेही विधान के उपरांत व्यय आबंटन प्रक्रिया को और कार्यक्षम बनाने के प्रयोजन से व्यय की कुछ श्रेणियों के संदर्भ में विशेष संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। वर्तमान में, कुछ राज्यों ने ही राजकोषीय जवाबदेही विधान के तहत ऋण जीएसडीपी नियमावली और ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति (आइपी-आरआर) लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऋण धारणीयता प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य ऋण जीएसडीपी और आइपी-आरआर लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

अर्थव्यवस्था में हाल की मंदी और राज्यों के वित्त पर इसके संबंधित प्रभाव बताते हैं कि राजकोषीय जवाबदेही विधान के बाद के ढांचे में प्रति-चक्रीय खंड शुरू करने की आवश्यकता है। कुछ देशों में, राजकोषीय जवाबदेही विधान में चक्रीय प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। इससे आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को सहायता करने में (विस्तारवादी नीतियों द्वारा) सुगमता होगी। यह पाया गया कि बजट परंपरा, पारदर्शिता नियमों, लेखांकन प्रणालियों, लोक खर्च प्रबंधन आदि के संदर्भ में राज्यों में मानकीकरण का अभाव है। इस प्रकार, राजकोषीय जवाबदेही विधान के बाद का ढांचा एक समान परंपरा अपनाए जाने के लिए संस्थागत सुधारों पर जोर दे सकता है।

सार रूप में, राजकोषीय जवाबदेही विधान के बाद के ढांचे का डिजाइन उक्त विधान के कार्यान्वयन में अब तक हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। राजकोषीय जवाबदेही विधान के बाद का ढांचा घाटे की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने के अलावा ऋण और व्यय हेतु विशिष्ट नियम बना सकती है। राज्य बजट संबंधी कार्यकलापों में पारदर्शिता बरतने और लेखांकन प्रणाली अपनाने पर जोर दे सकते हैं। राजकोषीय स्थिरीकरण निधि और प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति ढांचे की आवश्यकता और व्यवहार्यता भी मालूम की जा सकती है।

सारणी 2.51: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08*	2008-09*	2008-09* संअ	2009-10* बअ	प्रतिशत घटबढ़		
					स्तंभ 4/2	स्तंभ 4/3	स्तंभ 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
समग्र प्राप्तियां (1+2)	7,47,364 (15.8)	8,76,991 (16.5)	9,05,381 (17.0)	10,02,710 (17.1)	21.1	3.2	10.8
1. कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	6,10,261 (12.9)	7,04,518 (13.2)	7,22,054 (13.6)	7,85,046 (13.4)	18.3	2.5	8.7
(क) राज्यों के अपने राजस्व	3,60,363 (7.6)	3,99,851 (7.5)	4,06,198 (7.6)	4,46,310 (7.6)	12.7	1.6	9.9
राज्यों के अपने कर	2,84,169 (6.0)	3,34,143 (6.3)	3,27,711 (6.2)	3,63,511 (6.2)	15.3	-1.9	10.9
States Own non-Tax	76,194 (1.6)	65,708 (1.2)	78,487 (1.5)	82,798 (1.4)	3.0	19.4	5.5
(ख) केंद्रीय अंतरण	2,49,898 (5.3)	3,04,667 (5.7)	3,15,856 (5.9)	3,38,736 (5.8)	26.4	3.7	7.2
साझा योग्य कर	1,50,063 (3.2)	1,71,162 (3.2)	1,71,421 (3.2)	1,83,856 (3.1)	14.2	0.2	7.3
केंद्रीय अनुदान	99,835 (2.1)	1,33,505 (2.5)	1,44,436 (2.7)	1,54,879 (2.6)	44.7	8.2	7.2
2. पूंजीगत प्राप्तियां(क+ख)	1,37,103 (2.9)	1,72,473 (3.2)	1,83,327 (3.4)	2,17,664 (3.7)	33.7	6.3	18.7
(क) केंद्र से ऋण	6,789 (0.1)	14,741 (0.3)	9,786 (0.2)	17,284 (0.3)	44.1	-33.6	76.6
(ख) अन्य पूंजी प्रप्तिया	1,30,314 (2.8)	1,57,732 (3.0)	1,73,540 (3.3)	2,00,380 (3.4)	33.2	10.0	15.5

बअ: बजट अनुदान संअ: संशोधित अनुमान

*: 2007-08 से आगे के आंकड़े 27 राज्य सरकारों से संबंधित हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

संयुक्त वित्त : 2009-10

II.4.35 वर्ष 2009-10 की केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बजटीय स्थिति दर्शाती है कि मुख्य रूप से व्यय में तेज वृद्धि के कारण सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मुख्य घाटा संकेतकों के उच्च स्तरों पर बने रहने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 2.54)।

II.4.36 मुख्यतः कर राजस्व में वृद्धि होने के कारण संयुक्त राजस्व प्रप्तियों में वृद्धि होने का अनुमान है। तथापि, संयुक्त कर- सकल देशी उत्पाद अनुपात में 2008-09 की तुलना में 2009-10 में कमी आने का अनुमान है (सारणी 2.55)। जहां

तक व्यय का संबंध है, कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा 2008-09 सं.अ. के 59.6 प्रतिशत (18.6 प्रतिशत) से घटकर 2009-10 में 56.8 प्रतिशत (18.1 प्रतिशत) हो जाएगा। इसके विपरीत, गैर-विकासात्मक व्यय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और जीडीपी के अर्थ में इसमें वृद्धि दिखाई देगी। विकासेतर व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीडीपी से अनुपात के रूप में कुल व्यय में मामूली वृद्धि होगी।

II.4.37 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधारों का अनुपात अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, राज्य भविष्य निधि के अंश में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है, वर्ष 2009-10

सारणी 2.52 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08*	2008-09* बअ	2008-09* संअ	2009-10* बअ	प्रतिशत घटबढ़		
					स्तंभ 4/2	स्तंभ 4/3	स्तंभ 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
समग्र व्यय (1+2 =3+4+5)	7,31,679 (15.5)	8,74,663 (16.4)	9,21,673 (17.3)	10,34,426 (17.7)	26.0	5.4	12.2
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	5,66,856 (12.0)	6,79,482 (12.8)	7,14,718 (13.4)	8,22,104 (14.0)	26.1	5.2	15.0
ब्याज भुगतान	97,615 (2.1)	1,06,783 (2.0)	1,04,641 (2.0)	1,14,698 (2.0)	7.2	-2.0	9.6
2. पूंजीगत व्यय जिसमें से:	1,64,823 (3.5)	1,95,181 (3.7)	2,06,956 (3.9)	2,12,322 (3.6)	25.6	6.0	2.6
पूंजी परिव्यय	1,12,912 (2.4)	1,39,636 (2.6)	1,51,601 (2.8)	1,53,528 (2.6)	34.3	8.6	1.3
3. विकास व्यय	4,50,391 (9.5)	5,45,287 (10.2)	6,01,061 (11.3)	6,44,454 (11.0)	33.5	10.2	7.2
4. विकासेतर व्यय	2,26,962 (4.8)	2,69,929 (5.1)	2,61,521 (4.9)	3,22,012 (5.5)	15.2	-3.1	23.1
5. अन्य #	54,326 (1.2)	59,447 (1.1)	59,092 (1.1)	67,960 (1.2)	8.8	-0.6	15.0

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान
* : 2007-08 के बाद के आंकड़े 27 राज्य सरकारों से संबंधित हैं।
: इसमें स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन, अनुदान और अंशदान, आंतरिक ऋण का निपटान, केंद्र को ऋण की चुकौती शामिल है।
टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में अल्प बचतों के योगदान में काफी वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी 2.56)।

सामाजिक क्षेत्र व्यय

11.4.38 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संयुक्त सामाजिक क्षेत्र व्यय वर्ष 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में वर्ष 2009-10 (ब.अ.) में मामूली तौर पर बढ़ने का अनुमान है। अनुमान है कि शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय का हिस्सा उच्चतर स्तर पर रहेगा (सारणी 2.57)।

11.4.39 केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान महत्वपूर्ण घाटा सूचकों में कुछ नरमी रहने का अनुमान है लेकिन एफआरबीएम - पूर्व अवधि की स्थिति की तुलना में ये उच्च स्तरों पर ही रहेगा। राज्य सरकारों के मामले में लगातार तीन वर्ष से राजस्व खातों में दर्ज किया जा

रहा अधिशेष वर्ष 2009-10 में समाप्त हो जाएगा। तथापि, संयुक्त वित्त में यह क्षरण अस्थायी प्रकार का रहने की संभावना है जो घरेलू आर्थिक मंदी से राजस्व पर पड़ने वाले स्वतंत्र प्रभाव के अलावा अपवादात्मक वैश्विक आर्थिक स्थितियों के प्रभावों से निपटने के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रयोग करने के कारण उत्पन्न हुआ है।

11.4.40 अंत में, कहा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान राजकोषीय नीति ने बाह्य और घरेलू निजी मांग में संकुचन और वृद्धि में गिरावट से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब दिया है। वृद्धि की गति को बनाये रखने लिए यह जरूरी हो गया कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत राजकोषीय समेकन मार्ग से संबद्ध अपरिहार्य विचलन के बावजूद विवेकपूर्ण स्थिर कारकों का उचित प्रयोग किया जाए। करों में कटौतियों और उच्चतर सरकारी व्यय दोनों के रूप में दिया गया राजकोषीय प्रोत्साहन

सारणी 2.53 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तपोषण का स्वरूप

(प्रतिशत)

मद	2007-08*	2008-09* बअ	2008-09* संअ	2009-10* बअ
1	2	3	4	5
वियोजन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-63.3	-22.7	-5.1	18.8
2. पूंजी परिव्यय	164.7	126.4	105.3	77.9
3. निवल उधार	8.8	9.8	3.5	4.5
4. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां \$	10.1	13.6	3.7	1.1
वित्तपोषण (1 to 11)				
1. बाजार उधार	73.4	57.3	68.5	57.7
2. केंद्र से ऋण	-1.9	5.8	1.4	4.6
3. एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों पर ऋण	7.6	19.5	1.5	4.0
4. एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	5.4	5.9	5.8	4.2
5. भविष्य निधि आदि	17.1	11.2	9.7	10.5
6. आरक्षित निधियां	-8.6	1.0	1.3	1.1
7. जमा राशियां और अग्रिम	21.4	4.6	4.2	4.9
8. उच्यंत और विविध	5.5	-1.7	-2.4	-2.1
9. विप्रेषण	1.6	0.1	0.1	0.0
10. अन्य	1.4	-1.6	-1.4	-0.9
11. समग्र अधिशेष (-)/घाटा (+)	-22.9	-2.1	11.3	16.1
बअ : बजट अनुमान		संअ : संशोधित अनुमान		
* : 2007-08 के बाद के आंकड़े 27 राज्य सरकारों से संबंधित हैं।				
\$: विनिवेश और जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि आदि शामिल है।				
टिप्पणी : 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि से विनियोजन, अंतर-राज्यीय निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।				
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।				

सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3.1 प्रतिशत पर उल्लेखनीय रहा जो कि यद्यपि कई उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्षतया अधिक ही है, तो भी नीतिगत विषय के रूप में इसे

भारत के लिए नाजुक महत्व को देखते हुए उचित ही था कि उच्च वृद्धि के रेखापथ पर वापस लौटा जाए। भारतीय राजकोषीय प्रतिक्रिया के प्रति करों में कटौती, आधारभूत संरचना

सारणी 2.54: केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे की मात्रा

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)			जीडीपी का प्रतिशत		
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	53,580	23,871	28,585	9.4	4.2	5.0
1995-96	77,671	37,932	18,598	6.5	3.2	1.6
2000-01	1,99,852	1,38,803	75,035	9.5	6.6	3.6
2003-04	2,34,501	1,59,408	56,928	8.5	5.8	2.1
2004-05	2,34,721	1,14,761	42,408	7.5	3.6	1.3
2005-06	2,39,560	99,312	35,583	6.7	2.8	1.0
2006-07	2,30,432	55,366	-399	5.6	1.3	0.0
2007-08	1,97,037	9,163	-60,495	4.2	0.2	-1.3
2008-09 सं.अं.	4,71,520	2,33,938	1,86,034	8.9	4.4	3.5
2009-10 ब.अ.	5,95,090	3,19,793	2,66,430	10.2	5.5	4.5
बअ : बजट अनुमान		सअ : संशोधित अनुमान				
टिप्पणी : राज्यों से संबंधित आंकड़े वर्ष 2007-08 के बाद से अनंतिम हैं और 25 राज्यों के बजटों से संबंधित हैं। जिसमें से 13 लेखानुदान के अधीन हैं।						

सारणी 2.55: केंद्र और राज्यों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09 संअ	2009-10 बअ	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल प्राप्तियां (क+ख)	16,42,815	18,39,239	1,96,424	12.0
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	11,66,470	12,65,947	99,477	8.5
	(21.9)	(21.6)		
1. कर प्राप्तियां (क+ख)	9,65,102	10,21,585	56,483	5.9
	(18.1)	(17.4)		
क) प्रत्यक्ष कर	3,93,060	4,30,428	37,368	9.5
	(7.4)	(7.3)		
ख) अप्रत्यक्ष कर	5,72,042	5,91,157	19,115	3.3
	(10.7)	(10.1)		
2. करेतर प्राप्तियां	2,01,368	2,44,362	42,994	21.4
	(3.8)	(4.2)		
आ. पूंजी प्राप्तियां	4,76,345	5,73,292	96,947	20.4
	(9.0)	(9.8)		
कुल संवितरण (अ+आ)	16,59,109	18,70,955	2,11,846	12.8
	(31.2)	(31.9)		
अ. विकास व्यय	9,88,513	10,62,099	73,586	7.4
	(18.6)	(18.1)		
आ. विकासेतर व्यय	6,70,596	8,08,856	1,38,260	20.6
	(12.6)	(13.8)		

संअ: संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2. राज्यों से संबंधित आंकड़े 2007-08 के बाद से अनंतिम हैं और 27 राज्यों के बजटों संबंधित हैं जिसमें से 2 लेखानुदान हैं।

में निवेश और अन्य सरकारी व्ययों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार विभिन्न गुणक प्रभावों का अनुप्रयोग करते हुए वृद्धि पर लाभकारी प्रभाव 0.7 से 2.3

प्रतिशत अंकों के दायरे में पाया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों से केंद्र सरकार के घाटा मानदंडों में विचलन और राज्य सरकारों के राजकोषीय समेकन व्यवस्था में पिछड़ने

सारणी 2.56: केंद्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	राज्य भविष्य निधि	अल्प बचत	बाह्य उधार	अन्य	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	1,27,858	15,188	63,746	8,472	15,168	2,30,432
	(55.5)	(6.6)	(27.7)	(3.7)	(6.6)	(100.0)
2007-08	1,80,945	14,216	-4,474	9,315	-2,965	1,97,037
	(91.8)	(7.2)	(-2.3)	(4.7)	(-1.5)	(100.0)
2008-09 बअ	1,62,302	16,033	28,498	10,989	24,451	2,42,273
	(67.0)	(6.6)	(11.8)	(4.5)	(10.1)	(100.0)
2008-09 संअ	3,65,131	18,086	4,450	9,603	74,250	4,71,520
	(77.4)	(3.8)	(0.9)	(2.0)	(15.7)	(100.0)
2009-10 बअ	5,11,669	24,269	24,999	16,047	18,106	5,95,090
	(86.0)	(4.1)	(4.2)	(2.7)	(3.0)	(100.0)

बअ: बजट अनुमान। संअ: संशोधित अनुमान।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2. राज्यों से संबंधित आंकड़े 2008-09 के बाद से अनंतिम हैं और 27 राज्यों के बजटों संबंधित हैं जिसमें से 2 लेखानुदान हैं।

को अपवादात्मक परिस्थितियों से पैदा हुई जरूरतों द्वारा टाला गया। आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ ही राजस्व उछाल में बहाली लाने में लगे स्वचालित स्थिरक आवश्यक राजकोषीय दायरा बना सकेंगे जिसमें सुधार और समेकन के विगत मार्ग के लिए तैयार विवेकसम्मत राजकोषीय नीति के दृष्टिकोण को वापस लाने के लिए जरूरी राजकोषीय और प्रोत्साहनों से परिचालित घाटे के मानदंडों की व्यापकता के साथ जुड़ी वर्तमान चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।

सारणी 2.57: सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों का संयुक्त व्यय

(राशि करोड़ रूपए में)

	2007-08	2008-09 बअ	2008-09 सअ	2009-10 बअ
1	2	3	4	5
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय *	3,71,435	4,42,777	5,25,052	6,07,651
<i>जिसमें से:</i>				
सामाजिक सेवाएं	2,88,500	3,52,188	3,98,828	4,45,751
<i>जिसमें से:</i>				
i) शिक्षा	1,27,547	1,58,823	1,67,981	1,98,842
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	60,869	73,164	76,488	89,305
सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	7.9	8.3	9.9	10.4
<i>जिसमें से</i>				
सामाजिक सेवाएं	6.1	6.6	7.5	7.6
<i>जिसमें से:</i>				
i) शिक्षा	2.7	3.0	3.2	3.4
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.4	1.5
कुल व्यय का प्रतिशत				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	28.7	30.2	31.6	32.5
<i>जिसमें से:</i>				
सामाजिक सेवाएं	22.3	24.0	24.0	23.8
<i>जिसमें से:</i>				
i) शिक्षा	9.8	10.8	10.1	10.6
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4.7	5.0	4.6	4.8
* : सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय में सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्यान्न सब्सिडी शामिल है।				
टिप्पणी : राज्यों से संबंधित आंकड़े 2007-08 के बाद से अनंतिम हैं और 25 राज्यों के बजटों संबंधित हैं जिसमें से 3 लेखानुदान हैं।				

V. वित्तीय बाजार

II.5.1 विकसित देशों के वित्तीय बाजारों में 2008-09 के दौरान काफी उथल-पुथल रही और कई बार तो वे निष्क्रिय से हो गये क्योंकि वित्तीय संस्थाओं और वास्तविक अर्थव्यवस्था को संक्रमित करने से पहले सब-प्राइम संकट ने वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया। प्रतिकूल फीडबैक चक्र समय के साथ-साथ मजबूत होता गया, विफल हो रही संस्थाओं और कमजोर संवृद्धि प्रत्याशाओं ने वित्तीय बाजार में तनाव का स्तर और भी बढ़ा दिया। वैश्विक वित्तीय स्थितियों में महत्वपूर्ण गिरावट, खासकर सितंबर 2008 के मध्य से, ने अल्पकालिक वित्तपोषण बाजारों में भारी व्यवधान पैदा किया, जोखिम के दायरे बढ़ गये, इक्विटी की कीमतें तेजी से गिरीं और निजी आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों और उनसे संबद्ध व्युत्पन्नियों के लिए बाजार में सुस्ती छा गई। अनिश्चितता और जोखिम के प्रति बदलती धारणा के परिवेश को देखते हुए अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण समय के साथ कीमत व्यवस्था में प्रकट होने लगे और इनमें भारी उतार-चढ़ाव रहा। अमरीका के वित्तीय क्षेत्र में जिस संकट ने जन्म लिया था वह कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के धराशायी या लगभग धराशायी होने का कारण बन गया। बड़े वित्तीय निवेश पोर्टफोलियो वाली प्रत्येक प्रमुख इकाई को बाजार-मूल्य आधारित लेखांकन के कारण भारी हानि उठानी पड़ी क्योंकि आस्तियों की कीमतें धराशायी हो रही थीं। बाजार से चलनिधि के सूख जाने के कारण बैंक, निवेश बैंक, बीमा कंपनियों, पेंशन निधियाँ, निजी इक्विटी निधियाँ जैसी गैर बैंकिंग संस्थाएं, शैडो बैंक जैसे संरचनाबद्ध निवेश वाहक (एसआइबी), म्यूच्युअल फंड और यहां तक कि सामान्यतया सुरक्षित समझे जाने वाले मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड सभी दबाव में आ गये। बैंकों के तुलनपत्रों में उल्लेखनीय रूप से क्षरण हो जाने से बैंकों के बीच अविश्वास गहरा गया जिसके परिणामस्वरूप अंतर बैंक बाजारों का कार्य बाधित हो गया और मुद्रा बाजार सूख-सा गया। इसने ऋण संकुचन तैयार कर दिया जो कि डिलीवरेजिंग के तहत और प्रबल हो गया तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था में भी अंतरित हो गया।

II.5.2 धीरे-धीरे सामने आ रहे वैश्विक आर्थिक संकट का भारतीय वित्तीय बाजारों पर प्रभाव मुख्यतया सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के विफल होने के बाद शुरू हुआ और यह प्रभाव निवल पूंजी अन्तर्वाह में कमी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा इक्विटी बाजार में बिकवाली के कारण घरेलू स्टॉक बाजारों में महत्वपूर्ण गिरावट के रूप में रहा। भारतीय

इक्विटी बाजारों से निधियों के आहरण जैसा कि अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के मामले में हुआ और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भारतीय संस्थाओं द्वारा निधियों की उगाही में घटती संभावनाओं के कारण घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर चलनिधि पर काफी दबाव पड़ा। इन गतिविधियों से भुगतान संतुलन की कठिनाइयों के बारे में प्रतिकूल प्रत्याशाएं बनीं और गिरावट का दबाव बना तथा विदेशी मुद्रा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव रहे। सीमित विदेशी निधीयन और धुंधले पड़ गए घरेलू पूंजी बाजार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्यूचुअल फंडों जैसे वित्तीय प्रणाली के कुछ खंडों पर दबाव डाला। अन्य क्षेत्रों जैसे कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराने वाले म्यूचुअल फंडों पर पड़े चलनिधि के दबाव ने निधियों के प्रवाह में और भी बदलाव ला दिया। परिणामस्वरूप, चलनिधि के निधीयन का दबाव बैंकों पर ही आ गया।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार

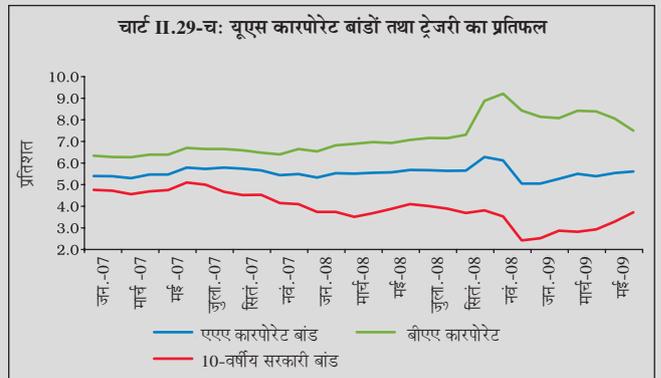
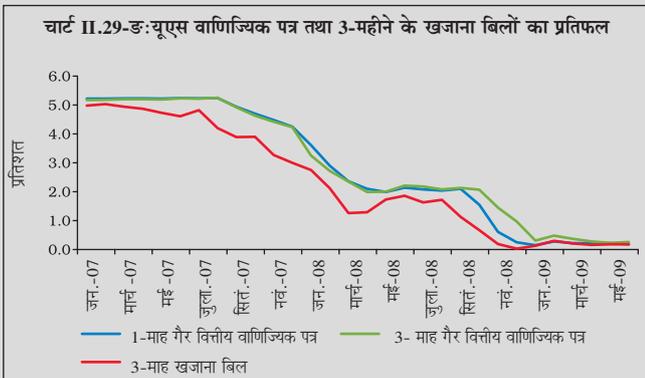
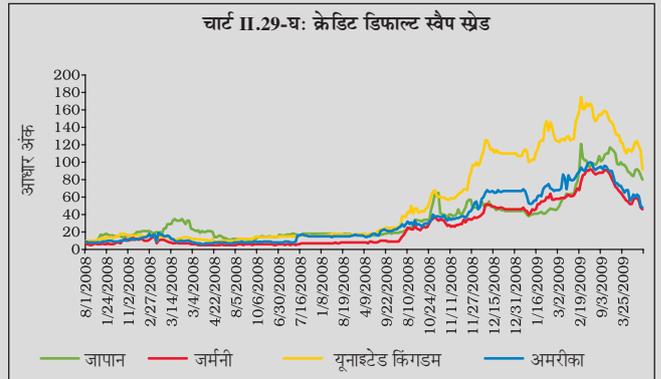
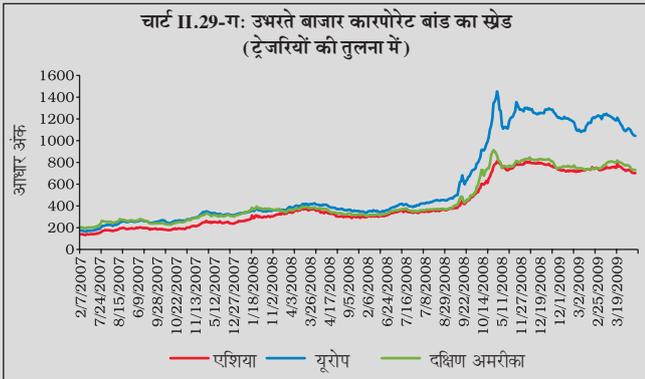
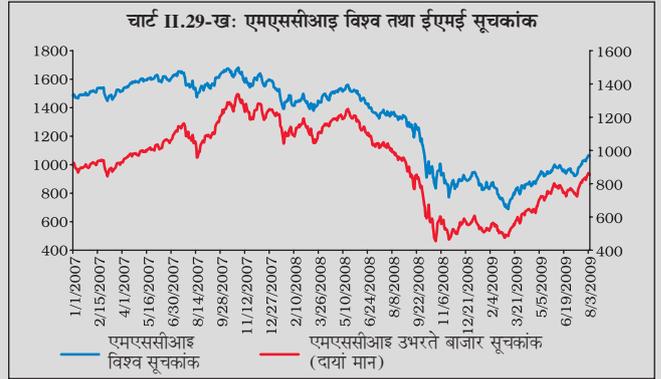
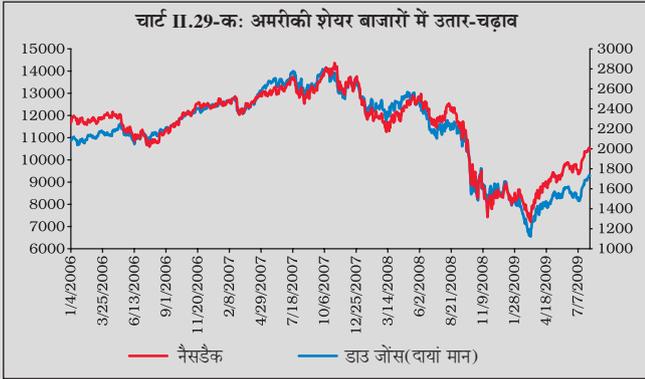
II.5.3 अमरीका और यूरोप में कई प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बैंकों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भारी हानियां उठानी पड़ीं जिसने उनके पूंजी आधार को कमजोर किया। कारपोरेट पत्र के क्रेडिट स्प्रेड तेजी से बढ़े। अमरीकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों/सरकारों को विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं का बड़े पैमाने पर सहायता पैकेजों के माध्यम से बचाव करना पड़ा था, लेकिन वित्तीय बाजारों में विश्वास का संकट लगातार बना हुआ है। आपस में जुड़े विश्व, जहां विशेष रूप से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के एक दूसरे से जुड़े एक्सपोजर तथा व्यापारिक संबंध अत्यंत सुदृढ़ तथा जटिल हैं, में तेजी से घटित हुए घटनाक्रमों का वृद्धि तथा स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

II.5.4 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने सितंबर 2008 तक इस संकट का पर्याप्त प्रतिरोध किया लेकिन 2008 की अंतिम तिमाही में वे इस संक्रमण से प्रभावित हो गयीं। सुरक्षा की ओर पलायन के चिन्ह के रूप में 2008 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों को विकसित देशों से पूंजी का प्रवाह तेजी से गिर गया। चालू और पूंजी खाते के माध्यम से न्यून प्रवाह को प्रकट करते हुए ईएमई की मुद्राओं में अमरीकी डॉलर की तुलना में गिरावट आई। पोर्टफोलियो प्रवाहों में विपर्यय के कारण ईएमई के इक्विटी बाजारों को भारी हानियां उठानी पड़ीं। ईएमई में बैंक

ऋण घट गया और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान ऋण संकट के कारण ऋण के स्प्रेड में तीव्र बढ़ोतरी हो गयी। इन सब के बावजूद, ईएमई के वित्तीय बाजार का परिवेश अलग ही प्रकार का रहा। कुल मिलाकर, इनकी वित्तीय संस्थाओं ने कोई आंतरिक कमजोरी नहीं दिखाई; अन्तर बैंक विश्वास सापेक्षतया सामान्य रहा और अन्तर-बैंक मुद्रा बाजारों में भी कारोबार चलता रहा। ईएमई को इस संकट ने मुख्यतया तीन प्रमुख वित्तीय चैनलों के माध्यम से प्रभावित किया। पहला मार्ग था - विदेशी पोर्टफोलियो इक्विटी निवेशों का निकास, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक बाजारों में गिरावट आई, और इसने निर्यात मांग में तीव्र गिरावट के साथ-साथ विनिमय दर पर भारी दबाव डाला। दूसरा मार्ग यह रहा कि बैंकों और कारपोरेटों के लिए विदेशी ऋण व्यवस्था कमजोर हो गई जिससे इनकी मांग का रुख घरेलू ऋण बाजार की ओर हो गया। तीसरा मार्ग था, व्यापार वित्त के स्रोत सूख जाने से व्यापार पर प्रचंड दबाव पड़ा। इसलिए ईएमई की मौद्रिक नीति कार्रवाई का ध्यान वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के बजाए वास्तविक अर्थव्यवस्था की उभरती समस्याओं को सुलझाने की ओर था।

II.5.5 वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्यवधानों और उतार-चढ़ाव की मात्रा को प्रमुख संकेतकों के रवैये से देखा जा सकता है, जैसाकि चार्ट II.29 में दिया गया है। यद्यपि स्टॉक बाजार में गिरावट बहुत तेज रही (चार्ट 29-क और 29-ख); उतार-चढ़ाव की मात्रा अप्रत्याशित स्तरों को छूने लगी; ईएमई के कारपोरेट बांडों से होने वाले प्रतिफल के स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गए जो जोखिम प्रीमियम में बढ़ोतरी दर्शाता है (चार्ट 29-ग) तथा क्रेडिट चूक (डिफाल्ट) प्रीमियम जो कि चूक के बीमे की लागत को दिखाता है, तेजी से बढ़ गया (चार्ट 29-घ)। अल्पावधि निधीयन बाजारों पर दबाव दर्शाते हुए वाणिज्यिक पत्रों का स्प्रेड बढ़ गया (चार्ट 29.ड), और कम रेटिंग वाले कारपोरेट बांडों से मिलनेवाले प्रतिफल भी काफी बढ़ गए (चार्ट 29.च)। विकसित देशों के वित्तीय बाजारों की इन प्रवृत्तियों में यह क्षमता थी कि वे भारतीय वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकें, खासकर बढ़ते हुए वैश्वीकरण और वित्तीय बाजारों के अधिकाधिक एकीकरण को देखते हुए। लगभग सभी ईएमई ने अपनी मुद्राओं के मूल्य में उल्लेखनीय हास के अलावा अपने स्टॉक की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट के रूप में प्रतिकूल वित्तीय बाजारों के दुष्प्रभाव को महसूस किया (सारणी 2.58)।

चार्ट II.29: वैश्विक वित्तीय बाजार की गतिविधियों के संकेतक



स्रोत: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तथा विश्व आर्थिक परिदृश्य डाटाबेस, आइएमएफ; फ़ैडरल रिज़र्व; यूएस।

II.5.6 आर्थिक और वित्तीय बाजारों पर परिदृश्य के प्रभाव स्वरूप वर्ष 2008-09 की खासियत रही दबावग्रस्त इक्विटी कीमतें। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी कीमत सूचकांक जुलाई और अगस्त 2008 के दौरान सापेक्षित रूप से स्थिर रहे लेकिन बाद में गिरावट की ओर अग्रसर हो गये और यही स्थिति वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही तक बनी रही (सारणी 2.58)। सरकार के बचाव पैकेजों के बारे में विस्तृत सूचना के अभाव में चौथी तिमाही के दौरान बाजारों में उतार-चढ़ाव और भी बढ़ गया।

II.5.7 वर्ष 2008-09 के दौरान सामान्यतया जापानी येन और चीनी युआन को छोड़कर अधिकांश मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई। अमरीकी डॉलर की वर्ष के प्रारंभ में कमजोर शुरुआत हुई, धीमी संवृद्धि, ग्राहक भरोसे में कमी, कमजोर इक्विटी बाजार तथा कमजोर कृषितर रोजगार जैसे कारणों के चलते, अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान अधिकांश मुद्राओं की तुलना में इसमें गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। तथापि, अगस्त 2008 के प्रारंभ से अमरीकी डॉलर में मजबूती आने लगी जिसका मुख्य कारण अमरीका में वित्तीय संकट के कारण अमरीकी निवेशकों की जोखिम उठाने

सारणी 2.58: अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार

देश (सूचकांक)	प्रतिशत में घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष)		पी/ई अनुपात		घट-बढ़ का सहगुणांक 2008-09 (अप्रैल-मार्च)
	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2009 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2009	
1	2	3	4	5	6
उभरते बाजार					
इंडोनेशिया (जकार्ता कम्पोजिट)	33.7	-41.4	14.8	17.7	26.6
ब्राजील (बोवेसा)	33.1	-32.9	13.8	14.4	25.3
थाईलैंड (सेट)	21.3	-47.2	16.5	15.1	27.9
भारत (बीएसई सूचकांक)	19.7	-37.9	16.2	11.0	24.2
दक्षिण कोरिया (केओएसपीआइ)	17.3	-29.2	12.6	26.0	20.4
चीन (शंघाई कम्पोजिट)	9.1	-31.7	26.1	23.0	23.4
ताईवान (ताईवान ताइएक्स)	8.7	-39.2	14.3	65.8	27.6
रूस (आरटीएस)	6.1	-66.4	9.4	5.7	54.3
मलेशिया (केएलसीआइ)	0.1	-30.1	13.7	15.0	15.4
सिंगापुर (स्ट्रेट टाइम्स)	-4.9	-43.5	10.8	9.4	26.5
विकसित बाजार					
यूएस (डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल)	-0.7	-38.0	15.2	18.8	19.3
यूएस (नैसडेक कम्पोजिट)	-5.9	-32.9	27.3	22.6	21.7
यूरो क्षेत्र (एफटीएसई यूरो टॉप 100)	-15.7	-40.1	11.2	15.4	20.4
यूके (एफटीएसई 100)	-9.6	-31.1	11.4	17.4	16.8
मेमो:					
एमएससीआइ विश्व	-5.1	-44.0	14.2	15.1	24.9
एमएससीआइ उभरते	18.9	-48.4	13.9	12.9	34.0
स्रोत : ब्लूमबर्ग और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)।					

की क्षमता में कमी आना था। इसके कारण सुरक्षा की तलाश की दृष्टि से उन्होंने वित्तीय बाजार में विदेशी बांड तथा इक्विटी बाजारों के अपनी पोजिशनों को बेच दिया तथा वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक डॉलर के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति में बदलाव आया क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अमरीका की ओर प्रवाहित होने वाली राशि में गिरावट आ गई थी, अमरीका में बड़े पैमाने पर मात्रात्मक सहूलियतें दी गई थी तथा डॉलर के प्रति बाजार के उत्साह में बदलाव आ गया था। मार्च 2009 के अंत तथा 13 अगस्त 2009 के बीच यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन की तुलना में डॉलर के मूल्य में क्रमशः 6.9 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत की गिरावट आई। एशियाई मुद्राओं के बीच, भारतीय रुपए, इंडोनेशियाई रुपिया, मलेशियाई रिंगिट, दक्षिण कोरियाई वॉन तथा थाई बाथ की तुलना में इसमें गिरावट आई (सारणी 2.59)।

देशी वित्तीय बाजार

II.5.8 संकटग्रस्त आस्तियों और विफल हो रही संस्थाओं में सीमित निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण नीतियों और देशी बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों की अपेक्षाकृत कम

सारणी 2.59: अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि (+)/ हास (-)

(प्रतिशत)

मुद्रा	मार्च 2007 के अंत में @	मार्च 2008 के अंत में @	मार्च 2009 के अंत में @	13 अगस्त, 2009*
1	2	3	4	5
यूरो	-9.12	-15.77	18.82	-6.89
पाउंड स्टर्लिंग	-11.40	-1.53	38.67	-13.74
जापानी येन	0.21	-14.92	-2.00	-2.04
चीनी यूआन	-3.53	-9.25	-2.61	-0.02
रूसी रुबल	-6.06	-9.68	44.25	-5.18
तुर्की लीरा	3.23	-5.75	27.69	-11.87
भारतीय रुपया	-2.46	-8.30	27.47	-5.52
इंडोनेशिया रुपिया	0.47	1.09	25.58	-14.04
मलेशियन रिंगिट	-6.24	-7.77	14.42	-3.52
दक्षिण कोरियाई वॉन	-3.65	5.47	38.86	-11.15
थाई बाथ	-9.90	-10.16	12.85	-4.21
अर्जेन्टाइन पेसो	0.65	2.08	17.32	3.29
ब्राजीलियन रियल	-6.41	-16.99	31.20	-17.83
मेक्सिकन पेसो	1.27	-3.48	32.90	-9.09
साउथ अफ्रिकन रैंड	17.24	11.34	17.22	-16.38
@ : वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़				
* : मार्च 2009 की समाप्ति की तुलना में घट-बढ़				

उपस्थिति के कारण सितंबर 2008 के मध्य तक भारतीय बैंकों/ वित्तीय क्षेत्र पर सब-प्राइम संकट का सीधा प्रभाव लगभग नगण्य था। तथापि, सितंबर 2008 के मध्य में लीमन ब्रदर्स के विफल होने के पश्चात बाह्य परिवेश में अचानक बदलाव आ गया। अन्य प्रमुख उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय इक्विटी बाजार से भारी मात्रा में निधियों को निकाला गया जो ऋण संकुचन और वैश्विक डिलीवरेजिंग का कारण बना और जिसके परिणामस्वरूप सितंबर-अक्टूबर 2008 के दौरान भारी मात्रा में पूंजी बहिर्वाह होने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बाजार पर भी दबाव पड़ा। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों द्वारा यह महसूस किया गया कि उन्हें विदेशों से मिलने वाला वित्तपोषण लगभग समाप्त हो गया है, जिसने उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें देशी बैंकिंग सेक्टर का रुख करने पर मजबूर किया। देशी वित्तपोषण द्वारा विदेशी वित्तपोषण का प्रतिस्थापन किए जाने से मुद्रा बाजार और ऋण बाजार दोनों पर दबाव आ गया।

11.5.9 अस्थिर हो गये विदेशी मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से अक्टूबर 2008 में विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन किए। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने विदेशों में शाखा/सहायक संस्था वाले भारतीय बैंकों के लिए उनकी अल्पकालीन विदेशी निधीयन आवश्यकताओं के प्रबंधन में सुविधा हेतु रुपया-डॉलर स्वैप सुविधा प्रारंभ की। इसने मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार में उस समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए जून 2008 में शुरू किए गए विशेष बाजार परिचालनों (एसएमओ) को आगे भी जारी रखा। अंत में, विदेशी मुद्रा चलनिधि की सुलभता बनाये रखने हेतु किए गए उपायों में अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर की उच्चतम सीमा में वृद्धि, कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) व्यवस्था को पर्याप्त रूप से उदार बनाये जाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को विदेशी उधार लेने की अनुमति दिए जाने जैसे उपाय भी शामिल थे जो पूंजी अंतर्वाह बढ़ाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए गए थे (बाक्स 11.27)।

11.5.10 रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गए कदमों का प्रभाव दर्शाते हुए नवंबर 2008 से मुद्रा बाजार में मांग दरें अनौपचारिक एलएएफ दायरे के भीतर आ गईं जो इसके पहले के दो माह के दौरान उच्चतर सीमाओं को पार कर गयी थीं। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपए की कीमतों में वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में वृद्धि आने से पहले वित्त वर्ष की समाप्ति तक प्रमुख मुद्राओं की तुलना में सामान्य रूप से कमी आयी (सारणी 2.60)। ऋण बाजार में, नवंबर 2008 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उधार दरों में क्रमिक रूप से नरमी आनी शुरू हो गयी। वर्ष 2008-09 की लगभग पूरी चौथी तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में मंदी छाया रही, परंतु विशेष रूप से मध्यावधि से दीर्घावधि परिपक्वता वाले प्रतिफल में वृद्धि हुई। वैश्विक बाजारों से संकेत लेते हुए भारतीय इक्विटी बाजारों में मार्च 2009 के अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ सुधार होता दिखाई दिया जो कि वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही तथा उसके बाद में भी बरकरार रहा।

11.5.11 वैश्विक वित्तीय संकट का नतीजा यह हुआ कि विदेशी निधीयन अत्यंत कम हो गया और घरेलू पूंजी बाजार में भारी गिरावट आई जिसने भारतीय वित्तीय प्रणाली के म्यूचुअल फंडों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे कुछ खंडों पर दबाव डाला। गैर-बैंकों के समक्ष आये वित्तीय दबाव का समाधान रिजर्व बैंक ने अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग चैनल तथा एसपीवी के माध्यम से, तुलन पत्र की आस्तियों की गुणवत्ता और प्रतिपक्ष पात्रता से समझौता किए बिना किया।

मुद्रा बाजार

मांग/सूचना मुद्रा बाजार

11.5.12 वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियां दर्शाते हुए, मांग दरें मोटे तौर पर रिवर्स रिपो और रिपो दरों के अनौपचारिक दायरे में ही रहीं। हालांकि, लीमन ब्रदर्स की विफलता ने घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ावों को बढ़ावा दिया। स्थिति का सामना करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के दृष्टिकोण से पर्याप्त डॉलर चलनिधि उपलब्ध करायी, जिसके प्रभाव से रुपया चलनिधि में कमी हो गई। बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर के बहिर्वाह जैसे घरेलू कारकों के कारण यह प्रभाव और भी बढ़ गया। सितंबर

बाक्स II.27

सितंबर 2008 के मध्य से रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत प्रतिक्रिया

मौद्रिक उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिपो दर में क्रमिक रूप से 425 आधार अंकों की कटौती कर उसे 9.0 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत किया गया।
- रिवर्स रिपो दर में क्रमिक रूप से 275 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.0 प्रतिशत से 3.25 प्रतिशत किया गया।

रुपया चलनिधि/ऋण सुपुर्दगी

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात में क्रमिक रूप से 400 आधार अंकों की कटौती कर इसे निवल मांग और देयताओं (एनडीटीएल) के 9.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत किया गया।
- 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रारंभ की गई जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को रिजर्व बैंक द्वारा 24 अक्टूबर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक की एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा दी जाती है।
- म्यूच्युअल फंडों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा महसूस किए जा रहे चलनिधि दबाव को कम करने हेतु बैंकों को सक्षम बनाये जाने के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के 1.5 प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत आवधिक रिपो सुविधा का प्रारंभ। यह सुविधा 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध होगी।
- 8 नवंबर 2008 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से सांविधिक चलनिधि अनुपात को एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से कम करके 24 प्रतिशत किया गया।
- एमएसएस के तहत जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद संबंधी प्रणाली की शुरुआत।
- 15 नवंबर 2008 और 28 नवंबर 2008 से क्रमशः पोत-लदान पूर्व और पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के प्रथम चरण की पात्रता अवधि को 90 दिन बढ़ा दिया गया।
- ईसीआर सुविधा की पात्रता सीमा को अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
- मार्च 2009 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में बैंकों की अनुमानित कमी के बदले में सिडबी और एनएचबी के लिए योगदान हेतु अग्रिम रूप से धनराशि का आबंटन किया गया।
- कृषि और एसएमई क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिमों के लिए 0.25 प्रतिशत का प्रावधानीकरण जारी रहेगा, इसके अलावा सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं को घटाकर 0.40 के एक समान स्तर पर कर दिया गया।
- कंपनियों पर सभी रेटिंग न किए गए दावों और वाणिज्यिक भू-संपदा की जमानत वाले दावों के लिए 100 प्रतिशत का एक समान जोखिम भार रखा गया जबकि पहले इसके लिए 150 प्रतिशत का जोखिम भार निर्धारित किया गया था। जमाराशियां स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रेटिंग किए गए तथा रेटिंग न किए गए दावों पर 100 प्रतिशत का समान जोखिम भार रखा गया है।

- आवास, निर्यात और एमएसई क्षेत्रों को चलनिधि समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने एनएचबी, एक्विजम बैंक और सिडबी को मार्च 2010 तक के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की है।
- नीलामी आधारित पद्धति के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करके ओएमओ के दायरे को बढ़ाया गया।

विदेशी मुद्रा चलनिधि

- घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए एजेंट बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अमरीकी डॉलर) की बिकवाली की अथवा मांग-आपूर्ति अंतरालों को ठीक करने हेतु सीधे ही हस्तक्षेप किया गया।
- सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकतों की पूर्ति हेतु तेल बांडों का विशेष बाजार परिचालन।
- विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर लाइबोर में 350 आधार अंक जोड़कर निर्धारित की गई।
- प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 के बैंकों को अपने प्रधान कार्यालयों, विदेश स्थित शाखाओं और व्यावसायिक संपर्कों से नोस्त्रो खातों में निधियां उधार लेने और ओवर ड्राफ्ट लेने की अनुमति दी गई, जिसकी सीमा उनकी अक्षत टीयर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत या 10 मिलियन अमरीकी डॉलर, दोनों में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई।
- आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को अनुमोदित मार्ग के तहत अल्पावधिक विदेशी मुद्रा उधार लेने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करें।
- विदेश में परिचालन वाले भारतीय सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को तीन माह तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा दी गई ताकि वे अपने विदेश स्थित कार्यालयों में अल्पावधि निधीयन अपेक्षाओं का प्रबंधन सहजता से कर सकें।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता और अनिवासी (विदेश) रुपया खाता सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा में 16 सितंबर 2008 से 175 आधार अंकों की संचयी बढ़ोतरी की गई।
- भारतीय कंपनियों द्वारा उनके विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की परिपक्वतापूर्व वापसी खरीद के प्रस्तावों पर अनुमोदन या स्वचालित मार्ग के तहत विचार किया जाए। एफसीसीबी के विस्तार की भी अनुमति दी गई।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए समग्र लागत सीमा को 31 दिसंबर 2009 तक समाप्त कर दिया गया और तीन वर्ष से कम के व्यापारिक ऋणों के लिए बढ़ाया गया (6 माह लिबोर में 200 आधार अंक जोड़कर)।
- स्वचालित मार्ग के तहत अनुमेय अंतिम उपयोगों के लिए रुपया/विदेशी मुद्रा व्यय हेतु प्रति उधारकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष ईसीबी को बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डॉलर किया गया।
- ईसीबी का लाभ उठाने के लिए आधारभूत संरचना क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया गया तथा उधारकर्ता द्वारा आधारभूत संरचना में रुपया पूंजी व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के ईसीबी के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया।
- जमाराशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी को अनुमोदन मार्ग से अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधारियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई, इसके लिए पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोजर मानदंड संबंधी विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करना जरूरी होगा।

सारणी 2.60: देशी बाज़ार एक नजर में

वर्ष/माह	मांग मुद्रा		सरकारी प्रतिभूतियां		विदेशी मुद्रा			चलनिधि प्रबंधन		इक्विटी				
	औसत दैनिक टर्नओवर (करोड़ रुपए)	औसत मांग दरें* (प्रति शत)	औसत टर्नओवर (करोड़ रु.)+ (प्रति शत)	औसत 10-वर्षीय प्रतिफल@ (प्रति शत)	औसत दैनिक अंतर-बैंक टर्नओवर (मिलियन अमरीकी डालर)	औसत विनिमय दर (रुपया प्रति अमरीकी डालर)	रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिक्री (-)/ खरीद (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	औसत 3-माह वाले एमएसएस# प्रीमियम (प्रति शत)	औसत बकाया एलएएफ (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बकाया एलएएफ (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बीएसई टर्नओवर (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक एनएसई टर्नओवर (करोड़ रुपए)	औसत बीएसई सूचकांक **	औसत एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006-07	21,725	7.22	4,863	7.78	18,717	45.28	26,824##	2.14	37,698	21,973	3,866	7,812	12,277	3,572
2007-08	21,393	6.07	8,104	7.91	34,044	40.24	78,203##	2.16	1,28,684	4,677	6,275	14,148	16,569	4,897
2008-09	22,436	7.06	7,344	7.54	34,812	45.92	-34,922##	3.47	1,48,889	2,885	4,498	11,325	12,366	3,731
जन-08	27,531	6.69	19,182	7.61	38,676	39.37	13,625	2.07	1,59,866	15,692	8,071	19,441	19,326	5,756
फर-08	22,716	7.06	12,693	7.57	42,068	39.73	3,884	0.24	1,75,166	-1,294	5,808	13,342	17,728	5,202
मार्च-08	22,364	7.37	5,881	7.69	39,087	40.36	2,809	1.25	1,70,285	-8,271	6,166	14,056	15,838	4,770
अप्रैल-08	19,516	6.11	6,657	8.10	37,580	40.02	4,325	2.68	1,70,726	26,359	5,773	13,561	16,291	4,902
मई-08	19,481	6.62	6,780	8.04	32,287	42.13	148	2.45	1,75,565	11,841	6,084	13,896	16,946	5,029
जून-08	21,707	7.75	6,835	8.43	38,330	42.82	-5,229	3.69	1,74,433	-8,622	5,410	12,592	14,997	4,464
जुलाई-08	24,736	8.76	5,474	9.18	37,173	42.84	-6,320	6.04	1,72,169	-27,961	5,388	12,862	13,716	4,125
अगस्त-08	23,408	9.10	7,498	9.06	38,388	42.94	1,210	4.71	1,71,944	-22,560	4,996	11,713	14,722	4,417
सितं-08	23,379	10.52	10,418	8.45	44,700	45.56	-3,784	2.35	1,75,666	-42,591	5,147	12,489	13,943	4,207
अक्टू-08	28,995	9.90	4,321	7.85	36,999	48.66	-18,666	1.13	1,69,123	-45,612	3,911	10,810	10,550	3,210
नव-08	21,812	7.57	5,866	7.41	31,322	49.00	-3,101	4.20	1,47,648	-8,017	3,539	9,618	9,454	2,835
दिसं-08	21,641	5.92	11,451	5.55	34,874	48.63	-318	4.59	1,24,848	22,294	3,851	10,141	9,514	2,896
जन-09	18,496	4.18	9,568	5.84	27,895	48.83	-29	3.10	1,13,535	45,474	3,526	9,559	9,350	2,854
फर-09	22,241	4.16	5,916	5.98	25,068	49.26	230	2.68	1,02,934	50,649	2,859	7,887	9,188	2,819
मार्च-09	23,818	4.17	5,322	6.59	33,126	51.23	-3,388	3.99	88,077	33,360	3,489	10,140	8,966	2,802
अप्रैल-09	21,820	3.28	7,998	6.55	27,796	50.06	-2,487	3.34	75,146	1,01,561	5,232	15,688	10,911	3,360
मई-09	19,037	3.17	7,292	6.41	32,227	48.53	-1,437	3.42	45,955	1,25,728	6,427	19,128	13,046	3,958
जून-09	17,921	3.21	7,288	6.83	32,431	47.77	1,044	3.30	27,140	1,23,400	7,236	21,928	14,782	4,436
जुलाई-09	14,394	3.21	-	-	-	48.48	-	2.60	22,159	1,30,891	6,043	18,528	14,635	4,343

* : दैनिक भारत मांग मुद्रा उधार दर का औसत
 @ : दैनिक अंतिम दरों का औसत
 ** : दैनिक अंतिम सूचकांक औसत
 - : उपलब्ध नहीं
 एलएएफ : चलनिधि समायोजन सुविधा
 बीएसई : बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
टिप्पणी: कॉलम 11 में (-) चलनिधि डालने, जबकि (+) चलनिधि के अवशोषण को दर्शाता है।

+ : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के दैनिक एकमुश्त टर्नओवर का औसत
 # : साप्ताहिक बकाया एमएसएस का औसत
 ## : वित्तीय वर्ष के लिए संचयी
 एमएसएस : बाजार स्थिरीकरण योजना
 एनएसई : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि

2008 के मध्य में मांग दर बढ़कर रिपो दर से अधिक हो गई (चार्ट II.30)। 2008-09 की दूसरी तिमाही में भारत औसत दैनिक मांग दर पहली तिमाही के 6.83 प्रतिशत से बढ़कर 9.46 प्रतिशत हो गई (सारणी 2.60)। बाजार के उत्साह में कमी के साथ-साथ चलनिधि की स्थिति में आई तंगी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसे कुछ खंडों पर दबाव डाला। म्यूचुअल फंडों के संग्रहण का महत्वपूर्ण अंश प्रकट करता है कि बड़ी राशियों की प्राप्ति मुद्रा बाजार योजनाओं के तहत कारपोरेट क्षेत्र से हुई जो अंशतः कर और अन्य नियामक खामियों को दर्शाता

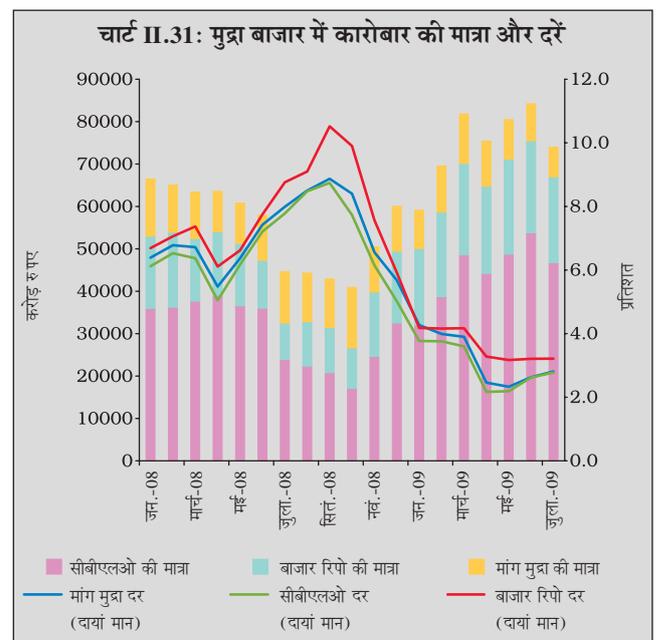
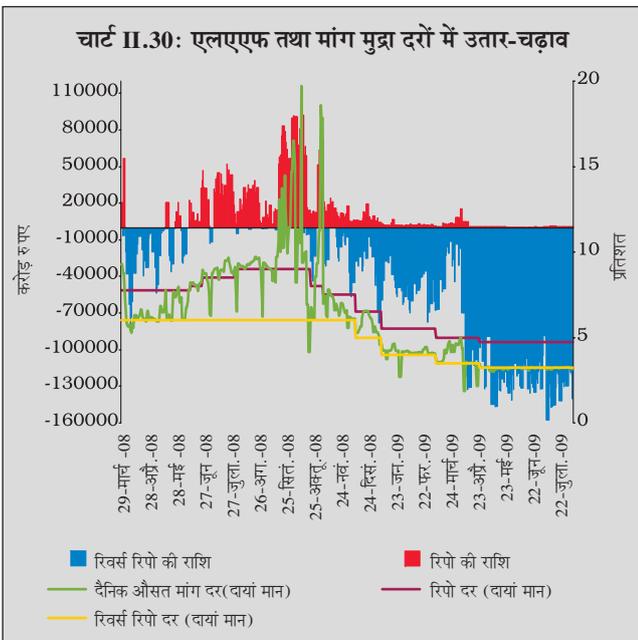
है। जोखिम विमुखता के कारण निधियन के स्रोत विलुप्त हो जाने से म्यूचुअल फंडों पर मोचन का भारी दबाव आ गया। म्यूचुअल फंडों के पास निधियों की कमी हो जाने से, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे अन्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराते थे, निधियों का प्रवाह और बाधित हो गया। कारपोरेट सेक्टर द्वारा इक्विटी बाजार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्यूचुअल फंडों से नया वित्तपोषण और बाह्य निधियां प्राप्त करने में असमर्थ हो जाने तथा उभरते हुए ऋण संकट की बढ़ती हुई धारणा के परिणामस्वरूप निधियों की उपलब्धता का सारा भार बैंकों पर आ गया।

II.5.13 वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही की शुरुआत में मुद्रा बाजारों पर दबाव बना रहा। मांग दर अक्टूबर 2008 के प्रथम पखवाड़े में अनौपचारिक दायरे से ऊपर रही। इसके बाद 11 अक्टूबर 2008 से प्रारंभ हुए पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में की गई कमी के प्रभावस्वरूप मांग दर में कमी आयी। चलनिधि में वृद्धि किए जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की श्रृंखला ने जैसे ही प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, मांग मुद्रा दरों के भारित औसत में गिरावट आई और नवंबर 2008 से यह ज्यादातर एलएएफ दायरे में रही (चार्ट II.30)। इसके अलावा, नवंबर 2008 से मुद्रा बाजार की मात्रा में भी वृद्धि हुई (चार्ट II.31), जो दर्शाती है कि प्रतिपक्ष जोखिम की कोई भी प्रतिकूल धारणा नहीं रही और इसके परिणामस्वरूप कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले बाजारों के विपरीत भारत में अन्तर-बैंक मुद्रा बाजार का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। सामान्य चलनिधि स्थितियों को दर्शाते हुए मांग मुद्रा दर 2008-09 की अंतिम तिमाही में एलएएल दायरे के नीचले स्तर के आसपास बनी रही और इसका औसत 4.17 प्रतिशत रहा। 2009-10 के दौरान अब तक अप्रैल 2009 में नीतिगत दरों में कमी किए जाने के अनुरूप तथा चलनिधि स्थिति में आगे और बेहतरी आने से मांग दर में कमी आई और यह एलएएफ दायरे के नीचले स्तर के आस-पास बनी रही। 2009-10 की पहली तिमाही में मांग दर का औसत 3.22 रहा और 18 अगस्त 2009 को 3.24 रहा।

II.5.14 मुद्रा बाजार के क्रियाकलापों में अब संपाश्वीकृत खंड 75 प्रतिशत से भी अधिक भाग के साथ वर्चस्व रखता है। बाजार रिपो (एलएएफ से बाहर) और संपाश्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) की ब्याज दर मांग दर के अनुरूप चलती रही परंतु वर्ष 2008-09 के दौरान, सामान्यतः मांग दर से कम रही। लगभग अक्टूबर 2008 तक चलनिधि की सख्त स्थितियों के कारण बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक से चलनिधि सुविधा लिए जाने से संपाश्वीकृत खंड में औसत दैनिक कारोबार की मात्रा में गिरावट आयी (देखें चार्ट II.31)। यद्यपि, वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही में कारोबार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो गयी जो मुख्यतः चलनिधि की स्थितियों में सहजता आने और म्यूचुअल फंडों की उधार देने की क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है (सारणी 2.61)।

जमा प्रमाण पत्र

II.5.15 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल का अप्रत्यक्ष प्रभाव जमा प्रमाणपत्र (सीडी) बाजारों के क्रिया-कलापों पर देखा गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि मार्च और सितंबर 2008 के दौरान बढ़ती रही लेकिन उसके बाद दिसंबर 2008 तक इसमें गिरावट जारी रही क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल और भी बढ़ गई थी। चलनिधि की स्थितियों में सुधार आने पर वर्ष से 2008-09



सारणी 2.61: मुद्रा बाजार खंडों की गतिविधियां

(करोड़ रुपए)

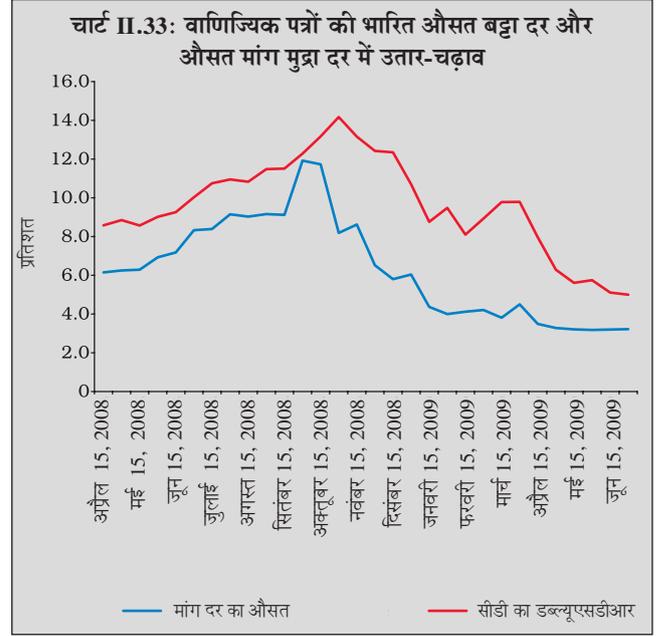
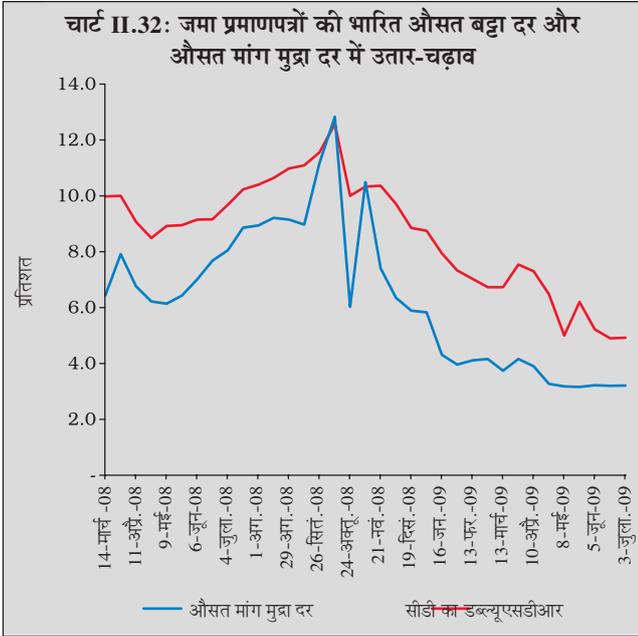
वर्ष/माह	औसत दैनिक मात्रा (एक चरण)				मोयादी मुद्रा बाजार	वाणिज्यिक पत्र		जमा प्रमाणपत्र	
	मांग मुद्रा बाजार	बाजार रिपो (एलएएफ के बाहर)	सीबीएलओ	कुल (2+3+4)		बकाया	भारित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)	बकाया	भारित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2006-07	10,863	8,419	16,195	35,477	506	21,336	8.08	64,821	8.24
2007-08	10,697	13,684	27,813	52,194	352	33,813	9.20	1,17,186	8.94
2008-09	11,218	14,330	30,776	56,323	397	47,183	10.54	1,62,574	9.31
अप्रैल-07	14,845	7,173	18,086	40,104	440	18,759	10.52	95,980	10.75
मई-07	10,238	8,965	20,810	40,013	277	22,024	9.87	99,715	9.87
जून-07	8,413	10,295	20,742	39,450	308	26,256	8.93	98,337	9.37
जुलाई-07	8,290	12,322	20,768	41,380	288	30,631	7.05	1,05,317	7.86
अगस्त-07	11,802	16,688	26,890	55,380	319	31,784	8.30	1,09,224	8.67
सितंबर-07	10,995	17,876	29,044	57,915	265	33,614	8.95	1,18,481	8.57
अक्टू.-07	9,275	15,300	29,579	54,154	221	42,183	7.65	1,24,232	7.91
नवंबर-07	10,073	12,729	28,614	51,416	184	41,308	9.45	1,27,142	8.48
दिसंबर-07	8,124	13,354	30,087	51,565	509	40,243	9.27	1,23,466	8.81
जन-08	13,765	17,029	35,711	66,505	312	50,062	11.83	1,29,123	8.73
फरवरी-08	11,358	17,682	36,007	65,047	525	40,642	9.73	1,39,160	9.94
मार्च-08	11,182	14,800	37,413	63,395	571	32,952	10.38	1,47,792	10.00
अप्रैल-08	9,758	14,966	38,828	63,552	374	37,584	8.85	1,50,865	8.49
मई-08	9,740	14,729	36,326	60,795	420	42,032	9.02	1,56,780	8.95
जून-08	10,854	11,262	35,774	57,890	253	46,847	10.03	1,63,143	9.16
जुलाई-08	12,368	8,591	23,669	44,628	226	51,569	10.95	1,64,892	10.23
अगस्त-08	11,704	10,454	22,110	44,268	501	55,036	11.48	1,71,966	10.98
सितंबर-08	11,690	10,654	20,547	42,891	335	52,038	12.28	1,75,522	11.56
अक्टू.-08	14,497	9,591	16,818	40,906	345	48,442	14.17	1,58,562	10.00
नवंबर-08	10,906	15,191	24,379	50,476	319	44,487	12.42	1,51,493	10.36
दिसंबर-09	10,820	16,943	32,261	60,024	415	40,391	10.70	1,51,214	8.85
जन-09	9,248	18,053	31,794	59,095	454	51,668	9.48	1,64,979	7.33
फरवरी-09	11,121	19,929	38,484	69,534	669	52,560	8.93	1,75,057	6.73
मार्च-09	11,909	21,593	48,319	81,821	451	44,171	9.79	1,92,867	7.53
अप्रैल-09	10,910	20,545	43,958	75,413	332	52,881	6.29	2,10,954	6.48
मई-09	9,518	22,449	48,505	80,472	338	60,740	5.75	2,18,437	6.20
जून-09	8,960	21,694	53,553	84,207	335	68,721	5.00	2,21,491	4.90
जुलाई-09	7,197	20,254	46,501	73,952	389	-	-	2,28,638 *	4.92 *

* : 3 जुलाई 2009 की स्थिति पर - : उपलब्ध नहीं डब्ल्यूएडीआर: भारित औसत बट्टा दर

की अंतिम तिमाही में सीडी कारोबार की मात्रा में गति आ गयी। जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों में से अधिकांश छह माह से अधिक अवधि वाले थे। वित्तीय बाजार में उथल-पुथल के गहराने और चलनिधि की स्थिति में गिरावट आने से जमा प्रमाण पत्रों के भारित औसत बट्टा दरों में जून के अंत से लेकर 10 अक्टूबर 2008 के बीच निरंतर बढ़ोतरी हुई, इसके बाद इसमें गिरावट आई (चार्ट II.32)।

वाणिज्यिक पत्र

II.5.16 वैश्विक वित्तीय संकट के परोक्ष प्रभावों को दर्शाते हुये वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजार ने निधियां जुटाने में भी विशेष रूप से सितंबर से मध्य दिसंबर 2008 के बीच उन कठिनाइयों का सामना किया जो कारपोरेटों ने सामना किया था। निर्गमकर्ताओं द्वारा मोचन को पूरा करने में चूक होने के कुछ मामलों को भी निर्गम एवं भुगतान एजेंटों द्वारा सामने लाया गया। तत्पश्चात्,



चलनिधि की स्थितियों में सुधार होने पर वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि में तेजी आयी (देखें सारणी 2.60)। मुख्य रूप से पट्टादायी और वित्तीय कंपनियों वाणिज्यिक पत्रों के जारीकर्ता रहे और उनके बाद 'विनिर्माण और अन्य कंपनियों' और वित्तीय संस्थानों का स्थान रहा (सारणी 2.62)। वाणिज्यिक पत्रों की भारत औसत बढ़ा दर जो मई 2008 के मध्य तक निरंतर गिरावट का रुझान दर्शा रही थी उसके पश्चात् अक्टूबर 2008 के अंत तक उसमें तीव्र उछाल दर्ज किया गया। चलनिधि की स्थितियों में सुधार होने के बाद भारत औसत ब्याज दरों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II.33)। सर्वाधिक तरजीह 180 दिनों से अधिक परिपक्वता अवधि वाले वाणिज्यिक पत्रों को दी गई।

विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.17 वैश्विक वित्तीय संकट का परिणामी प्रभाव घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पर निवल पूंजी अंतर्वाह के निचले स्तर से उत्पन्न होने वाले डॉलर चलनिधि आघातों के जरिए महसूस किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में सही स्थितियां बनाये रखने के अपने नीतिगत उद्देश्य से साम्य रखते हुये रिजर्व बैंक ने बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री की ताकि विदेशी मुद्रा बाजार के असंतुलन को दूर किया जा सके। अमरीका में वित्तीय संकट के गहराने और आर्थिक गतिविधियों में आयी कमजोरी के बावजूद सुरक्षित निवेश की तलाश के कारण वर्ष 2008-09 के दौरान अमेरिकी डॉलर अधिकतर मुद्राओं के प्रति सुदृढ़ हुआ जिसमें अगस्त 2008 के आरंभ से विशेष रूप में भारतीय रुपए का भी समावेश है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय रुपये में 39.89 रुपये और 52.09 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के बीच दो तरफा गतिविधि दृष्टिगोचर हुई (चार्ट II.34)। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान रुपये में सामान्यतया गिरावट आयी जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के बर्हिगमन, उच्च मुद्रास्फीति और कच्चे तेल के उच्चतर मूल्य के चलते डॉलर की अधिक मांग का परिणाम है। मार्च 2008 के अंत तक जो रुपया 39.99 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था वह अप्रैल 2008 तक इसी रेंज के भीतर रहा परंतु बाद में इसमें और गिरावट आयी और यह मई के तीसरे सप्ताह से अगस्त 2008 के मध्य तक 42-43 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की संकीर्ण रेंज में बना रहा। बाहरी आघातों के गहरे होने के साथ ही इसमें तेजी से

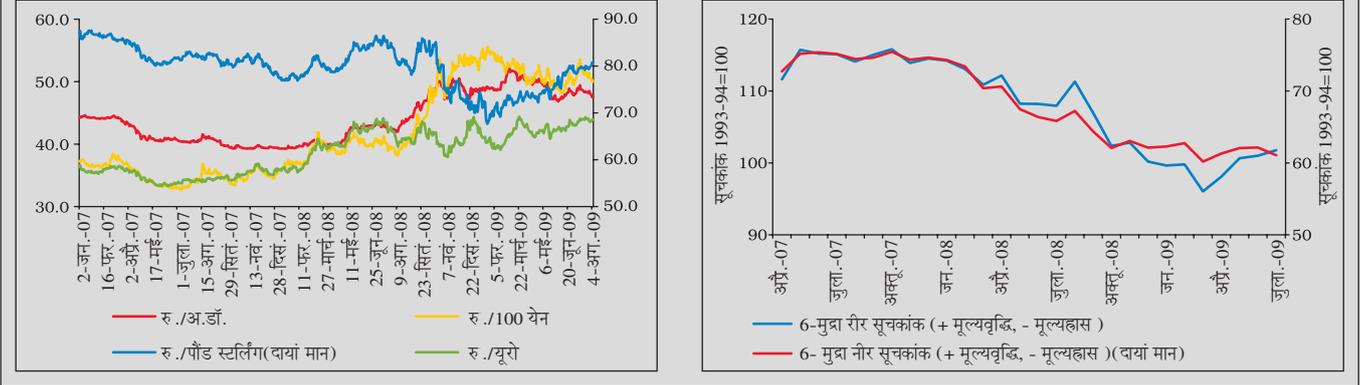
सारणी 2.62: वाणिज्यिक पत्र - प्रमुख जारीकर्ता

(करोड़ रुपये)

जारीकर्ता की श्रेणी	जून-08 के अंत में	सितं-08 के अंत में	दिसं-08 के अंत में	मार्च-09 के अंत में	जून-09 के अंत में
1	2	3	4	5	6
पट्टेदारी और वित्त	34,957 (74.6)	39,053 (75.0)	27,965 (73.5)	27,183 (61.5)	34,437 (50.1)
विनिर्माण	8,150 (17.4)	9,925 (19.1)	6,833 (18.0)	12,738 (28.9)	23,454 (34.1)
वित्तीय संस्थान	3,740 (8.0)	3,060 (5.9)	3,257 (8.5)	4,250 (9.6)	10,830 (15.8)
कुल	46,847	52,038	38,055	44,171	68,721

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

चार्ट II.34: भारतीय रुपए की सांकेतिक और वास्तविक विनिमय दर



गिरावट आई और 27 अक्टूबर 2008 को यह 50 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। वर्ष की दूसरी छमाही में कच्चे तेल के मूल्यों और मुद्रास्फीति संबंधी दबावों में काफी नरमी आने के बावजूद निर्यात के घटने, पूंजी के निरंतर बहिर्वाह और अन्य प्रमुख मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर के सुदृढ़ होने से रुपये में गिरावट का दबाव बढ़ता रहा और 5 मार्च 2009 को अमेरिकी डॉलर - रुपये की विनिमय दर ने 52.09 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के निम्न स्तर को छू लिया।

II.5.18 2009-10 के दौरान अगस्त के मध्य तक एफआइआइ अंतर्वाह में हुए उल्लेखनीय सुधार, एफडीआइ तथा एनआरआइ जमाराशियों के अंतर्गत अंतर्वाह के बने रहने, 2008-09 की चौथी तिमाही में समष्टि आर्थिक स्थिति का अपेक्षा से बेहतर निष्पादन तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमरीकी डॉलर के कमजोर पड़ने के चलते अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए में सामान्यतः मजबूती आई। इसके अलावा, आम चुनाव के परिणाम से राजनीतिक स्थिरता की संभावना बनने से बाजार के उत्साह में वृद्धि हुई और इसने विशेष रूप से मई 2009 के उत्तरार्ध में रुपए की मजबूती में मदद की। इसके परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान (14 अगस्त 2009 तक) रुपए के मूल्य में अमरीकी डॉलर की तुलना में 5.5 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परंतु, पौंड स्टर्लिंग तथा यूरो की तुलना में रुपए के मूल्य में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत की गिरावट आई।

II.5.19 मई 2008 तक विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक की गतिविधियां पूंजी अंतर्वाह के द्वारा निर्मित वृद्धि स्तरीय उतार-चढ़ाव, से होनेवाले प्रभाव के अनुसार निर्देशित थी जो बाद की अवधि में बढ़ते व्यापार घाटे और पूंजी बहिर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा की बढ़ती मांग को दूर करने की ओर झुक गई (सारणी 2.63)।

तथापि, दिसंबर 2008 से बाजार परिचालनों में नरमी आयी क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजारों में चलनिधि की स्थितियां अपने सामान्य स्तर पर आ गई थी।

सारणी 2.63: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर की खरीद और बिक्री

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष/माह	खरीद	बिक्री	निवल खरीद (+) / बिक्री (-)	निवल बकाया वायदा खरीद (+)/ बिक्रियां (-)
1	2	3	4	5
2005-06	15,239	7,096	(+)8,143	0
2006-07	26,824	0	(+)26,824	0
2007-08	79,696	1,493	(+)78,203	(+)14,735
2008-09	26,563	61,485	(-)34,922	(-)2,042
अप्रै-08	4,325	0	(+)4,325	(+)17,095
मई-08	1,625	1,477	(+)148	(+)15,470
जून-08	1,770	6,999	(-)5,229	(+)13,700
जुला-08	3,580	9,900	(-)6,320	(+)11,910
अग-08	3,770	2,560	(+)1,210	(+)9,925
सितं-08	2,695	6,479	(-)3,784	(+)2,300
अक्टू-08	1,960	20,626	(-)18,666	(+)90
नवं-08	2,355	5,456	(-)3,101	(-)487
दिसं-08	2,005	2,323	(-)318	(-)1,752
जन-09	1,055	1,084	(-)29	(-)1,723
फर-09	1,063	833	(+)230	(-)1,953
मार्च-09	360	3,748	(-)3,388	(-)2,042
अप्रै-09	204	2,691	(-)2,487	(-)1,071
मई-09	923	2,360	(-)1,437	(+)131
जून-09	1,279	235	(+)1,044	(+)745

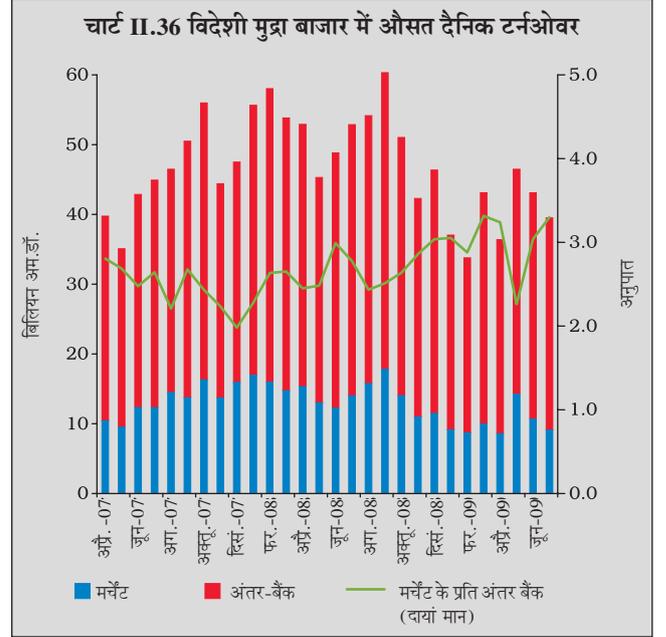
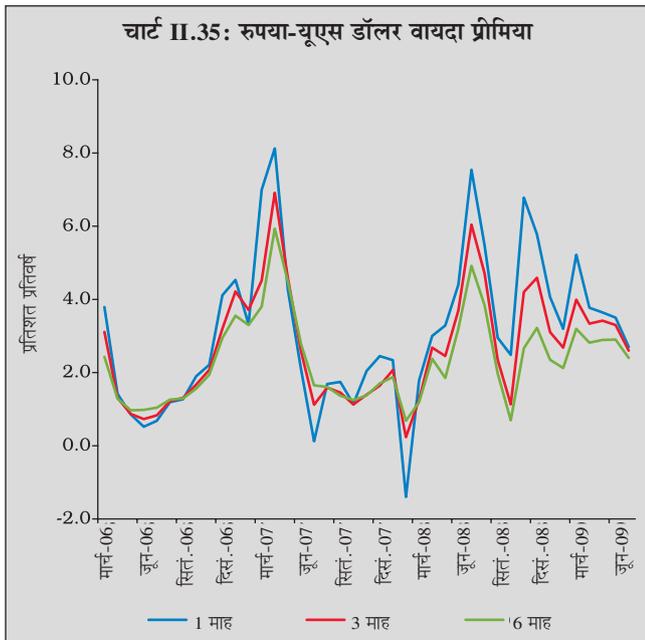
(+) : खरीद में स्वैप और तत्काल वायदों के अंतर्गत खरीद का चरण भी शामिल है।

(-) : बिक्री में स्वैप और तत्काल वायदों के अंतर्गत बिक्री का चरण भी शामिल है।

टिप्पणी : सारणी मूल्य निर्धारण की तारीखों पर आधारित है और इसमें इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के तहत किए गए लेनदेनों के आकड़े शामिल हैं।

II.5.20 मार्च 2008 और मार्च 2009 के बीच 6 मुद्राओं के व्यापार पर आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में (आधार: 1993-94=100) 13.4 प्रतिशत की कमी आयी (चार्ट II.34. परिशिष्ट सारणी-38)। इसी अवधि के दौरान 36 मुद्राओं के व्यापार-भारित व्यापक आरईईआर में भी 13.3 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष 2008-09 के दौरान अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन तथा चीनी युआन जैसी प्रमुख मुद्राओं के प्रति रुपये में आयी उल्लेखनीय गिरावट और भारत में मुद्रास्फीति की दर में अत्यधिक कमी के चलते आरईईआर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई। 14 अगस्त 2009 को 6 मुद्राओं का आरईईआर 100.5 पर था।

II.5.21 वर्ष 2008-09 के दौरान वायदा प्रीमियम में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किए गए जो अंतर्निहित मांग-आपूर्ति स्थितियों और संबंधित ब्याज दरों में तीव्र परिवर्तन दर्शाते हैं (चार्ट II.35)। एक, तीन छह माह के प्रीमियम में घरेलू मुद्रा बाजार की तत्कालीन चलनिधि की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय अंतर-बैंक बाजारों में डॉलर चलनिधि की कमी के कारण बैंकों द्वारा खरीद-बिक्री स्वैप से तादात्म्य रखते हुये ही संचलन दृष्टिगत हुये। तथापि, नवंबर 2008 के बाद डॉलर चलनिधि में सुधार होने के साथ ही वायदा प्रीमियम में सामान्यतः नरमी का रुझान देखा गया। 2009-10 के दौरान (जुलाई तक) पूंजी के प्रवाह में हुए सुधार से बाजार में आपूर्ति की स्थिति में सहजता आने के कारण वायदा प्रीमियमों में सामान्यतः घटने की प्रवृत्ति देखी गई।



II.5.22 सीमा-पार व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट और व्यापक रूप से पूंजी बहिर्वाह दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा बाजार के कुल टर्नओवर में पिछले वर्ष में हुई 86.4 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 1.3 प्रतिशत की कमी आयी (चार्ट II.36 और परिशिष्ट सारणी 39)। विदेशी मुद्रा बाजार के औसत दैनिक टर्नओवर में भी थोड़ी-सी कमी आयी। अंतर बैंक मर्चेट टर्नओवर का अनुपात 2007-08 के 2.5 से बढ़कर 2008-09 में 2.8 हो गया। विदेशी मुद्रा बाजार के कुल टर्नओवर में गिरावट की प्रवृत्ति 2009-10 के अप्रैल-जुलाई में भी जारी रही। मई-जून 2009 में सुधार के लक्षण दिखाई देने के बाद जुलाई 2009 में विदेशी मुद्रा बाजार के दैनिक औसत टर्नओवर में गिरावट के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए।

सरकारी प्रतिभूति (द्वितीयक) बाजार

II.5.23 वैश्विक पण्य मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने और नकद आरक्षित अनुपात और एलएएफ रिपो दर में वृद्धि के रूप में साथ-साथ किये गये मौद्रिक नीतिगत उपायों के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीतिक संभावनाओं के कारण 2008-09 की प्रथम तिमाही में द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों से होनेवाले प्रतिफल में वृद्धि हुई। तत्पश्चात, कच्चे तेल के मूल्यों में आयी कमी से मुद्रास्फीतिक दबावों में कुछ कमी होने से, सितंबर 2008 के मध्य

के आस-पास प्रतिफल में सामान्यतया कुछ कमी आई। तथापि, अग्रिम कर बहिर्वाह होने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रतिकूल गतिविधियों के कारण चलनिधि स्थितियां संख्त हो गयी और सितंबर 2008 का अंत होते-होते प्रतिफल में कुछ बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही में वित्तीय बाजार में मची उथल-पुथल से मुद्रा बाजार पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिये नीतिगत दरों में की गई कमी और पर्याप्त चलनिधि की व्यवस्था से प्रतिफल में तेजी से कमी आई।

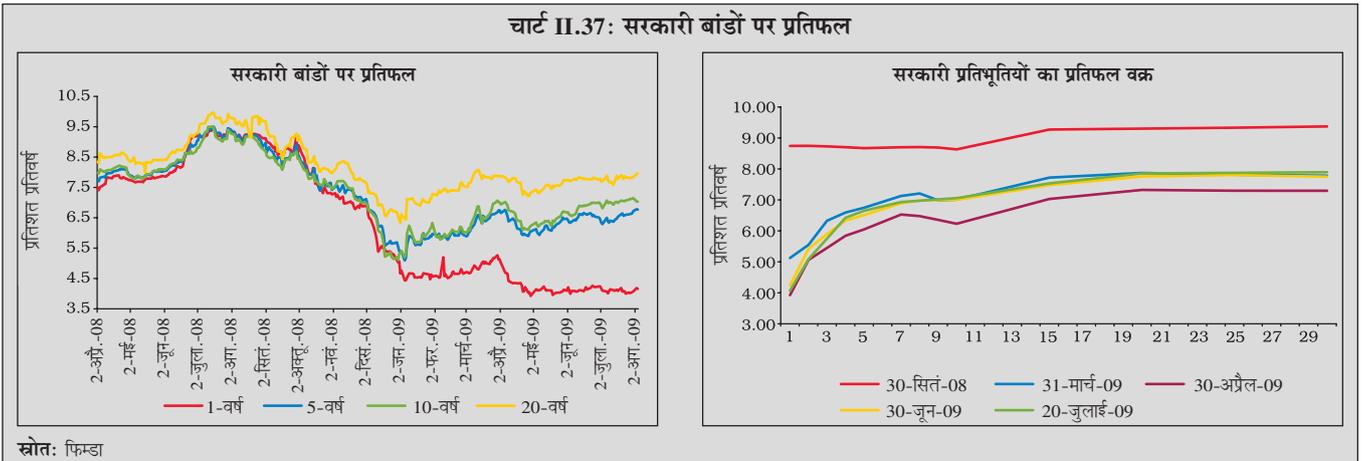
11.5.24 अर्थव्यवस्था को राजकोषीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के चलते बाजार से सरकार के ऋण उठाने के कार्यक्रम में आयी अचानक तेजी और अत्यधिक वृद्धि के कारण जनवरी 2009 में सीआरआर और एलएएफ में और कटौती होने के बावजूद जनवरी और फरवरी 2009 में बाजार के उत्साह में कमी आई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के लिए सरकार की बाजार से बड़ा ऋण उठाने की आवश्यकताओं का भी बाजार पर असर पड़ा। 16 फरवरी 2009 को अंतरिम बजट घोषित होने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम के जरिए दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद के अतिरिक्त सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी आधारित खरीद की श्रृंखला प्रारंभ करने के बावजूद फरवरी 2009 के अंत तक 10 वर्षीय प्रतिलाभ 6.02 प्रतिशत से बढ़कर 12 मार्च 2009 को 6.88 प्रतिशत हो गया, 5 मार्च 2009 से प्रभावी एलएएफ ब्याज दरों में की गई और कटौती का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा (चार्ट II.37)। राज्य सरकारों की बढ़ी हुयी उधारियों ने भी बाजार के उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी आधारित अधिक राशि की खरीद संबंधी इसके बाद की गयी घोषणाओं ने बाजार में उत्साह

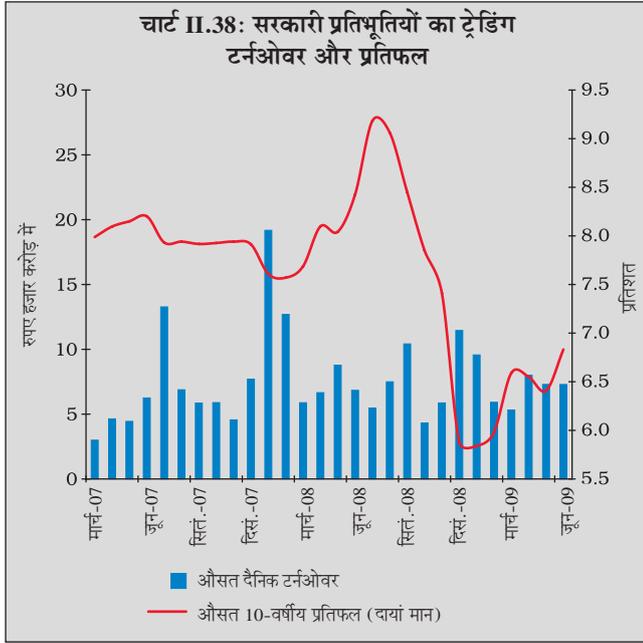
बढ़ाने में सहायता प्रदान की जिससे प्रतिलाभ में गिरावट आई। 26 मार्च 2009 को सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी के कैलेंडर की घोषणा होने पर प्रतिलाभ में पुनः वृद्धि हुई। 2009-10 के प्रारंभिक अवधि में चलनिधि की स्थिति में बेहतर आने, खुला बाजार परिचालन खरीद तथा नीतिगत दरों में कटौती के चलते प्रतिफल में कमी आई; हालांकि, मई के उत्तरार्ध से प्रतिफल में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ।

11.5.25 2008-09 के प्रतिफल वक्र का उतार-चढ़ाव मौद्रिक स्थिति में परिवर्तन तथा उच्चतर सरकारी उधार को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिलाभ वक्र ऊपर होता गया और जुलाई 2008 के अंत तक इसने अपनी उच्चतम सीमा को छू लिया और तत्पश्चात् दिसंबर 2008 के अंत तक यह निरंतर नीचे की ओर झुकता गया, जबकि 2008-09 की अंतिम तिमाही के दौरान यह पुनः बढ़ने लगा (चार्ट II.37)। चलनिधि की स्थिति संतोषजनक होने पर भी 2009-10 की पहली तिमाही में प्रतिफल वक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगा (अप्रैल 2009 को छोड़कर)। पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के कारण अल्पावधि प्रतिफल वक्र में गिरावट आई जबकि उच्चतर सरकारी उधार की चिंताओं के कारण मध्यावधि एवं दीर्घावधि प्रतिफल में वृद्धि हुई।

11.5.26 बाजार अनिश्चितताओं के चलते सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में दैनिक औसत टर्न-ओवर में कुछ उतार-चढ़ाव रहा। रिजर्व बैंक द्वारा डाली गई चलनिधि के प्रभाव और अर्थव्यवस्था में कमजोर ऋण मांग ने मिलकर सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकारी प्रतिभूति की मात्रा बढ़ाने में, विशेष रूप से नवंबर 2008 से अंशतः योगदान किया (चार्ट II.38)।

चार्ट II.37: सरकारी बांडों पर प्रतिफल





ऋण बाजार

11.5.27 अक्टूबर 2008 तक जो बैंक जमा और ऋण दरें सुदृढ़ हो गयी थीं उनमें नवंबर 2008 से कुछ नरमी आयी जो घरेलू ऋण बाजारों पर वैश्विक वित्तीय संकट के बिखरे हुए प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये उपायों को दर्शाता है। मार्च 2008 और मार्च 2009 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सभी प्रकार की परिपक्वता वाली जमा राशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों में कुछ कमी आयी जबकि एक वर्ष से तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों पर निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरों में वृद्धि हुई (सारणी 2.64)। मांग और मीयादी ऋणों पर, निर्यात ऋण को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वास्तविक उधार दरों में मार्च 2008 तथा दिसंबर 2008 के बीच बढ़ोतरी हुई। गिरती हुई नीतिगत दरों और कम होती मुद्रास्फीति के सम्मुख इसने अंतरण तंत्र को जटिल

सारणी 2.64: जमा और उधार दर में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	मार्च 2007	मार्च 2008	सितंबर 2008	दिसंबर 2008	मार्च 2009	अप्रैल 2009	मई 2009	जुलाई 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मीयादी जमा दरें								
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
क) 1 वर्ष तक	2.75-8.75	2.75-8.50	2.75-10.25	2.75-10.25	2.75-8.25	2.50-7.50	2.50-7.50	1.00-7.00
ख) 1 से 3 वर्ष तक	7.25-9.50	8.25-9.25	8.75-10.25	8.50-10.75	8.00-9.25	7.00-8.75	6.50-8.50	6.50-8.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.50-9.50	8.00-9.00	8.50-9.75	8.50-9.75	7.50-9.00	7.25-8.50	7.00-8.50	6.75-8.25
निजी क्षेत्र के बैंक								
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.00	2.50-9.25	3.00-9.75	3.00-10.00	3.00-8.75	2.75-8.50	2.75-8.25	2.00-7.50
ख) 1 से 3 वर्ष तक	6.75-9.75	7.25-9.25	8.30-10.50	9.00-11.00	7.50-10.25	7.50-9.25	7.00-9.00	5.25-8.25
ग) 3 वर्ष से अधिक	7.75-9.60	7.25-9.75	8.25-10.25	8.50-11.00	7.50-9.75	7.50-9.25	7.00-9.00	5.75-8.50
विदेशी बैंक								
क) 1 वर्ष तक	3.00-9.50	2.25-9.25	3.50-9.75	3.50-9.75	2.50-8.50	2.25-8.25	2.25-8.25	1.25-8.00
ख) 1 से 3 वर्ष तक	3.50-9.50	3.50-9.75	3.50-10.50	3.50-11.25	2.50-9.50	2.25-9.00	2.25-9.00	2.25-8.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	4.05-9.50	3.60-9.50	3.60-11.00	3.60-11.00	2.50-10.00	2.25-9.50	2.25-9.50	2.25-9.50
बीपीएलआर								
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12.25-12.75	12.25-13.50	13.75-14.75	12.50-14.00	11.50-14.00	11.50-13.50	11.00-13.50	11.00-13.50
निजी क्षेत्र के बैंक	12.00-16.50	13.00-16.50	13.75-17.75	13.00-17.25	12.75-16.75	12.50-16.75	12.50-16.75	12.50-16.75
विदेशी बैंक	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-16.00	10.00-17.00	10.00-17.00	10.00-17.00	10.00-17.00	10.50-16.00
वास्तविक उधार दर*								
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4.00-17.00	4.00-17.75	6.00-18.75	5.25-18.00	3.50-18.00	-	-	-
निजी क्षेत्र के बैंक	3.15-25.50	4.00-24.00	5.06-23.00	5.06-30.00	4.75-26.00	-	-	-
विदेशी बैंक	5.00-26.50	5.00-28.00	5.00-25.50	5.00-26.00	5.00-25.50	-	-	-
भारित औसत उधार दरें#								
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.81	12.18	-	-	10.99 @	-	-	-
निजी क्षेत्र के बैंक	11.91	12.68	-	-	12.54 @	-	-	-
विदेशी बैंक	13.03	13.05	-	-	10.73 @	-	-	-

* : 2 लाख रुपए से अधिक के निर्यातेतर मांग और मीयादी ऋणों पर ब्याज दर जिसमें दोनों ओर पाँच प्रतिशत की अधिकतम उधार दरें शामिल नहीं हैं।

: 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा पर आधारित आंकड़े जिसमें खरीदे और भुनाए गए देशी और विदेशी बिल शामिल नहीं हैं। औसत उधार दरों की गणना करने के लिए बकाया राशियों को भार के रूप में प्रयोग किया गया है।

@ : आंकड़े अनंतिम हैं और 32,693 शाखाओं पर आधारित हैं।

बना दिया। यद्यपि, अक्टूबर 2008 की शुरुआत से नीतिगत दरों को काफी कम किए जाने पर भी बैंकों की जमा और ऋण दरें, पिछले कुछ महीनों में थोड़ी नरमी आने के बावजूद, उल्लेखनीय रूप से ऊंची बनी रहीं। इस ऊंची दर के लिये कई घटक उत्तरदायी हैं। पहला, लघु जमाराशियों पर ब्याज दर अभी भी नियंत्रित की जा रही है क्योंकि बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर में कमी बैंक जमाराशियों को अपेक्षाकृत अनाकर्षक बना सकती है जिससे बैंक जमाराशियों में होने वाली वृद्धि में कुछ कमी आ सकती है, जैसा कि पहले भी हुआ है। दूसरा, जबकि वृद्धिशील सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर नीचे जा रही है, जमाराशियों की औसत लागत अभी तक ऊंची बनी हुई है क्योंकि पहले बैंकों की अधिकांश सावधि जमाराशियां अधिक ब्याज पर उठाई गयी थीं। इसके फलस्वरूप, यह उधार दरों में तत्काल पर्याप्त कमी करने के लिये बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा, जोखिम विमुखता में वृद्धि होने के चलते गिरती हुयी ऋण मांग वाली अवधि के दौरान भी उधार दरें ऊंची बनी रहती हैं।

II.5.28 वर्ष 2009-10 में अब तक चलनिधि स्थितियों के सहज बने रहने और जोखिमों के कम प्रतीत हो जाने और नीतिगत रियायतों के असर के चलते, जमा और उधार दरों में कटौती कुछ और अधिक मुखर हुयी। सभी बैंक समूहों में एक समान रूप से सावधि जमा दरों और बेंचमार्क प्रमुख उधार दरों (बीपीएलआर) में कमी हुई (सारणी 2.65)।

II.5.29 बीपीएलआर में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर बैंकों द्वारा 125-275 आधार अंकों की और निजी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों द्वारा 100-125 आधार-अंकों की कटौती की गई। तथापि, बीपीएलआर में होने वाला परिवर्तन प्रभावी उधार दरों में होने वाले परिवर्तन को पूर्णतया नहीं दर्शाता है। रिजर्व बैंक के साथ नीति-पूर्व विचार विमर्श के दौरान बैंकों ने संकेत दिया कि केवल बीपीएलआर में कटौती के रूप में उधार दरों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यहां तक कि कृषि, निर्यात क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अच्छी रेटेड कंपनियों को दिए गए तीन चौथाई ऋण बीपीएलआर से कम दर पर दिया जा रहा है। भारत औसत उधार दर वर्ष 2006-07 के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 12.3 प्रतिशत हो गयी परंतु इसके मार्च 2009 तक घटकर 11.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। प्रभावी ऋण दर 2009-10 में अब तक और भी कम होने की प्रत्याशा है।

सारणी 2.65: जमा और उधार दरों में परिवर्तन

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	अक्टूबर 2008	जुलाई 2009 के अंत में	घट-बढ़* (आधार अंक)
1	2	3	4
मीयादी जमा दरें			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	2.75-10.25	1.00-7.00	175-325
ख) 1 से 3 वर्ष तक	9.50-10.75	6.50-8.00	275-300
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.50-9.75	6.75-8.25	150-175
निजी क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	3.00-10.50	2.00-7.50	100-300
ख) 1 से 3 वर्ष तक	9.00-11.00	5.25-8.25	275-375
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.25-11.00	5.75-8.50	250
पांच प्रमुख विदेशी बैंक			
क) 1 वर्ष तक	3.50-9.50	2.25-7.00	125-250
ख) 1 से 3 वर्ष तक	3.60-10.00	2.25-7.00	135-300
ग) 3 वर्ष से अधिक	3.60-10.00	2.25-7.00	135-300
बीपीएलआर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	13.75-14.75	11.00-13.50	125-275
निजी क्षेत्र के बैंक	13.75-17.75	12.50-16.75	100-125
पांच प्रमुख विदेशी बैंक	14.25-16.75	14.25-15.50	0-125

* : अक्टूबर 2008 की तुलना में 31 जुलाई 2009 को घट-बढ़।

इक्विटी और ऋण बाजार

प्राथमिक बाजार

II.5.30 वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय पूंजी बाजार में प्राथमिक निर्गम कमजोर रहे जो दबावयुक्त द्वितीय बाजारों, घरेलू उत्पाद वृद्धि में गिरावट और उससे सम्बद्ध निवेश मांग में संकुचन, भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की सहभागिता में तीव्र गिरावट और वैश्विक संकट के कारण उत्साह में समग्र कमी को दर्शाता है। वैश्विक वित्तीय संकट ने जनवरी 2008 से प्राथमिक बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पूर्व निर्धारित सार्वजनिक निर्गमों को वापस लिया गया, कम अभिदान प्राप्त हुए तथा मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण आबंटन के तत्काल बाद पुनः मूल्यन हेतु नवोन्मेषी प्रयत्न किए गए। मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए प्राथमिक पूंजी बाजार में यही रुझान जारी रहा। द्वितीयक बाजार में अनिश्चितता जैसी स्थितियों की पृष्ठभूमि में कारपोरेट जगत द्वारा संसाधन जुटाने की योजनाओं को टालने के कारण सार्वजनिक निर्गमों, निजी स्थानों, यूरो निर्गमों और म्यूचुअल फंडों के जरिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में तीव्र गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक निर्गमों के औसत आकार कम होने के साथ ही वर्ष 2008-09 के दौरान

सार्वजनिक निर्गमों के जरिए प्राथमिक बाजार से कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जुटाये गये संसाधनों में भी तीव्र संकुचन आया (सारणी 2.66 और परिशिष्ट सारणी 42)।

II.5.31 प्राथमिक बाजार में संसाधन जुटाने की प्रक्रिया दो मुख्य गतिविधियों का खुलासा करती है। पहली यह कि सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थानन दोनों के जरिये निजी क्षेत्र द्वारा जुटाये गये संसाधनों में तीव्र गिरावट आयी। दूसरी यह कि प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के बावजूद निजी स्थाननों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जुटाये गये संसाधनों में कुछ सुदृढ़ता अवश्य दृष्टिगत हुई और संभवतः इस प्रकार के निर्गमों में कम ऋण जोखिम की संभावना इसका मुख्य कारण थी। वर्ष 2008-09 के दौरान

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आइपीओ) की भागीदारी में, निर्गमों की संख्या और संसाधन जुटाने दोनों रूपों में उल्लेखनीय कमी आयी। 2008-09 के 45 आइपीओ में से 21 आइपीओ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किये गये और 20 अधिकार निर्गम (राइट इश्यू) जारी किये गये जो जुटाये गये कुल संसाधनों का क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 81.8 प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किये गये सभी आइपीओ इक्विटी निर्गम स्वरूप के थे। इक्विटी निर्गमों में निजी गैर-वित्तीय कंपनियों का उल्लेखनीय अंश था जबकि वर्ष के दौरान निजी वित्तीय कंपनियों के केवल दो निर्गम आये जो वैश्विक वित्तीय संकट के दूरस्थ प्रभावों के कारण निधियों तक पहुंच बनाने में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के कुछ भागों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को दर्शाता

सारणी 2.66: प्राथमिक बाजार से संसाधनों का संग्रहण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08		2008-09 अ	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
क. प्राप्तेवटस और राइट्स निर्गम*				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	115	63,638	45	14,671
क) वित्तीय	11	14,676	2	466
ख) वित्तेतर	104	48,962	43	14,205
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	4	20,069	-	-
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-
ख) सरकारी कंपनियां	2	2,516	-	-
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	2	17,553	-	-
3. कुल (1+2)	119	83,707	45	14,671
जिसमें से:		(158.5)		(-82.5)
(i) इक्विटी	116	82,398	45	14,671
(ii) उधार	3	1,309	-	-
ख. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	1,616	1,29,677	1,053	93,036
क) वित्तीय	905	88,291	683	60,246
ख) वित्तेतर	711	41,386	370	32,790
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	199	83,048	228	1,09,709
क) वित्तीय	132	56,185	123	64,608
ख) वित्तेतर	67	26,863	105	45,101
3. कुल (1+2)	1,815	2,12,725	1,281	2,02,745
जिसमें से:				
(i) इक्विटी	2	1,410	8	960
(ii) ऋण	1,813	2,11,315	1,273	2,01,785
ग. यूरो निर्गम (एडीआर और जीडीआर)	26	26,556	13	4,788

अ : अनंतिम

* : बिक्री प्रस्तावों को छोड़कर

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और विभिन्न मर्चेन्ट बैंकर।

है। वर्ष 2008-09 के दौरान अंतिम तिथियों में विस्तार और कम अंशदान के चलते कुछ सार्वजनिक निर्गमों को वापस लेने की घटनाओं से भी पूंजी बाजार के प्राथमिक क्षेत्र से संसाधन जुटाने में निहित कठिनाइयां स्पष्ट थीं।

II.5.32 हाल के वर्षों में भारतीय कारपोरेट सेक्टर के लिए निधीयन के एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत के रूप में देशी निजी स्थानन बाजार सामने आया है। प्रतिकूल पूंजी बाजार स्थितियों के कारण वर्ष 2008-09 के दौरान इसमें भी शिथिलता दर्ज की गई। 2008-09 के दौरान निजी स्थाननों के जरिये जुटाए गए संसाधन 2007-08 की तुलना में कम थे। वर्ष 2008-09 में कुल निजी स्थानन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की काफी बड़ी भागीदारी रही (चार्ट II.39)। 2008-09 के दौरान वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में कमी आयी, तथापि गैर-वित्तीय मध्यस्थों ने वृद्धि दर्ज की।

II.5.33 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में चलनिधि की कठिन स्थितियों के चलते यूरो निर्गमों-अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर) और वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) के जरिए भारतीय कारपोरेटों द्वारा जुटाये गये संसाधनों में उल्लेखनीय कमी आयी।

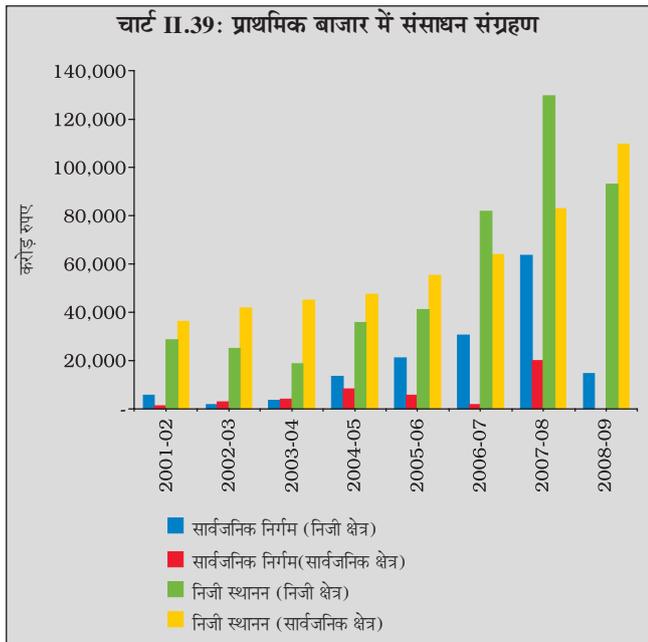
द्वितीयक बाजार

II.5.34 वैश्विक शेयर बाजार की टूटन व्यापक थी तथा आधारभूत संरचनाओं के रूप में देशों के बीच मौजूद अंतरों और

वास्तविक अर्थव्यवस्था पर वित्तीय संकट के प्रभाव की सीमा की परवाह न करते हुये संपूर्ण विश्व में लगभग सभी देशों में शेयर के मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आयी। विकसित देशों में हलचल के व्यापक होते ही बहुत सी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आस्ति मूल्य के बुलबुले का एक अंश बन गयीं। वर्ष 2008-09 के दौरान देशी शेयर बाजार सामान्यतया कमजोर रहा और इसमें हाल के वर्षों की सर्वोच्च क्षमता की उथल-पुथल देखी गयी। 9 मार्च 2009 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स गिरकर 8160 के न्यूनतम स्तर पर आ गया जो 8 जनवरी 2008 की सर्वोत्तम ऊंचाई से 60.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शा रहा था। बाजार पूंजीकरण में तदनुसूची गिरावट 63 प्रतिशत की थी। वर्ष 2008-09 के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स. निफ्टी में क्रमशः 37.9 प्रतिशत और 36.2 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष 2008-09 के दौरान शेयर मूल्यों में आयी गिरावट निरंतर आती नकारात्मक खबरों का प्रभाव परिलक्षित करती है (बॉक्स II.28)।

II.5.35 मार्च 2009 के अंत तक बीएसई के बाजार पूंजीकरण में 39.9 प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखने को मिला जो शेयरों की कीमतों में गिरावट तथा नई प्रतिभूतियों को निम्न मूल्य पर सूचीबद्ध किए जाने की स्थिति का परिचायक है (सारणी 2.67 और परिशिष्ट सारणी 44)। बीएसई सेंसेक्स के मूल्य-अर्जन अनुपात में भी उल्लेखनीय कमी हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान शेयर बाजारों की अस्थिरता में तेज वृद्धि हुई लेकिन उसके साथ-साथ नकदी एवं डेरिवेटिव दोनों खंडों के टर्नओवर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई (परिशिष्ट सारणी 45)।

II.5.36 वर्ष 2008-09 के दौरान देशी शेयर बाजार में हुए घाटे का प्रभाव सभी क्षेत्रों के शेयरों पर पड़ा। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, धातु, पूंजीगत वस्तुओं और बैंकिंग क्षेत्र के सूचकांकों को वर्ष 2008-09 के दौरान बीएसई सेंसेक्स के औसत से भी अधिक घाटा उठाना पड़ा जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, आटो तेल व गैस, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, हेल्थकेयर एवं शीघ्र खपत वाली उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रगत सूचकांकों में तुलनात्मक रूप से कम घाटा हुआ। बीएसई सेंसेक्स के उपर्युक्त पहले समूह को जो उच्चतर घाटा सहना पड़ा उससे आर्थिक गिरावट एवं वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति इन क्षेत्रों की अधिक संवेदनशीलता का पता चलता है। वर्ष 2008-09 के दौरान बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप में उच्चतर घाटा दर्ज किया गया जिसका कारण था आंशिक रूप से इस श्रेणी की कंपनियों के लिए ऋण संकुचन



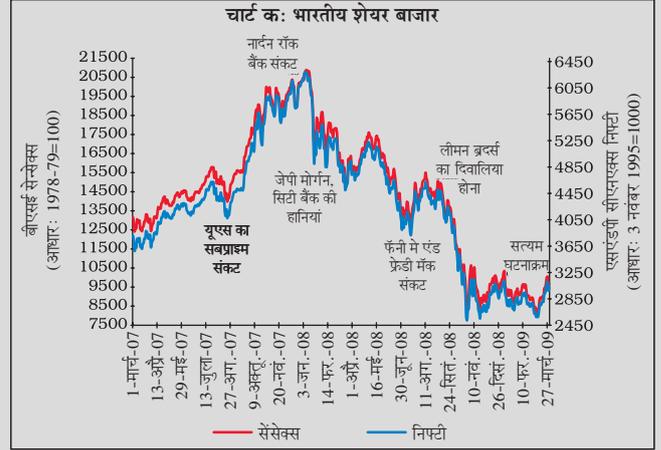
बॉक्स II.28

वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल - भारतीय पूंजी बाजार पर प्रभाव

पूरे विश्व के पूंजी बाजारों में सब-प्राइम संकट की धीरे-धीरे सम्मुख आती गंभीर परिस्थितियों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उनमें तेज गिरावट का दौर देखने को मिला। इसका आस्तित्व संवर्धन पर प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हुआ और जिससे आगे चलकर समग्र मांग में भारी कमी हुई। जहां लाभार्जन की कमजोर पड़ती संभावनाओं एवं डिलीवरेजिंग की वजह से आरंभ में मूल्यों में गिरावट को प्रोत्साहन मिला वहीं आगे चलकर प्रतिकूल प्रत्याशाओं और सतत अनिश्चितता के दौर ने बाजारों में मंदी का रुख बनाए रखा। वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति भारतीय शेयरों के मूल्यों में उल्लेखनीय प्रतिसाद देखने को मिला जो भारतीय शेयर बाजारों के वैश्विक शेयर बाजारों के साथ बढ़ते तादात्म्य का आंशिक परिचायक है। इससे वर्ष 2008-09 के दौरान बीएसई सेंसेक्स का डाउजॉस के साथ 0.13 और एफटीएसई के साथ 0.37 की तुलना में एमएससीआई (उभरते) के साथ 0.63 के उच्चतर सहसंबंध में परिलक्षित होता है। हालांकि सब-प्राइम संकट की शुरुआत वर्ष 2007 के दूसरे भाग में हो चुकी थी लेकिन भारतीय इक्विटी बाजारों पर उसका प्रभाव जनवरी 2008 के आरंभ में ही महसूस किया गया। बीएसई सेंसेक्स ने 8 जनवरी 2008 को तब तक के सर्वोच्च सूचकांक 20873 तक छलांग लगाई लेकिन उसके बाद उसमें तेजी से गिरावट आने लगी। वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की तर्ज पर कमजोरी और अस्थिरता का दौर जारी रहा।

प्रमुख घटनाओं के अनुक्रम में और भारत में शेयरों के मूल्यों पर उनके प्रभाव (चार्ट-क) के अनुसार जुलाई 2008 में जब अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित गारंटीदाता फ़नी मे. एंड फ़ेडी मॅक, जिन्होंने अमेरिकी होम मार्टगेज ऋणों में 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की गारंटी प्रदान की थी, की आस्तियों के उचित मूल्य में तीव्र गिरावट दर्ज हुई तो उसकी वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल और भी गहरी हो गई। 16 जुलाई 2008 को बीएसई सेंसेक्स में 12576 के सूचकांक तक गिरावट दर्ज हुई जो मार्च 2008 के अंत के सूचकांक से 19.6 प्रतिशत कम तथा 8 जनवरी 2008 के सर्वोच्च सूचकांक से 39.8 प्रतिशत कम थी। 15 सितंबर 2008 को जब एक प्रमुख अमेरिकी निवेश बैंक लीमन ब्रदर्स ने दिवालियापन के लिए अर्जी दाखिल की और दूसरे प्रमुख निवेश बैंक मेरिल लिंच को बैंक ऑफ अमरीका में विलय करके बचा लिया गया तथा सबसे बड़े अमेरिकी बीमाकर्ता एआइजी को अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता देकर बचा लिया गया तो उसके बाद शेयरों पर बिकवाली के दबाव के दूसरे दौर के प्रभाव को महसूस किया गया। बीएसई सेंसेक्स 15 सितंबर 2008 को 13531 के निम्नतर अंकों पर बंद हुआ जिसमें पूर्ववर्ती कारोबारी दिन की तुलना में 3.4 प्रतिशत की

गिरावट दर्ज हुई, यह 8 जनवरी 2008 के सर्वोच्च अंक से 35.2 प्रतिशत (चार्ट-क) कम था। बाजार पूंजीकरण में मार्च 2008 की तुलना में 15 सितंबर 2008 को 13.5 प्रतिशत की गिरावट हुई और इसी अवधि के दौरान मूल्य-अर्जन अनुपात भी 20.11 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 16.77 प्रतिशत पर आ गया।



जैसे-जैसे वैश्विक मंदी के रूप में वित्तीय संकट का वास्तविक प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा, बाजार में मंदी का दौर बना रहा और सत्यम में कारपोरेट गवर्नेंस की असफलता की बुरी खबर ने इसमें और भी इजाफा कर दिया। बीएसई सेंसेक्स ने अपने उच्चतम स्तर (8 जनवरी 2008) से 60.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9 मार्च 2009 को एक नए न्यून स्तर को छू लिया। बीएसई सेंसेक्स की अस्थिरता (घट-बढ़ का सहगुणांक) में वृद्धि हुई, बाजार पूंजीकरण में कमी हुई तथा मूल्य/ अर्जन अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई।

इस संकट की वजह से, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा किये गये निवेश से जुड़ी पूंजी का जो बहिर्वाह हुआ उससे भारतीय इक्विटी बाजार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह देखने में आया। विदेशी संस्थागत निवेशकों के बहिर्वाह के कारण भारत के भुगतान संतुलन के प्रति आशंकाएं बढ़ गईं जिसका परिणाम रूप के अवमूल्यन और आरक्षित जमाराशियों में हानि के रूप में परिलक्षित हुआ। सूचीबद्ध कंपनियों की लाभार्जन संभावनाओं के कमजोर पड़ने से बाजार में विश्वास का माहौल डगमगा गया जिससे बाजार सेंटीमेंट को और भी धक्का लगा।

का अत्यधिक प्रभाव और लघु व मध्यम आकार की कंपनियों पर निर्यात में आई मंदी का अत्यधिक प्रभाव (सारणी 2.68)।

II.5.37 वैश्विक डिलीवरेजिंग प्रक्रिया और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर जोखिम टालने की प्रवृत्ति में हुई आम वृद्धि के एक भाग के रूप में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से अपने निवेश राशि की बड़ी मात्रा को वापस निकाल

लिया। सेबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में जहां बड़े पैमाने पर निवल खरीद की वहीं वर्ष 2008-09 के दौरान उनके रुख में परिवर्तन देखने को मिला और उन्होंने इस दौरान निवल बिकवाली पर जोर दिया। वर्ष 2008-09 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में भी गिरावट दर्ज की गई जबकि ऋण प्रतिभूतियों में उनके द्वारा किए गए निवेश

सारणी 2.67: भारतीय शेयर बाजार - प्रमुख संकेतक

Indicator	बीएसई			एनएसई		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
1. बीएसई सेंसेक्स/एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी						
(i) औसत	12277	16569	12366	3572	4897	3731
(ii) वर्ष के अंत में	13072	15644	9709	3822	4735	3021
2. घट-बढ़ का सहगुणांक (प्रतिशत)	11.1	13.7	24.2	10.4	14.4	23.2
3. मूल्य-अर्जन अनुपात@	20.3	20.1	13.7	18.4	20.6	14.3
4. मूल्य-बही मूल्य अनुपात@	5.1	5.2	2.7	4.9	5.1	2.5
5. प्रतिफल@ (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	1.3	1.1	1.8	1.3	1.1	1.9
6. सूचीबद्ध कंपनियां (संख्या)	4,821	4,887	4,929	1,228	1,381	1,432
7. नकदी खंड टर्नओवर (करोड़ रुपए)	9,56,185	15,78,858	11,00,074	19,45,285	35,51,038	27,52,023
8. डेरिवेटिव खंड टर्नओवर (करोड़ रुपए)	59,007	2,42,308	12,268	73,56,242	1,30,90,478	1,10,10,482
9. बाजार पूंजीकरण(करोड़ रुपए)#	35,45,041	51,38,015	30,86,076	33,67,350	48,58,122	28,96,194
10. जीडीपी के प्रति बाजार पूंजीकरण अनुपात (प्रतिशत)	85.5	108.8	58.0	81.6	102.9	54.4

@ : बीएसई सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों पर आधारित और मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार।

: मार्च के अंत की स्थिति।

स्रोत : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमि.(बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमि.(एनएसई)।

में बढ़ोतरी दर्ज की गई क्योंकि सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश में जोखिम कम होती है (सारणी 2.69)।

सारणी 2.68: बीएसई क्षेत्रवार शेयर सूचकांक

(आधार: 1978-79=100)

क्षेत्र	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2009 के अंत में	8 जनवरी 2008 की तुलना में मार्च 2008 के अंत में	8 जनवरी 2008 की तुलना में मार्च 2009 के अंत में
1	2	3	4	5
ऑटो	-7.1	-32.3	-19.1	-45.3
बैंकेक्स	18.0	-41.8	-36.1	-62.8
पूंजीगत वस्तुएं	54.4	-53.8	-30.7	-68.0
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.8	-58.1	-40.9	-75.3
शीघ्र खपत वाली उपभोक्ता वस्तुएं	31.7	-11.1	-8.6	-18.7
हेल्थकेयर	5.4	-26.5	-10.4	-34.1
सूचना प्रौद्योगिकी	-27.6	-35.6	-16.4	-46.2
धातु	65.2	-58.7	-28.2	-70.3
तेल एवं गैस	56.0	-29.6	-28.7	-49.8
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	25.4	-29.6	-31.2	-51.6
बीएसई 500	24.3	-42.8	-30.0	-60.0
बीएसई सेंसेक्स	19.7	-37.9	-25.1	-53.5
बीएसई मिड कैप	19.4	-54.0	-34.5	-69.9
बीएसई स्मॉल कैप	21.2	-58.6	-42.0	-76.0

स्रोत : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमि. (बीएसई)

11.5.38 वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के अनुरूप देशी शेयर बाजारों में सुधार का रुख देखने को मिला और आम चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही इस सुधार प्रक्रिया में और भी तेजी आ गई। इस सुधार प्रक्रिया में कई सकारात्मक घटनाक्रमों का योगदान रहा जैसे कि अप्रैल 2009 में नीतिगत दरों में कटौती, वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के दौरान कुछ भारतीय बैंकों और कारपोरेटों के सकारात्मक परिणाम, चुनाव बाद की अवधि में राजनैतिक स्थिरता में हुआ इजाफा और 2009-10 के केंद्रीय बजट में अधिक प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा तथा देशी शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि का फिर से जागृत होना। 17 अगस्त 2009 को बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी

सारणी 2.69: संस्थागत निवेश की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी संस्थागत निवेशक		म्यूचुअल फंड	
	इक्विटी में निवल निवेश	ऋण में निवल निवेश	इक्विटी में निवल निवेश	ऋण में निवल निवेश
1	2	3	4	5
2003-04	43,631	5,534	1,308	22,701
2004-05	40,991	1,927	448	16,987
2005-06	48,487	-7,334	14,302	36,801
2006-07	26,031	5,881	9,062	52,543
2007-08	52,574	12,499	15,775	73,790
2008-09	-48,248	1,866	6,985	81,803

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

सीएनएक्स निफ्टी दोनों में मार्च 2009 के अंत की तुलना में क्रमशः 52.3 प्रतिशत तथा 45.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

11.5.39 वर्ष 2008-09 के दौरान एनएसई के थोक ऋण बाजार खंड की गतिविधियों में सुधार हुआ और टर्नओवर में 19.0 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

म्यूचुअल फंड

11.5.40 वैश्विक चलनिधि में हुए संकुचन के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकों और कारपोरेटों ने यह महसूस किया कि उनके वित्तपोषण का विदेशी जरिया समाप्त हो चला है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी ऋण मांगों को पूरा करने के लिए देशी बैंकिंग क्षेत्र का रुख करना पड़ा। इसके साथ ही, ऐवजी वित्तपोषण का जरिया तलाशने के अपने अथक प्रयास में कारपोरेटों ने देशी मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों से अपने निवेशों को निकालना शुरू कर दिया जिससे म्यूचुअल फंडों पर मोचन (रिडेंप्शन) का दबाव बढ़ा और इसने उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रभावित किया जहां उन्होंने अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया था। म्यूचुअल फंडों के संग्रहण का एक प्रमुख हिस्सा मुद्रा बाजार योजना के तहत कारपोरेट क्षेत्र से प्राप्त थोक निधियों को दर्शाता है जो अंशतः कर एवं अन्य विनियामक आर्बिट्रेज को दर्शाता है। म्यूचुअल फंडों ने जहां तत्काल मोचन के वादे किए वहीं सापेक्षतया उनकी आस्तियों में तरलता का अभाव था। म्यूचुअल फंडों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वताओं में विद्यमान असंतुलन ने समस्या में और इजाफा कर दिया। जून, सितंबर और अक्टूबर 2008 में शेयर बाजार में अनिश्चितता के माहौल और बैंकों तथा कारपोरेट इकाइयों द्वारा मोचन के लिए पड़ते दबाव की वजह से म्यूचुअल फंडों से बड़ी मात्रा में निधियों को निकाल लिया गया। म्यूचुअल फंडों द्वारा प्रबंधित निवल आस्तियों में भी वर्ष 2008-09 के दौरान 17.4 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 2.70)। तब रिजर्व बैंक ने तत्काल ही म्यूचुअल फंडों को बैंकों के माध्यम से चलनिधि उपलब्ध कराने की घोषणा की। चलनिधि की समग्र स्थिति में सुधार होते ही म्यूचुअल फंडों में निवेश फिर से आकर्षक बन गया (बॉक्स II.29)। नवंबर 2008 फरवरी 2009 के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण में सकारात्मक रुख देखने को मिला लेकिन मार्च 2009 के दौरान इनकी निधियों में पर्याप्त बहिर्वाह होने से स्थिति में प्रतिकूल बदलाव आया।

11.5.41 योजनाओं की संख्या और म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन जुटाने, दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गयी (सारणी 2.71)।

सारणी 2.70: म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	2007-08		2008-09अ	
	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां #	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां#
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र	1,33,304	4,15,621	-34,018	3,35,527
सार्वजनिक क्षेत्र *	20,497	89,531	5,721	81,772
कुल	1,53,801	5,05,152	-28,297	4,17,299

अ : अर्न्तम

@ : मोचनों को घटाकर

: अवधि के अंत में

* : यूटीआइ म्यूचुअल फंड सहित।

टिप्पणी : निधियों की निधि योजना के तहत संगृहीत निधियों के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

11.5.42 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों तरह के संसाधन जुटा सकती हैं, बशर्ते उनके अद्यतन लेखाकृत तुलनपत्र के अनुसार किसी एक समय पर उनकी कुल बकाया राशि उनकी निवल धारित निधियों के 10 गुना से अधिक न हो। इस समग्र सीमा के भीतर चार वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् एक्जिम बैंक, सिडबी, आवास बैंक और नाबार्ड को मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, अंतर-कारपोरेट जामाराशियों, जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों जैसे लिखतों के माध्यम से उनकी अपनी निवल धारित निधियों के 100 प्रतिशत के बराबर संसाधन जुटाने की समग्र सीमा प्रदान की गई। एक्जिम बैंक और आवास बैंक के मामले में क्रमशः दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 से इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया है। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने की समग्र सीमा बढ़कर 31 मार्च 2009 को 26,292 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जुटाए गए बकाया संसाधनों में वर्ष 2008-09 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई।

11.5.43 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड एवं डिबेंचरों के रूप में जुटाए गए कुल संसाधनों में वर्ष 2008-09 के दौरान 54.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (सारणी 2.72, परिशिष्ट सारणी 46)। यह प्रमुख रूप से वित्तीय बाजार की उन प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके कारण अधिकतर वित्तीय संस्थाएं देशी पूंजी बाजार में सहभागिता से दूर ही रहीं।

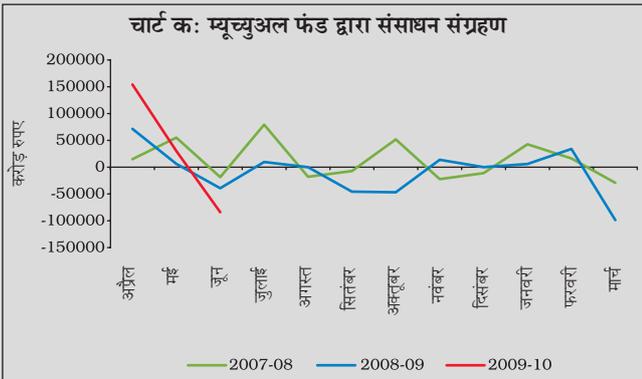
11.5.44 सार रूप में कहा जा सकता है कि वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न प्रतिकूल विश्वास के चैनल ने व्यापार और वित्त चैनलों

बॉक्स II.29

भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग - वर्तमान मुद्दे

शेयर की कीमतों में लगातार आती गिरावट के दौर में लघु और खुदरा निवेशकों की वित्तीय बचतों के गिरते मूल्यों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूंजी बाजार में इन निवेशकों का डगमगाता विश्वास ऐसे कारक थे जिनसे भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग जगत में चिंता की लहर दौड़ गई। भारत में वर्ष 1963 में भारत सरकार और रिजर्व बैंक की पहल पर स्थापित किए गए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड उद्योग ने एक लंबा सफर तय किया है। वर्ष 1987-1993 के बीच इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे कि सरकार के स्वामित्ववाले बैंक, जीवन बीमा कंपनियों और साधारण बीमा निगम तथा वर्ष 1993 में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। भारत के नीति निर्माताओं ने लगभग एक दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने, शेयर संस्कृति को विकसित करने और एक गहन तथा चलनिधि की प्रचुरतावाले पूंजी बाजार के विकास के लिए म्यूचुअल फंडों को खुदरा एवं छोटे निवेशकों द्वारा निवेश करने का एक सुरक्षित जरिया बनाने के प्रयास जारी रखे। इस उद्योग को करों में राहत के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए ताकि इस उद्योग का विस्तार हो और पूंजी बाजार में इसकी महत्ता में भी इजाफा हो।

वर्ष-दर-वर्ष आस्तियों में हो रही वृद्धि को देखते हुए म्यूचुअल फंडों की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्ष 2004-07 के दौरान शेयर बाजारों में छाप अनुकूल माहौल ने निधियों के नए निवेशों को अपनी ओर आकर्षित किया। तथापि वर्ष 2008-09 के पहले आठ माह के दौरान चलनिधि की कठोर स्थिति और शेयर बाजारों में आई गिरावट के साथ ही म्यूचुअल फंड उद्योग को अभूतपूर्व दबाव से गुजरना पड़ा जिसके लिए उत्तरदायी कारक थे - अग्रिम करों का बहिर्वाह, विदेशी ऋण बाजारों पर ठहराव आ जाने की वजह से आपूर्तिकर्ताओं के ऋणों को हटा लिया जाना तथा मुद्रा बाजार चलनिधि का सूख जाना। विशेष रूप से, जून, सितंबर, अक्टूबर 2008 और मार्च 2009 माह के दौरान निवल संसाधन संग्रहण में गिरावट प्रखर रूप से देखने को मिली (चार्ट-क)।



रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों को बैंकों के माध्यम से चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2008 में कई त्वरित उपायों की घोषणा की। म्यूचुअल फंडों की नकदी स्थिति पर कोई प्रभाव डाले बिना मोचन में उनकी सहायता करने के लिए सेबी ने यह घोषणा की कि 12 दिसंबर 2008 को या उसके बाद आरंभ की जानेवाली सभी नियतकालिक योजनाओं (इक्विटी सम्बद्ध बचत योजनाओं को छोड़कर) के लिए यूनिटों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दिनांक 19 जनवरी 2009 के सेबी के परिपत्र के अनुसार तरल योजनाओं के संविभाग में शामिल प्रतिभूतियों की अवधि को कम कर दिया गया। राजकोषीय मौद्रिक प्रेरक

उपायों के साथ-साथ इन उपायों ने समग्र चलनिधि की स्थिति को सुधारने में मदद की जिससे म्यूचुअल फंड उद्योग भी वैश्विक स्तर पर चल रही वित्तीय उथल-पुथल से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में अपने आपको समर्थ बनाने में सफल हो सका। तथापि कुछ प्रणालीगत मुद्दे उभरकर सामने आए हैं जो इस उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही मायने रखते हैं।

हाल के वर्षों में भारत में म्यूचुअल फंडों के प्रबंधन के तहत योजनाओं की संख्या और आस्तियों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद अन्य देशों की तुलना में उनकी पैट का दायरा सीमित ही है। इसका पता उनके द्वारा प्रबंधित आस्तियों के छोटे आकार (जो जीडीपी के 5 प्रतिशत से भी कम है जबकि अमरीका में यह 70 प्रतिशत और फ्रांस में 61 प्रतिशत तथा ब्राजील में 37 प्रतिशत है) तथा म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में घरेलू बचत के छोटे अंश को देखकर चलता है। आरएनसीओएस द्वारा हाल ही में प्रकाशित शोध रिपोर्ट ‘‘इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री’’ के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इस उद्योग में वर्ष 2015 तक आस्ति का आकार बढ़कर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। वृद्धि की अपार संभावनाओं के बावजूद जानकारी के अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्र की सीमित सहभागिता इसकी प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है।

यद्यपि हाल के वर्षों में इक्विटी आधारित योजनाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथापि अभी भी यह इस उद्योग की आस्तियों के 25 प्रतिशत के भी कम है। म्यूचुअल फंडों में लगाई गई अधिकतर निधियां चलनिधि/मुद्रा बाजार योजनाओं के माध्यम से जुटाई जा रही हैं जो कि कारपोरेट इकाइयों एवं बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए लघु अवधि संभावनाओं वाला धन विनिवेश का एक आकर्षक जरिया है। निधि के लिए कारपोरेटों पर बड़े पैमाने पर निर्भरता का तात्पर्य खुदरा निवेशकों की भूमिका का अर्थहीन हो जाना है। इसके अलावा इसकी वजह से इन फंडों में उथल-पुथल की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं क्योंकि कारपोरेट और अन्य संस्थागत निवेशक अल्प सूचना पर कभी भी अपनी निधियां आहरित कर सकते हैं। इन फंडों को एक सुरक्षित घेरे में लाने के लिए योजनाओं को संस्थागत और खुदरा के रूप में अलग-अलग करने के प्रयास भी अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं और अब सेबी कारपोरेट निवेशकों के लिए अधिक विस्तृत प्रकटीकरण मानकों को तैयार कर रही है।

योजनाओं के प्रकारों की बहुलता (1000 से 5000 प्रकार) से निवेशकों में संभ्रम पैदा होता है। पिछले कुछ माह के दौरान चार लाख से अधिक सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) खाते बंद हो चुके हैं। अनुमोदित योजनाओं की संख्या को निवल धारित निधियों के साथ जोड़कर इस उद्योग में कुछ हद तक समेकन को प्रभावी किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा सब प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा स्थावर संपदा फर्मों के ऋण पत्रों में निवेश पर कुछ शंकाएं व्यक्त की जा रही थीं तथापि सेबी ने स्थावर संपदा के म्यूचुअल फंडों के लिए विस्तृत विनियम जारी किए जिसके अधीन म्यूचुअल फंडों को स्थावर संपदा की आस्तियों अथवा अन्य अनुमोदित आस्तियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

संदर्भ:

1. जी.सेतु (2006), ‘‘गवर्नेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एवं दि इंस्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्टीज’’, इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 15 अप्रैल.
2. एस.एस.तारापोर (2009), ‘‘म्यूचुअल फंड्स नीड फॉर रिफॉर्म्स’’ बिजनेस लाइन में संपादकीय, 10 अप्रैल.

सारणी 2.71: म्यूच्युअल फंडों द्वारा निधियों का संग्रहण - स्कीमों के प्रकार

(राशि करोड़ रूप में)

स्कीम	2007-08			2008-09 अ		
	स्कीमों की संख्या	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां*	स्कीमों की संख्या	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां*
1	2	3	4	5	6	7
क. आय/ऋण उन्मुख योजनाएं	593	1,03,867	3,12,997	599	-32,161	2,94,349
(i) चलनिधि/मुद्रा बाजार	58	14,976	89,402	56	-3,599	90,594
(ii) गिल्ट	30	434	2,833	34	3,606	6,413
(iii) ऋण (निश्चित प्रतिफल से इतर)	505	88,457	2,20,762	509	-32,168	1,97,343
(iv) ऋण (निश्चित प्रतिफल)	0	0	0	0	0	0
ख. वृद्धि/इक्विटी उन्मुख योजनाएं	313	46,933	1,72,742	340	4,024	1,08,244
(i) इक्विटी सम्बद्ध बचत स्कीमें	43	6,151	16,020	47	2,969	12,428
(ii) अन्य	270	40,782	1,56,722	293	1,055	95,816
ग. संतुलित योजनाएं	37	5,768	16,283	35	61	10,629
घ. एक्सचेंज में ट्रेड की जाने वाली निधि +	13	-2,767	3,130	17	-998	1,396
(i) स्वर्ण ईटीएफ	5	276	483	5	84	736
(ii) अन्य ईटीएफ	8	-3,043	2,647	12	-1,083	660
ड. निधियों की निधि योजना	37	1,162	3,742	10	778	2,681
च. कुल #	956	1,53,801	5,05,152	1001	-28,296	4,17,300

* : मार्च के अंत में।

: कुल योग में निधियों की निधि स्कीम शामिल नहीं हैं।

अ : अनंतिम

+ : एक्सचेंज में ट्रेड की जाने वाली निधियां सबसे पहले दिनांक 24 जनवरी 2006 के सेबी के परिपत्र सं.आइएमडी/सीआइआर सं.4158422/06 द्वारा आरंभ की गई थीं।

ध्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड।

के प्रभावों को अत्यधिक बढ़ा दिया जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आस्ति कीमतों में तीव्र गिरावट आई और काफी उतार-चढ़ाव देखने में आया। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धि

की संभावनाएं कमजोर हुईं और परिणामतः वित्तीय बाजारों के लिए मंदी तथा उथल पुथल वाला दौर और लंबा खिंच गया। सितंबर 2008 तक संकट का सामना करने की सामर्थ्य दिखानेवाली

सारणी 2.72: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड/डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन

(करोड़ रूप में)

संस्था	जुटाए गए संसाधन		बकाया उधारी		निधियों की भारत औसत लागत (प्रतिशत)		भारत औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2007-08	2008-09	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्विजि बैंक	3,555	2592	11,871	11950	8.11	8.74	4.09	4.09
सिडबी	5,415	1,353	6.84	8.56	3.88	7.29
नाबार्ड	13,620	4,251	32,630	23,704	9.50	9.16	3.95	7.09
राष्ट्रीय आवास बैंक	..	1,063	7,262	4,001	..	8.94	..	6.65
जोड़	17,175	7,906	57,178	41,008

.. : शून्य/लागू नहीं

टिप्पणी : 1. आंकड़े केवल रुपया संसाधनों से संबंधित हैं।

2. जुटाए गए संसाधनों के आंकड़ों में बांड/डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए दीर्घकालीन संसाधनों में; वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों, अन्तर कार्पोरेट जमाराशियों, मीयादी जमाराशियों और मीयादी मुद्रा के माध्यम से जुटाए गए अल्पकालीन संसाधनों का समावेश है।

3. आंकड़े अनंतिम हैं।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी इससे अछूती न रह सकीं और वे 2008 की अन्तिम तिमाही में दबाव में आ गईं। इसका प्रमुख कारण वित्तीय इकाइयों द्वारा अपने मूल देश में पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर डिलीवरेजिंग का सहारा लिया जाना और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के प्रति समग्र जोखिम का बढ़ जाना था। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों को निवेश संविभाग के प्रवाह की प्रतिकूलता, बैंक ऋणों में आई गिरावट और क्रेडिट स्प्रेड की तीव्र वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ा। तथापि इन अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय संस्थाओं में उन्नत अर्थव्यवस्था की संस्थाओं के समान भंगुरता और दबाव की व्यापकता नहीं दिखाई दी। 2009-10 की दूसरी तिमाही तक व्यापक सार्वजनिक नीति के चलते वित्तीय बाजारों में थोड़ी-सी स्थिरता दिखाई दी, तथापि, वित्तीय बाजार के कुछ खंड अभी भी संवेदनशील हालत में हैं।

11.5.45 अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समान यद्यपि भारत के वित्तीय बाजारों पर सितंबर 2008 तक बंधक (मोर्टगेज) संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ने पाया लेकिन लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने और एफआइआइ द्वारा बिकवाली के कारण निवल पूंजी अंतर्वाह में आई गिरावट की वजह से भारतीय वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों, विशेषकर विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजार पर दबाव पड़ा। रिजर्व बैंक ने देशी और विदेशी मुद्रा चलनिधि में वृद्धि के लिए कई परंपरागत और गैर परंपरागत उपायों को अपनाया। रिजर्व बैंक और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सभी उपाय बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए गए फिर चाहे वह चलनिधि की समस्या से निपटना रहा हो या म्यूच्युअल फंडों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों की मोचन (रिडेंप्शन) जरूरतों को पूरा करना रहा हो। मौद्रिक संप्रेषण की कमजोरियां एक मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आईं क्योंकि नीति दरों की प्रतिक्रिया स्वरूप बाजार ब्याज दरों में होनेवाला समायोजन धीमी गति से और एक अंतराल के बाद देखने को मिला। भारत में वित्तीय बाजार के विविध खंडों पर मौद्रिक संप्रेषण का अलग-अलग प्रभाव परिलक्षित होता है। मुद्रा और बांड बाजार पर जहां इस संप्रेषण का प्रभाव तेजी से हुआ वहीं कई प्रकार की संरचनागत सख्तियों के कारण ऋण बाजार पर इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से धीमा रहा। समग्र रूप से, हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न हुए आघातों से शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर आस्तियों के मूल्य में कमी आने के अलावा देशी मुद्रा बाजार और विदेशी

मुद्रा बाजारों में चलनिधि की समस्या उभरी लेकिन इसके बावजूद उक्त दबाव का प्रभाव आम तौर पर अस्थायी रहा और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों के कारण उसका शीघ्रता से तथा पर्याप्त रूप से सहज ही सामना किया जा सका। वित्तीय संकट की चरम अवस्था के दौरान भी भारतीय बाजारों ने सामान्य रूप से कार्य किया तथा बाजारों में जो अत्यधिक उतार-चढ़ाव आए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए समुचित नीतिगत उपायों से नवंबर 2008 तक नियंत्रित कर लिया गया। जोखिम विमुखता की आम प्रवृत्ति के चलते क्रेडिट बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई। जोखिम तथा उतार-चढ़ाव में कमी आने के कारण 2009-10 की पहली तिमाही में बाजार की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि स्प्रेड में कमी आने के साथ-साथ बाजार की गतिविधियों में तेजी आ गई थी। सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में उधार लेने से उत्पन्न चिंता को दर्शाते हुए 2009-10 की पहली तिमाही में बांडों के प्रतिफल, विशेष रूप से मध्यावधि तथा दीर्घावधि परिपक्वता वाले बांडों के प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतकों एवं घरेलू गतिविधियों की पृष्ठभूमि में इक्विटी बाजारों में उल्लेखनीय लाभ दर्ज किया गया जिससे आगे चलकर निवेश मांग में बढ़ोतरी होते ही प्राथमिक इक्विटी बाजारों की बहाली में सहायता मिल सकती है।

VI. बाह्य क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

11.6.1 2008-09 के दौरान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार की स्थिति अभूतपूर्व रूप से बिगड़ गई जिसने न केवल उन्नत अर्थव्यवस्थाओं बल्कि भारत सहित सभी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए एक ऐसा आघात दिया जो गंभीरतम आघातों में से एक था। देश के वैश्वीकरण का स्तर तथा देशी नीतिगत परिवेश की सुदृढ़ता चाहे जैसी भी रही हो, उन्नत देशों में गहराते संकट ने, संक्रमण के संप्रेषण के विशिष्ट चैनलों में समय के साथ गति तथा तीव्रता में वृद्धि के साथ, एक साथ घटित होने वाले वैश्विक संकुचन का रूप धारण कर लिया। 'नकारात्मक फ्रीडबैक चक्र' ने हर क्षेत्र को संदूषित कर दिया और दुनिया भर के देशों द्वारा तैयार और लागू किए गए नीतिगत प्रोत्साहन के बड़े खुराक भी निम्नगामी प्रवृत्ति को रोकने में लगभग बेअसर रहे, जिससे संकट की जटिल प्रकृति तथा विशाल आयाम का पता चलता है।

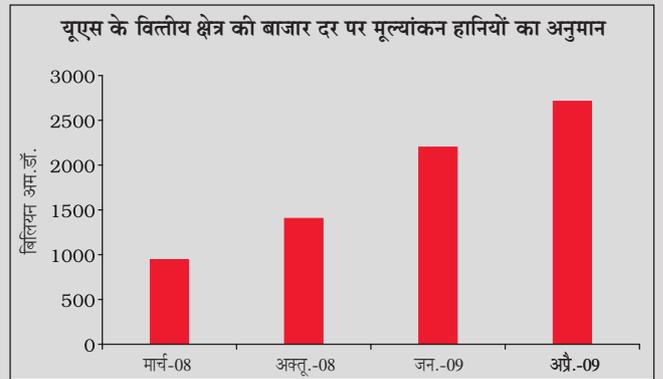
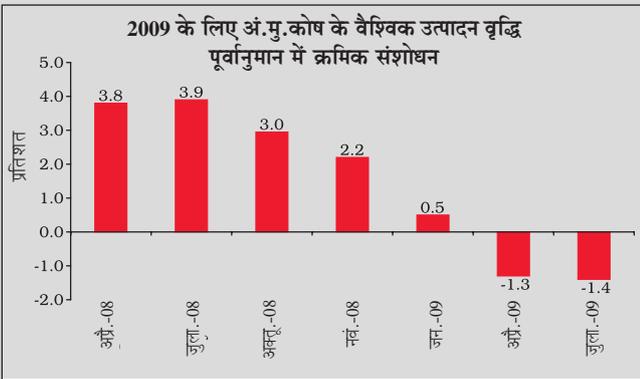
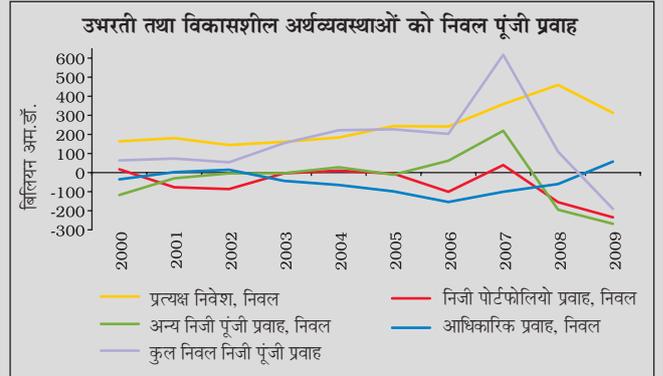
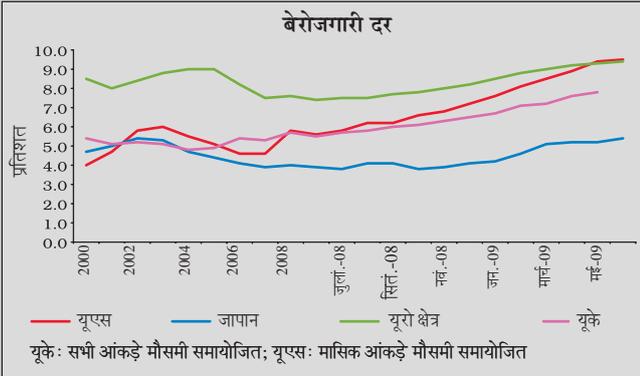
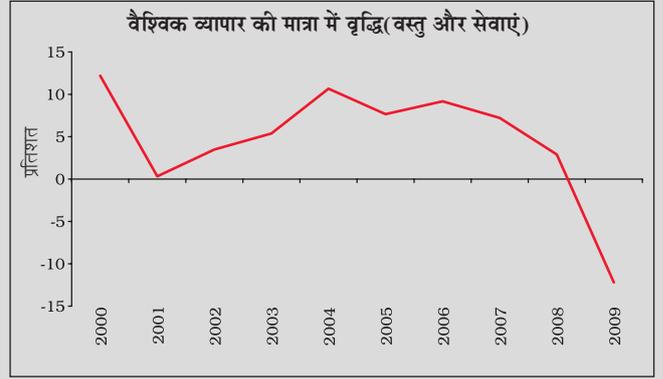
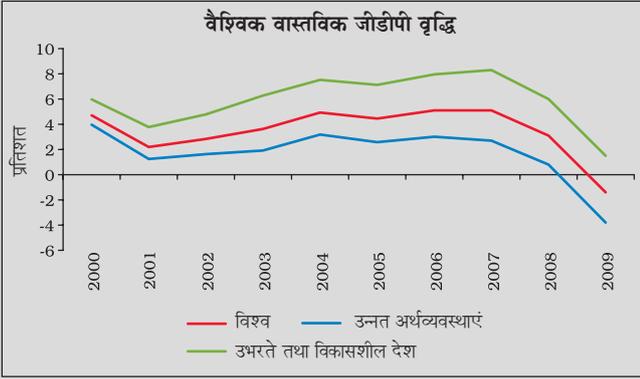
II.6.2 2007 की दूसरी छमाही में यूएस के आवास बंधक बाजार से उत्पन्न सबप्राइम संकट के तेजी से वैश्विक वित्तीय संकट का रूप धारण कर लेने से वर्ष 2008 के दौरान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया जिसके कारण बड़ी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं या तो विफल हो गईं अथवा विफल होने से बचाने के लिए उनका पुनर्गठन किया गया। वित्तीय संकट के फैलने पर, समय के साथ वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा जिसने कुछ प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इस संकट का बहुआयामी प्रभाव, अत्यंत गंभीर डिलीवरेजिंग, जोखिम विमुखता के चरम स्तर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती हानियों, पण्यों के मूल्यों में उनके उच्चतम स्तर से तेजी से गिरावट तथा आस्तियों के मूल्यों में तेज गिरावट के रूप में पड़ा और इन सभी ने पूंजी के प्रवाह में बड़ी मात्रा में कमी लाने के अतिरिक्त वृद्धि तथा व्यापार के प्रवाह में तेजी से गिरावट लाने और बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य किया (चार्ट II.40)। बड़ी वित्तीय संस्थाओं की डिलीवरेजिंग, बाजार के हालात के कारण उनके तुलन-पत्र के आस्तिक पक्ष में आए संकुचन के दबाव तथा बढ़ती हानियों के फलस्वरूप पूंजी की अपर्याप्तता के कारण, अव्यवस्थित थी। इस डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया ने अल्पावधि निधीयन बाजारों में भारी व्यवधान पैदा किया जैसा कि बाजार में पहुंच की कठिनाई तथा बढ़ते जोखिम स्प्रेड से परिलक्षित होता है। संकट के दौरान आस्तियों के मूल्यों में तेजी से कमी आने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियां भी दबाव में आ गईं। जहां पेंशन निधियों की आस्तियों के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई, वहीं जीवन बीमा कंपनियों को अपनी इक्विटी और कारपोरेट बांड धारिताओं पर हानि उठानी पड़ी। आस्तियों के मूल्य में तेजी से कमी आने के कारण वित्तीय स्थिति में अत्यधिक गिरावट आने से कंपनी तथा घरेलू इकाइयों दोनों की आर्थिक स्थिति पर भारी प्रतिकूल असर पड़ा और रोजगार की बिगड़ती स्थिति ने इसे और गंभीर बना दिया। इसके कारण उपभोक्ता के विश्वास में कमी आने के साथ-साथ उपभोग मांग में गिरावट आई, साथ ही इसने कंपनियों के संपार्श्विकों के मूल्य में गिरावट लाने तथा संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता में कमी लाने का कार्य किया। इस प्रकार, वित्तीय संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वित्तीय, व्यापार तथा विश्वास चैनलों के माध्यम से क्रमिक प्रभाव पड़ा। वृद्धि के परिदृश्य में गिरावट की गति इस प्रकार तेज थी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को वर्ष 2009 के लिए अपने वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान की दर में बार-बार कमी करनी पड़ी, अर्थात् अप्रैल

2008 की 3.8 प्रतिशत कुछ अच्छी दर को कम करके जुलाई 2009 में (-)1.4 प्रतिशत करना पड़ा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे गंभीर मंदी है (आइएमएफ, 2009)। जहां प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में चली गईं, वहीं 2008 के प्रारंभिक समय तक असंबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखी जा रही ईएमई की वृद्धि दर में भी उल्लेखनीय कमी आई।

II.6.3 तीव्रता के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वित्त के जरिए वैश्विक एकीकरण के उच्चतर स्तर के कारण वैश्विक मंदी भी अधिक व्यापक थी तथा यह विभिन्न देशों में एक साथ फैली। यहां तक कि सुदृढ़ समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय पूर्व-शर्त वाली उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी 2008 के उत्तरार्ध में फैले वित्तीय संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुईं और यह संक्रमण गिरते निर्यात तथा सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में कमी आने तथा विश्व भर में व्यापार वित्त की उपलब्धता कम होने से वास्तविक क्षेत्र में फैल गया था। इस प्रकार, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की असंबद्धता (डिकपलिंग) की धारणा, जिसे 2008 तक मान्यता प्राप्त थी, संकट के गहराने और देशों के बीच तेज गति से इसके फैलने से गलत साबित हुई (बॉक्स II.31)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में संकट के प्रतिकूल असर का सम्प्रेषण वित्तीय तथा व्यापार चैनलों के माध्यम से हुआ, विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों में जो विनिर्माण निर्यातों पर अत्यधिक आश्रित थे, तथा उभरते यूरोपीय तथा राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देश (सीआइएस) अर्थव्यवस्थाओं में, जो वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु पूंजी के अंतर्वाह पर अत्यधिक आश्रित थे। दक्षिण अमरीका, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका में गिरते पण्य मूल्यों तथा कमजोर निर्यात मांग का असर पड़ा। यद्यपि, उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की, समूह के रूप में वृद्धि दर में 2009 में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है, तथापि गिरती निर्यात मांग, पण्यों के कम मूल्य तथा जटिल वित्तीय बाधाओं के कारण कई देशों में वास्तविक जीडीपी कम होने की संभावना है।

II.6.4 वैश्विक वित्तीय संकट का असर सभी देशों में बड़ी वित्तीय संस्थाओं के पूंजी आधार में भारी गिरावट के रूप में हुआ। आइएमएफ की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (अप्रैल 2009) में यूएस में प्रवर्तित आस्तियों के सभी धारकों द्वारा उठायी जाने वाली संभावित हानि की राशि वृद्धि के बिगड़ते परिदृश्य के परिणामस्वरूप संकट के प्रारंभ से 2010 तक की अवधि में शुरू में आकलित 945 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2.7 ट्रिलियन

चार्ट II.40: प्रमुख वैश्विक संकेतक



स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य डेटाबेस तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अं.मु.कोष; संबंधित देश की वेबसाइट से आधिकारिक आंकड़े।

अमरीकी डॉलर हो जाने का अनुमान है (देखें चार्ट II.40)। अन्य आस्तियों पर भी होने वाली हानियों के अनुमान को शामिल करके, हालांकि यह अनिश्चित ही है, यह राशि 4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास हो सकती है, जिसमें से दो-तिहाई हिस्सा बैंकों द्वारा उठायी जाएगी।

II.6.5 वैश्विक व्यापार में वृद्धि की दर 2007 में 7.2 प्रतिशत से घटकर 2008 में 2.9 प्रतिशत हो जाने से व्यापार चैनल के महत्व का पता चलता है तथा आइएमएफ के अद्यतन पूर्वानुमान के अनुसार 2009 में इसमें 12.2 प्रतिशत की कमी होने की संभावना

है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) (2009) के अनुमान के अनुसार 2009 में मात्रात्मक रूप में वैश्विक निर्यात में 10.0 प्रतिशत की कमी हो सकती है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखी गई सबसे अधिक कमी है।

II.6.6 वित्तीय चैनल के माध्यम से आघातों का सम्प्रेषण सुरक्षा की खोज तथा देशी कारोबार की प्रधानता, डिलीवरेजिंग की बाध्यता, जिसने विश्व भर में बिक्री के लिए दबाव बनाया, के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक वृद्धि दर में संकुचन के अनुमान के अनुरूप 2009 में निजी पूंजी प्रवाह में कमी आने की संभावना है।

बॉक्स II.30

वैश्वीकरण तथा वैश्विक वृद्धि की प्रवृत्ति: असंबद्धता के मुद्दे

जब उन्नत देशों में वित्तीय संकट प्रारंभ हुआ अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तात्कालीन चिंता यह थी की अपने देश में वित्तीय स्थिरता को किस प्रकार बनाये रखा जाए। जैसा कि बाद में स्पष्ट हुआ, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणाली, विशेषरूप से भारत की, विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं तथा बाधाग्रस्त आस्तियों के प्रति सीमित एक्सपोजर के कारण संकट के प्रतिकूल असर से कमोबेश अछूती रही। इससे संभावित 'असंबद्धता' (डिकप्लिंग) की धारणा का जन्म हुआ तथा यह तर्क दिया गया कि उन्नत देशों में वृद्धि की दर उल्लेखनीय रूप से कम होने पर भी बाह्य मांग पर कम अश्रित देशों की वृद्धि की संभावना प्रभावित नहीं होगी।

असंबद्धता की अवधारणा इस आधार पर है कि यदि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मंदी के दौर में चली जाती हैं तो भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर उनके पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, उन्नत नीतिगत ढांचा, कारपोरेटों के सुदृढ़ तुलनपत्रों तथा तुलनामूलक रूप से स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र के कारण कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। उन्नत देशों में तीव्र मंदी से असंबद्धता संबंधी यह धारणा उस समय कुछ कमजोर हुई है, जब वैश्विक प्रक्रिया में शामिल अधिकांश देशों ने 2008-09 के दौरान वैश्विक संकट के असर का अनुभव किया और इसे स्वीकार करना शुरू किया।

1980 के दशक के मध्य से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभरी हैं तथा इस समय वे वैश्विक उत्पादन में एक चौथाई हिस्से का योगदान करती हैं और वैश्विक वृद्धि में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। कोस, ओट्टोक तथा प्रसाद (2008) ने हाल के एक अध्ययन में पाया कि वैश्वीकरण की अवधि (1985-2005) के दौरान औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के समूह तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समूह के बीच व्यापार चक्र उतार-चढ़ाव में कुछ समानता रही है। आश्चर्यजनक रूप से, इसके साथ ही वैश्विक कारक के सापेक्षिक महत्व में कमी आई है। अन्य शब्दों में, इन समूहों में से प्रत्येक में व्यापार चक्र संकेन्द्रण के लक्षण पाये गये हैं, परंतु इन समूहों के बीच विकेन्द्रण (अथवा असंबद्धता) है। बढ़ते वित्तीय संबंध, बाह्य आघातों, के संपदा प्रभाव के माध्यम से व्यापार चक्र में साथ-साथ उच्चतर उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। तथापि, वे अपने देश के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप पूंजी के पुनः आबंटन के जरिए उत्पादन में विशिष्टीकरण बढ़ाकर विभिन्न देशों के बीच स्थित उत्पादन सहसंबंध को कम कर सकते हैं। व्यापारिक संबंधों से देशों के बीच मांग-पक्षीय तथा आपूर्ति-पक्षीय स्पिलओवर हो सकता है, जिसके कारण उच्चतर संबंधयुक्त उत्पादन में उतार-चढ़ाव आ सकता है। दूसरी ओर, यदि सुदृढ़ व्यापारिक संबंधों के कारण देशों के बीच उत्पादन में अधिक विशिष्टीकरण आता है, और यदि क्षेत्र-विशिष्ट आघात प्रवल होता है, तो उत्पादन में साथ-साथ होने वाले उतार-चढ़ाव के स्तर में कमी आएगी (बाक्सटर तथा कुपारित्सास 2005)।

वर्तमान वैश्विक संकट के पहले भाग की असंबद्धता की घटना की व्याख्या दो प्रकार से की गयी। यह देखा गया कि व्यापार चक्र का सहसंबंध व्यापार चक्र को नियंत्रित करने वाले आघातों के अनुरूप होता है। 2001 तथा 2002 में अमरीकी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद अन्य देशों की वृद्धि दर में तेजी से आई कमी प्रौद्योगिकी बुलबुलों के फटने की वैश्विक प्रकृत तथा इक्विटी तथा विनिर्माण बाजारों के जरिए इसके विश्व भर में फैलने की बात को प्रतिबिंबित करता है। परंतु, हाल की आर्थिक गिरावट में अमरीका के सकल देशी उत्पाद की दर को नीचे लाने में आवास क्षेत्र में हुए अंतःस्फोट ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि आवास निर्माण में स्थानीय निविष्टियों का उपयोग किया जाता है तथा उससे उत्पादित वस्तुओं का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है, अतः विदेशों में इसका असर रहने होने की आशा थी। परंतु, वित्तीय नवोन्मेष ने आवास को विपणनीय बना दिया तथा अंतर्निहित आवास ऋण के संदर्भ में डेरिवेटिवों की भूमिका, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के इस बाजार के प्रति एक्सपोजर होने को देखते हुए, काफी बड़ी थी।

आइएमएफ के अनुसार, 2007 की दूसरी तिमाही में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय तनाव संकेतक धनात्मक हुए तथा उसके बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। इसके विपरीत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय तनाव संकेतक 2008 की पहली तिमाही तक उल्लेखनीय रूप से ऋणात्मक रहा। 2008 की दूसरी तिमाही के बाद से यह धनात्मक हुआ तथा इसमें तीसरी तिमाही में तथा विशेष रूप से चौथी तिमाही में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार इस घटनाक्रम में, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रारंभिक जवाबी कार्रवाई का स्तर सीमित था परंतु बाद में इसमें तेजी आई। इस प्रकार, प्रारंभ में कुछ असंबद्धता थी तथा समय के साथ संकट के गहराने पर ज्युनः संबद्धता की स्थिति देखी गई। तेजी से वैश्वीकृत होते विश्व में असंबद्धता की अवधारणा पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थी। इस धारणा को बल देते हुए कि वैश्वीकृत विश्व में कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की संभावनाओं को तेजी से फैलते वित्तीय संकट ने कमजोर बनाया, हालांकि विभिन्न देशों में इसके असर का स्तर एक समान नहीं था।

संदर्भ:

1. आइएमएफ (2009), विश्व आर्थिक परिदृश्य, आइएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यू पी/08/143, जून।
2. कोस, एम. ऐहन तथा ओट्टोक, क्रिस्टोफर और प्रसाद, ईश्वर (2008), 'विश्व व्यापार चक्र: कनवर्जेन्स या डिगपलींग?' अप्रैल।
3. बक्सटर, मरिने तथा कौपरित्सास, मिचेल (2005), 'डिटर्मिनान्ट्स ऑफ बिजनस साइकल कोमोवमेंट: ए रोबस्ट अनालिसिस,' जर्नल ऑफ मानीटरी, इकॉनॉमिक्स, खंड 52, पृ. 133-57।

निवल आधार पर, पूंजी का प्रवाह उन देशों की ओर था जहाँ सरकारी प्रतिभूति बाजार चलनिधियुक्त तथा सुरक्षित था। आइएमएफ के अनुसार 2008 में उभरती तथा विकासशील देशों में निजी पूंजी प्रवाह में उल्लेखनीय रूप से कमी आयी और यह

2007 के 618 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2008 में 109 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गयी (देखें चार्ट II.40)। प्रमुख घटकों के बीच, जहाँ 2008 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर

बढ़कर 459 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने का अनुमान है वहीं निवल निजी पोर्टफोलियो प्रवाह तथा बैंक तथा अन्य उधारियों सहित 'अन्य पूंजी प्रवाह' में 2008 में उल्लेखनीय बहिर्वाह हुआ। समग्र रूप में, 2009 में उभरते बाजारों से उनके जीडीपी के 1 प्रतिशत से भी अधिक पूंजी का बहिर्वाह होने का अनुमान है।

11.6.7 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति (2009) के अनुसार श्रम बाजारों की गतिविधियों तथा सुधारात्मक प्रयासों के समय तथा प्रभाविता के अनुसार, खराब से खराब स्थिति में, वैश्विक बेरोजगारी की दर 7.1 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और इसके कारण बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 50 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार संकट के उन्नत तथा उभरते बाजार देशों दोनों में घरेलू इकाइयों, कंपनियों तथा बैंकिंग क्षेत्रों तक फैल जाने से वैश्विक वित्तीय प्रणाली दबावों में आ गई।

11.6.8 मुद्रास्फीतिजन्य चिंताओं के कम होने के कारण वित्तीय बाजार संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा देशी मांग को समर्थन देने हेतु उन्नत तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापक मौद्रिक तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को लागू किया। आइएमएफ के अनुसार, पहले ही किए जा चुके तथा आयोजित उपायों के आधार पर, यह अनुमान है कि सरकारी ऋण अनुपात तथा राजकोषीय घाटे में, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। जी-20 देशों द्वारा 2009 में जीडीपी के 2.0 प्रतिशत और 2010 में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत की राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण उनके समग्र सरकारी शेष की स्थिति उल्लेखनीय रूप से बिगड़ सकती है। कुछ देशों में अल्पावधि में राजकोषीय लागत अधिक हो सकती है, परंतु उत्पादन तथा रोजगार की हानि एवं संकट की तीव्रता तथा अवधि के आधार पर राजकोषीय प्रोत्साहन अथवा वित्तीय क्षेत्र का समर्थन न देने का विकल्प अत्यंत गंभीर हो सकता है (आइएमएफ, 2009)। इस प्रकार 2008-09 के दौरान भारत की समष्टि आर्थिक गतिविधियों को इन प्रतिकूल वैश्विक स्थितियों के संदर्भ में देखना होगा।

11.6.9 इस स्तर के संकट के समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोगिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, जी-20 देशों के नेताओं ने 2 अप्रैल 2009 को लंदन शिखर सम्मेलन में सहयोगिता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया और भविष्य में सुदृढ़

पर्यवेक्षी तथा विनियामक ढांचा तैयार करने की जरूरत को रेखांकित किया। जी-20 द्वारा गठित विभिन्न कार्य दलों ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में विनियमन तथा पर्यवेक्षण का लक्ष्य जोखिम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता को बढ़ाना, विनियामक खामियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि देशों के बीच सहयोगिता में बढ़ोतरी हो। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में एक नए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की अधिक अधिकारों के साथ स्थापना करना था जिसमें जी-20 के सभी देश, एफएसएफ के सदस्य, स्पेन तथा यूरोपियन कमीशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जी-20 देशों ने आइएमएफ से जनवरी 2011 तक कोटा और प्रतिनिधित्व (वॉइस) सुधार की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आह्वान किया। उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए जी-20 देशों के सदस्यों से द्विपक्षीय उधारी के जरिए निधि की राशि में उल्लेखनीय रूप से 250 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी करने हेतु सहमत हुए, जिसे बाद में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर तक उधार प्राप्त करने हेतु एक विस्तारित तथा लचीली उधार की नई व्यवस्था (एनएवी) में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आइएमएफ ने वैश्विक चलनिधि को सुदृढ़ करने हेतु अपने सदस्यों के लिए एसडीआर आबंटन में 250 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की। इसने शर्तों को आधुनिक बनाकर, नयी लचीली ऋण व्यवस्था प्रारंभ करके, सीमाओं को बढ़ाकर दुगुना करके तथा अपनी उधारी की लागत तथा परिपक्वता ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर संकटकालीन उधार की राशि में भी वृद्धि की। आइएमएफ कम आय वाले देशों के लिए रियायती उधार सुविधाओं तथा वित्तीय ढांचे को युक्तिसंगत बना रहा है।

11.6.10 तथापि, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में कमजोरियों का दौर जारी है। घरेलू इकाइयों तथा कारपोरेट क्षेत्रों की चूक की बढ़ती घटनाएं बैंकिंग क्षेत्रों की आर्थिक हालत को और बिगाड़ सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों के कारण वित्तीय बाजारों में स्थिरता आ गई है, फिर भी कुछ खंडों की कमजोरियों से वृद्धि की संभावना पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़े स्तर के राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाओं तथा इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे तथा ऋण में बढ़ोतरी

होने की चिंताओं ने अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसके अलावा, राजकोषीय तथा मौद्रिक विस्तार की गति तथा समय एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर आया है।

भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां

II.6.11 बाहरी आघात के तीव्रतम असर के सम्मुख भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) ने आघात सहनीयता का परिचय दिया जिसका कारण चालू खाता घाटे (सीएडी) का वहनीय सीमा के अंदर रहना तथा भारी पूंजीगत बहिर्वाह के दबावों के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार का सीमित उपयोग किया जाना था। वैश्विक वित्तीय संकट का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न बाहरी क्षेत्र लेनदेनों के माध्यम से पड़ा, जिनमें से कुछ की प्रवृत्तियों में वर्ष के दौरान भारी बदलाव आया। निर्यात वृद्धि पर बाह्य मांग आघात का संप्रेषण शीघ्र तथा तीव्र था जिसके चलते निर्यात, बीओपी आधार पर 2008-09 की पहली तिमाही के 43 प्रतिशत के शीर्ष से घटकर तीसरी तिमाही में (-)9 प्रतिशत हो गया तथा चौथी तिमाही में और घटकर (-)24 प्रतिशत हो गया, जो कि 2001-02 के बाद ऐसी पहली गिरावट है। आयात मांग वृद्धि, जो 2008-09 की दूसरी तिमाही तक सुदृढ़ थी, घरेलू औद्योगिक मांग में कमी तथा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल तथा अन्य प्राथमिक वस्तुओं कीमतों में तेज गिरावट के अनुरूप तीसरी तिमाही में गिरकर एक अंकीय स्तर तक आ गई तथा चौथी तिमाही में भी गिरावट (-27 प्रतिशत) जारी रही। इस प्रकार कच्चे तेल कीमतों में वृद्धि से बढ़े हुए आयात तथा बाह्य मांग में कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में व्यापार घाटे में सामान्यतः बढ़ोतरी हुई। तथापि, आयात में कमी की दर निर्यात में कमी की दर से अधिक होने के कारण 2008-09 की चौथी तिमाही में व्यापार घाटे में उल्लेखनीय कमी हुई। तथापि, राजकोषीय वर्ष 2008-09 में व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूप से बढ़कर जीडीपी का 10.3 प्रतिशत हो गया। वैश्विक मंदी के दौरान भी तुलनात्मक रूप से आघात-सह बने रहनेवाले चालू प्राप्तियों के दो घटक, सॉफ्टवेयर सेवाएं तथा कामगारों का विप्रेषण थे। विदेश में रहने वाले भारतीयों के विप्रेषणों का प्रवाह, 2008-09 की दूसरी छमाही में कमी के बावजूद, खाड़ी संकट तथा एशियाई संकट के दौरान हुए पहले के आघातों के तुलना में तुलनात्मक रूप से सुस्थिर था। उच्च अदृश्य मद अधिशेषों के बावजूद, जिसने 2008-09

की चौथी तिमाही में चालू खाते को आधिक्य में बदल दिया, व्यापार घाटे में हुए बड़े विस्तार के कारण 2008-09 में चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.6 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर था (एक वर्ष पूर्व जीडीपी का 1.5 प्रतिशत)।

II.6.12 वित्तीय चैनल के माध्यम से संकट के प्रभाव का असर पूंजी प्रवाह चक्र में तेज बदलाव के रूप में पड़ा जिसके कारण लंबे दौर के पूंजी आप्रवाह बड़े बहिर्वाह में बदल गए, विशेष रूप से 2008-09 की तीसरी तिमाही में, और यही स्थिति चौथी तिमाही में भी जारी रही। वित्तीय संकट के पूंजी आप्रवाह पर असर का पूर्व संकेत फरवरी 2008 के प्रारंभ में हुए पोर्टफोलियो बहिर्वाह में परिलक्षित हुआ। लीमन ब्रदर्स की असफलता के बाद बाह्य वातावरण में अकस्मात परिवर्तन आया जिसके कारण पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा देशी इक्विटी बाजार में बिक्री का दौर प्रारंभ हुआ जो अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप डिलीवरेजिंग को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार, सितंबर - अक्टूबर 2008 के दौरान पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा पूंजी का भारी बहिर्वाह किया गया जिसका असर विदेशी मुद्रा बाजार पर पड़ा। बाह्य वित्तीयन की बिगड़ती स्थिति ने भी भारतीय फर्मों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारियों तथा व्यापार ऋण तक पहुंच को कुछ कठिन बना दिया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में देखे गए लचीलेपन से दीर्घावधि निवेश स्थान के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास बरकरार रहने की बात स्पष्ट होती है (परिशिष्ट सारणी 51)।

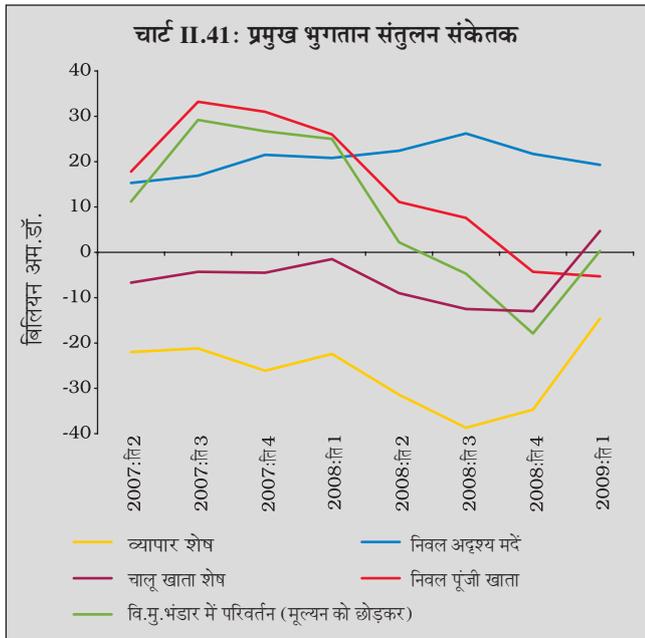
II.6.13 यद्यपि 1990 के दशक के प्रारंभ के एशियाई संकट के दौरान भारत से पूंजी का बहिर्वाह हुआ था, फिर भी वर्तमान संकट की विशेषता यह थी कि डिलीवरेजिंग के अत्यधिक दबाव के कारण पूंजी के प्रवाह में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। इस प्रकार, 2008-09 की पहली तिमाही तक नीतिगत फोकस पूंजी के अंतर्वाह में वृद्धि के प्रबंधन पर था परंतु 2008-09 की दूसरी तिमाही से क्रमशः बदलती वैश्विक गतिविधियों एवं पूंजी अंतर्वाह के कम होने से नीतिगत रुख बढ़ते चालू खाता घाटे के वित्तपोषण की ओर झुक गया। भुगतान संतुलन पर वैश्विक व्यापार तथा वित्तीय आघात के प्रतिकूल असर को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में पर्याप्त आधार के चलते रोका जा सका। 2008-09 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) में 20.1 बिलियन अमरीकी डालर की कमी हुई, यद्यपि वर्ष के दौरान विदेशी

मुद्रा भंडार के स्तर (मूल्यांकन प्रभाव सहित) में 57.7 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट हुई जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में वृद्धि को परिलक्षित करती है (चार्ट II.41)।

II.6.14 संकट की तीव्रता तथा निर्यात पर इसके प्रतिकूल असर से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण तथा इसके वित्तपोषण के उदारीकरण, ऐसे ऋणों पर उच्चतम ब्याज दर में परिवर्तन, विदेशी ऋण की ब्याज दर तथा बैंकों द्वारा डालर चलनिधि के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा की सीमा के उदारीकरण के जरिए निर्यात को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए। सितंबर 2008 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का लक्ष्य वस्तुतः विदेशी मुद्रा चलनिधि में सुधार लाना था और इनमें ये उपाय शामिल थे - बाजार में डालर की बिक्री, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा राशियों की उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी, बैंकों को विदेशी बाजारों से उधार लेने हेतु लचीलापन उपलब्ध कराना, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) की समयपूर्व पुनर्खरीद का उदारीकरण तथा अल्पावधि व्यापार ऋण तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर उच्चतम ब्याज दर में छूट दिया जाना। भारत की भुगतान संतुलन स्थिति की तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ता इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि उसे असामान्य उपायों का सहारा नहीं लेना पड़ा। संकट के असर को कम करने

की चुनौती से निपटने के लिए सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों ने आपसी समन्वय एवं परामर्श से कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों का लक्ष्य पर्याप्त डालर चलनिधि सुनिश्चित करना तथा उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी के प्रवाह की निरंतरता को प्रोत्साहन देने वाले बाजार परिवेश को बनाए रखना था। साथ ही, पूंजी बहिर्वाह के उच्चतर स्तर से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पूंजी के विभिन्न देशों के बीच के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले विनियमों को और शिथिल करके पूंजी खाता उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा गया।

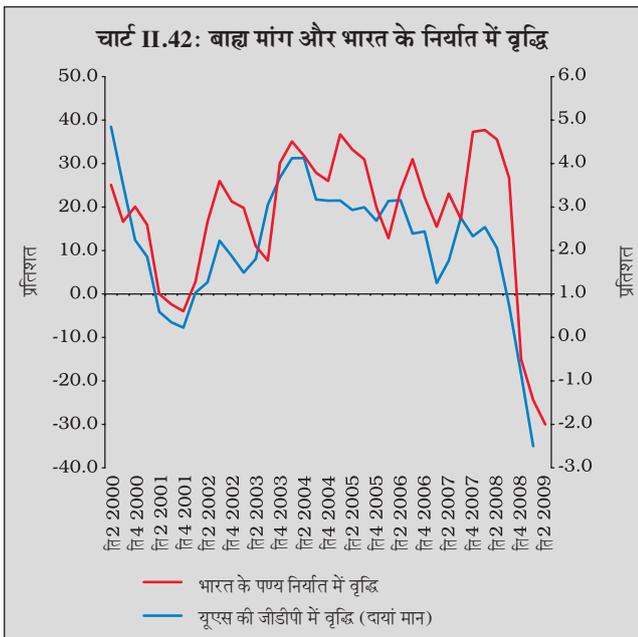
II.6.15 सबसे गंभीर वित्तीय संकट के सम्मुख भारतीय वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता का श्रेय वित्तीय वैश्वीकरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को भी दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता चालू खाते को पूर्णतः खोल देना परंतु पूंजी खाते को खोलने की दिशा में नपातुला दृष्टिकोण अपनाया रही है। जबकि विदेशी निवेश प्रवाह, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है वहीं ईसीबी के रूप में ऋण प्रवाह सामान्यतः उच्चतम सीमा के अधीन रहता है तथा इनके अंतिम उपयोग में कुछ प्रतिबंध होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट बांडों में पोर्टफोलियो निवेश के लिए समग्र सीमा निर्धारित की गयी है। पूंजीगत बहिर्वाहों को भी क्रमशः उदारीकृत किया गया है। पूंजी खाते को उदार बनाने के संबंध में नपातुला दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमनों को भी सुदृढ़ किया गया है।



वणिक् व्यापार

II.6.16 संकट के सितम्बर 2008 के बाद के दौर में गहन हुए संक्रमण के व्यापार चैनल ने भारत के वणिक् व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिसके कारण वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभिक समय की मंदी की तुलना में निर्यात में अधिक गहनता से तथा अधिक तेजी से कमी आयी। डीजीसीआईएण्डएस द्वारा जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार भारत का वणिक् निर्यात की वृद्धि दर, बड़े अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ, 2007-08 के 29.0 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2008-09 में 3.4 प्रतिशत रह गई। यद्यपि, अगस्त 2008 तक निर्यात में वृद्धि की दर अच्छी थी (अप्रैल-अगस्त 2008 में 35.6 प्रतिशत), तथापि सितंबर 2008 में इसमें उल्लेखनीय कमी आना शुरू हुआ और यह घटकर 14.2 प्रतिशत रह गयी, जिसके

बाद उन्नत देशों में मंदी के गहराने के अनुरूप 2008-09 के शेष महीनों में निर्यात में कमी आई (चार्ट II.42 तथा बॉक्स II.31)। 2008-09 में आयात में वृद्धि की दर भी एक वर्ष पूर्व के 35.5 प्रतिशत से गिरकर 14.3 प्रतिशत हो गयी; तथापि, लचीली देशी मांग के कारण आयात में कुछ समय अंतराल के बाद कमी आई। देशी आर्थिक कार्यक्रमों में गिरावट आने तथा कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप, वणिक आयात की वृद्धि दर में, जो 2008-09 की पहली छमाही के दौरान काफी अधिक थी (अप्रैल-सितंबर 2008 के दौरान 43.9 प्रतिशत), अक्टूबर और नवम्बर में तेजी से कमी आयी तथा उसके बाद दिसम्बर 2008 से मार्च 2009 के दौरान इसमें गिरावट आयी। तेल के आयात, जिसमें अप्रैल-अक्टूबर 2008 के दौरान 60.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, में नवम्बर 2008-मार्च 2009 के दौरान तेल की कीमतों में तेजी से कमी आने के कारण 29.0 प्रतिशत की कमी हुई। गैर तेल आयातों में 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान तेजी रहने के बाद (22.7 प्रतिशत वृद्धि), मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं तथा सोने और चांदी के आयातों की वृद्धि दर में कमी आने के कारण 2008-09 की चौथी तिमाही में 15.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। 2008-09 के दौरान व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 2007-08 के 88.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 119.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (परिशिष्ट सारणी 48)।



II.6.17 विश्व के सभी देशों में निर्यात की संभावना के कमजोर पड़ने के दौर में निर्यात के क्षेत्र में विभिन्न देशों के तुलनात्मक कार्यनिष्पादन में काफी अंतर था। वैश्विक मंदी के गंभीर रूप लेने के बाद, 2008-09 की तीसरी तिमाही से भारत के निर्यात में हुई गिरावट कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आयी गिरावट से काफी कम थी (चार्ट II.43)।

II.6.18 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के लिए उपलब्ध पण्यवार निर्यात संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा सबसे अधिक था उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राथमिक वस्तुओं का था (परिशिष्ट सारणी 49)। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों के बीच, चमड़ा तथा उससे निर्मित उत्पाद, टेक्सटाइल तथा तत्संबंधी उत्पाद और रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों की वृद्धि दर में कमी आयी तथा उन्नत देशों में रत्न तथा आभूषण की मांग में कमी आने से यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और इनके निर्यात में कमी आयी (चार्ट II.44)। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में कमी आयी और यह मुख्यतः निर्यात के सबसे महत्वपूर्ण देश अर्थात यूएस में मंदी की स्थिति को दर्शाती है। टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल उत्पाद क्षेत्र, जो रोजगार देनेवाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के निर्यात की वृद्धि दर में 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान उल्लेखनीय कमी आयी। भारत के कुल निर्यात में एक चौथाई से भी अधिक हिस्से का योगदान देने वाली इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, 2007-08 में हुई 24.4 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर, 23.5 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हुई जिसमें परिवहन उपकरणों, लोहा तथा इस्पात तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का योगदान प्रमुख था।

II.6.19 यूरोपियन यूनियन, ओपेक, पूर्वी यूरोप तथा दक्षिण अमरीकी विकासशील देशों को किए जाने वाले भारत के निर्यात की वृद्धि दर में कमी आयी जबकि उत्तरी अमरीका, एशिया तथा ओसेनिया एवं एशियाई और अफ्रीकी विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात में कमी आयी। भारत के निर्यात बाजार के हिस्से के रूप में पिछले वर्ष के 12.8 प्रतिशत से कम होकर 11.7 प्रतिशत रह जाने के बावजूद 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान यूएस भारत के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार बना रहा जिसके बाद यूएई, चीन तथा सिंगापुर का क्रम था (सारणी 2.73)।

II.6.20 2008-09 के आयातों के पण्यवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पेट्रोलियम, तेल तथा लुब्रिकेंट (पीओएल) के आयात

बॉक्स II.31

भारत के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय संकट का प्रभाव

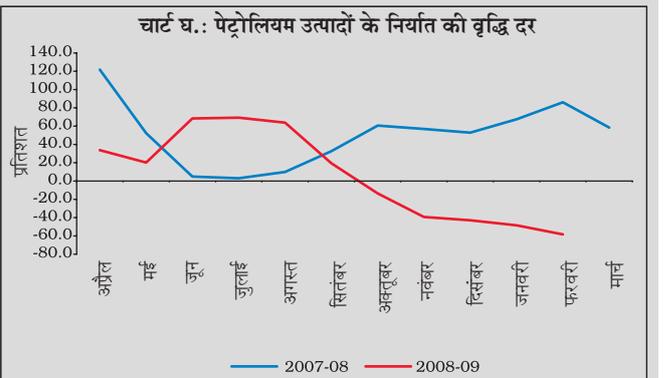
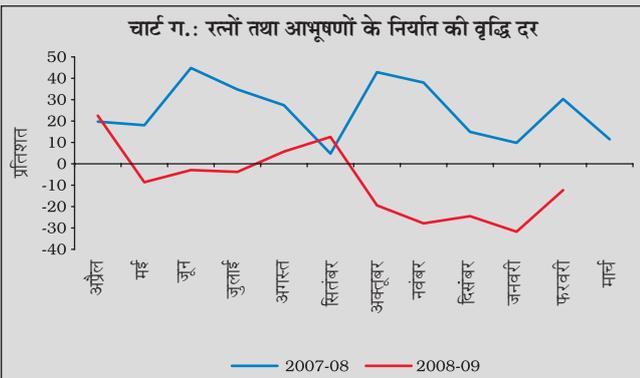
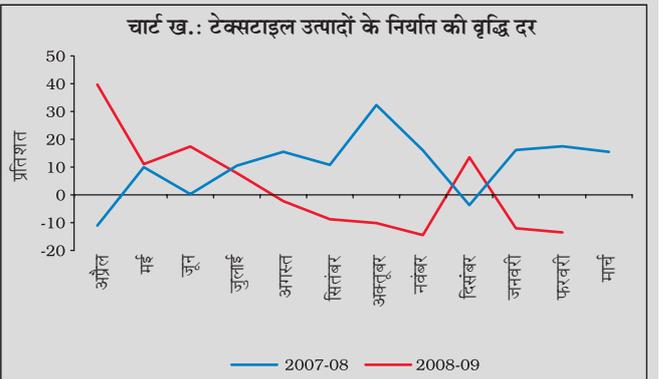
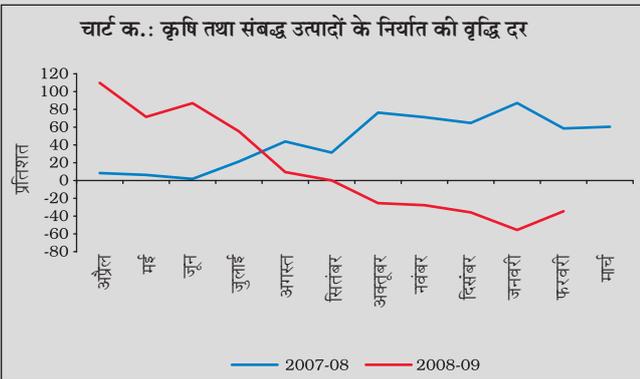
पिछले दशक के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण उल्लेखनीय तेजी के साथ हुआ है। भारत का वणिज्य व्यापार 2002-03 से उच्च वृद्धि के पथ पर था और यह प्रवृत्ति 2008-09 (अप्रैल-अगस्त) के पहले पांच माह तक बनी रही। हाल के वर्षों में निर्यात में हुई निरंतर वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, सकारात्मक नीतिगत परिवेश, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बदलाव, बाजार विविधीकरण, विनिमय दर में स्थिरता तथा निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार की शर्तों में प्राप्त लाभ के कारण हुई। टेक्सटाइल, चमड़ा तथा हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर विशेष नीतिगत फोकस के बावजूद ढांचागत कारणों से उच्च निर्यात के दौर में उनका कार्यनिष्पादन अपेक्षाकृत मंथर था। साथ ही, विनिर्मित उत्पाद जैसे कि इंजीनियरी वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पाद तथा रसायन, निर्यात में वृद्धि के प्रमुख चालकों के रूप में उभरे।

2008-09 के दौरान निर्यात में कमी मुख्यतः ओईसीडी तथा विकासशील देशों में, जिनका भारत के निर्यात में लगभग 38 प्रतिशत का प्रमुख हिस्सा है, मांग में कमी आने के कारण आई। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, मुख्यतः यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमरीका तथा एशिया और ओशेनिया को निर्यात में कमी आने से ओईसीडी देशों को निर्यात में कमी आई। विकासशील देशों को निर्यात में कमी आई जो मुख्यतः सार्क तथा अन्य एशियाई विकासशील देशों एवं अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी विकासशील देशों को निर्यात घटने / निर्यात की वृद्धि दर में कमी आने के कारण थी। भारत के निर्यात में ओपेक का हिस्सा लगभग 19 प्रतिशत है, जहां उच्च वृद्धि दर बनी रही।

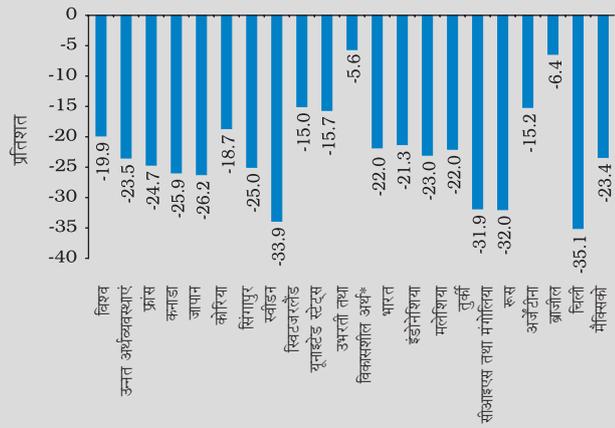
केवल 'इंजीनियरिंग वस्तु' ऐसा क्षेत्र था जो वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव को झेलने में सफल रहा तथा उच्च वृद्धि दर बनाये रखा, इसको छोड़कर

अन्य सभी क्षेत्र संकट से प्रभावित हुए। कृषि तथा संबंधित उत्पादों, रत्नों तथा आभूषणों एवं अयस्क तथा खनिज का निर्यात घटा जबकि अन्य क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि दर में तेज गिरावट आई। अप्रैल 2008- फरवरी 2009 के दौरान प्राथमिक उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर में पिछले वर्ष के 38.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट कृषि तथा संबंधित उत्पादों एवं अयस्क तथा खनिजों के निर्यात ने कमी आने के कारण थी। (चार्ट क)।

अप्रैल 2008-फरवरी 2009 के दौरान टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर में तेजी से कमी आई जो सभी प्रमुख घटकों, विशेषरूप से सिले-सिलाए वस्त्रों, टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात में जिसका हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत था, के निर्यात में कमी आने के कारण थी (चार्ट ख)। प्रमुख देश यूएस में मंदी की स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में गिरावट आई (चार्ट ग)। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात, जो भारत के निर्यात का दूसरा प्रमुख घटक है, की वृद्धि दर में अंतरराष्ट्रीय पीओएल की कीमतों में तेजी से कमी आने एवं भारत के निर्यात के प्रमुख गंतव्य देशों में मंदी की स्थिति को दर्शाते हुए कमी आई (चार्ट घ)। चमड़ा तथा उससे निर्मित उत्पादों के निर्यात की वृद्धि दर में कमी आई। श्रम प्रधान वाले क्षेत्रों, अर्थात् रत्नों तथा आभूषणों, टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल उत्पाद तथा चमड़ा तथा उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात में आई कमी रोजगार पर इसके प्रतिकूल असर की दृष्टि से एक चिंता की बात है। इस प्रकार, श्रम प्रधान तथा तुलनात्मक रूप से कम प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों के निर्यात में आई अत्यधिक गिरावट से रोजगार के क्षेत्र में होने वाली क्षति के कारण भी वैश्विक मंदी के प्रतिकूल असर में वृद्धि की संभावना है।

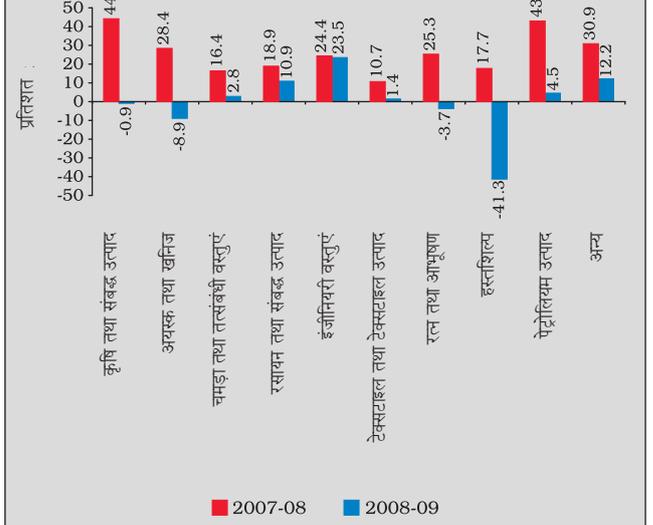


चार्ट II.43: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अक्टूबर 2008- फरवरी 2009 में भारत के निर्यात में वृद्धि



* अक्टूबर 2008 से जनवरी 2009

चार्ट II.44: भारत के निर्यात में वृद्धि - प्रमुख वस्तुएं (अप्रैल-फरवरी)



में वृद्धि की दर 2007-08 के 35.8 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटकर 26.8 प्रतिशत हो गयी जिसका मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से कमी आना था (चार्ट II.45)। 2008-09 के दौरान कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की मासिक औसत कीमत जुलाई 2008 के 132.5 अमरीकी डालर प्रति

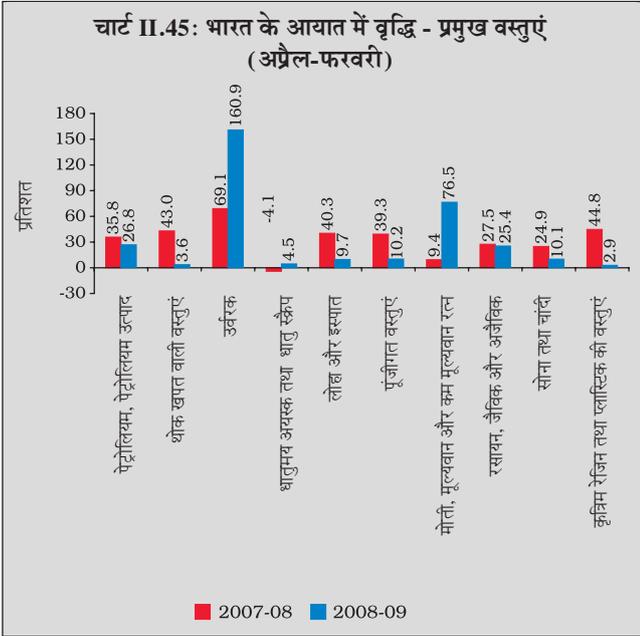
बैरल से घटकर दिसम्बर 2008 में 40.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल के निचले स्तर तक आ गयी, हालांकि मार्च 2009 में यह बढ़कर 46.0 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गयी। पूरे राजकोषीय वर्ष भर, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की औसत कीमत 82.7 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रही। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप पीओएल के आयात में नवंबर 2008 से मार्च

सारणी 2.73: भारत के निर्यातों की दिशा

समूह/ देश	बिलियन अमरीकी डॉलर			Variation (per cent)		
	2007-08	2007-08 सं		2007-08	2007-08	
		2008-09अ	अप्रैल-फरवरी		अप्रैल-फरवरी	
1	2	3	4	5	6	7
1. ओईसीडी देश जिनमें से :	62.6	57.2	60.1	20.4	20.2	5.1
क) ईयू	32.9	30.6	34.1	27.6	27.5	11.4
ख) उत्तरी अमरीका	22.0	19.8	19.7	10.0	10.4	-0.9
यूएस	20.7	18.7	18.4	9.8	10.2	-1.6
2. ओपेक जिनमें से:	26.7	23.9	29.6	28.8	26.7	24.1
यूएई	15.6	14.0	16.6	29.9	29.3	18.0
3. विकासशील देश जिनमें से:	69.6	60.5	60.2	37.1	33.6	-0.5
एशिया	51.5	45.0	44.5	36.9	33.0	-1.0
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना	10.8	9.5	7.7	30.6	27.1	-18.1
सिंगापुर	7.4	6.4	7.3	21.4	17.3	13.0
4. कुल निर्यात	163.1	145.9	157.2	29.0	28.5	7.8

सं : संशोधित अ : अनंतिम

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस



पीओएल आयात में अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु उसके बाद जनवरी-मार्च 2009 के दौरान प्रति माह आयात में कमी आती रही। गैर-पीओएल आयातों के बीच, जहां 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान पूँजीगत वस्तु के आयात की वृद्धि दर घटकर 10.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 39.3 प्रतिशत) रह गयी, वहीं सोने और चांदी के आयात में 10.1 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 24.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (चार्ट II.45 तथा परिशिष्ट सारणी 50)। भारत में आयात के 10.3 प्रतिशत के हिस्से के साथ चीन आयात का मुख्य स्रोत था (सारणी 2.74)। आयात के अन्य प्रमुख स्रोतों में सऊदी अरब, यूएई, यूएस, ईरान तथा स्विट्जरलैंड थे।

2009 के दौरान लगातार कमी आई। 2008-09 में गैर-पीओएल आयातों की वृद्धि दर भी कम होकर 13.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 33.5 प्रतिशत) थी। वृद्धि दर में आयी यह कमी आर्थिक मंदी के कारण देशी मांग में हुए संकुचन को प्रतिबिंबित करती है। गैर-

II.6.21 यद्यपि 2008-09 की दूसरी छमाही में भारत के निर्यात तथा आयात दोनों में गिरावट आई, तथापि इस अवधि के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जो कि भारत के निर्यात के प्रमुख बाजार रहे हैं, में भारी मंदी के कारण आयात की तुलना में निर्यात में गिरावट की दर अधिक थी (बॉक्स II.32)। इसके अतिरिक्त जहां सितंबर 2008 में निर्यात में मंदी के लक्षण दिखे, वहीं तेल की कीमतों तथा गैर-तेल आयात मांग में कमी के कारण अक्टूबर 2008 से आयातों में कमी आई। निर्यात की तुलना में आयात

सारणी 2.74: भारत के आयातों की दिशा

समूह/ देश	बिलियन अमरीकी डॉलर			घटबढ़ (प्रतिशत)		
	2007-08	2007-08सं	2008-09 अ	2007-08	2007-08	2008-09
	अप्रैल-फरवरी			अप्रैल- फरवरी		
1	2	3	4	5	6	7
1. ओईसीडी देश जिनमें से:	87.4	70.6	82.4	36.6	30.4	16.7
क) ईयू	36.8	31.6	35.5	29.5	30.4	12.2
जर्मनी	9.9	8.6	9.6	30.8	27.7	11.2
यूके	5.0	4.6	5.5	18.7	25.1	18.3
ख) उत्तरी अमरीका	23.0	14.0	17.8	70.1	33.7	27.0
यूएस	21.0	12.2	15.7	79.1	31.8	29.1
2. ओपेक	76.1	68.8	87.5	35.7	34.7	27.2
जिनमें से:						
यूएई	13.5	12.2	17.0	55.6	60.5	39.1
3. विकासशील देश जिनमें से:	80.6	72.4	86.0	34.9	35.7	18.8
एशिया	64.1	58.6	69.4	35.4	37.3	18.5
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना	27.1	24.8	28.1	55.2	58.1	13.3
सिंगापुर	8.1	7.1	6.6	47.9	43.5	-6.6
दक्षिण कोरिया	6.0	5.4	7.5	25.6	25.4	38.8
4. कुल आयात	251.7	228.1	272.2	35.5	35.3	19.3

सं : संशोधित

अ : अनंतिम

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस

बॉक्स II.32

भारत के लिए निर्यात मांग फलन: भारत पर वैश्विक मंदी के असर पर कुछ निष्कर्ष

वस्तुओं और सेवाओं के निवल निर्यात को आम तौर पर ऐसी बाह्य मांग के रूप में माना जाता है जो वृद्धि की प्रक्रिया के अनुकूलन में सकल घरेलू मांग के अनुपूरक का कार्य करती है। भारत में, वृद्धि की दर को निर्धारित करने में घरेलू मांग की प्रमुख भूमिका के बावजूद देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में निर्यात का महत्व क्रमशः बढ़ रहा है। वैश्विक मंदी के दौरान वैश्विक वृद्धि में संकुचन की तुलना में वैश्विक व्यापार वृद्धि से संकुचन अधिक तेज होने से पड़ने वाले भारत के निर्यात के निष्पादन एवं संभावनाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। यद्यपि, वैश्विक मंदी के दौर में घरेलू तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों से जुड़े कई सारे कारकों से निर्यात के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, तथापि, इस संदर्भ में वैश्विक जीडीपी में संकुचन तथा व्यापार की मात्रा के भारत के निर्यात पर असर का आकलन करना महत्वपूर्ण होगा।

अधिकांश प्रयोगाश्रित अध्ययनों में निर्यात की मात्रा द्वारा समर्थित निर्यात मांग की व्याख्या प्रभावी विनिमय दर में परिवर्तन, सापेक्षिक निर्यात मूल्य तथा वैश्विक वास्तविक आय के रूप में की जाती है। भारत के संदर्भ में, भारत की निर्यात मांग प्राचलों का सबसे पहला आकलन मूर्ति तथा शास्त्री (1951) तथा अगरवाला (1970) के प्रकाशनों में उल्लिखित है। अगरवाला (1970) द्वारा आकलित निर्यात मांग फलन के अनुसार मांग तथा मूल्य लोच क्रमशः 0.35 तथा -0.44 थी। हाल की अवधि में, भारत के निर्यात मांग फलन का आकलन विरमानी (1991), शर्मा (2000) तथा भारिबैं (2001) ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक (2003) अध्ययन ने पाया था कि वैश्विक जीडीपी में वृद्धि के संदर्भ में भारत के निर्यात की दीर्घावधि मांग लोच 1.5 थी जो इस बात की पुष्टि करती है कि उच्च वैश्विक वृद्धि को देखते हुए भारत के निर्यात को प्रभावित करने वाला खिंचाव प्रभाव उल्लेखनीय हो सकता है। तथापि, अल्पावधि लोच 0.8 पर निम्नतर थी।

1980-81 से 2007-08 की अवधि के भारत के निर्यात के एक आकलन से स्पष्ट होता है कि भारत के निर्यात की वैश्विक जीडीपी के संदर्भ में दीर्घावधि मांग लोच भारत के तुलनात्मक निर्यात मूल्य के संबंध में 3.7 तथा -1.9 है। प्रयोगाश्रित संबंध को सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वैश्विक जीडीपी तथा तुलनात्मक मूल्य के ऐसे प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है

जो भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकता है।

$$\text{Ln } X = - 56.96 + 3.73 \text{ Ln } YW - 1.94 \text{ Ln } RXP + 0.81 \text{ AR}(1)$$

(-7.72) (8.43) (-1.78) (7.28)

$$R^2 = 0.99 \quad DW = 1.65 \quad SEE = 0.07$$

जहां, X = भारत का निर्यात का मात्रात्मक सूचकांक, YW = अमरीकी डॉलर में नियत मूल्य पर वैश्विक जीडीपी, RXP = वैश्विक निर्यात मूल्य (अमरीकी डॉलर में वैश्विक निर्यात का इकाई मूल्य सूचकांक) की तुलना में भारत के निर्यात मूल्य का अनुपात (रुपया - अमरीकी डॉलर सांकेतिक विनिमय दर द्वारा अपस्फीत भारत के निर्यात का इकाई मूल्य)।

निर्यात मांग फलन के आधार पर, वर्तमान वैश्विक संकट से भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अक्टूबर 2008 से जून 2009 के दौरान भारत के निर्यात में आई सतत कमी से इस बात की पर्याप्त रूप से पुष्टि होती है। आइएमएफ के डब्ल्यूईओ अद्यतन जानकारी (जुलाई 2009) के अनुसार 2009 में वैश्विक वणिक् व्यापार में मात्रात्मक (वस्तुओं और सेवाओं) रूप में 12.2 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। 2009 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पण्य निर्यात की मात्रा में क्रमशः 15.0 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। अमरीकी डॉलर के रूप में, उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वणिक् निर्यात में 2009 में 27.1 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। एक प्रमुख चिंता यह है कि एशिया से इतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आई गहन तथा लंबी अवधि की मंदी से बाह्य मांग में और कमी आ सकती है जिसका निर्यात संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

संदर्भ:

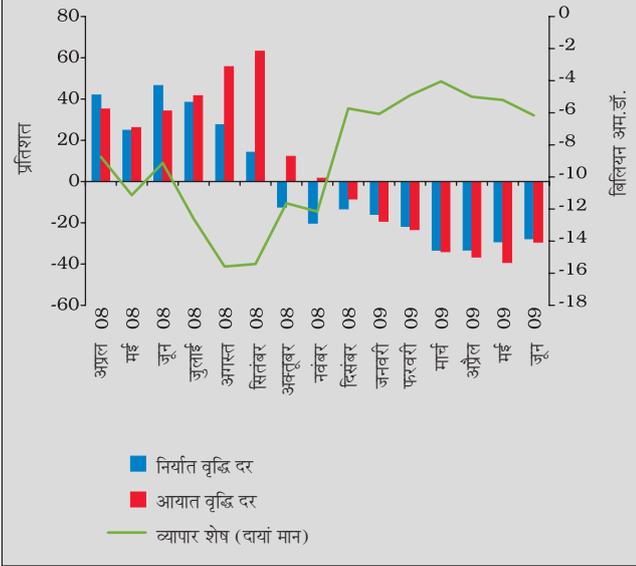
1. भारतीय रिजर्व बैंक (2004), मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट 2002-03।
2. विरमानी, ए.(1991), 'डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स इन इंडियाटस ट्रेड', इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 26(6) फरवरी।
3. मूर्ति, वी.एन. तथा शास्त्री, वी.के.(1951), 'इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर सर्विसेस एंड एक्सपोर्ट', संख्या, खंड 11।

में भी, कुछ पश्चता के साथ ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई (चार्ट II.46)।

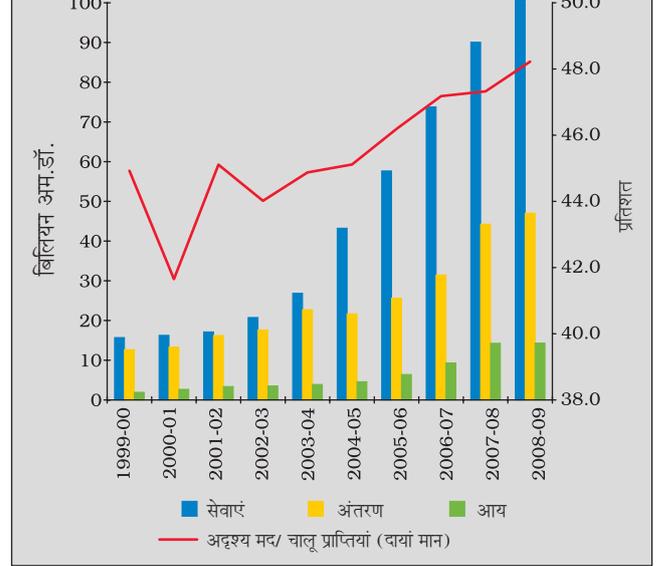
II.6.22 2009-10 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के दौरान 31.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारत के निर्यात में गिरावट का दौर जारी रहा जबकि अप्रैल-जून 2008 के दौरान इसमें 43.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, निर्यात में गिरावट की दर में कमी आना शुरू हुआ और इसमें सतत सुधार दिखाई दिया। अप्रैल-

जून 2009 के दौरान आयात में भी 36.5 प्रतिशत की गिरावट आई (एक वर्ष पूर्व 34.7 प्रतिशत) और यह प्रवृत्ति मई 2009 तक (39.2 प्रतिशत) लगातार जारी रही परंतु बाद में जून 2009 में इसमें सुधार आया जो घरेलू बाजार की बाह्य लक्ष्य का परिचायक है। अप्रैल-जून 2009 के दौरान गैर-पीओएल आयातों में अप्रैल-जून 2008 में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 24.6 प्रतिशत की तेज गिरावट आई जबकि मुख्यतः कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से कमी आने से पीओएल आयातों

चार्ट II.46: निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष में मासिक घटबढ़



चार्ट II.47: भारत की सकल अदृश्य मद प्राप्तियां



में 56.8 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 73.8 प्रतिशत की वृद्धि) की उल्लेखनीय कमी आई। अप्रैल-जून 2009 के दौरान कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की औसत कीमत 59.1 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल थी (अमरीकी डॉलर 50.1-69.1 प्रति बैरल के बीच) जो कि अप्रैल-जून 2008 के 118.8 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल (अमरीकी डॉलर 105.8-129.7 प्रति बैरल के बीच) की तुलना में काफी कम है। तिमाही के दौरान आयात में कमी की दर निर्यात में कमी की दर से अधिक होने के कारण 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2008 के 28.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 15.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

अदृश्य मदें: सेवाएं, आय तथा अंतरण

II.6.23 अदृश्य मद लेखा सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अनिवासी आस्तियों तथा देयताओं से संबंधित आय, श्रमिक तथा संपत्ति तथा अंतर-देशीय अंतरण, मुख्यतः श्रमिकों के विप्रेषणों से संबंधित लेनदेनों के सामग्रिक प्रभाव को परिलक्षित करता है। अदृश्य मद प्राप्तियों में, विशेष रूप से वर्तमान दशक के प्रारंभ से वैश्विक वृद्धि दर काफी लंबे समय तक उच्च स्तर पर बने रहने तथा मुद्रास्फीति की दर कम रहने के कारण, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। भारत की निवल अदृश्य मद प्राप्तियों (अदृश्य मद प्राप्तियां घटाव भुगतान) में मुख्यतः निजी अंतरणों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं के कारण 2008-09 में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी 52)। सकल अदृश्य मद

प्राप्तियों में वृद्धि की दर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से 2007-08 के 29.7 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 9.4 प्रतिशत रह गई जिसने मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा निजी अंतरण प्राप्तियों में वृद्धि को प्रभावित किया, साथ ही यात्रा, व्यापार सेवाओं तथा निवेश आय प्राप्तियों में कमी आई (चार्ट II.47)। 2007-08 में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अदृश्य मद भुगतान में 2008-09 में 1.4 प्रतिशत की थोड़ी-सी कमी आई जो मुख्यतः यात्रा तथा परिवहन से संबंधित भुगतानों की वृद्धि दर में गिरावट होने तथा सॉफ्टवेयर, कारोबारी तथा वित्तीय सेवाओं तथा निवेश आय खाते में कमी आने के कारण थी। निवल अदृश्य मद अधिशेष 2007-08 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में जीडीपी का 7.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.75)।

सेवाएं

II.6.24 वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत के भुगतान संतुलन के अन्य घटकों की तुलना में सेवाओं ने तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ता का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप मुख्यतया सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात के कारण निवल सेवा अधिशेष 2007-08 के 37.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2008-09 में 49.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। तथापि, लगभग 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के लंबे दौर के बाद, सेवाओं के निर्यात में 2008-09 की दूसरी छमाही में 0.5 प्रतिशत की मामूली-सी कमी आई। भारत की सेवा प्राप्तियों में मुख्यतः यात्रा आय,

सारणी 2.75: भुगतान संतुलन - प्रमुख संकेतक

(बिलि.अम.डॉलर)

मद/संकेतक	1990-91	2001-02	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 सं	2008-09 प्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	
मदें (बिलि. अम. डॉ.)								
i) व्यापार शेष	-9.4	-11.6	-33.7	-51.9	-61.8	-91.6	-119.4	
ii) अदृश्य, निवल	-0.2	15.0	31.2	42.0	52.2	74.6	89.6	
iii) चालू खाता शेष	-9.7	3.4	-2.5	-9.9	-9.6	-17.0	-29.8	
iv) पूंजी खाता	7.1	8.6	28.0	25.5	45.2	108.0	9.1	
v) विदेशी मुद्रा भंडार* (वृद्धि- / कमी +)	1.3	-11.8	-26.2	-15.1	-36.6	-92.2	20.1	
संकेतक(प्रतिशत में)								
1. व्यापार								
i) निर्यात/ जीडीपी	5.8	9.4	12.1	13.0	14.1	14.2	15.1	
ii) आयात/जीडीपी	8.8	11.8	16.9	19.4	20.9	22.0	25.5	
iii) व्यापार शेष /जीडीपी	-3.0	-2.4	-4.8	-6.4	-6.8	-7.8	-10.3	
iv) निर्यात की मात्रा में वृद्धि	11.0	3.9	17.5	11.8	15.8	5.4	..	
2. अदृश्य मदें								
i) अदृश्य प्राप्तियां/जीडीपी	2.4	7.7	9.9	11.1	12.5	12.7	14.0	
ii) अदृश्य भुगतान /जीडीपी	2.4	4.6	5.5	5.9	6.8	6.3	6.3	
iii) अदृश्य (निवल)/ जीडीपी	-0.1	3.1	4.4	5.2	5.7	6.4	7.7	
3. चालू खाता								
i) चालू प्राप्तियां @/जीडीपी	8.0	16.9	21.9	24.0	26.6	26.8	29.1	
ii) चालू भुगतान/जीडीपी	11.2	16.3	22.4	25.3	27.7	28.3	31.8	
iii) चालू प्राप्तियों में वृद्धि @	6.6	4.5	29.3	26.0	25.1	29.3	7.4	
iv) चालू खाता शेष/जीडीपी	-3.1	0.7	-0.4	-1.2	-1.1	-1.5	-2.6	
4. पूंजी खाता								
i) भारत में विदेशी निवेश(निवल)/जीडीपी	-	1.7	2.2	2.6	3.3	5.4	1.8	
ii) पूंजी प्रवाह (निवल)/जीडीपी	2.2	1.8	4.0	3.1	4.9	9.2	0.8	
iii) पूंजी अंतर्वाह/जीडीपी	7.2	9.1	14.0	17.9	25.4	36.9	26.1	
iv) पूंजी बहिर्वाह/जीडीपी	5.0	7.3	10.0	14.7	20.5	27.7	25.3	
5. अन्य								
i) ऋण- जीडीपी अनुपात	28.7	21.1	18.5	17.2	18.1	19.0	22.0	
ii) ऋण-चुकौती अनुपात	35.3	13.7	6.1	9.9	4.7	4.8	4.6	
iii) देयता-चुकौती अनुपात	35.6	14.9	7.1	11.2	6.1	5.9	5.5	
iv) आरक्षित निधियों का आयात कवर (महीनों में)	2.5	11.5	14.3	11.6	12.5	14.4	10.3	
आंसं : आंशिक संशोधित	प्रा. : प्रारंभिक	@ : आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर						- : नगण्य
* : मूल्यांकन को छोड़कर	.. : उपलब्ध नहीं							

सॉफ्टवेयर तथा कारोबारी सेवाएं होती हैं जो भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भाररुचि, भारत के उच्च कौशल वाले कामगारों के बढ़ते महत्व तथा टेक्नॉलॉजी समर्थित सेवाओं के निर्यात में तुलनात्मक बेहतर स्थिति को दर्शाता है (सारणी 2.76)। उसी प्रकार, देशी अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वृद्धि, भाड़े की बढ़ी हुई लागत, विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, कारोबार तथा प्रबंधन परामर्श संबंधी भुगतान, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाओं के संबंध में भुगतान के कारण सेवा भुगतानों में वृद्धि हुई।

II.6.25 विश्व सेवा निर्यात में 1995 में 0.6 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी की तुलना में 2007 में 2.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ बाजार हिस्सेदारी में भारत का स्थान 11वां था जो सेवा

निर्यात के कुछ खंडों में भारत के तुलनात्मक लाभ संबंधी सकारात्मक गतिविधियों को परिलक्षित करता है (सारणी 2.77)।

II.6.26 भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात पर वैश्विक आर्थिक आघात का असर 2008-09 के दौरान स्पष्टतः दिखा, विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में, जब उसके सॉफ्टवेयर निर्यात में 0.9 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि हुई (चार्ट II.48)। इसके बावजूद 2008-09 (47.0 बिलियन अमरीकी डॉलर) के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2007-08 के दौरान 28.8 प्रतिशत)। वैश्विक मंदी तथा बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के बावजूद परिचालन की कम लागत, सेवाओं की ऊंची गुणवत्ता तथा कुशल श्रम शक्ति की सुलभ उपलब्धता के कारण भारत हाल के वर्षों में सॉफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि दर को बनाए रखने में सफल रहा है (बॉक्स II.33)।

सारणी 2.76: भारत की सेवाओं के निर्यातों की संरचना

वर्ष	राशि (बिलि.अम. डॉलर)	सेवाओं के कुल निर्यात में हिस्सा (प्रतिशत)					
		यात्रा	परिवहन	बीमा	जीएनआईई	सॉफ्टवेयर	विविध *
1	2	3	4	5	6	7	8
1970-71	0.3	16.8	49.7	5.5	13.7	0.0	14.4
1980-81	2.8	43.5	16.3	2.3	4.0	0.0	33.9
1990-91	4.6	32.0	21.6	2.4	0.3	0.0	43.6
2000-01	16.3	21.5	12.6	1.7	4.0	39.0	21.3
2005-06	57.7	13.6	11.0	1.8	0.5	40.9	32.1
2006-07	73.8	12.4	10.8	1.6	0.3	42.4	32.4
2007-08	90.1	12.6	11.1	1.8	0.4	44.7	29.4
2008-09	101.2	10.8	10.9	1.4	0.4	46.4	30.1

*: सॉफ्टवेयर सेवाओं को छोड़कर जीएनआईई : सरकार, अन्यत्र शामिल न किए गए

इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप, 2007 में भारत विश्व में कंप्यूटर तथा सूचना सेवाओं का प्रमुख निर्यातक देश बना रहा(सारणी 2.78)।

II.6.27 प्रमुख सेवाओं के बीच, वैश्विक आर्थिक मंदी के फलस्वरूप देश में पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय कमी आने के कारण 2008-09 के दौरान यात्रा प्राप्तियों में प्रतिकूल असर पड़ा(सारणी 2.79)। यह 2003-04 से 2007-08 के दौरान की स्थिति के ठीक विपरीत है जिस दौरान भुगतान प्रणाली में उदारीकरण के कारण कारोबारी तथा अवकाश यात्रा, बढ़ते वैश्वीकरण और सेवाओं के बढ़ते निर्यात के कारण पर्यटन आय में यथेष्ट वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर, इस अवधि में बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से यात्रा भुगतान की राशि में भी वृद्धि हुई जो पण्य तथा सेवा व्यापार में वृद्धि के साथ कारोबार तथा अवकाश यात्रा में वृद्धि, निवासियों की अवशिष्ट आय में बढ़ोतरी तथा उदारीकृत भुगतान व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है।

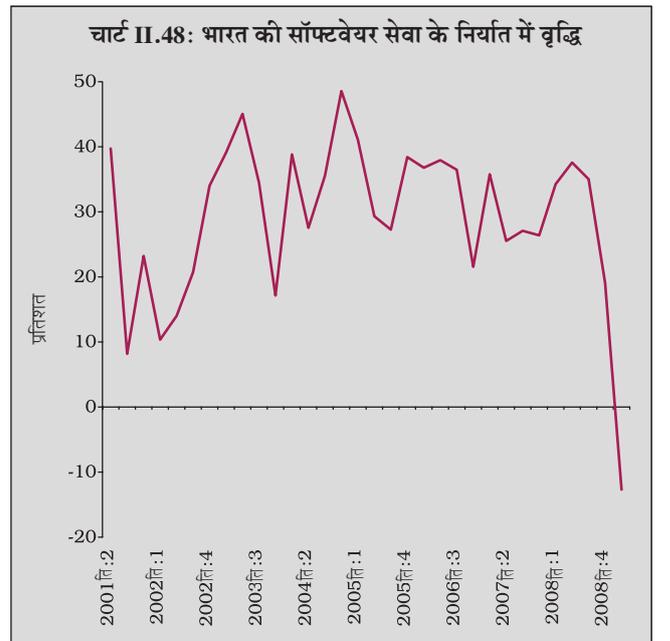
II.6.28 वैश्विक व्यापार में गिरावट की इस पृष्ठभूमि में, 2008-09 में तिमाहियों के दौरान वृद्धि दर में घट-बढ़ के साथ

सारणी 77: वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा

वर्ष	(प्रतिशत)	
	वस्तुएं	सेवाएं
1	2	3
1995	0.6	0.6
2000	0.7	1.1
2005	1.0	2.2
2007	1.1	2.6

स्रोत : भुगतान संतुलन सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका 2008, आइएमएफ; तथा भारतीय रिज़र्व बैंक।

कारोबारी सेवा निर्यात में थोड़ी-सी कमी आई और वर्ष की दूसरी छमाही में इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। 2008-09 के दौरान जहां कारोबार तथा प्रबंधन परामर्शी सेवाओं से प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई, वहीं व्यापार संबद्ध सेवाओं तथा आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाओं से संबंधित व्यापार से प्राप्त राशि में कमी आई। कारोबारी सेवाओं के सभी प्रमुख घटकों की मांग में कमी आने से भुगतान में भी कमी आई। 2008-09 के दौरान विल्लीय सेवाओं से प्राप्त राशियों में वृद्धि हुई जबकि मुख्यतः वर्ष की अंतिम तिमाही में सेवाओं में उल्लेखनीय कमी आने से भुगतानों में कमी आई (सारणी 2.80)।



बॉक्स II.33

सॉफ्टवेयर निर्यात: परिदृश्य तथा संभावनाएं

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी तथा कारोबार प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग (आइटी-बीपीओ) उद्योग, जिसमें बढ़ते वैश्वीकरण से प्राप्त लाभ के कारण असामान्य वृद्धि हुई, वृद्धि में योगदान, निर्यात आय, निवेश, रोजगार तथा सामग्रिक आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से समय के साथ अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। बाह्य मांग पर इस क्षेत्र की उल्लेखनीय निर्भरता को देखते हुए, वैश्विक मंदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के बावजूद परिचालन की कम लागत, उत्पादों और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, तथा सुलभ उपलब्ध कुशल श्रम शक्ति के कारण भारत सॉफ्टवेयर निर्यात का एक आकर्षक स्रोत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तर अमरीका तथा यूरोप के साथ अनुकूल समय क्षेत्र अंतर भारतीय कंपनियों को चौबीसों घंटे अंतरराष्ट्रीय परिचालन तथा ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात देश के व्यापार घाटे की उल्लेखनीय रूप से भरपाई करता आ रहा है और इसने चालू खाते के घाटे को संतोषजनक स्तर पर बनाये रखने में मदद की है। वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट तथा बाह्य मांग पर पड़े संबंधित दबावों के बावजूद 2008-09 के दौरान सॉफ्टवेयर तथा आइटी समर्थित सेवाओं के निर्यातों में लगभग 16 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान, कुल सॉफ्टवेयर निर्यातों में से आइटी सेवाओं का योगदान 57.2 प्रतिशत था जिसके बाद बीपीओ निर्यात (27.4 प्रतिशत) तथा इंजीनियरी सेवाओं तथा प्रोडक्ट निर्यात (15.3 प्रतिशत) का क्रम था। नियत मूल्य संविदा, ऑनसाइट से ऑफशोर की ओर जाने तथा एंड-टू-एंड रूपांतरण डीलियों के कारण सॉफ्टवेयर निर्यात को समर्थन मिला। साथ ही, विविधीकरण पर जोर दिए जाने के कारण ऊर्ध्व तथा भौगोलिक वृद्धि मूल बाजारों के लगभग तीन गुना थी।

वर्षों के दौरान भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात सुदृढ़ बने रहने के बावजूद, संकट के कारण वैश्विक मांग में आई कमी ने निर्यात के निष्पादन को कुछ हद तक प्रभावित किया है। चूंकि वर्तमान वित्तीय संकट से प्रभावित कुछ बड़े वैश्विक बैंक भारतीय सेवा प्रदाताओं के बड़े ग्राहक रहे हैं अतः लागत को कम करने की दृष्टि से कुछ करारों के समाप्त किए जाने तथा कुछ के आकार में कमी किए जाने की संभावना है। अतः, सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय एसोसिएशन (नेस्कॉम) ने बड़े डीलियों के अभाव; वेंडरों के समेकन तथा मूल्यन के दबाव के कारण 2009-10 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में 4-7 प्रतिशत (लगभग 48-50 बिलियन अमरीकी अमरीकी डॉलर) की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। नेस्कॉम की 'पर्सपेक्टिव 2020: ट्रांसफॉर्म बिजनेस, ट्रांसफॉर्म इंडिया' शीर्षक एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संकट के कारण ग्राहकों के बजटों में अल्पकालीन कटौती (उदाहरणस्वरूप, विवेकाधीन आइटी निवेश) हो सकती है तथा कुछ खंडों में मूल्यांकन का दबाव बढ़ सकता है विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों (उदाहरणस्वरूप, बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र तथा बीमा अथवा बीएफएसआइ) एवं भौगोलिक विस्तारों (उदाहरणस्वरूप, यूएस, पश्चिमी यूरोप) में।

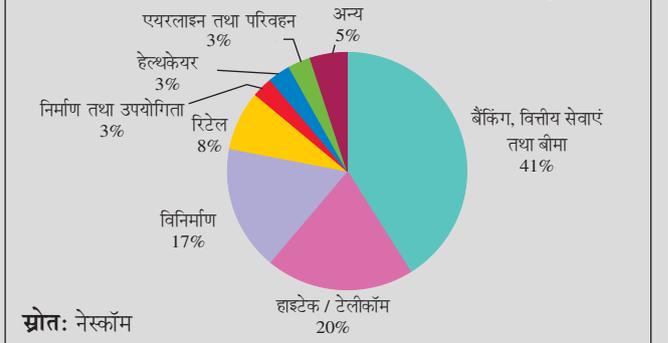
नेस्कॉम के अनुसार 2007-08 के दौरान जहां यूएस (60 प्रतिशत) तथा यूके (19 प्रतिशत) भारत के आइटी-बीपीओ निर्यात के सबसे बड़े बाजार के रूप में बने रहे वहीं यह उद्योग अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से महाद्वीपीय यूरोप में, जहां 2003-04 से 2007-08 के दौरान निर्यात में 51 प्रतिशत से भी अधिक की चक्रवृद्धि दर पर वार्षिक वृद्धि हुई, में भी सुदृढ़ता से विस्तार कर रहा है। उत्पादकता

में तीव्र फोकस के साथ भौगोलिक विस्तार, बेंचमार्किंग, तथा बढ़ी हुई परिचालनगत दक्षता की रणनीति से उद्योग को सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के वैश्विक लीडर के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता बनाये रखने में मदद मिलेगी।

नेस्कॉम के अनुसार उद्योग का अनुलंब बाजार एक्सपोजर विभिन्न परिपक्व तथा उभरते क्षेत्रों में विविधीकृत था। भारतीय आइटी-बीपीओ निर्यातों के लिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा (बीएफएसआइ) सबसे बड़े अनुलंब बाजार थे। जिसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार का स्थान था और आइटी-बीपीओ निर्यातों में 2007-08 में इनका कुल हिस्सा लगभग 61 प्रतिशत था (चार्ट क)। ग्राहकों की दृष्टि से जो समेकन, एकीकरण, तथा विनियमन पर था फोकस और इनसे भारतीय आइटी उद्योग के लिए कारोबार की नई संभावनाएं उभरकर आने की संभावनाएं हैं।

नेस्कॉम के अनुसार वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात का बाजार (कुल राजस्व संभावनाएं) इस समय के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों (यूएस, पश्चिमी यूरोप तथा जापान) में बढ़ता रहेगा और 2020 तक यह बढ़कर 500 से 550 बिलियन अमरीकी डॉलर तक हो जाने की संभावना है। कारोबारी सेवाओं की 610 से 720 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल राजस्व संभावना को शामिल करने पर वैश्विक मेगाट्रेंड के कारण बाजार के वर्तमान के 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020 तक 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने की संभावना है। भारत का आइटी संबंधी निर्यात, ग्राहकों की मांग में वृद्धि तथा दक्ष कर्मियों की अधिक संख्या में उपलब्धता के कारण तीन गुना बढ़कर 2020 तक 175 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने की संभावना है। नेस्कॉम के अनुसार वैश्विक मंदी के कारण अल्पावधि में वैश्विक आइटी खर्च में कमी आने से भारत का प्रौद्योगिकी तथा कारोबारी सेवा निर्यात 2011-12 तक 65 से 75 बिलियन अमरीकी डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है।

चार्ट क: 2007-08 में भारतीय आइटी-बीपीओ निर्यातों के लिए अनुलंब बाजार



संदर्भ:

1. 'नेस्कॉम (2009), पर्सपेक्टिव 2020: ट्रांसफॉर्म बिजनेस, ट्रांसफॉर्म इंडिया' अप्रैल।
2. (2009) प्रेस प्रकाशनी, जुलाई 29।
3. (2009), 'स्ट्रैटेजिक रिव्यू 2009-दि आइटी इंडस्ट्री इन इंडिया' फरवरी।

सारणी 2.78: कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

श्रेणी	देश	2000	2005	2007
1	2	3	4	5
1	भारत	6.3	22.0	37.0
2	आयरलैंड	7.5	19.6	26.1
3	ब्रिटेन	4.3	11.2	14.1
4	यू.एस.ए.	5.6	7.3	12.7
5	जर्मनी	3.8	8.4	12.2
6	स्वीडन	1.2	2.7	6.5
7	इजराइल	4.2	4.5	5.8
8	स्पेन	2.0	3.6	5.3
9	कनाडा	2.4	3.6	4.4
10	चीन	0.4	1.8	4.3

स्रोत : भुगतान संतुलन सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका 2008 तथा भारतीय रिजर्व बैंक।

निजी अंतरण

II.6.29 निजी अंतरणों में विदेश स्थित भारतीय कामगारों द्वारा परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजा गया विप्रेषण, अनिवासी भारतीय रुपया जमाराशि से स्थानीय आहरण, पैसेंजर बैगेज के माध्यम से लाए गए सोने और चांदी तथा पुण्यार्थ/ धार्मिक संस्थाओं को दिया गया निजी उपहार/दान शामिल होते हैं। निजी अंतरण प्राप्तियों, जिनमें मुख्यतः विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजा गया विप्रेषण होता है, में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में वृद्धि हुई (सारणी 2.81)। तथापि, विप्रेषण के तिमाही घटबढ़ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने से रोजगार की संभावना पर प्रतिकूल असर पड़ने तथा तेल की

सारणी 2.79: भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन तथा विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या

वर्ष (कैलेंडर)	आगमन (मिलियन)	वृद्धि दर (%)	प्रस्थान (मिलियन)	वृद्धि दर (%)
1	2	3	4	5
2000	2.65	6.7	4.42	7.3
2001	2.54	-4.2	4.56	3.4
2002	2.38	-6.0	4.94	8.2
2003	2.73	14.3	5.35	8.3
2004	3.46	26.8	6.21	16.1
2005	3.92	13.3	7.18	15.6
2006	4.45	13.5	8.34	16.1
2007	5.08	14.3	9.78	17.3
2008	5.37	5.6

.. : अनुपलब्ध

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

कीमतें तेजी से घटने के कारण तेल निर्यातक खाड़ी के देशों, जहां से भारत में विप्रेषणों का प्रमुख हिस्सा आता है, में प्रवासी श्रमिकों की मांग प्रभावित होने से 2008-09 की दूसरी छमाही में विप्रेषणों में कमी आई (चार्ट II.49)।

II.6.30 अनिवासी भारतीय जमाराशियों के बहिर्वाह का एक प्रमुख हिस्सा स्थानीय आहरण के रूप में होता है और यह राशि वस्तुतः देश से बाहर न भेजकर देश में ही उपयोग की जाती है जिसके कारण ये राशियां बिना किसी प्रतिदान के एकपक्षीय अंतरण के समान होती हैं। ऐसे स्थानीय आहरण/ चुकौतियां पूंजी खाते में बाह्य देयता के रूप में नहीं रह जातीं। 2008 के दौरान भारत ने विप्रेषण प्राप्त करने वाले विश्व के प्रमुख देश के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा और ऐसे आप्रवाह में अपेक्षाकृत स्थिरता

सारणी 2.80: सॉफ्टवेयर से इतर विविध प्राप्तियां और भुगतान

(बिलि.अम.डॉलर)

1	प्राप्तियां			भुगतान		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
1. संचार	2.3	2.4	2.2	0.8	0.9	1.0
2. निर्माण	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9
3. वित्तीय	3.1	3.2	3.9	3.0	3.1	3.0
4. समाचार एजेंसी	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.4
5. रॉयल्टी, कॉपीराइट और लाइसेंस शुल्क	0.1	0.2	0.1	1.0	1.1	1.8
6. कारोबारी सेवाएं	14.5	16.8	16.3	15.9	16.7	15.3
7. वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक	0.2	0.6	0.7	0.1	0.2	0.3
8. अन्य	2.6	2.1	5.6	4.5	4.2	1.9
जोड़(1 से 8)	23.9	26.4	30.5	26.2	27.3	24.5

सारणी 2.81: भारत में निजी अंतरणों की संरचना

(बिलि.अम.डॉलर)

वर्ष	कुल निजी अंतरण	जिसमें से			
		परिवार के रखरखाव के लिए आवक विप्रेषण	अनिवासी भारतीय जमाराशियों से स्थानीय आहरण/ मोचन	अनिवासी भारतीय जमाराशियों से स्थानीय आहरण/ मोचन	अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल चुकींती के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6
2005-06	25.0	10.5	12.5	49.9	82.8
2006-07	30.8	14.7	13.2	42.8	84.7
2007-08 आं. सं.	43.5	21.9	18.9	43.5	64.7
2008-09 प्रा.	46.4	23.1	20.6	44.5	62.9
आं. सं. : आंशिक संशोधन	प्रा. : प्रारंभिक				

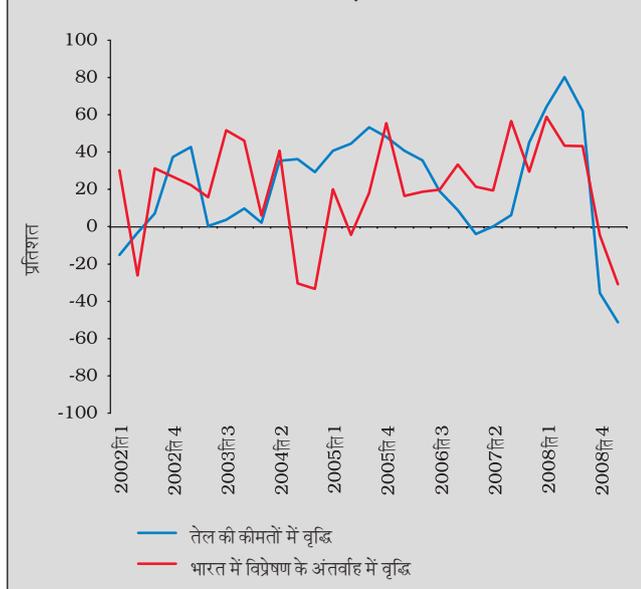
थी (सारणी 2.82)। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट तथा विकासशील देशों में प्राप्त होने वाले विप्रेषणों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि मूल देश की गतिविधियों के कारण भारत में प्राप्त होने वाले विप्रेषणों में कमी आएगी। परंतु, अब तक के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि भारत में प्राप्त होने वाले विप्रेषणों पर वैश्विक वित्तीय संकट का कोई खास असर नहीं पड़ा (बॉक्स II.34)।

चालू खाता शेष

II.6.31 वैश्विक वित्तीय आघातों ने भारत के भुगतान संतुलन को मुख्यतः व्यापार चैनल के माध्यम से प्रभावित किया। वैश्विक

मांग में कमी के कारण निर्यात में शीघ्रता से कमी आने तथा 2008-09 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से कमी आने के बावजूद देशी मांग में कमी के प्रत्युत्तर में अपेक्षाकृत देरी से आयात में कमी आने से व्यापार घाटा व्यापक हो गया। वर्ष के दौरान व्यापार घाटे के काफी व्यापक हो जाने के कारण समग्र चालू खाते पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात की तुलनात्मक सुदृढ़ता तथा विदेश स्थित भारतीयों के विप्रेषणों के कारण अंशतः कम किया जा सका। तथापि, 2008-09 की अंतिम तिमाही की उल्लेखनीय विशेषता निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से कमी आने से व्यापार घाटे का कम हो जाना थी, जिसके कारण अदृश्य मद अधिशेष की निरंतरता के कारण तिमाही के दौरान अच्छा चालू खाता अधिशेष रहा। अदृश्य मद

चार्ट II.49: तेल की कीमतों में घटबढ़ और भारत में विप्रेषण अंतरवाह



सारणी 2.82: कामगारों के विप्रेषण-सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश

देश	2000	2005	2006	2007	2008#
1	2	3	4	5	6
1 भारत	12.9	21.3	25.4	38.7	52.0
2 चीन	6.2	20.3	23.3	32.8	40.6
3 मैक्सिको	7.5	23.1	26.9	27.1	26.3
4 फिलीपींस	6.2	13.6	15.3	16.3	18.6
5 फ्रान्स	8.6	11.9	12.3	13.7	15.1
6 स्पेन	4.5	8.0	8.9	10.7	11.8
7 जर्मनी	3.6	6.9	7.6	9.8	11.1
8 पोलन्ड	1.7	6.5	8.5	10.5	10.7
9 नाइजीरिया	1.4	3.3	5.4	9.2	10.0
10 इजिप्त	2.9	5.0	5.3	7.7	9.5

#: अनुमान
 स्रोत: विश्व बैंक

बॉक्स II.34

विप्रेषणों पर वैश्विक मंदी का प्रभाव

कामगारों द्वारा भारत में किए गए विप्रेषण ने पूर्व में विशेष रूप से उल्लेखनीय पूंजी बहिर्वाह अथवा प्रतिकूल बाह्य आघातों की स्थिति में, भारत के भुगतान संतुलन को पर्याप्त लचीलापन तथा सुदृढ़ता प्रदान किया था। यह धारणा बनी हुई है कि मूल देश में वैश्विक मंदी तथा रोजगार की संभावना कमजोर पड़ने पर भारत का आवक विप्रेषण प्रवाह प्रभावित हो सकता है। विश्व बैंक के अनुमान (जुलाई 2009) के अनुसार विकासशील देशों में प्रभावित होने वाले विप्रेषणों में 2009 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है जबकि यह 2007 के 285 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2008 में 328 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था। विकासशील देशों के बीच, प्रवासी नागरिकों से विप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष के देशों में भारत, चीन तथा मैक्सिको थे। विश्व बैंक के संशोधित परिदृश्य के अनुसार, 2008 की अंतिम तिमाही में विप्रेषणों के प्रवाह में जो कमी आई थी वह 2009 की पहली छमाही में भी जारी रही। यूएस के रोजगार बाजार में कमजोरी की स्थिति के जारी रहने से दक्षिण अमरीका तथा कैरेबियन क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले आधिकारिक विप्रेषण प्रवाहों में 2009 की पहली छमाही में उल्लेखनीय रूप से कमी आई। इसके विपरीत, 2009 में दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया में विप्रेषण प्रवाहों में सुदृढ़ वृद्धि जारी रही। यह आंशिक रूप से इसलिए भी है कि एशियाई आप्रवासियों के नियोजन के प्रमुख स्थल अर्थात् खाड़ी सहयोग काउंसिल (जीसीसी) के देशों ने आप्रवासियों के नियोजन में उल्लेखनीय रूप से कमी नहीं की। जीसीसी के देश संचित रिजर्व के निधीयन से ढांचागत विकास की दीर्घावधि रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं तथा यह संभावना कम है कि ऐसे निवेश की गति को कम किया जाएगा तथा आप्रवासी कामगारों को बड़ी संख्या में काम से निकाला जाएगा। दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया में विप्रेषणों में वृद्धि का दूसरा कारण विप्रेषण के प्रेरक कारण में बदलाव आना है, अर्थात् आस्तियों के मूल्यों में गिरावट, ब्याज दर अंतर में क्रमशः वृद्धि तथा स्थानीय मुद्रा के मूल्यों से कारण खपत की अपेक्षा निवेश को तरजीह दिए जाने के कारण इन देशों ने आप्रवासियों के निवेश को आकर्षित किया। 2008 में भारत में विप्रेषण में तेज वृद्धि का यह एक प्रमुख कारण है। 2009 में सभी विकासशील देशों में विप्रेषण प्रवाहों में कमी आने की संभावना है। सभी विकासशील देशों के बीच 2009 में यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में सबसे अधिक गिरावट (15 प्रतिशत) आने की संभावना है। तथापि, दक्षिण एशिया में विप्रेषण प्रवाहों में 4 प्रतिशत की थोड़ी-सी कमी आने की संभावना है। इन प्रवाहों में 2010 और 2011 में सकारात्मक वृद्धि होने की संभावना है।

1980 के दशक में मध्य-पूर्व के तेल की भारी मांग तथा 1990 के दशक की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चलते भारत में कामगारों के विप्रेषणों में वृद्धि हुई तथा इसके कारण भारत विश्व में सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया। विप्रेषणों ने भारत के वणिक् व्यापार घाटे को काफी हद तक कम करने में मदद की। अन्य पूंजी खाता मदों

जैसे, एनआरआई जमाराशियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में, ऐसे अंतरणों की तुलनात्मक स्थिरता ने अन्य खातों पर पड़े दबावों के समय में चालू खाता घाटे को समुचित स्तर पर बनाए रखने में मदद की। परंतु, वैश्विक मंदी के दौर के बाद यह आशंका है कि यूएस तथा यूरोप में मंदी के कारण रोजगार में कमी आने से प्रवासी कामगार बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी से न हटाये जाने पर भी वित्तीय संकट के साथ सामंजस्य लाने के प्रयास में लागतों में कटौती के प्रयास के चलते कामगारों को आम तौर पर कम मजदूरी स्वीकार करना पड़ सकता है। यह भी आशंका की जा रही है कि खाड़ी के देशों में काम करने वाले श्रमिकों का प्रति-प्रव्रजन हो सकता है जिसके कारण विप्रेषणों के अंतर्वाह तथा एनआरआई जमाराशियों में कमी आएगी। खाड़ी क्षेत्र का निर्माण उद्योग, विशेष रूप से यूएई का, वैश्विक आर्थिक गिरावट के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है और इसके कारण निर्माण उद्योग में काम करने वाले लाखों कामगारों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसके अतिरिक्त, तेल की कीमतों में कमी के कारण खाड़ी क्षेत्र के कामगारों की आय में कमी आने से भारत में विप्रेषण से जुड़े अप्रवाह में भी कमी आ सकती है।

उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट होता है कि वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारत के आवक विप्रेषणों पर उल्लेखनीय रूप से नहीं पड़ा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में 2007 के 38.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2008 में उल्लेखनीय रूप से अधिक अर्थात् 52 बिलियन अमरीकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ। रुपए का मूल्योस, सितंबर 2008 से एनआरआई जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी तथा तेल की अनिश्चित कीमतें जैसे कई कारकों के चलते ऐसा हो सकता है जिसने बेहतर वृद्धि की संभावना के कारण कामगारों को बचाव व्यवस्था के रूप में भारत में अपने पैसे भेजने के लिए प्रेरित किया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व के अध्ययन के अनुसार, क्षेत्रवार रूप में उत्तर अमरीका का हिस्सा भारत में भेजे जाने वाले कुल विप्रेषणों का लगभग 44 प्रतिशत था जिसके बाद मध्य-पूर्व (24 प्रतिशत) तथा यूरोप (13 प्रतिशत) का स्थान था। उन्नत अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट की स्थिति तथा मध्य-पूर्व में वृद्धि दर में तेज गिरावट को देखते हुए अल्पावधि में विप्रेषणों में कुछ कमी आ सकती है।

संदर्भ:

1. रथ, डी.,एस. महापात्र तथा जेड जू (2008), 'आउटलुक फॉर रेमिटेन्सेस 2008 - 10' डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स ग्रुप, माइग्रेशन एंड रेमिटेन्सेस टीम, विश्व बैंक, नवंबर।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (2006), 'अनिवासी भारतीयों से विप्रेषण: अंतरण,लागत तथा समय की पद्धति का अध्ययन', भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर अंक में प्रकाशित लेख, 'भारत के भुगतान संतुलन में अदृश्य मदें'।
3. विश्व बैंक (2009), माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, संख्या 10 जुलाई,।

अधिशेष बढ़कर जीडीपी का 7.7 प्रतिशत हो जाने के बावजूद 2008-09 में चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का 2.6 प्रतिशत हो गया जो व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण था। 2005-06 से

2007-08 के दौरान अदृश्य मद में निरंतर वृद्धि होने से भारत के चालू खाता शेष का घाटा औसतन जीडीपी के 1.0 से 1.5 प्रतिशत के बीच रहा।

II.6.32 वैश्विक वित्तीय संकट ने 2008 में रूस और मलेशिया को छोड़कर, अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाते की स्थिति में गिरावट लाने का कार्य किया। जहां चीन, इंडोनेशिया तथा अर्जेंटीना जैसी कतिपय उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधिशेष में कमी आई वहीं ब्राजील, कोरिया तथा थाईलैण्ड जैसे अन्य देशों का अधिशेष घाटे में बदल गया। अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत तथा मैक्सिको के हाल की अवधि के चालू खाता घाटे में और थोड़ी-सी वृद्धि हुई (सारणी 2.83)।

पूंजी खाता

II.6.33 लगभग सितंबर 2008 के मध्य से बाह्य परिवेश में अकस्मात प्रारंभ हुए परिवर्तन ने प्रतिकूल स्थिति का निर्माण किया जिसके कारण चलनिधि में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट आई तथा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने बढ़ती जोखिम विमुखता का परिचय दिया। अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा देशी इक्विटी बाजारों से कुछ निधियों का आहरण किया गया जो वैश्विक डीलिवरेजिंग प्रक्रिया तथा भारतीय कंपनियों की विदेशी वित्तीयन के स्रोतों तक पहुंच में कमी आना प्रतिबिंबित करता है। इसके परिणामस्वरूप, 2008-09 की तीसरी तिमाही में पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी का बहिर्वाह किया गया। जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों

में सुदृढ़ता देखी गई वहीं बाह्य वाणिज्यिक उधारों तथा व्यापार ऋणों तक पहुंच में कुछ कठिनाइयां आयीं। समग्र रूप में 2008-09 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजार की उथल-पुथल का प्रतिकूल प्रभाव 2008-09 के दौरान कम सकल पूंजी आप्रवाह के रूप में परिलक्षित हुआ (सारणी 2.84)। वस्तुतः, 1998-99 की पहली तिमाही के बाद से 2008-09 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में पहली बार पूंजी खाता शेष ऋणात्मक हो गया जो मुख्यतः पोर्टफोलियो निवेश, बैंकिंग पूंजी तथा अल्पावधि व्यापार ऋण में निवल बहिर्वाह के कारण था। यह प्रवृत्ति 2008-09 की चौथी तिमाही के दौरान भी जारी रही। इन प्रतिकूल घटनाक्रमों के बावजूद विदेशी प्रत्यक्ष प्रवाहों की सुदृढ़ता ने लंबी अवधि के निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को परिलक्षित किया।

II.6.34 भारत जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में उच्च जीडीपी वृद्धि हेतु मौद्रिक समुच्चयों, जिसके लिए आधार मुद्रा में भी वृद्धि आवश्यक है, में भी तदनु रूप वृद्धि जरूरी है। इस सीमा तक, पूंजी प्रवाह तथा केन्द्रीय बैंक के तुलनपत्र में अनिष्ट्रभावीकृत विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अपेक्षित दर पर आधार मुद्रा का विस्तार करने में सहायक होती है। तथापि, ऐसी अपेक्षाओं से अधिक पूंजी प्रवाह हेतु निष्ट्रभावीकरण एवं अधिक सक्रिय मौद्रिक तथा समष्टि आर्थिक प्रबंधन की जरूरत होती है। इस प्रकार, वर्तमान वित्तीयन आवश्यकता से काफी अधिक मात्रा में पूंजी के आप्रवाह से भारी देशी ऋण तथा

सारणी 2.83: चुनिंदा देशों में व्यापार और चालू खाता शेष

(जीडीपी का प्रतिशत)

देश	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू खाता शेष						व्यापार शेष					
अर्जेंटीना	6.3	2.1	1.7	2.3	1.6	1.4	13.2	8.7	7.2	6.6	5.1	4.9
ब्राजील	0.8	1.8	1.6	1.3	0.1	-1.8	4.5	5.1	5.1	4.3	3.0	1.6
चीन	2.8	3.6	7.2	9.5	11.0	10.0	2.7	3.1	6.0	8.2	9.3	..
भारत #	2.3	-0.4	-1.2	-1.1	-1.5	-2.6	-2.3	-4.8	-6.4	-6.8	-7.8	-10.3
इंडोनेशिया	3.5	0.6	0.1	3.0	2.4	0.1	10.5	7.8	6.1	8.1	7.6	4.6
कोरिया	1.9	3.9	1.8	0.6	0.6	-0.7	3.4	5.2	3.9	2.9	2.8	0.6
मलेशिया	12.0	12.1	15.0	16.7	15.4	17.4	23.3	22.1	24.0	23.4	20.0	..
मैक्सिको	-1.0	-0.7	-0.5	-0.5	-0.8	-1.4	-0.8	-1.2	-0.9	-0.6	-1.0	-1.6
रूस	8.2	10.1	11.0	9.5	5.9	6.1	13.9	14.5	15.5	14.1	10.1	10.7
थाईलैंड	3.4	1.7	-4.3	1.1	5.7	-0.1	7.8	6.7	1.9	6.7	10.4	..
तुर्की	-2.5	-3.7	-4.6	-6.0	-5.8	-5.7	-4.4	-5.8	-6.8	-7.7	-7.2	-7.3

: आंकड़े वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के हैं।

.. : अनुपलब्ध

टिप्पणी : (-) घाटा सूचित करता है

स्रोत : विश्व आर्थिक परिदृश्य तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अं.मु.कोष, 2009.

सारणी 2.84: सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अंतर्वाह			बहिर्वाह		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	23.6	36.8	36.3	15.9	21.4	18.8
2. पोर्टफोलियो निवेश	109.6	235.9	128.7	102.6	206.4	142.7
3. बाह्य सहायता	3.8	4.2	5.0	2.0	2.1	2.4
4. बाह्य वाणिज्यिक उधार	20.9	30.4	15.4	4.8	7.7	7.2
5. अनिवासी भारतीय जमाराशियां	19.9	29.4	37.1	15.6	29.2	32.8
6. बैंकिंग पूंजी, अ.भा. जमाराशियों को छोड़कर	17.3	26.4	27.9	19.7	14.8	35.6
7. अल्पावधि व्यापार ऋण	30.0	48.9	39.7	23.4	31.7	45.5
8. रुपया ऋण चुकौती	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
9. अन्य पूंजी	8.2	20.9	12.4	4.0	11.4	8.2
कुल (1 से 9)	233.3	433.0	302.5	188.1	325.0	293.3

मौद्रिक वृद्धि, इक्विटी तथा अन्य आस्तियों के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा देशी मांग में आम बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। पूंजी के प्रवाह में अकस्मात विपर्यय आने से मौद्रिक तथा समष्टि आर्थिक प्रबंधन में काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं। पूंजी के प्रवाह में विपर्यय, जैसा कि हाल के वित्तीय संकट के दौरान देखा गया, तेज हो सकता है जिसके कारण बैंक ऋण में मजबूरी वश समायोजन करना पड़ता है तथा आस्तियों की कीमतें गिरकर निचले स्तर तक आ जाती हैं। इस प्रकार, यदि पूंजी प्रवाह में देखे जाने वाले भारी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति का प्रबंधन समय पर न किया जाए तो इससे समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है (बॉक्स II.35)।

विदेशी निवेश

II.6.35 तीव्र वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के बावजूद 2008-09 के दौरान भारत में विदेशी निवेश मुख्यतः पर्याप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्रेरित था, यद्यपि संकट के कारण उत्पन्न डिलीवरेजिंग से भारी मात्रा में पोर्टफोलियो बहिर्वाह भी हुआ (चार्ट II.50)। वर्ष के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी तथा पुनर्निवेशित आय से प्रेरित था (सारणी 2.85)। 2008-09 के दौरान विदेशी फर्मों द्वारा स्थानीय इक्विटी बाजारों तक पहुंच को व्यापक बना कर इक्विटी मार्ग को समर्थन देने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु किये गये और उपायों ने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बाजार में देखे गये उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद की।

II.6.36 एफडीआई को मुख्यतः 21.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ विनिर्माण क्षेत्र तथा 19.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वित्तीय सेवाओं में लगाया गया। मॉरीशस के जरिए किया गया निवेश 44.8 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे अधिक था, उसके बाद 14.8 प्रतिशत हिस्से के साथ सिंगापुर का स्थान था (सारणी 2.86)। पिछली प्रवृत्ति के विपरीत, हाल की अवधि में भारत में एफडीआई प्रवाह में हुई बढ़ोतरी के साथ-साथ बाहरी इक्विटी निवेश में भी भारी वृद्धि हुई है जो नई प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के साथ-साथ भारतीय फर्मों द्वारा विदेश में उत्पादन, विपणन तथा वितरण नेटवर्क स्थापित करने के प्रयासों के कारण थी।

II.6.37 वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने और विदेशी मुद्रा बाजार में दबावों के बावजूद 2008-09 की दूसरी छमाही में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। इस प्रकार, वैश्विक ऋण बाजारों में स्थितियां बिगड़ने के बावजूद भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों ने देशी विदेशी मुद्रा बाजारों से चलनिधि लेकर विदेशों में विस्तार करना जारी रखा (सारणी 2.87)। बाहरी निवेश को उदार करने के उद्देश्य से 2008-09 के दौरान किये गये विशिष्ट उपायों में भारतीय कंपनियों, सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंडों के निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना, तथा भारत से बाहर उसी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था में निवेश करने हेतु अनुमत विनिर्माण / शैक्षणिक / स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत ट्रस्टों तथा समितियों को अनुमति दिया जाना शामिल है।

बॉक्स II.35

वैश्विक वित्तीय संकट और पूंजी प्रवाह

1980 के दशक से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रवाह तेजी से बढ़ा है, परंतु बीच-बीच में उतार-चढ़ाव भी आये हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के बड़े प्रवाह के कारणों में आकर्षण और विकर्षण के अनेक कारक रहे हैं। आकर्षण के जिन कारणों से उच्चतर पूंजी प्रवाह हुआ उनमें पिछले दशक के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी आना, समष्टि आर्थिक स्थिरता, पूंजी खाते में खुलापन तथा वृद्धि की प्रचुर संभावना रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के रुख को इस अर्थ में एक प्रमुख प्रेरक कारक माना जाता है कि मौद्रिक नीति के नरम रुख की अवधि तथा प्रतिफल की तलाश के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रवाह भारी मात्रा में होता है तथा मौद्रिक नीति के कड़े रुख के दौरान स्थिति इसके विपरीत होती है। इस प्रकार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति के चक्र ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के प्रवाह के चक्रों एवं उतार-चढ़ाव को प्रभावित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नवोन्मेषों ने भी पूंजी के दोतरफा प्रवाह में योगदान दिया है। समग्र रूप में, इन कारकों के फलस्वरूप उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है, हालांकि प्रवाह में बड़े उतार-चढ़ाव भी हुए हैं (वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति, 2009)।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की पिछली अवधियों के संकट की तरह हाल के वित्तीय संकट के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से पुनः अनुभव किये जा रहे पूंजी के विपर्यय सामान्यतः काफी शीघ्रता से हुए हैं तथा इसके कारण अर्थव्यवस्था में कष्टप्रद समायोजन लागत आई है। ऐसे विपर्यय तथा विदेशी मुद्रा भंडार में हुई हानि से केन्द्रीय बैंक के तुलनपत्र में संकुचन होता है तथा इससे घरेलू आस्तियों में की जाने वाली भरपाई के रूप में मौद्रिक प्रबंधन हेतु चुनौती पैदा होती है।

ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय निभाव की लंबी अवधि के दौरान सामान्यतः उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है। वर्तमान के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने पुनः मौद्रिक नीति में अत्यधिक नरमी का रुख अपनाया और नीतिगत दरें 2002 में देखे गये स्तर से भी नीचे चली गयीं। अमरीका में आधार मुद्रा में हाल के महीनों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई; कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी यही स्थिति रही। पिछले अनुभवों से यह कहा जा सकता है कि यदि हाल के मौद्रिक विस्तार को समय पर समेट नहीं लिया जाता है तो इस प्रकार के बड़े स्तर के मौद्रिक विस्तार से, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निकट भविष्य में भारी मात्रा में पूंजी का आप्रवाह हो सकता है (मोहन, 2009)।

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ होने से पूर्व, हाल के वर्षों में भारत में भारी मात्रा में पूंजी का प्रवाह हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा में खरीद के चलनिधि प्रभाव को आरक्षित नकदी निधि अनुपात में लगातार वृद्धि तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के जरिए निष्प्रभावी करना पड़ा। तथापि, लीमन ब्रदर्स के समाप्त हो जाने के बाद जो घटनाक्रम हुए उनके कारण पोर्टफोलियो निवेशकों ने अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह अपनी डीलिवरेजिंग की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में घरेलू इक्विटी बाजारों में भारी मात्रा में बिक्री करके प्राप्त राशि को प्रत्यावर्तित किया। समग्र रूप में, 2008-09 में निवल पूंजी आप्रवाह 2007-08 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था तथा इससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई क्योंकि पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसी स्थिति के कारण विदेशी मुद्रा बाजार तथा घरेलू मुद्रा बाजारों में दबाव बढ़ने से भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा तथा रुपया चलनिधि में वृद्धि हेतु विभिन्न उपाय करने पड़े। ऋण का सृजन करने वाले प्रवाहों में भी कमी आई जिससे ऋण की सीमित उपलब्धता तथा अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों से उधारियों की उच्च लागत प्रतिबिंबित होती है। पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने कई उपाय किए जिनके सकारात्मक परिणाम एनआरआई प्रवाहों में उल्लेखनीय सुधार तथा एफआईआई के अंतर्गत निवल आप्रवाह के रूप में, विशेष रूप से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 से, सामने आए। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने के बीच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में आई सुदृढ़ता एक सकारात्मक विशेषता है जो भारत को निवेश के एक पसंदीदा देश के रूप में प्रतिबिंबित करता है। समग्र रूप में, पूंजी प्रवाह पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव का प्रबंधन विदेशी मुद्रा भंडार से आहरण के जरिए किया गया ताकि वित्तीय बाजारों पर अत्यधिक प्रतिकूल असर डाले बिना प्रवाहों को आकर्षित किया जा सके। पूंजी खाते के विवेकपूर्ण प्रबंधन तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में स्व-बीमा ने भारत को संकट के कारण देश से जाने वाली पूंजी के असर को कम करने में मदद की।

संदर्भ:

1. मोहन, राकेश (2009), 'वैश्विक वित्तीय संकट: कारण, परिणाम तथा भारत की संभावनाएं' 23 अप्रैल 2009 को लंदन बिजनेस स्कूल में दिया गया भाषण।
2. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2009), पूंजी प्रवाह तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर सीजीएफएस कार्य-दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष डॉ. राकेश मोहन), जनवरी।

II.6.38 यद्यपि, 2007 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे अधिक पोर्टफोलियो अंतर्वाह प्राप्त करनेवाले देशों में एक प्रमुख देश था, तथापि वैश्विक वित्तीय संकट के व्यापक हो जाने से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेशों तथा अमरीकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर)/ ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों में 2008-09 में भारी बहिर्वाह देखा गया (देखें सारणी 2.85)। विश्व के प्रमुख स्टॉक

बाजारों में उतार-चढ़ाव एवं कमजोरियों तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से निधियों के आहरण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में भारतीय बाजारों से पोर्टफोलियो इक्विटी बहिर्वाह फरवरी 2008 से ही प्रारंभ हो गया था (देखें चार्ट II.50)। पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत उल्लेखनीय बहिर्वाह से एफआईआई द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार में इक्विटी की भारी बिक्री तथा एडीआर/जीडीआर

चार्ट II.50: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा निवल पोर्टफोलियो आप्रवाह में मासिक उतार-चढ़ाव



तथा एफसीसीबी के लिए विदेशी बाजारों में चलनिधि की अनुपलब्धता परिलक्षित हुई। 2008-09 के दौरान अगस्त तथा

दिसंबर 2008 को छोड़कर प्रत्येक माह एफआइआई में निवल बहिर्वाह होता रहा तथा सबसे अधिक बहिर्वाह अक्टूबर 2008 (5.3 बिलियन अमरीकी डॉलर) में हुआ। एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत अंतर्वाह में उल्लेखनीय कमी देखी गई जबकि सितंबर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान नगण्य अंतर्वाह हुआ।

ऋण प्रवाह

II.6.39 वैश्विक ऋण बाजार में तंगी की स्थिति के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऋण आप्रवाह में कमी आई और इसने 2008-09 के दौरान विशेष रूप से ईसीबी तथा व्यापार ऋण प्रवाह के जरिए भारत को भी प्रभावित किया (परिशिष्ट सारणी 53)। विदेशी ऋण बाजारों में चलनिधि की अनुपलब्धता तथा नये उधारकर्ताओं के लिए बढ़ते जोखिम प्रीमियम को प्रतिबिंबित करते हुए 2008-09 के दौरान भारत को सकल ईसीबी संवितरण में तेजी से कमी आई। 2008-09 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा सकल ईसीबी भुगतानों में भी थोड़ी-सी बढ़ोतरी हुई।

सारणी 2.85: भारत में विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2005-06	2006-07	2007-08 (अ)	2008-09 (अ)
1	2	3	4	5
अ. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	8,961	22,826	34,362	35,168
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ)	5,975	16,481	26,867	27,995
क) सरकार (एसआइए/एफआइपीबी)	1,126	2,156	2,298	4,699
ख) रिज़र्व बैंक	2,233	7,151	17,129	17,998
ग) शेयरों की खरीद*	2,181	6,278	5,148	4,632
घ) अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	435	896	2,292	666
II. पुनर्निवेशित आय	2,760	5,828	7,168	6,426
III. अन्य पूंजी #	226	517	327	747
आ. पोर्टफोलियो निवेश (क+ख+ग)	12,492	7,003	27,271	-13,855
क) जीडीआर/एडीआर	2,552	3,776	6,645	1,162
ख) एफआइआई @	9,926	3,225	20,328	-15,017
ग) अपतटीय निधियां और अन्य	14	2	298	-
इ. कुल (अ+आ)	21,453	29,829	61,633	21,313

अ: अनंतिम - : शून्य/नगण्य

* : फेमा, 1999 की धारा 6 के तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद से संबंधित।

: आंकड़े एफडीआई संस्थाओं के अंतर-कंपनी ऋण लेनदेनों से संबंधित हैं।

@ : आंकड़े एफआइआई द्वारा निधियों के निवल अंतर्वाह को दर्शाते हैं।

नोट: 1. अनिगमित संस्थाओं की इक्विटी पूंजी के आंकड़े तथा 2007-08 और 2008-09 के पुनर्निवेशित आय के आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं।

2. इस सारणी में प्रस्तुत विदेशी निवेश के आंकड़े देश में अंतर्वाह को दर्शाते हैं तथा हो सकता है कि ये अन्य सारणियों में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल न खाएं। वे एफआइआई द्वारा शेयर बाजारों में निवल निवेश संबंधी आंकड़ों से भी भिन्न हो सकते हैं।

सारणी 2.86: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह: देशवार और उद्योगवार*

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्रोत	2006-07	2007-08	2008-09अ	उद्योग	2006-07	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल एफडीआई	9,307	19,427	22,697	क्षेत्रवार अंतर्वाह	9,307	19,427	22,697
मारीशस	3,780	9,518	10,165	विनिर्माण	1,641	3,726	4,777
सिंगापुर	582	2,827	3,360	वित्तीय सेवाएं	1,330	3,850	4,430
यूएसए	706	950	1,236	निर्माण	967	2,551	2,237
साइप्रस	58	570	1,211	संचार सेवाएं	423	66	2,067
यूके	1,809	508	690	भू-संपदा संबंधी कार्यकलाप	431	1,336	1,886
नीदरलैंड	559	601	682	कंप्यूटर सेवाएं	824	1,035	1,647
जर्मनी	116	486	611	विविध सेवाएं **	298	1,901	1,458
फ्रांस	100	136	437	बिजली तथा अन्य बिजली उत्पादन	174	829	669
स्पेन	62	48	363	व्यावसायिक सेवाएं	2,425	1,158	643
रूस	25	1	306	परिवहन	165	816	401
जापान	80	457	266	ट्रेडिंग	82	176	400
इटली	57	21	249	रेस्तराँ और होटल	153	280	343
यूएई	215	226	234	खुदरा और थोक व्यापार	47	200	294
हांगकांग	60	106	155	शिक्षा, अनुसंधान और विकास	43	156	243
स्विटजरलैंड	57	192	135	खनन	42	461	105
अन्य	1,041	2,780	2,597	अन्य	262	886	1,097

* : इस सारणी के आंकड़े स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के अंतर्गत सिर्फ इक्विटी पूंजी से संबंधित हैं। फेमा, 1999 की धारा 6 की तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद तथा अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी को शामिल नहीं किया गया है।

** : विविध सेवाओं में समुदाय, सांस्कृतिक कार्यकलाप, कार्मिक, जनता, सफाई, स्वास्थ्य, मरम्मत, अंतरराष्ट्रीय और अन्य से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

अ: अंतिम

II.6.40 वैश्विक वित्तीय संकट ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार वित्त तक की पहुंच को बुरी तरह प्रभावित किया (बॉक्स II.36)। आइएमएफ के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2009) के अनुसार देश तथा प्रतिपक्षी जोखिमों में बढ़ोतरी के साथ व्यापार वित्त के स्प्रेड में 100-150 आधार अंक से लिबोर के ऊपर 400 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों में विद्यमान कठिन वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप तथा उधारदाता प्रतिपक्षी की बढ़ी हुई जोखिम विमुखता के कारण भारत को अल्पावधि व्यापार ऋण का सकल संवितरण 2007-08 की तुलना में कम था (देखें सारणी 2.84)। तथापि, मुख्यतः 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान देखी गई रोलओवर की कुछ समस्याओं के कारण 2008-09 के दौरान अल्पावधि व्यापार ऋण की चुकौतियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

II.6.41 बाह्य सहायता, अपनी प्रकृति के अनुसार, अनुचक्रीय नहीं होती। 2008-09 के दौरान भारत को प्राप्त बाह्य सहायता पिछले

वर्ष प्राप्त सहायता से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी 54)। भारत द्वारा दिए गए अनुदान तथा ऋण में उल्लेखनीय गिरावट नहीं थी (सारणी 2.88)।

सारणी 2.87: भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

उद्योग	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4
विनिर्माण	4,185	5,409	8,096
वित्तीय सेवाएं	28	88	143
गैर-वित्तीय सेवाएं	7,527	1,748	1,154
ट्रेडिंग	659	1,050	937
अन्य	1,499	10,435	6,450
कुल	13,898	18,730	16,780

* : नवीनतम सूचित संशोधित आंकड़ों पर आधारित। अतः ये आंकड़े भुगतान संतुलन के तहत प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

नोट: 1. आंकड़ों में इक्विटी और ऋण घटक शामिल हैं।

2. आंकड़े विदेश में भारतीय निवेश प्रस्तावों से संबंधित हैं (5 मिलियन अम.डॉ. तथा अधिक)।

बॉक्स II.36

व्यापार ऋण

2008-09 की दूसरी छमाही के वैश्विक ऋण संकुचन ने निर्यातकर्ताओं तथा आयातकर्ताओं को व्यापार ऋण तक पहुंच तथा उसकी लागत की दृष्टि से प्रभावित किया है। इसके लिए व्यापार ऋण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय लागू करने की जरूरत पड़ी। व्यापार ऋण सामान्यतः प्रतिपक्षियों के बीच विश्वास के स्तर तथा बैंकों से निधीयन अवश्यता की मात्रा के अनुसार विभिन्न रूप लेता है। जब लेनदेन पूर्णतः आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता के बीच होता है तो यह *अग्रिम में नकदी आधार पर* (वस्तुओं को भेजने से पूर्व भुगतान प्राप्त किया जाता है) अथवा *खुला खाता आधार पर* (भुगतान प्राप्त करने से पहले ही वस्तुएं भेज दी जाती हैं) किया जा सकता है। अन्यथा, बैंक पण्यों के विभिन्न देशों में आवागमन के लिए मददकर्ता की भूमिका अदा करते हैं तथा वास्तविक वस्तुओं की जमानत पर व्यापार उधारियों (इसे निर्यात कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है) के अतिरिक्त भुगतान न किये जाने की जोखिम को कम करने (जैसे, साख-पत्र) हेतु उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में हुई गतिविधियों ने व्यापार ऋण तथा वित्तीय ऋण के बीच के अंतर को अस्पष्ट कर दिया है तथा संकट के समय अन्य ऋणों की तुलना में व्यापार ऋण के भुगतान को वरियता दिये जाने से अंतरराष्ट्रीय बैंकों का विश्वास कम हो गया है। व्यापार ऋण भी वित्तीय तनावों के दौरान अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास में कमी आने से पूंजी के पलायन के प्रति अधिक जोखिम संभाव्यतापूर्ण हो गया है। व्यापार ऋण व्यवस्थाएं सामान्यतः अल्पावधि प्रकृति की तथा शीघ्रता से सममूल्य पर चुकाए जाने योग्य होने के कारण ये आसित की परिचालनगत रूप से ऐसी आसान श्रेणी होती हैं जिन्हें बढ़ी हुई जोखिम विमुखता के दौर में आसानी से कम किया जा सकता है तथा संकट के दौरान देश संबंधी एक्सपोजर में समग्र कटौती करने संबंधी बैंक की नीति के हिस्से के रूप में ये ऐसे परिपक्व होने वाले ऋण के रूप में होते हैं जिनका सामान्यतः रोलओवर नहीं किया जाता।

बिगड़ती वैश्विक वित्तीय बाजार स्थितियों के कारण बैंकों द्वारा व्यापार ऋण सहित सभी कार्यों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय प्रवाह की कुल मात्रा में नाटकीय रूप से कमी आई है। आइएमएफ के अनुसार निधि की उच्चतर लागत, चलनिधि प्रीमियम, तथा उच्चतर जोखिम ने मिलकर अल्पावधि व्यापार ऋण की कीमत में तीव्र बढ़ोतरी की है। चूंकि वित्त की उपलब्धता में कमी के साथ लागत में बढ़ोतरी में घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु किये गये हाल के प्रयासों को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता है, अतः व्यापार वित्त को समर्थन देने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास किये गये हैं। उदाहरणार्थ, जी-20 के देश व्यापार वित्त को समर्थन देने के लिए अगले दो वर्षों के दौरान कम से कम 250 बिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध कराने हेतु सहमत हुए हैं। इन प्रस्तावों में, चलनिधि की सामान्य कमी को दूर करने के लिए वित्तीयन के विभिन्न उपायों के उपयोग, गारंटी प्रदान करके जोखिम प्रीमियमों में कमी लाने के साथ-साथ निजी वित्तीय प्रवाहों को पुनः आकर्षित करना शामिल है।

यद्यपि, व्यापार वित्त की लागत में वृद्धि एक वैश्विक घटना है, तथापि व्यापार ऋण की उपलब्धता में कमी का अनुभव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (इएमइ), विशेष रूप से एशियाई इएमइ द्वारा अधिक किया जा रहा है, जहां अंतर क्षेत्रीय व्यापार कम लाभ मार्जिन वाली वस्तुओं में किया जाता है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात हेतु उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होती है। आइएमएफ-वित्त तथा व्यापार हेतु बैंकों के एसोसिएशन (बीएएफटी) के उन्नत, उभरती बाजार तथा विकासशील देशों के बैंकों द्वारा मध्यस्थन किए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त पर किए गए सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि बैंकों की निधियों की लागत में बढ़ोतरी होने से व्यापार वित्त की लागतों में तेजी से वृद्धि हुई जो कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अति प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों के मूल्य प्रभाव के असर से भी प्रभावी रहा है। विनियामकों द्वारा तथा बैंकों द्वारा अपनी उधारियों के लिए पूंजी का उच्चतर स्तर निर्धारित किये जाने के कारण बैंकों की निधियों की लागत तथा अपने ग्राहकों को दिये गये व्यापार ऋण की कीमत के बीच के स्प्रेड में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त, चूक/प्रतिपक्षी जोखिम के भय के कारण बैंकों को उधार संबंधी दिशानिर्देशों में कड़ाई करना पड़ रहा है। सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान मूल्यन की प्रवृत्ति 2009 में बनी रहेगी तथा यह सुझाव दिया है कि उभरते बाजार तथा पण्य व्यापार सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

व्यापार वित्त संबंधी समस्या देश / क्षेत्र विशिष्ट होने के साथ-साथ सेक्टर विशिष्ट भी है। भारत अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों में चलनिधि के संकुचन के संकट से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। सितंबर 2008 से विदेशी बाजारों में चलनिधि में तंगी के बावजूद भारत को संवितरित अल्पावधि ऋण परवर्ती महीनों में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की मासिक प्रवृत्ति के आसपास रहा। यद्यपि 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान के उच्चतर भुगतान परिपक्व हो रहे व्यापार ऋण के रोलओवर में कुछ समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, तथापि संवितरण की जारी प्रवृत्ति संकेत करती है कि अल्पावधि ऋण की चुकौती में कोई उल्लेखनीय समस्या नहीं आई। यह भारतीय आयातकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हासिल किये गये विश्वास का द्योतक है। इस संबंध में उठाये गये विभिन्न नीतिगत प्रयासों, जैसे व्यापार ऋण जुटाने हेतु सभी लगात सहित की उच्चतर सीमा में बढ़ोतरी, बैंकों द्वारा विदेश से उधारी हेतु उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी, एक्जिम बैंक को ऋण सुविधा तथा स्वैप सुविधा उपलब्ध कराया जाना आदि ने व्यापार वित्तीयन के दबाव को कम करने में सहायता की है।

संदर्भ:

1. डोर्से थॉमस (2009), 'ट्रेड फिनांस स्टम्बल्स', वित्त और विकास, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मार्च।
2. वांग, जियान-ये तथा हेलावे टेडसी (2005), 'एन ओवरव्यू', जे.वाइ.वांग तथा एम रोंची (संपा.) 'एक्सेस टू ट्रेड फिनांस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस: एन ओवरव्यू', अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

सारणी 2.88: विदेशी सरकारों को भारत का अनुदान तथा ऋण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2007-08			2008-09		
	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अ. योजना (विदेशी मामले)	63	12	75	73	25	98
आ.योजनेतर (i+ii+iii)	359	17	376	313	1	314
i. विदेशी मामले	349	0	349	304	0	304
बांग्लादेश	15	0	15	1	0	1
भूटान	132	0	132	121	0	121
नेपाल	25	0	25	22	0	22
अफ्रीकी देशों को सहायता	12	0	12	21	0	21
मालदीप	5	0	5	1	0	1
म्यांमार	5	0	5	7	0	7
श्रीलंका	7	0	7	7	0	7
मध्य एशिया	5	0	5	4	0	4
आइटीईसी कार्यक्रम	15	0	15	14	0	14
लैटिन अफ्रीकी देश	0	0	0	0	0	0
अफगानिस्तान	83	0	83	74	0	74
अन्य विकासशील देश	45	0	45	33	0	33
ii. वित्तीय	10	17	27	8	1	9
iii. जहाजरानी	1	0	1	1	0	1
इ. कुल जोड़(अ+आ)	422	29	451	386	26	412

स्रोत : केंद्रीय बजट, भारत सरकार

II.6.42 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीय जमाराशि योजनाओं की ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी किए जाने से एनआरआइ जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत प्रवाहों में टर्नअराउंड आया जैसा कि 2008-09 के दौरान अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि से ज्ञात होता है (सारणी 2.89)। सितंबर 2008 में वित्तीय संकट के गहराने से राशि के प्रवाह को बढ़ाने हेतु अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में तीन बार बढ़ोतरी की गई (सारणी 2.90)।

सारणी 2.89: अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं के तहत शेष राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया (मार्च के अंत में)		निवल अंतर्वाह (अप्रैल-मार्च)	
	2008	2009	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
एफसीएनआर(बी)	14,168	13,211	-960	-957
एनआर(ई)आरए	26,716	23,570	109	2,508
एनआरओ	2,788	4,773	1030	2,738
कुल	43,672	41,554	179	4,289

बाह्य ऋण

II.6.43 दीर्घावधि ऋण में वृद्धि होने के कारण मार्च 2009 के अंत में भारत के बकाया बाह्य ऋण में थोड़ी-सी वृद्धि हुई (सारणी 2.91 तथा परिशिष्ट सारणी 55)। दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः व्यापार ऋण तथा द्विपक्षीय ऋण के कारण हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान अनिवासी जमाराशियों में सकारात्मक अंतर्वाह होने से मूल्यांकन प्रभाव के कारण अनिवासी जमाराशियों के अंतर्गत

सारणी 2.90: एनआरआइ जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दरें

अवधि	एनआर(ई)आरए जमाराशिया	एफसीएनआर (बी) जमाराशिया
1	2	3
(+) / (-) लिबोर/स्वैप दर		
अप्रैल 24, 2007	लिबोर/स्वैप दर	-75 आधार अंक
सितंबर 16, 2008	+ 50 आधार अंक	- 25 आधार अंक
अक्तूबर 15, 2008	+ 100 आधार अंक	+ 25 आधार अंक
नवंबर 15, 2008	+ 175 आधार अंक	+ 100 आधार अंक

सारणी 2.91: भारत का बाह्य ऋण

मद	(मिलियन अमरीकी डॉलर)		प्रतिशत घट-बढ़	
	मार्च-08	मार्च-09 अ	मार्च-07 की तुलना में मार्च-08	मार्च-08 की तुलना में मार्च-09
1	2	3	4	5
1. बहुपक्षीय	39,490	39,566	11.8	0.2
2. द्विपक्षीय	19,701	20,587	22.6	4.5
3. आइएमएफ	0	0	0	0
4. व्यापार ऋण	10,358	14,604	44.6	41.0
5. वाणिज्यिक उधार	62,337	62,676	50.4	0.5
6. एनआरआई जमाराशियां	43,672	41,554	5.9	-4.8
7. रुपया ऋण	2,016	1,527	3.3	-24.3
8. अल्पावधि ऋण	46,999	49,373	67.1	5.1
कुल ऋण (1 to 8)	224,573	229,887	31.1	2.4
जापन मदे:				
क. दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	177,574	180,514	24.0	1.7
ख. अल्पावधि ऋण	46,999	49,373	67.1	5.1
अ: अनंतिम				
स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक				

बकाया ऋण में मार्च 2008 अंत के स्तर से कमी आई। मूल परिपक्वता के अनुसार, मार्च 2009 के अंत में कुल ऋण में दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋण का हिस्सा क्रमशः 78.5 प्रतिशत तथा 21.5 प्रतिशत था। मुद्रा संयोजन के अनुसार मार्च 2009 के अंत में कुल बाह्य ऋण में यूएस डॉलर में मूल्यवर्गित ऋण का हिस्सा 57.1 प्रतिशत था, जिसके बाद जापानी येन (14.2 प्रतिशत), भारतीय रुपया (13.2 प्रतिशत), एसडीआर (9.2 प्रतिशत) तथा यूरो (4.1 प्रतिशत) का स्थान था।

अल्पावधि ऋण

II.6.44 वैश्विक ऋण बाजारों में तंगी के कारण 2008-09 की दूसरी छमाही में अल्पावधि व्यापार ऋणों की उपलब्धता के बारे में आशंकाओं के बावजूद भारत में अल्पावधि व्यापार ऋण के वित्तीयन में कोई विशेष समस्या नहीं आई। अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर, कुल अल्पावधि ऋण दायित्व मार्च 2009 के अंत में स्थित कुल बाह्य ऋण का 40.6 प्रतिशत था। मार्च 2009 के अंत में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार कुल अल्पावधि ऋण (93.3 बिलियन अमरीकी डॉलर) में 49.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का मूल परिपक्वता आधारित अल्पावधि ऋण तथा 43.9

बिलियन अमरीकी डॉलर का एक वर्ष के अंदर भुगतान किए जाने वाले दीर्घावधि बाह्य ऋण शामिल था। 43.9 बिलियन अमरीकी डॉलर में से अधिकांश हिस्सा (32.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) एनआरआई जमाराशियों का था तथा पिछली प्रवृत्ति को देखते हुए इनके रोलओवर किए जाने की संभावना है।

II.6.45 मार्च 2009 के अंत में अल्पावधि ऋण में, कुल ऋण तथा विदेशी मुद्रा भंडारों के अनुपात के रूप में वृद्धि हुई (सारणी 2.92)। ऋण चुकौती अनुपात भी सुस्थिर तथा यथोचित रूप से कम रहा। बाह्य क्षेत्र की सुभेद्यता के प्रमुख संकेतक विश्व के तीव्र संकटों में से एक की चुनौती के सम्मुख भारत की सतत आघात सहनीयता दर्शाते हैं।

II.6.46 विश्व बैंक द्वारा कैलेंडर वर्ष 2007 के लिए जारी विकासशील देशों के शीर्ष के दस ऋणी देशों के आंकड़ों से स्पष्ट

सारणी 2.92: बाह्य ऋण चुकौती संबंधी भुगतान

मद	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
घटक (मिलि. अम. डॉ.)			
1. बाह्य सहायता @	2,942	3,241	3,381
2. बाह्य वाणिज्यिक उधार*	6,331	9,771	10,401
3. एनआरआई जमाराशियां (ब्याज भुगतान)	1,969	1813	1,547
4. रुपया ऋण चुकौती	162	121	101
5. कुल ऋण चुकौती	11,404	14,946	15,430
6. कुल चालू प्राप्तियां #	242,811	314,014	337,095
सूचक (प्रतिशत)			
7. जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण अनुपात	18.1	19.0	22.0
8. कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण अनुपात	16.4	20.9	21.5
9. विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अल्पावधि ऋण अनुपात	14.1	15.2	19.6
10. बाह्य ऋण के प्रति विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात	116.2	137.9	109.6
11. ऋण चुकौती अनुपात	4.7	4.8	4.6
12. चालू प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान अनुपात	2.3	2.1	1.9
13. चालू प्राप्तियों के प्रति ऋण अनुपात	70.6	71.5	68.2
14. देयता चुकौती अनुपात	6.1	5.9	5.5

@ : गैर-सरकारी ऋणों सहित।

* : व्यापार ऋणों के ब्याज घटकों सहित।

: आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर।

टिप्पणी: 1. इस सारणी में ऋण चुकौती भुगतान के आंकड़ों का लेखांकन भुगतान संतुलन संकलन पद्धति के अनुसार उपचयात्मक लेखांकन पद्धति से किया गया है, इसलिए ये नकदी आधार पर दर्ज किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

2. देयता चुकौती, चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण चुकौती भुगतान तथा लाभ और लाभांश के भुगतान का प्रतिशत दर्शाती है।

सारणी 2.93: दस सर्वाधिक ऋणी देशों की अंतरराष्ट्रीय तुलना, 2007

देश	बाह्य ऋण (बिलि.अम.डॉ.)	जीएनआइ के प्रति बाह्य ऋण(%)	ऋण चुकौती अनुपात(%)	कुल ऋण के प्रति वि.मु.भंडार(%)	रियायती ऋण/ कुल ऋण(%)	अल्पावधि ऋण/ कुल ऋण(%)
1	2	3	4	5	6	7
चीन	374	11.6	2.2	413.9	10.1	54.5
रूस	370	29.4	9.1	129.1	0.4	21.4
तुर्की	252	38.8	32.1	30.4	2.1	16.6
ब्राजील	238	18.7	27.8	75.9	1.0	16.5
भारत	225	19.0	4.8	137.9	19.7	20.9
पोलैंड	195	47.7	25.6	33.6	0.4	30.9
मैक्सिको	178	17.7	12.5	49.0	0.6	5.1
इंडोनेशिया	141	33.9	10.5	40.4	26.2	24.8
अर्जेंटीना	128	49.7	13.0	36.1	1.3	29.8
कजाकिस्तान	96	103.7	49.6	18.4	1.0	12.2

स्रोत : भारत से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा 2007-08 के लिए प्रकाशित आंकड़े हैं तथा अन्य देशों के आंकड़े विश्व बैंक के ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनांस ऑनलाइन डाटाबेस में यथा उपलब्ध दिसंबर 2007 के अंत के आंकड़े हैं।

होता है कि सबसे अधिक बाह्य ऋण वाले देशों के बीच भारत का स्थान पांचवां बना हुआ है (सारणी 2.93)। तथापि, चीन का ऋण चुकौती अनुपात सबसे कम था, उसके बाद भारत का था।

विदेशी मुद्रा भंडार

II.6.47 2008-09 के दौरान, निवल पूंजी बहिर्वाह के साथ-साथ चालू खाता घाटे के बढ़ जाने से विदेशी मुद्रा भंडार में 20.1 बिलियन अमरीकी डॉलर (मूल्यांकन को छोड़कर) की कमी आई जबकि 2007-08 में विदेशी मुद्रा भंडार में 92.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई थी। अमरीकी डॉलर की तुलना में प्रमुख मुद्राओं के मूल्यों में कमी आने के कारण 37.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की मूल्यांकन हानियों को हिसाब में लेने पर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2008-09 के 57.7 बिलियन अमरीकी डॉलर घटकर मार्च 2009 के अंत में 252.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (परिशिष्ट सारणी 56 तथा सारणी 2.94)। विदेशी मुद्रा भंडार में इस मात्रा की कमी ने विदेशी मुद्रा बाजार में कुछ दबाव बनाया। यद्यपि अमरीकी डॉलर तथा यूरो दोनों हस्तक्षेप मुद्राएं हैं, तथापि विदेशी मुद्रा भंडार को अमरीकी डॉलर में ही मूल्यवर्गित तथा प्रकट किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में कोई भी परिवर्तन मुख्यतः विदेशी मुद्रा की दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को ठीक करने हेतु रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण मूल्यांकन में हुए बदलाव के कारण होता है।

II.6.48 भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला एक प्रमुख देश बना रहा, तथा ऐसे भंडार ने गंभीर बाह्य आघातों से निपटने में मदद की (सारणी 2.95)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, संकट के दौरान आहरणों के बावजूद, संतोषजनक स्तर पर बना रहा जैसा कि पर्याप्तता संबंधी विभिन्न संकेतकों, जैसे कि वणिक आयात कवर (मार्च 2009 के अंत में 10.3 माह) तथा ऋण के प्रति भंडार के अनुपात (मार्च 2009 के अंत में 109.6 प्रतिशत) से स्पष्ट होता है।

सारणी 2.94: विदेशी मुद्रा भंडार में घटबढ़ के स्रोत

(मिलियन अम.डॉ.)

मद	2007-08	2008-09
1	2	3
I. चालू खाता शेष	(-) 17,034	(-) 29,817
II. पूंजी खाता (निवल)*	109,198	9,737
<i>जिसमें से:</i>		
(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15,401	17,496
(ii) एफआइआइ	20,327	(-) 15,017
(iii) बाह्य वाणिज्यिक उधार	22,633	8,158
III. मूल्यन में परिवर्तन जोड़ (I+II+III)	18,380	(-) 37,658
	110,544	(-) 57,738

* : 'भूल-चूक' शामिल है।

टिप्पणी: वि.मु. भंडार में वृद्धि (+) /कमी (-).

सारणी 2.95: दस प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का विदेशी मुद्रा भंडार
(मार्च 2009 के अंत में)

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

देश	विदेशी मुद्रा भंडार*
1	2
1. चीन	1,953.7
2. रूस	368.1
3. ताइवान	300.1
4. भारत	242.4
5. दक्षिण कोरिया	206.3
6. ब्राजील	189.4
7. हांगकांग	186.2
8. सिंगापुर	166.3
9. थाईलैंड	113.7
10. मैक्सिको	85.5

* : चीन को छोड़कर शेष में सोना शामिल नहीं है।

टिप्पणी : भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आइआइएफसी(यूके) द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में निवेशित 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि शामिल नहीं है।

स्रोत : दि इकोनॉमिस्ट

II.6.49 सोने के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार की धारिता 31 मार्च 2009 को 357.8 टन थी, जो मूल्य के रूप में कुल भंडार का 3.8 प्रतिशत है। इसमें से 65 टन सोना 1991 से बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक(बीआइएस) के पास विदेश में रखा गया है। सोने की धारिता अपरिवर्तित रही है तथा इस रिजर्व का प्रबंधन निष्क्रिय रूप से किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) निर्गम विभाग (विदेशी प्रतिभूतियां) तथा बैंकिंग विभाग (विदेश में रखी राशियां तथा निवेश) की आस्तियों के रूप में रखी जाती हैं। सोना निर्गम विभाग (स्वर्ण मुद्रा तथा बुलियन के अंतर्गत) के साथ-साथ बैंकिंग विभाग में भी रखा जाता है। एसडीआर तथा आरटीपी भारत के आधिकारिक रिजर्व का हिस्सा होने पर भी ये भारत सरकार के पास रखे जाते हैं तथा ये भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में परिलक्षित नहीं होते।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

II.6.50 विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री लेनदेनों के कारण होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के

पोर्टफोलियो में रखी विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के नियोजन से आय होती है। विदेशी सहायता के रूप में भारत सरकार को प्राप्त राशि भी भंडार में शामिल होती है। विदेशी मुद्रा भंडार को प्रकट करने की अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अपने भंडार को अमरीकी डॉलर में प्रकट करता है, अतः मुद्रा का आवधिक पुनर्मूल्यांकन भंडार के स्तर को प्रभावित करता है।

II.6.51 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के निर्देशित लक्ष्य इस संबंध में व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सुरक्षा, तरलता तथा प्रतिलाभ रहे हैं। देश की विदेशी मुद्रा मांग में समय के साथ काफी अंतर हो सकता है और यह अंतर देश द्वारा स्वीकार की गयी विदेशी मुद्रा दर व्यवस्था तथा देश की अर्थव्यवस्था के खुलेपन की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों से आता है।

II.6.52 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) तथा सोने के नियोजन हेतु विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के निवेश के व्यापक क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस), विदेशी वाणिज्य बैंक के पास जमा, सरकारी तथा अधिराष्ट्र संस्थाओं की 10 वर्ष से अनधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाली ऋण संबंधी प्रतिभूतियां एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखतें अथवा संस्थाएं शामिल हैं (सारणी 2.96)। अधिनियम के अनुसार निवेश संबंधी रणनीति का लक्ष्य मुद्रा, बाजार तथा लिखतों में विविधता लाना है। इसलिए, विदेशी मुद्रा आस्तियों का निवेश बहु-मुद्रा तथा बहु-बाजार पोर्टफोलियो में किया जाता है। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय बाजार के घटनाक्रमों की जवाबी कार्रवाई के रूप में विदेशी वाणिज्य बैंकों के प्रति एक्सपोजर संबंधी रिजर्व बैंक की रणनीति में समुचित बदलाव लाया गया। निवेश के स्वरूप संबंधी निर्णय पोर्टफोलियो प्रबंधन के व्यापक मानदंडों अर्थात् सुरक्षा, तरलता तथा प्रतिलाभ के आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों का निवेश उन श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली आस्तियों में किया जाता है जिनमें से उल्लेखनीय हिस्से को अल्प नोटिस पर नकदी में बदला जा सकता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों को विभिन्न पोर्टफोलियो हिस्सों में रखा गया है ताकि तरलता तथा प्रतिलाभ संबंधी विभिन्न लक्ष्यों के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखा जा सके।

सारणी 2.96: विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन का स्वरूप

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

31 मार्च को	विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख+ग)	(क) प्रतिभूतियां	(ख) अन्य केंद्रीय बैंक, बीआइएस और अं.मु.कोष के पास	(ग) विदेशी वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियां / बाहरी निधि प्रबंधकों के पास रखी निधियां
1	2	3	4	5
2004	1,07,448	35,024	45,877	26,547
2005	1,35,571	36,819	65,127	33,625
2006	1,45,108	35,172	65,399	44,537
2007	1,91,924	52,996	92,175	46,753
2008	2,99,230	1,03,569	1,89,645	6,016
2009	2,41,426*	1,34,792	1,01,906	4,728

* : आइआइएफसी (युके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में निवेश किए गए 250 मिलियन अम. डॉलर को छोड़कर।

II.6.53 भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार एवं विदेशी मुद्रा बाजार में अपने परिचालनों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव संबंधी आंकड़े साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक (डब्ल्यूएसएस) में साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ा संप्रसारण (एसडीडीएस) मानक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि स्थिति संबंधी प्रकटन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टों तथा अन्य प्रकाशनों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन संबंधी विषय रहता है ताकि समुचित जानकारी विश्लेषण के साथ उपलब्ध करायी जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर भी डाली जाती है।

अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति

II.6.54 मार्च 2008 के अंत और मार्च 2009 के अंत के बीच अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में कमी की दर अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी की दर से अधिक होने के कारण भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 12.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में आई कमी मुख्यतः रिज़र्व आस्तियों में 57.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की कमी आने के कारण थी। तथापि, मार्च 2008 के अंत तथा मार्च 2009 के अंत के बीच प्रत्यक्ष बाह्य निवेश में 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय देयताओं में आई कमी मुख्यतः विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बहिर्वाह के कारण पोर्टफोलियो इक्विटी

निवेश की मात्रा में कमी आने तथा मूल्यांकन परिवर्तन के प्रभाव के कारण थी (सारणी 2.97)।

सारणी 2.97: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	मार्च अंत में			
	2006	2007	2008 आंस	2009 अ
1	2	3	4	5
अ. आस्तियां	183.9	247.3	385.6	349.9
1. प्रत्यक्ष निवेश	15.9	31.0	49.8	67.3
2. पोर्टफोलियो निवेश	1.0	0.9	1.5	0.8
2.1. इक्विटी प्रतिभूतियां	0.5	0.5	1.4	0.8
2.2. ऋण प्रतिभूतियां	0.5	0.4	0.1	0.0
3. अन्य निवेश	15.4	16.2	24.5	29.9
3.1. व्यापार ऋण	-0.3	0.7	-0.1	6.8
3.2. ऋण	2.4	3.5	11.6	6.2
3.3. मुद्रा और जमाराशियां	10.0	7.8	7.8	10.3
3.4. अन्य आस्तियां	3.3	4.2	5.2	6.6
4. आरक्षित आस्तियां	151.6	199.2	309.7	252.0
आ. देयताएं	243.7	308.7	438.4	415.3
1. प्रत्यक्ष निवेश	52.4	77.0	118.3	124.8
2. पोर्टफोलियो निवेश	64.2	79.4	120.1	84.9
2.1. इक्विटी प्रतिभूतियां	54.7	63.3	98.6	64.8
2.2. ऋण प्रतिभूतियां	9.5	16.2	21.5	20.2
3. अन्य निवेश	127.1	152.2	200.0	205.6
3.1. व्यापार ऋण	21.2	27.7	45.2	48.0
3.2. ऋण	68.0	80.8	106.9	114.1
3.3. मुद्रा और जमाराशियां	37.3	41.7	44.8	42.3
3.4. अन्य देयताएं	0.6	2.1	3.1	1.3
इ. निवल स्थिति (अ-आ)	-59.8	-61.4	-52.9	-65.3
जापान :				
ऋण देयताएं / कुल देयताएं (प्रतिशत)	56.1	55.5	51.2	55.4
आंसं.: आंशिक संशोधित	अ: अनंतिम			

II.6.55 2008-09 के दौरान की गतिविधियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट के गहरे आघातों, जिनके कारण भारत के निर्यात में कमी आई, चालू खाता घाटे में हुई वृद्धि, पूंजी प्रवाह में आए विपर्यय तथा विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के बावजूद भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ रही तथा इसके कारण विदेशी मुद्रा बाजार में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया। सीएडी-जीडीपी अनुपात व्यवस्थित सीमा के अंदर बना रहा। गहरे वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सेवा निर्यातों तथा विप्रेषणों ने भारत के चालू खाते की स्थिति को सतत समर्थन दिया। वर्ष की दूसरी छमाही में पूंजी प्रवाह में विपर्यय की कतिपय स्थितियों के बावजूद, एफडीआई तथा एनआरआई जमा राशियों के अंतर्गत आप्रवाह में सुदृढ़ता देखी गई, जो दीर्घावधि निवेश स्थल के रूप में भारत के प्रति आकर्षण के साथ-साथ पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए किये गये विभिन्न उपायों के प्रभाव को परिलक्षित करती है। चालू खाता, बाह्य ऋण तथा रिज़र्व की पर्याप्तता संबंधी बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ता के विभिन्न संकेतक दर्शाते हैं कि बाह्य स्थिरता पर निरंतर

नीतिगत बल दिए जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर वैश्विक संकट के आघातों को झेल सकी तथा समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकी।

II.6.56 भारत में पूंजी प्रवाह संबंधी विनियमों को पिछले तीन वर्षों के दौरान समष्टि आर्थिक स्थितियों, वित्तीय क्षेत्र विकास के हालात, वित्तीय संस्थाओं की जोखिम उठाने की क्षमता एवं वित्तीय बाजारों की गहनता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त रूप से उदार किया गया है। साथ ही, पूंजी के प्रवाह के उदारीकरण के क्षेत्र में सरकार ने विविधीकृत पूंजी खाते को महत्व देने की दृष्टि से वरीयता क्रम में ऋण आप्रवाह की अपेक्षा इक्विटी आप्रवाह को महत्व दिया है। चालू खाता घाटे एवं बाह्य ऋण के वहनीय स्तर तथा देश की सुविवेचित आवश्यकता के अनुरूप क्रमिक उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए पूंजी खाते के सक्रिय प्रबंधन और वैश्वीकृत विश्व में पर्याप्त रिज़र्व के रूप में स्व-बीमा को सुदृढ़ करने पर जो समष्टि स्तरीय नीतिगत फोकस रहा है वह वर्तमान वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में सही प्रमाणित हुआ है।